मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई, 2014 सत्र

बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2014

(25 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 13]

मध्यप्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2014

(25 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री विश्वास सारंग--अध्यक्षजी, आज बहुत खुशी की बात है कि ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हिन्दुस्थान की हैसियत को और बढ़ाया है. जो ब्रिक्स बैंक बनने वाला है उसका पहला सीईओ भी भारतीय होगा . यह सबके लिए बहुत खुशी की बात है. सदन की ओर से श्री नरेन्द्र मोदी जी को और भारत सरकार को बहुत बधाई.

प्रश्न क्रमांक--1

लांजी तहसील में पी.आर.एल. कंपनी द्वारा बिना डायवर्सन के हाट मिक्स प्लांट लगाया जाना

1. (*क्र. 1555) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लांजी-सालेटेकरी मार्ग पर नगर पंचायत की सीमा में खसरा नं. 693/1ग रकबा 0.365 हेक्टेयर खसरा क्र. 694/1ड रकबा 0.405 हेक्टेयर पर विषयांकित कंपनी द्वारा हाट मिक्स प्लांट लगाया गया है? (ख) क्या उक्त प्लांट डायवर्सन किये बगैर उक्त भूमि पर चालू कर दिया गया? क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसकी अनुमति ली गयी है? यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्या यह सही है कि इसके पूर्व भी उक्त कंपनी ने शासकीय जमीन पर अवैध रूप से प्लांट लगाया था जिसे बाद में शासन ने खाली करवाया? क्या यह सही है कि प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित भूमि पर भारी मात्रा में अवैध उत्खनन से निकाली गयी रेत इकट्ठा की गयी है?

मंत्री,राजस्व(श्री रामपाल सिंह)-- (क) जी हां. (ख) जी हां. प्रकरण विचाराधीन है.(ग) जी नहीं. हां उत्खनन से निकाली गई रेत इकट्ठा की गई है. खनिज रेत का अवैध उत्खनन/भण्डारण का प्रकरण दर्ज किया गया है. जो वर्तमान में विचाराधीन है.

सुश्री हिना लिखीराम कांवरे-- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के प्रश्नांश 'ग' के उत्तर में यह बताया है कि पी आर एल कंपनी ने किसी शासकीय जमीन पर अवैध रुप से प्लांट नहीं लगाया था. मैं माननीय मंत्रीजी के इस उत्तर से सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, जिसमें कलेक्टर बालाघाट द्वारा पी आर एल कंपनी को दिनांक 13.09.2010 को 5 एकड़ शासकीय भूमि जो कि बड़े झाड़ का जंगल है, जिसे प्लांट हेतु आवंटित किया ही नहीं जा सकता. तहसीलदार किरनापुर ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रुप से इस बात का उल्लेख किया था, इसके बावजूद कलेक्टर बालाघाट द्वारा लीज़ आवंटित कर दी गई. मैं उसका गहराई में नहीं जाना चाहती. अध्यक्ष महोदय, शिकायत होने के बाद कलेक्टर बालाघाट ने लीज़ स्वीकृत होने के मात्र 4 महीने बाद दिनांक 25.01.2011 को लीज़ निरस्त कर दी तथा प्लांट को तत्काल 7 दिन अंदर हटाने की कार्रवाई करने के लिए उन्होंने तहसीलदार किरनापुर को कहा. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि तहसीलदार के बार बार नोटिस देने के बावजूद इस कंपनी ने प्लांट खाली नहीं किया और तहसीलदार को इतना प्रताड़ित किया कि तहसीलदार ने अपने शासकीय आवास में आत्महत्या कर ली. आज भी उनका परिवार इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या मानते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया प्रश्न करें.

सुश्री हिना लिखीराम कांवरे-- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि कलेक्टर बालाघाट द्वारा लीज़ निरस्त होने के बावजूद कैसे यह प्लांट दो वर्षों तक अवैध रुप से चलता रहा. क्या माननीय मंत्रीजी इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायेंगे?

श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, यह जो बिना डायवर्सन के प्लांट चालू किया गया था, उसके खिलाफ हमने कार्यवाही की है और इसमें धारा 172 के तहत 540540 रुपए का उस पर जुर्माना किया है. माननीय सदस्य और जो जानकारी दे रहे हैं और विस्तार से अगर ऐसी कोई बात जो किसी की आत्महत्या की बात कर रही हैं, यह प्रश्न में तो नहीं है लेकिन अलग से आप बताएंगी तो हम उस पर भी कार्यवाही करेंगे.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे - अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब 'जी नहीं' दिया था, उसी लिए मैंने यह बात स्पष्ट रूप से कही है.

अध्यक्ष महोदय- इसमें तो (क) और (ख) में उत्तर 'जी हां' आया है.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे - अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी संशोधित उत्तर आया है इसमें प्रश्नांश (ग) में 'जी नहीं' लिखा है.

अध्यक्ष महोदय - वह अभी खाली करवाया नहीं है ना कि हो गया खाली?

सुश्री हिना लिखीराम कावरे - अध्यक्ष महोदय, वह खाली हो गया है, परन्तु कैसे खाली हुआ है, इसी की मुझे जांच करवानी है.

अध्यक्ष महोदय - अब तो वह खाली हो गया है. अब क्या है?

सुश्री हिना लिखीराम कावरे - अध्यक्ष महोदय, जैसा आप आदेश करें, मैं एक और प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहती हूं, जिसका उत्तर उन्होंने मुझे अभी यहां पर दिया है. एक बार गलती करने के बावजूद सारे नियमों की अनदेखी करते हुए पीआरएल कंपनी के द्वारा एक निजी भूमि-स्वामी हक की जमीन पर नगर पंचायत लांजी की बिना एनओसी लिये, पर्यावरण विभाग की बिना एनओसी लिये, वन विभाग की बिना एनओसी लिये, यहां तक कि ..

अध्यक्ष महोदय - यह प्रश्न इससे उद्भूत नहीं होता है.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे - अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्‌भूत होता है क्योंकि उन्होंने उसी बात का उत्तर दिया है.

श्री रामपाल सिंह - उत्तर दे दिया है तो आप संतुष्ट हो जाइए. आपके पूछने के पहले ही उत्तर दे दिया है.

अध्यक्ष महोदय - यह प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है. प्रश्न क्रमांक 2..

सुश्री हिना लिखीराम कावरे - अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्‌भूत होता है, मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि इस कंपनी पर कठोर से कठोर कार्यवाही करते हुए इस कंपनी के पूरे प्लांट को जप्त करने के लिए कार्यवाही की मांग करती हूं.

श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही करेंगे.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे - धन्यवाद, माननीय मंत्री जी.

मजरों एवं टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

2. (*क्र. 1922) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मजरों एवं टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? (ख) भोपाल एवं जबलपुर संभाग में कितने मजरा एवं टोला ऐसे हैं, जिनको शासन की नीति अनुसार राजस्व ग्राम बनाया जा सकता है? उनको राजस्व ग्राम क्यों नहीं बनाया गया? (ग) कब तक उनको राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जायेगा? (घ) शेष मजरा टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में विभाग की क्या योजना है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 के नियमों के अनुसार तथा जिनकी आबादी 200 से अधिक है और जो मूल ग्राम से 2 कि.मी. या अधिक दूरी पर स्थित हैं, ऐसे मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने के शासन निर्देश हैं. (ख) भोपाल एवं जबलपुर संभाग में 163 मजरे टोले हैं, जिन्हें शासन की नीति अनुसार राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित किया गया है. राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु अधिकार अभिलेख बनाये जाने की कार्यवाही चल रही है. (ग) ग्रामवार अधिकार अभिलेख पूर्ण होने पर अभिलेख एवं नक्शा जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिया जायेगा. अक्टूबर 2014 तक 125 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने का लक्ष्य है. (घ) शेष 38 मजरे टोलों को मार्च 2015 तक राजस्व ग्राम बनाये जाने का लक्ष्य है.

श्री गोविन्द सिंह पटेल - अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी और मध्यप्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेजरे टोले उपेक्षा की जिंदगी जी रहे थे उनको राजस्व ग्राम बनाया, उससे वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, यह एक बहुत अच्छा कदम है. इसमें मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि शासन के निर्देश जारी होने के बाद से प्रश्न दिनांक तक उक्त संभाग में कितने मेजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किया है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि प्रश्नांश (ख) के उत्तर में बताया है कि अधिकार अभिलेख बनाये जाने की कार्यवाही चल रही है तो उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी, समयावधि बताएं?

श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, 2 संभागों के बारे में माननीय विधायक जी ने पूछा था तो जबलपुर में 97 मेजरे टोले लिये हैं और भोपाल संभाग में 66 मेजरे टोले लिये हैं, उनकी समयावधि लिखित में माननीय विधायक जी को दे चुके हैं, उसमें लिखा हुआ है. समयावधि है 6 टोले आपके नरसिंहपुर जिले के हैं, इसकी जानकारी आपको दी है, उसमें भी हम जल्दी कार्यवाही करेंगे. यह बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मध्यप्रदेश में हो रहा है, इसको जल्दी प्राथमिकता में कर रहे हैं.

श्री गोविन्द सिंह पटेल - अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 125 अभी अक्टूबर में हो रहे हैं और बाकी मार्च में होंगे तो 163 मेजरे टोले अभी अक्टूबर में क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं, यह पूछना चाहता हूं? और यह भी पूछना चाहता हूं कि 2 संभागों में और ज्यादा मजरे टोले होंगे, पूरे मजरे टोले चिह्नित नहीं हुए हैं तो बाकी मेजरे टोले जो 200 की आबादी और 2 कि.मी. की दूरी पर हैं, कब तक चिह्नित कर लिये जाएंगे, जिससे वे भी मुख्यधारा से जुड़ सकें?

श्री रामपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो मध्यप्रदेश के अंदर पहल हो रही है, मजरे, टोले हैं, 200 जहां की जनसंख्या है वहां के तो चिन्हित किए हैं. माननीय विधायक जी ने कहा है कि और

छोटे भी मजरे टोले हैं उनके बारे में भी हम विचार करेंगे और माननीय विधायक जी की जो चिन्ता है ,इसकी गति और हम बढ़ायेंगे.

श्री गोविन्द सिंह पटेल- धन्यवाद मंत्री जी.

प्रश्न संख्या(3) (अनुपस्थित)

वैज्ञानिकों द्वारा बिना जुताई के खेती करना लाभदायक साबित किया जाना

4. (*क्र. 3002) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बोरलॉग इंस्टीट्यूट फार साऊथ एशिया की यूनिट लखनवाड़ा, जिला जबलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा बिना जुताई के खेती करना लाभदायक साबित किया गया है? (ख) क्या यह सही है कि जोते गये खेतों की तुलना में बिना जुताई के खेतों में प्रति एकड़ पैदावार गेहूं की 15 से 23 क्विंटल एवं धान क्रांति की 27 क्विंटल हो रही है? (ग) क्या यह भी सही है कि कृषि विभाग द्वारा (गहरी) जुताई को प्रोत्साहित किया जाता है एवं जुताई हेतु रोटावेटर तथा अन्य यंत्रों के अधिक उपयोग करने हेतु अनुशंसा की जाती है एवं ऐसे यंत्रों पर अनुदान भी दिया जाता है? (घ) यदि बिना जोते खेतों से खर्च में 30 प्रतिशत की बचत होती है एवं तुलनात्मक रूप से अधिकतम पैदावार हो रही है, तो क्यों न प्रदेश के किसानों को ऐसी तकनीक का प्रदर्शन कराया जावे ताकि आम किसान को लाभ हो? क्या कृषि विभाग इस तकनीक के माध्यम से कृषकों को लाभांवित कराने हेतु इंस्टीट्यूट में भ्रमण करायेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरी शंकर बिसेन) : (क) जी हां. (ख) जी हां. बिना जोते गये खेतों में वर्ष 2013-14 में गेहूं की पैदावार 12 से 22.2 क्विंटल प्रति एकड़ मिली है. खरीफ 2013 में क्रांति धान की पैदावार 27 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिली थी. (ग) जी हां. (घ) जी हां. राज्य शासन द्वारा बोरलॉग संस्थान को राज्य एवं जिला स्तर का खेत तीर्थ घोषित किया गया है. इस तकनीक से कृषकों को लाभान्वित करने हेतु बोरलॉग संस्थान में कृषि मेले का आयोजन, फील्ड भ्रमण, जिला एवं अंतर जिला कृषक भ्रमण, आदि कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में कराया जा रहा है.

श्री सुशील कुमार तिवारी- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है ,वैसे उससे तो मैं संतुष्ट हूं. किन्तु एक बात बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी दिनांक 25/5 को बोरलॉग इन्स्टीट्यूट मे गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने भ्रमण किया है. पहली बार ऐसा अवसर हुआ है कि वे सीधे रेलवे स्टेशन से सुबह छः बजे पूरे अमले के साथ वहां गए जिससे हम लोगों को भी सुबह 5 बजे जाना पड़ा. कृषकों के मामले में इतनी चिन्ता करना भी बड़ा कठिन काम है. खुद भी नहीं सोते,दूसरों को भी नहीं सोने देते. माननीय मंत्री जी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि बोरलॉग इन्स्टीट्यूट में पांच किलो मीटर दूर तक रूकने के लिए कहीं छाया या रूकने का स्थान नहीं है, इसलिए निवेदन है कि वहां पर एक कृषक भवन बनाया जाय और वहां जाने के लिए सुलभ मार्ग बनाया जाय.

श्री गौरी शंकर बिसेन- माननीय अध्यक्ष महोदय,ये एशिया का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रिसर्च इंन्स्टीट्यूट है. इसमें शुष्क खेती के ऊपर अनुसंधान हो रहा है और मध्यप्रदेश सरकार की हमारी जो खेत तीर्थ दर्शन योजना है इसके तहत भी हम यहां समय समय पर किसानों को भेजते हैं. मैं तो आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं ,इस संस्थान को हम सबको देखने की आवश्यकता है. यहां पर जो अनुसंधान हो रहा है कि बगैर जुताई के सीधे सोईंग हम किस तरह से जमीन में कर सकें जिससे कि काश्त कम होकर प्रोडक्शन में कोई अंतर नही आएगा. काफी महत्वपूर्ण हमारा यह संस्थान है. जिसके संदर्भ में जवाहर लाल कृषि विश्व विद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी , उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा यह कहा है. मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मई महीने में उन्होंने सूखे धान की सोईंग कर दी थी और काफी अच्छा मक्के के ऊपर, गेहूं के ऊपर,धान के ऊपर यहां पर अनुसंधान का काम हो रहा है और यहां पर मशीनरी , जिस संदर्भ में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने ,सरकार ने मशीनरी पर व्याज में छूट दी है उसको भी हम मशीनीकरण करने में तीन संस्थानों से अच्छी ट्रेनिंग मिलती है. जो माननीय सदस्य ने चिन्ता

जाहिर की कि वहां पर जो हमारे कृषक जाते हैं उनके रूकने के लिए वहां पर कोई रेस्ट हाऊस इत्यादि हो या छाया का कोई प्रबंध हो. तो इस संस्थान के अधिकारियों के साथ हम बैठ कर के कोई न कोई रास्ता निकालेंगे. इसमें पैसे की कमी नहीं है. यह world granted और भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था है इसमें अच्छा से अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे.

श्योपुर जिले में स्वीकृत नल-जल योजनाएं

5. (*क्र. 168) श्री रामनिवास रावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले के विजयपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2009 से लेकर नवम्बर 2013 तक किन-किन स्थल जल/नल-जल/मुख्यमंत्री/बी.आर.जी.एफ./पुनर्वास एवं विधायक निधि से पेयजल योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय कर निर्माण कार्य कराया गया? कृपया योजना का नाम, प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक सहित योजनावार बतावें? (ख) प्रश्नांश "क" के अन्तर्गत स्वीकृत की गई योजनाओं हेतु स्वीकृत राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना पर व्यय की गई एवं कितनी-कितनी राशि शेष है? योजनावार बतावें? (ग) क्या यह सही है कि आज भी कई ग्रामों की पेयजल योजनाएं केवल इसलिए बंद हैं कि वहां पर जनरेटर सेट प्रदाय नहीं किए गए हैं? क्या विभाग ऐसी योजनाएं जहां विद्युत नहीं है, को चिन्हित कर शेष राशि से जनरेटर क्रय कर प्रदाय करेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो उक्त योजनाओं का संचालन किस प्रकार किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार. (ग) जी नहीं. जी हां. माह अक्टूबर, 2014 तक. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

श्री रामनिवास रावत- अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से मैने अपने क्षेत्र की नल जल योजना के संबंध में प्रश्न किया था और मेरा जो मूल प्रश्न था उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे कई प्रश्नों के मूल स्वरूप परिर्तित करके उत्तर दिये जा रहे हैं. अतः भविष्य में मेरी बिना सहमति के मूल स्वरूप को परिवर्तित न किया जाय...

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जरा जोर से बोलें.

श्री रामनिवास रावत- मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैने जो मूल प्रश्न पूछा था , प्रश्न(ख) कि -प्रश्नांश (क) के अंतर्गत स्वीकृत की गई योजनाओं हेतु स्वीकृत की गई राशि में से कितनी कितनी राशि किस किस कार्य पर व्यय की गई. तो वह किस किस कार्य की जगह किस किस योजना में व्यय की गई यह लिखा है. तो वह इकट्ठी राशि बता दी गई है. हमारा उद्देश्य था कि योजना में किस

किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की, कितनी शेष थी और उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं. यह उद्देश्य था. अध्यक्ष महोदय, भविष्य में आपसे अपेक्षा चाहूंगा कि सदस्यों के मूल प्रश्नों में तब तक संशोधन न करें जब तक कि सदस्य उसमें सहमति न दे.

अध्यक्ष महोदय—असल में कई बार माननीय सदस्य बहुत विस्तृत जानकारियां मांग लेते हैं. इसलिए संशोधित करके ग्राह्य करते हैं. नियम 38 में ऐसा प्रावधान है, पर आपसे जानकारी बुला लेंगे.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, सदस्य से संशोधन करा लेना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय—जानकारी में ला देंगे.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 110 नल जल योजनाएं स्वीकृत हुईं, उसमें काफी पूर्ण बताई गईं और काफी अपूर्ण बताई गईं. वर्ष 2010 की 7 नलजल योजनाएं जो अपूर्ण हैं, इनको कब तक पूर्ण करा देंगे? क्रमांक 15 पर अपूर्ण है और क्रमांक-7 पर केरका नलजल योजना को पूर्ण बता रहे हैं. मैंने प्रश्न ही इस तरह की योजनाओं की वजह से किया. यहां पर 7.40 लाख की स्वीकृति है और आपने 4.15 लाख व्यय किया है और इसको पूर्ण बता दिया. बोर कर दिया गया है, मोटर दे दी गई है, पाईप लाईन डाल दी गई है, लेकिन वहां लाइट नहीं है. माननीय मंत्री जी वह पूर्ण होकर काहे से चल रही है, बता दें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—आपकी विधानसभा में सारी योजनाओं में काम चल रहा है. हमने परिशिष्ट में सारी जानकारी दे दी है.

अध्यक्ष महोदय—आप कोई प्वाइंटेड प्रश्न पूछ लें.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा. माननीय मंत्री जी से मैं सीधा सीधा प्रश्न करता हूं कि आप यहां से किसी अधिकारी को भेजकर मेरे यहां की संपूर्ण

योजनाओं का आप परीक्षण करा लेंगी कि कितनी बंद हैं, कितनी चालू हैं, उनमें क्या क्या कमी है और इन्हें कितने समय में सभी को चालू करा देंगी?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—अध्यक्ष महोदय, इनके यहां सारी योजनाओं पर काम चल रहा है और हमने कहने के पहले वहां जांच के लिए एक दल भेजा था, हमने जांच करवा ली और काम सही नहीं पाया गया, इसलिए हमने इ.इ. को सस्पेन्ड कर दिया है और शिवपुरी के इंजीनियर को चार्ज दे दिया है और त्वरित गति से काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी योजनाएं पूरी हो जाएंगी.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उद्देश्य न किसी को निलंबित करना है, न किसी के खिलाफ कार्यवाही करना है. मेरा उद्देश्य है कि मेरे क्षेत्र की जनता को पानी मिले. शासन ने राशि स्वीकृत की है, शासन राशि व्यय कर रहा है, इसलिए यह योजनाएं कब तक पूर्ण करा दी जाएंगी, और कब तक चालू करा दी जाएंगी? मेरा कहना है कि केरका केवल आदिवासी गांव है और वहां पंचायत का जनरेटर तक खराब पड़ा है, 11 हजार रूपए मैंने अपनी जेब से दिए हैं और उसे ठीक कराया है. डीजल के लिए पैसे एक महीने के लिए दिए हैं और उसके बाद वह लोग खुद चंदा करके पैसा उगाह कर जनरेटर चला रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां विभाग का जनरेटर जाना चाहिए था, जो नहीं पहुंचा. इस तरह से आपकी योजनाएं चल रही हैं. मेरा यह कहना है कि आप इनकी व्यवस्था करा दें. दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इन योजनाओं का संधारण ग्राम पंचायत से किया जाता है. ग्राम पंचायतें इनका संधारण नहीं करतीं और पी.टी.जी. ग्रुप, विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया आदिवासी इनके गांव में भी यह योजना है. डीजल की व्यवस्था ग्राम पंचायतें नहीं करतीं.

अध्यक्ष महोदय—आप एक प्वाइंटेड प्रश्न कर दें.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि क्या ऐसे लोगों को जो पी.टी.जी. ग्रुप है या ट्रायबल एरिया है या अधिसूचित क्षेत्र है, वहां लोगों के पास डीजल के पैसे नहीं होते तो

क्या ऐसी व्यवस्था कराएंगी कि डीजल सरकार दे और उस योजना को चलवाएं और इन योजनाओं का संधारण पी.एच.इ. विभाग ले लें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हम ऐसी आवश्यक व्यवस्था वहां कराएंगे और हम दो महीने के अंदर वहां पर जनरेटर रखा देंगे.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय,वहां कौन व्यवस्था कराएगा?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—सरकार कराएगी. दो महीने में सारी चालू हो जाएंगी.

श्री रामनिवास रावत—धन्यवाद मंत्री जी, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको घर में आकर भी धन्यवाद दूंगा.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—आपकी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य है.

श्री दुर्गालाल विजय—अध्यक्ष महोदय, यह श्योपुर जिले से संबंधित प्रश्न है, मुझे एक सवाल पूछ लेने दें.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, पर्याप्त हो गया है और सदस्यों के भी प्रश्न हैं.

प्रश्न संख्या—(6)—

छतरपुर जिले की कृषि उपज मण्डियों की आय-व्यय

6. (*क्र. 3010) श्रीमती ललिता यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितनी कृषि उपज मण्डी हैं? किस-किस मण्डी में कौन-कौन लायसेंसधारी व्यापारी हैं? (ख) छतरपुर जिले की कृषि उपज मण्डियों को वर्ष 2012-13, 2013-14 में कितनी-कितनी आय किन-किन स्त्रोतों से हुई और उसके ऐवज में कितना व्यय किस-किस कार्य में किया गया? मण्डीवार, कार्य का नाम खर्च की राशि सहित बतायें? (ग) छतरपुर जिले की कृषि उपज मण्डियों द्वारा खर्च की गई राशि किस-किस के आदेश से की गई?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरी शंकर बिसेन) : (क) छतरपुर जिले में 07 कृषि उपज मण्डियां हैं, मण्डीवार लायसेंसधारी व्यापारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है. (ख) छतरपुर जिले की 07 कृषि उपज मण्डी समितियों को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में हुई आय का मण्डीवार मदवार स्त्रोतवार तथा वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर दर्शित है. आय के ऐवज में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में विभिन्न कार्यों/मदों में किया गया विवरण मंडीवार, कार्यवार/मदवार तथा वर्षवार व्यय का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' पर दर्शित है. (ग) छतरपुर जिले की कृषि उपज मंडियों द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में खर्च की गई राशि प्रत्यायोजित वित्तीय प्रशासनिक अधिकार स्वीकृत बजट प्रावधान के अनुरूप व्यय की गई.

श्रीमती ललिता यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि आप व्यापारियों की फर्मों की जांच करा लें, क्योंकि

व्यापारी पल्लेदारों के नाम लायसेन्स बनवाते हैं. अपने कर्मचारियों के नाम लायसेन्स बनवाकर साल छः महीने में फर्म बंद कर देते हैं और इस तरह टैक्स की चोरी करते हैं.माननीय मंत्री जी से मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि क्या मध्यप्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना किसानों को 5 रुपये भोजन देने की है?

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने प्रश्न के उत्तर में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी किस किस मण्डी में कितने हैं, पूरी सूची दी है और इनकी संख्या 490 है. लायसेंसी व्यापारी वही होता है जो अपने लायसेंस का रिन्यूअल करता है और उस मण्डी प्रांगण में खरीदी करता है अथवा मण्डी के बाहर भी यदि खरीदी करता है और यदि हमारे इन्स्पेक्टर, मण्डी सचिव के नोटिस में आता है तो उसका भी मण्डी टैक्स वसूला जाता है. जिन जिन खाद्यानों पर, जिन जिन उपभोक्ता की सामग्री पर मण्डी टैक्स निर्धारित है. माननीय सदस्य ने जैसा कि विषय रखा है कि व्यापारी अपने नाम के अलावा अन्य अपने कर्मचारी या अन्य व्यक्ति या कोई पल्लेदार या किसी अन्य के नाम से लायसेंस लेते हैं तो निश्चित रुप से इस तरह का अधिकार लेने का अधिकार नहीं होता. लायसेंस वही ले सकता है जो व्यापार करे फिर भी माननीय स सदस्य की उपस्थिति में ऐसी कोई शिकायत होगी तो हम इसकी जांच करा लेंगे. लायसेंसी को ही व्यापार करने का अधिकार है क्योंकि उनके नाम से उनको अपना विवरण प्रत्येक दिन का, प्रत्येक मास का भी देना पड़ता है और इसलिए यहां पर किसी को भी मण्डी टैक्स की चोरी की इजाजत नहीं हो सकती. पांच रुपये में भोजन की थाली की अभिनव योजना हमारी सरकार की नीति है और मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित होती है. प्रदेश की 253 मण्डियों में कृषि उपज के विक्रय के लिए आये कृषकों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और जो अन्तर की राशि होती है जो छोटी मण्डियां होती है, डी और सी श्रेणी की मण्डियां होती हैं इनका पैसा समायोजित होता है और हम इसके लिए पैसा उनको जो

खर्च करती हैं, क्योंकि 5 रुपये में भोजन तो मिलता नहीं है, भोजन ज्यादा में मिलेगा तो राशि को भी उसमें समायोजित किया जाता है.

श्रीमती ललिता यादव—अध्यक्ष महोदय, किसानों का अनुबंध तो कट रहा है लेकिन भो भोजन नहीं मिल रहा है . मेरा कहना है कि आप आदेश करें ताकि किसानों को सभी मण्डियों में भोजन मिल सके.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- अध्यक्ष महोदय, 253 मण्डियां हैं इसके लिए वे पात्र हैं और वे दे रही हैं और हमारी तरफ से बंधन नहीं है. प्रदेश की कोई भी मण्डी अपने आय-व्यय का का अंदाजा लगाकर के अपने बोर्ड में प्रस्ताव पारित करे और पांच रुपये में भोजन दें. कहीं कोई बंधन नहीं है.

श्रीमती ललिता यादव—धन्यवाद.

मनासा वि. स. क्षेत्र की संचालित नल-जल योजनाएं

7. (*क्र. 1904) श्री कैलाश चावला : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मनासा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में कितनी नल-जल योजनाएं बनाई गई हैं? ग्रामवार जानकारी देवें? (ख) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ऐसे ग्रामों के कितने सरपंचों द्वारा या स्वयं की जानकारी अनुसार यह शिकायत प्राप्त हुई है कि उक्त योजना में लगाए गए पी.वी.सी. पाईप क्षमता से कम प्रेशर के होने के कारण पानी का दबाव सहन न करने से टूट गए हैं वे योजनाएं बंद पड़ी हैं? क्षमता से कम गुणवत्ताहीन पाईप लाईन क्रय किये जाने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है? क्या उस अधिकारी के विरुद्ध जांच करवाई जायेगी व उसे दंडित किया जावेगा? (ग) क्या उक्त योजनाओं को प्रारंभ करने हेतु पूर्ण क्षमता की नई पाईप लाईन विभाग द्वारा पुनः डलवाई जाएगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 20 नल-जल योजनाएं. शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) 4 ग्रामों की जलप्रदाय योजनाओं में डाले गये पाईपों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थीं. संबंधित पाईप प्रदाय एजेंसी द्वारा गुणवत्ता विहीन पाईपों को बदला जा चुका है. वर्तमान में 1 ग्राम में जलप्रदाय सुचारू चालू कर दिया गया है, शेष 3 योजनाओं में पााईप लाईन परीक्षण कार्य प्रगति पर है. पाईपों का क्रय शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत म. प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया गया है, अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री कैलाश चावला—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि गुणवत्ताविहीन पाइप लगाये गये और उसको बदला जा रहा है. यद्यपि उन्होंने चार योजनाओं के बारे में जानकारी दी है किन्तु मनासा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कई योजनाएँ हैं जिनके पाइप गुणवत्ताविहीन होने से योजनाएं बंद पड़ी हैं तो क्या किसी अधिकारी को भेजकर उन सबका सर्वे फिर से मंत्री जी करायेंगी और जिनके पाइप टूट गये हैं, गुणवत्ताविहीन हैं, उनको बदलवाने के लिए निर्देश देंगी? दूसरा, मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि

गुणवत्ताविहीन पाइप खरीदने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि यह मध्यप्रदेश शासन के लघु उद्योग निगम के प्रक्रिया के अनुसार क्रय किये जाते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि सामूहिक जवाबदारी मंत्रिमण्डल की है अगर गुणवत्ताविहीन पाइप खरीदे गये हैं तो क्या उद्योग मंत्री जी से चर्चा कर ऐसे सप्लायर के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी जिन्होंने गुणवत्ताविहीन पाइप सप्लाई किये हैं और जिन्होंने पाइप की गुणवत्ता का परीक्षण किया है उस एजेन्सी के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगी क्या?

सुश्री कुसुमसिंह महदेले-- माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइप सीधे पीएचई विभाग नहीं खरीदता है और लघु उद्योग निगम के द्वारा पाइप खरीदे जाते हैं और आपकी चिन्ता से मैं बिलकुल सहमत हूँ और यह अकसर शिकायतें मिलती हैं कि जो लघु उद्योग निगम से पाइप वगैरह खरीदे जाते हैं,गुणवत्ता से ठीक नहीं होते हैं और निश्चित रुप से मैं अधिकारी भेजूंगी और जांच कराऊंगी और हमने पाइप बदलने की प्रक्रिया चालू भी कर दी है और जहां नहीं बदले गये हैं वहां हम बदलवा देंगे और माननीय उद्योग मंत्री जी मेरे बगल में बैठी हैं उनसे चर्चा करुंगी कि गुणवत्ता वाले पाइप खरीदे जाएं.

सहायक संचालक, कृषि (गन्ना), कार्यालय, सागर को नरसिंहपुर स्थानांतरित किया जाना

8. (*क्र. 2372) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2007-08 से सागर स्थित सहायक संचालक, कृषि (गन्ना) कार्यालय को, अमला, सामग्री, उपकरण सहित नरसिंहपुर स्थानांतरित किया गया है? (ख) क्या यह सही है कि संचालक, कृषि, भोपाल के आदेश से प्रश्नांकित ''क'' कार्यालय को अमले सहित नरसिंहपुर स्थानांतरित कर दिया है? (ग) वर्ष 2011-2012 से 2013-2014 तक उक्त कार्यालय द्वारा कितनी राशि किस कार्य हेतु संचालनालय से मांगी गई? प्राप्त राशि किस मद पर कितनी व्यय की गई? कितनी राशि शासन को समर्पित की गई? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्नांकित ''क'' कार्यालय एवं अमला प्रश्न दिनांक तक नरसिंहपुर नहीं गया है? यदि नहीं, तो शासन आदेश नहीं मानने एवं आदेश पालन नहीं कराने के लिए कौन-कौन दोषी हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरी शंकर बिसेन) : (क) जी नहीं. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार. (ख) जी हां. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार. (ग) वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक किसी प्रकार की कोई राशि की मांग संचालनालय से नहीं की गई है. किन्तु वेतन भत्तों में मांग संख्या-13-2401-103-2976-बीज परीक्षण, पर्यवेक्षण और प्रमाणीकरण की योजना मद में निम्नानुसार राशि का आवंटन जारी कर व्यय किया गया है. कोई भी राशि समर्पित नहीं की गयी है.

वर्ष	वेतन भत्तों से प्राप्त राशि	व्यय राशि
2011-12	16,34,821	11,58,205
2012-13	18,05,982	17,96,282
2013-14	17,39,967	17,30,343
योग . .	51,80,770	46,84,830

(घ) जी नहीं. कलेक्टर, सागर ने लोक सभा चुनाव 2014 संबंधी आचार संहिता के बाद भारमुक्त करने के लिए निर्देशित किया गया था. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार. संबंधित कर्मचारियों को दिनांक 31-5-2014 को भारमुक्त किया गया है. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार.

इन्जी.प्रदीप लारिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कृषि मंत्री बड़े दरियादिल भी हैं और उदार भी हैं लेकिन हमारे यहाँ जो गन्ना का कार्यालय है वह 4.10.2013 को पूरे अमले के साथ सागर से नरसिंहपुर स्थानांतरण कर दिया जबकि 2007-08 में वह कार्यालय रतलाम से सागर में स्थापित हुआ था तो उसमें लगातार गन्ना का उत्पादन बढ़ा. 2007-08 में 300 हेक्टेयर में गन्ना की कृषि होती थी 2013 आते-आते वह कृषि 800 हेक्टेयर में हो गई . मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है कि जब उत्पादन बढ़ रहा था तो फिर यह कार्यालय क्यों स्थानांतरित किया गया.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि सागर में गन्ने का उत्पादन बढ़े और इसलिए वहाँ पर सहायक संचालक ,गन्ने का कार्यालय स्थापित भी किया गया था और हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री मेरे बड़े भाई गोपाल भार्गव जी बैठे हैं यह भी चाहते थे कि वहाँ पर गन्ने का उत्पादन बढ़े लेकिन गन्ना का उत्पादन 961 हेक्टेयर तक ही पहुंच सका और ऐसी

स्थिति में क्षेत्रफल नहीं बढ़ने का मूल कारण था, जल स्तर की कमी. गन्ने का बहुत ज्यादा पानी लगता है , जैसे ही गन्ने का क्षेत्र सागर में बढ़ेगा उसके बारे में सरकार जरूर विचार करेगी .रहा सवाल कि इसको हमने नरसिंहपुर क्यों भेजा तो यह पूरा सदन जानता है और अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं नरसिंहपुर के पड़ोसी हैं . नरसिंहपुर में 45575 हेक्टेयर में गन्ना पैदा होता है जो पूरे प्रदेश का सर्वाधिक है और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में जितना गन्ना पैदा होता है उसका करीब 40 परसेंट गन्ना अकेले नरसिंहपुर में होता है और इसी गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रोडेक्टिविटी और शक्कर का तादाद उसमें ज्यादा है, इसको बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ हमने नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र भी खोला है . अध्यक्ष महोदय, हमारे गोविंदसिंह पटेल जी को परसों ही मैंने अपने बजट भाषण के उत्तर में कहा था और इसके लिए हमने अनुसंधान केंद्र का अमला भी ट्रांसफर किया है . अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करता हूं और हम चाहते हैं कि न केवल सागर अपितु पूरे प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो . मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि गन्ने का ऐतिहासिक प्रोडक्शन पिछले वर्ष हुआ था. उसका मूल कारण था भारी वर्षा होना और इसलिए इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक सहायक संचालक विशेष तौर से गन्ने का काम सागर में देखेंगे और उसमें एक दक्ष अधिकारी की हम पोस्टिंग करेंगे उसके साथ-साथ उसके अमले को भी रखेंगे और जिन अधिकारियों को सागर से ट्रांसफर किया गया था उनके ट्रांसफर हमने निरस्त कर दिये हैं जो भृत्य का ट्रांसफर हुआ है उसका भी ट्रांसफर हम निरस्त कर देंगे उसको वापस सागर भेज देंगे. सागर के अमले में हम कमी नहीं करेंगे . हमने नरसिंहपुर के अमले को ही युक्तियुक्तकरण करके इस कार्यालय को चलाने का निर्णय लिया है .

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहा हूं. मैंने बोला था. अध्यक्ष महोदय, मैं लारिया जी को भी अवगत कराना चाहता हूं कि सागर जिले में

कोपरेटिव सैक्टर में एक शुगर मिल खोलने का प्रस्ताव था और क्षेत्राच्छादन भी गन्ने का काफी हो गया था इस बीच में वह शुगर मिल नहीं खुल पाई , भारत सरकार से हमको लोन लेना था वह नहीं मिल पाया. मैं आग्रह करता हूं कि हम फिर इसको बढ़ाने का काम करे ताकि सागर जिला भी नरसिंहपुर के बराबर आ जाए और बाकी जिलों में हम इसकी कोशिश कर रहे हैं.

इन्जी.प्रदीप लारिया-- मेरा एक प्रश्न और है.

अध्यक्ष महोदय—उन्होंने आपका पूरा उत्तर दे दिया औऱ काम कर दिया है....(व्यवधान)....यह बात ठीक नहीं है.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन स्वीकार कर ले. जावरा, महिदपुर औऱ दलोदा शुगर मिल और वह संपूर्ण क्षेत्र गन्ना उत्पादन में अग्रणी रहा था तो कृषि नीति आ रही है गन्ना उत्पादन की नीति है, शक्कर का उत्पादन बढ़ रहा है....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- आपकी बात आ गई...(व्यवधान)..प्रश्न क्रमांक 9 सुश्री उषा ठाकुर..(व्यवधान)...उनको प्रश्न करने दें...(व्यवधान)..

इंजी.प्रदीप लारिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न मेरा है..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- पहले आप तो बैठें...(व्यवधान)..आप एक सेकंड में पूछिए.

इंजी.प्रदीप लारिया-- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि केन्द्र शासन से यह फैक्ट्री खुलना थी.

अध्यक्ष महोदय-- आप भाषण देते हैं.

इंजी.प्रदीप लारिया-- मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या राज्य शासन इसके लिए प्रयासरत रहेगा और जब गन्ना कार्यालय रतलाम से सागर शिफ्ट हुआ था, मेरा यह निवेदन है कि उसमें पूर्ण अमला नहीं दिया था, छोटा सा अमला था उसके बाद भी उत्पादन बढ़ा है.

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने उसका उत्तर दे दिया.

इंजी.प्रदीप लारिया-- मेरा प्रश्न यह है कि, सहकारिता मंत्री जी भी हैं, क्या राज्य शासन इसमें फैक्ट्री खोलकर गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगा.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी के साथ बैठ करके भारत सरकार के पास अपना पक्ष रखेंगे और गन्ने के उत्पादन के लिए मध्यप्रदेश में जो अच्छा हो सकेगा वह करने का प्रयास करेंगे...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अब कोई एलाउ नहीं...(व्यवधान)..प्रश्न क्रमांक 9....

बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं नियंत्रण

9. (*क्र. 2197) सुश्री उषा ठाकुर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में व्याप्त भिक्षावृत्ति (बाल) पर नियंत्रण हेतु शासन की नीति निर्धारित होकर, इसका पालन किया जा रहा है? (ख) बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या पहल की गई, इस पर नियंत्रण न होने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? इनके विरुद्ध कब, क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) बाल भिक्षुकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, स्वस्थ जीवन-यापन करने तथा सुखद भविष्य निर्माण हेतु इनके लिये शासन द्वारा कोई रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम / योजना बनाई है / विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कब तक लागू की जावेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां. मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति अधिनियम, 1973 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 प्रदेश में प्रभावशील है. (ख) बाल भिक्षावृत्ति रोकने हेतु प्रश्नांश ''क'' के उत्तर अनुसार प्रावधान प्रभावशील है. शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है. (ग) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों हेतु 53 बालगृह, 14 आश्रय गृह, 07 खुला आश्रय गृह संचालित है. जिसमें गृह में प्रवेशित होने वाले बालकों को संरक्षण, भरण-पोषण, शिक्षण-व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं चिकित्सकीय देखभाल की जाती है. अतः इसके लिये किसी नवीन योजना की आवश्यकता नहीं है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

सुश्री उषा ठाकुर-- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जवाब आया है, उससे तीन प्रश्न उद्भूत होते हैं. मैं आपके माध्यम से उन तीनों का जवाब चाहती हूँ. अध्यक्ष जी, मध्यप्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण अधिनियम 1973 का प्रभावी क्रियान्वयन मध्यप्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देता. मैं जानना चाहती हूँ कि इन 40 वर्षों में कितने लोगों को जेल भेजा गया और कितने लोगों को रिसीविंग सेंटर पहुँचाया गया? क्या वात्सल्यमयी मंत्री माननीया माया सिंह जी संविधान में संशोधन करके जिला महिला बाल विकास अधिकारी एवं उनकी टीम को अधिकार प्रदत्त कराएँगी? ताकि धारा 11 और 12 का प्रभावी क्रियान्वयन विभाग के माध्यम से किया जा सके. क्या

रिसीविंग सेंटर में पहुँचाए गए बच्चों के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा?

श्रीमती माया सिंह-- माननीय अध्यक्ष जी, उषा जी ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि भिक्षावृत्ति अधिनियम 1973 और नियम 1977 में भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को, बच्चों को, जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है. उन्हें सुधारगृह भेजकर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है. जेजे एक्ट के तहत भिक्षावृत्ति के लिए नियोजित या उसको प्रेरित करने वालों को सजा का प्रावधान है और इन्दौर जिले में, आप ही के यहाँ पर, एक व्यक्ति के खिलाफ 2012 में एफआईआर दर्ज की गई है और जेजे एक्ट का संचालन महिला बाल विकास विभाग वर्ष 2010 से कर रहा है. आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या अधिकारियों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएँगे, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक्ट के तहत पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है. अतः इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है.आपका तीसरा सवाल बच्चों के लिए था कि जो किशोर न्याय अधिनियम 2002 के तहत जो भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चे हैं, जो निराश्रित हैं, बेसहारा हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी देखरेख और संरक्षण की श्रेणी में ये लोग जो आते हैं ऐसे बच्चों के लिए आश्रय गृह बने हुए हैं और वहाँ उन बच्चों को हम रखते हैं. उनके पोषण, शिक्षण और प्रशिक्षण की सारी जिम्मेदारी विभाग की होती है तो किसी भी संस्था में निवासरत बच्चों के शिक्षण, पोषण और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. अब इसके तहत हम यह सब चिन्ताएँ करते हैं तो मैं आप से कहना चाहूँगी कि वर्तमान में भी प्रदेश के जो गृह हैं उनमें इस श्रेणी के 64 बच्चे हैं, इन बच्चों की शिक्षण, पोषण और प्रशिक्षण की सारी जिम्मेदारी विभाग निभा रहा है.

सुश्री उषा ठाकुर-- अध्यक्ष महोदय, 1973 की धारा 11 में प्रावधान है कि भिक्षा मंगवाने वाला, चाहे वह माता पिता ही क्यों न हो, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए और यह जो केन्द्रों पर व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं वह अंशकालीन हैं, यदि उनके बच्चों को हम लाएँ तो एक दीर्घकालीन योजना

बनाकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर शिक्षा-दीक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि सारा अपराध जगत इन भिखारियों के बीच में ही पल रहा है. हम देख रहे हैं शिक्षा संस्कृति से विहीन नर पिशाचों की संख्या आए दिन इस प्रदेश और देश में बढ़ रही है इसलिए बहुत ही फिक्र के साथ इसका समाधान किया जाना चाहिए. धन्यवाद.

श्रीमती माया सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने पूर्व में भी आपसे कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा (24) के तहत यदि कोई व्यक्ति बच्चों को भीख मांगने के लिये नियोजित करता है या प्रेरित करता है तो उसे 3 साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है. सरकार बच्चों के विकास और संरक्षण के लिये चिन्ता के साथ कार्य कर रही है.

पापुलर वृक्षों की पैदावार को प्रोत्साहन दिया जाना

10. (*क्र. 1578) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि सोनकच्छ विधासभा क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकबा ज्यादा है एवं पानी भी पर्याप्त मात्रा में है? क्या शासन द्वारा पापुलर वृक्ष की पैदावार करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना प्रस्तावित है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : उद्यानिकी विभाग में पॉपुलर वृक्ष की पैदावार करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने संबंधी कोई योजना संचालित नहीं है.

श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की और सरकार की यह मंशा है कि खेती लाभ का धंधा बने और किसान समाज की मुख्य धारा में आगे आयें.

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पापुलर वृक्ष से संबंधित है. यह ऐसा वृक्ष होता है जिसमें कोई खाद, बीज की आवश्यकता नहीं होती है और इसको खेत की मेढ़ पर लगाया जाता है और यह पानी

की मात्रा से फूलता है. पंजाब और हरियाणा में इसको कमर्शियल खेती माना जाता है. मंत्रीजी से मेरा यह आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है क्या वे वहां पर विशेषज्ञों की टीम भेजकर उसकी जांच करायेंगी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पंजाब में पार्टिकल बोर्ड और प्लाई बोर्ड की 400-500 यूनिटें इस पापुलर वृक्ष के कारण लगी हैं क्या वहां पर किसानों को भेजकर इसका अध्ययन करवायेंगी ?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय अध्यक्ष महोदय, पापुलर वृक्ष तराई क्षेत्रों में होते हैं जैसे हिमालय की तराई आदि. मध्यप्रदेश की धरती न उतनी नमीयुक्त है न ही उतनी पानीयुक्त है इसलिये हमारे विभाग ने पापुलर वृक्ष लगाने का विचार नहीं किया है क्योंकि हमारे यहां का वातावरण और जमीन उसके लायक नहीं है.

श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह कहना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उसकी खेती हो रही है. इसमें जैसे ही पानी जाता है यह पानी के कारण फूलता है इसमें तराई क्षेत्र और हिमालय की नमी का सवाल नहीं है. मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषक इसका उपयोग कर रहे हैं, क्या मंत्री महोदय यहां से विशेषज्ञों को भेजकर दिखवायेंगी. यह किसानों के लिये बिना खर्च की खेती है. इसके द्वारा हरियाणा में यमुना नगर में पार्टिकल बोर्ड की व प्लाई बोर्ड की 500 यूनिटें लगी हैं. वहां के किसान इसकी खेती कर रहे हैं और मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है मेरा मंत्रीजी से एक ही आग्रह है कि वहां विशेषज्ञों को भेजकर दिखवा लें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपके विधान सभा क्षेत्र में पानी है, नमी है तो हम जांच दल भेज देंगे हमें कोई एतराज नहीं है जांच दल जांच कर आयेगा और वहां की धरती मुफीद है तो लगाओ पापुलर वृक्ष.

श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

बलराम तालाबों की स्वीकृति में अनियमितता

11. (*क्र. 2886) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक कितने बलराम तालाब बनाये गये? इन तालाबों को नियमानुसार कितनी राशि का अनुदान दिया गया है? कितने पूर्ण एवं अपूर्ण हैं? कार्य संपादित कराने वाले किसानों की जानकारी वर्षवार देवें? (ख) क्या यह सही है कि वर्तमान स्थिति में अनेक तालाब सूख गये हैं? यदि हां, तो कारण दर्शाते हुए ऐसे हितग्राहियों/किसानों की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या यह सही है कि तालाबों की स्वीकृति हेतु संबंधित किसानों से अनियमितता किये जाने की शिकायतें जिला कलेक्टर/उप संचालक, कृषि, सिवनी स्तर के कार्यालय में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन शिकायतों पर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? (घ) बलराम तालाब के लिये शासन द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं? उसकी प्रति उपलब्ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरी शंकर बिसेन) : (क) सिवनी जिले में प्रश्नांकित अवधि में 415 बलराम तालाब बनाये गये व रुपये 415.33 लाख का अनुदान पात्रतानुसार कृषकों को दिया गया शेष विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' पर है. (ख) जी हां. तालाब में संग्रहित वर्षा जल का फसल में जीवन रक्षक सिंचाई में उपयोग करने एवं वर्तमान में गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होने के कारण अधिकांश तालाब सूख गये हैं. शेष विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' पर है. (ग) जी नहीं. शेष का प्रश्न ही नहीं उठता. (घ) बलराम ताल योजनान्तर्गत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' पर है.

श्री दिनेश राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, बलराम तालाब की स्वीकृति में अनियमितता के संबंध में मैंने कृषि मंत्रीजी से प्रश्न पूछा था उनके द्वारा मुझे 415 तालाबों की लिस्ट दी गई है उसमें सूखे तालाब ज्यादा बताये गये हैं और हमारे क्षेत्र में वर्षा भी बहुत हुई है इसमें लिखा है कि सूखा पड़ने के कारण, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वे मेरे साथ स्थल निरीक्षण के लिये समय देंगे क्या ?

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिवनी जिले का प्रभारी मंत्री हूं माननीय सदस्य जिस-जिस तालाब को देखने चलेंगे मैं जाऊंगा और स्थल निरीक्षण करुंगा.

श्री दिनेश राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है यह योजना 2007 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की महत्वाकांक्षी योजनाओं से यह प्रारंभ हुई है इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है, जल स्तर भी बढ़ रहा है. बलराम तालाब के लिये 2 लाख रुपये की मद दी

जाती है, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे इस राशि को बढ़ायेंगे जिससे मेरे जिले सहित पूरे मध्यप्रदेश के किसानों को फायदा मिल सके.

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव तर्कसंगत और व्यावहारिक है. 2007 में यह योजना चालू की गई यह पूर्ण रुप से राज्यांश से संचालित है. इसमें 2 लाख अधिकतम लागत रखी गई है. 2007 से 2014 में महंगाई भी बढ़ी है मूल्य सूचकांक भी ऊपर गये हैं इसलिये इस पर पुनर्विचार करने के संदर्भ में राज्य शासन विचार करेगा. वित्त की इसमें अनुमति चाहिये होती है. हम खुद इस अभिमत के हैं कि इसकी सीलिंग को बढ़ाया जाना चाहिये.

प्रश्न संख्या—12 (अनुपस्थित)

ओला पीड़ित किसानों की राहत राशि वितरण में अनियमितता

13. (*क्र. 2946) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधान सभा क्षेत्र में ओला पीड़ित किसानों के रकबे की गलत जानकारी देकर अधिक राहत राशि मंगवाई गई थी? क्या यह सत्य है तथा कैलारस तहसील के बडरेण गांव के पास पहाड़ व पहाड़ के नजदीक की जमीन के पट्टों पर अवैध रूप से राहत राशि वितरण की गई है, जहां आज तक कोई फसल नहीं उगाई गई है? क्या इसकी जांच करवाई गई? यदि नहीं, तो कब तक करवाई जाएगी? (ख) राहत राशि में से लगभग 1 करोड़ रुपये अपात्र लोगों के खातों में जमा किये गये, जो वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में है या नहीं तथा संज्ञान में आने के पश्चात् क्या कार्यवाही की गई है. (ग) इस प्रकार शासन के साथ धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? नहीं तो कब तक की जाएगी? समय-सीमा बतायें? (घ) सर्वे के अनुसार जो पात्र लोग हैं उनको राहत राशि नहीं दी गई है जबकि उनके नजदीकी जमीन वालों को दी गई है? क्या उनको राहत राशि दी जाएगी? और कब तक दी जाएगी? समय-सीमा बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) :-

(क) जी नहीं । कैलारस तहसील के बधरेंटा गांव के पास पहाड़ व पहाड़ के नजदीक की जमीन के पट्टे पर अवैध रूप से राहत राशि वितरण नहीं की गई है ।

(ख) जी नहीं । अपात्र लोगों के खातों में कोई राशि जमा नहीं की गई है। कैलारस तहसील क्षेत्रान्तर्गत ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों में गठित सर्वे दल द्वारा ओलावृष्टि का सर्वे कराया गया । सर्वे दल में पटवारी कृषि विभाग के आर.ऐ.ई.ओं. एवं सचिव, ग्राम पंचायत शामिल थे । सर्वे कार्य पूर्ण पारदर्शिता से किया गया था। सर्वे में किसी अपात्र व्यक्ति को राहत राशि प्रदाय नहीं की गई है ।

(ग) जी नहीं । शासन से कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) जी नहीं । कैलारस तहसील क्षेत्रान्तर्गत सर्वे पूर्णतः पारदर्शिता से किया गया है एवं सर्वे की वीडियोग्राफी भी कराई गई है । ओलावृष्टि का प्रभाव नजदीकी जमीन पर पृथक–पृथक हो सकता है । सर्वे में पात्र कृषकों को आर.बी.सी.6–4 के प्रावधानों के तहत राहत राशि प्रदाय की गई ।

श्री सूबेदार सिंह रजौधा – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जौरा क्षेत्र के कैलारस तहसील में ओला पीड़ित किसानों को गलत रकबे की गलत जानकारी देकर कैलारस तहसील के बधरेंटा गांव के पास पहाड़ के नजदीक पड़त जमीन पर अपात्र लोगों को राहत राशि बांटी गई है क्या इसकी माननीय मंत्री जांच कराएंगे ? दूसरा मेरा प्रश्न है राहत राशि में से लगभग 1 करोड़ रुपये तहसीलदार के खाते में जमा किया गया जबकि रुपया सीधा बैंक के खाते में जाना चाहिये था. साढ़े नौ करोड़ रुपये की क्षति हुई कैलारस तहसील में उसके विपररीत 23 करोड़ रुपये मंगाये गये और उनको फिर वापस किया गया क्या इनके खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री रामपाल सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नावली लंबी है. मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं जैसा आपने जांच का कहा है तो हम जांच कराएंगे दूसरा अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी भी जांच होगी और गलत ढंग से अगर राशि दी है तो आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि वहां के तहसीलदार को

तुरंत हटाएंगे. दो पटवारियों को निलंबित कर दिया है और इसके बाद और भी जरूरत होगी तो एफ.आई.आर. भी कराएंगे. गलत ढंग से मध्यप्रदेश में अगर कोई भी माननीय सदस्य बताएंगे तो निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही करेंगे.

श्री रामनिवास रावत – पूरे प्रदेश में हुआ है. पूरे प्रदेश की जांच करा लें.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – आप बैठ जाएं कृपया.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि सर्वे के दौरान अपात्र लोगों को मुआवजा दिया गया.

अध्यक्ष महोदय – जांच कराने का बोल तो दिया.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा – माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पटवारी द्वारा मुआवजा दिया गया. मैंने जिला योजना समिति में शिकायत की.

अध्यक्ष महोदय – सस्पेंड कर दिया.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा – माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको सस्पेंड किया गया है. मैं मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि सस्पेंड कोई पनिशमेंट नहीं है. अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिये. एफ.आई.आर.होनी चाहिये और जो पात्र लोग रह गये हैं क्या उनको मुआवजा देंगे माननीय मंत्री जी ?

श्री हर्ष यादव – पूरे प्रदेश का मामला है. पूरे प्रदेश में ओला वृष्टि का पैसा नहीं मिला.

एक माननीय सदस्य – पूरे प्रदेश के किसानों का मामला है. इस पर चर्चा होना चाहिये.

(..व्यवधान.)

अध्यक्ष महोदय – प्रश्नकाल में चर्चा नहीं हो सकती. सब माननीय सदस्य खड़े हो गये किस-किसको अलाउ करेंगे ?

श्री सूबेदार सिंह रजौधा – माननीय अध्यक्ष महोदय, बधरेंटा के आसपास पटवारी के सर्वे में कई लोग छूट गये हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है उसका पुन: सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा क्या ?

एक माननीय सदस्य – पूरे प्रदेश का सर्वे कराया जाएगा क्या ?

अध्यक्ष महोदय – पूरे प्रदेश का सर्वे कैसे कराएंगे ?

श्री रामपाल सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सब सदस्य लिखकर दीजिये कार्यवाही करेंगे और माननीय विधायक ने जो कहा है कि पटवारी ने अगर लापरवाही की है तो मैं अधिकारियों से चर्चा करूंगा.

(..व्यवधान..)

मत्स्य पालन की योजनाओं की जानकारी

14. (*क्र. 3038) श्रीमती ममता मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म. प्र. में मत्स्य पालन की कौनसी योजनाएं चल रही हैं? जानकारी दें? (ख) गुना एवं अशोकनगर जिलों में एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. योजना आदिवासी उपयोजना (आदिम जाति कल्याण विभाग, गुना द्वारा प्रदाय राशि) अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में क्या-क्या कार्य किये गये हैं? हितग्राहियों की जानकारी दें? (ग) गुना जिले में पदस्थ सहायक संचालक एवं मत्स्य निरीक्षक कितने वर्षों से पदस्थ हैं? क्या इनके स्थानांतरण की शिकायतें की गईं? यदि हां तो स्थानांतरण क्यों नहीं किया? यदि किया जाएगा तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार. (ख) प्रश्नांगत अवधि में एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. योजनान्तर्गत गुना जिले में 126 एवं अशोकनगर जिले में 85 हितग्राहियों को अनुदान स्वरूप नाव, जाल, इन्सूलेटेड बॉक्स, तराजू, मत्स्य बीज एवं प्रशिक्षण दिया गया है. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत गुना जिले में केवल वर्ष 2011-12 में राशि रुपये 7.32 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिससे 46 हितग्राहियों को फसला जाल, घुमुआ जाल, झोलनी जाल, इन्सूलेटेड बॉक्स एवं प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन''. (ग) गुना जिले में श्रीमती अनीता चौधरी, सहायक संचालक, मत्स्योद्योग के पद पर दिनांक 13-7-2011 से पदस्थ थीं, शिकायतों के आधार पर विभागीय आदेश दिनांक 24-6-2014 द्वारा उनका स्थानांतरण कर दिया गया है. श्री शेख फिरोजुद्दीन पासा, मत्स्य निरीक्षक वर्ष 1988 से एवं श्री एन. एस. दण्डोतिया की शिकायतें प्राप्त हुई. उनका गुना से अन्यत्र स्थानान्तरण का प्रचलन में है. समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है.

श्रीमती ममता मीना – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के ख में माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी भेजी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मेरा जो प्रश्न था वह गुना अशोकनगर जिले में एम.पी.डब्लू.एस.आर.पी. योजनान्तर्गत आदिवासी योजना के पिछले तीन वर्षों में कितने हितग्राहियों को वास्तविक योजना का लाभ दिया, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिलाया साथ ही जो

मंत्री जी द्वारा जानकारी भेजी है वह असत्य तथा अधूरी जानकारी दी है. मेरा कहना है कि जितने भी आदिवासी हैं भील, सहरिया, इन लोगों को आदिवासी योजनाओं में अनुदान दिया गया, मछली विभाग से जो बीज वितरण किया जाता है वह दिया गया अथवा नहीं, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत जानकारी भेजी है. जिन लोगों की सूची दी गई है उनके पास में न तो कोई तालाब है और अगर तालाब ही नहीं है तो उनको कैसे बीज दिया गया, कैसे उनको जाल दिये गये, कैसे उनको अनुदान दिया गया यह मंत्री जी से जानकारी चाहती हूं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी जानकारी परिशिष्ट में दी है इसमें कोई प्वाईंटेड प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दे देती हूं.

श्रीमती ममता मीना—माननीय अध्यक्ष महोदय, गुना, अशोक नगर जिले में एम.टू.डब्ल्यू.एस.आर.पी. आदिवासी योजनाओं के पिछले तीन वर्षों में इसमें जितनी भी सामग्री क्रय की गई है वह उत्तरप्रदेश की कम्पनी के द्वारा क्रय की गई.

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्न कहां है.

श्रीमती ममता मीना—माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जानकारी दी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जितने भी आदिवासी जैसे भील, सहरिया और केवट इसमें जो नाम दिये गये हैं इसमें एक भी व्यक्ति के पास में तालाब नहीं है, जब तालाब ही नहीं है तो उनको जाल कैसे दे दिया.

अध्यक्ष महोदय—126 तथा 85 किसी के पास में कुछ भी नहीं है.

श्रीमती ममता मीना—माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं है इसमें 7 लाख 32 हजार रूपये की राशि खर्च की गई है वह गलत की गई है इसमें जांच होना चाहिये, जांच के माध्यम से पूरा सत्यापन कराना चाहिये.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी जानकारी परिशिष्ट में है.

अध्यक्ष महोदय—इनका कहना है कि जिनको पात्रता नहीं थी उनको भी दे दिया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य कुछ जानकारी चाहती हैं तो कृपा करके मुझको बता दें मैं जानकारी को पूरा कर दूंगी.

श्रीमती ममता मीना—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें जांच कराना चाह रही हूं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के लायक कुछ है नहीं, फिर भी कह रही हैं तो मैं इसकी जांच करवा दूंगी.

प्रश्न संख्या 15 -

फसल बीमा योजना का लाभ

15. (*क्र. 3281) श्री वीरसिंह पंवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि किसानों से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा प्रीमियम राशि ली जाती है? यदि हां तो फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दावा प्रक्रिया क्या है? (ख) विदिशा एवं रायसेन जिले में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में फसल बीमा के प्रीमियम की कितनी राशि किसानों से ली गई एवं फसल बीमा का लाभ कितने किसानों को दिया गया? (ग) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में विदिशा एवं रायसेन जिलों में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्राकृतिक आपदाओं से फसलें खराब हुई हैं? क्या किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कोई बीमा दावा भुगतान किया गया? यदि हां तो किसानों की संख्या बतावें? (घ) जून, 2014 की स्थिति में उक्त जिलों में कितने किसानों के फसल बीमा योजना के दावा भुगतान के प्रकरण लंबित हैं? तथा कब तक किसानों को राशि का भुगतान होगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरी शंकर बिसेन) : (क) जी हां. दावा प्रक्रिया पत्रक †संलग्न प्रपत्र ''एक'' पर है. (ख) विदिशा एवं रायसेन जिले में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की बीमा आवरण की जानकारी †संलग्न प्रपत्र ''दो'' पर है. (ग) विदिशा एवं रायसेन जिलों में वर्ष 2012-13 दावा राशि का भुगतान खरीफ एवं रबी का किया गया है. खरीफ 2013 क्षतिपूर्ति की गणना प्रक्रियाधीन है. रबी 2013-14 बीमांकन का कार्य प्रगति पर है. (घ) उक्त दोनों जिलों में खरीफ 2013 के किसानों के क्षतिपूर्ति की गणना प्रक्रियाधीन है. रबी 2013-14 बीमांकन का कार्य प्रगति पर है.

श्री वीरसिंह पंवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदिशा एवं रायसेन जिले के राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खरीफ 2013 में क्षतिपूर्ति की गणना में क्रिया में उक्त कार्य कब तक होगा एवं छोटे किसान जो इसमें छूट गये हैं उनको बीमा राशि का लाभ कब मिलेगा ?

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है उस नीति से माननीय सदस्य पूर्ण रूप से अवगत हैं, जो किसान बैंकों से ऋण लेते हैं वह

अनुपातिक फसलवार जो तय है वह बीमे की प्रीमियम देते हैं इसके अलावा ऐच्छिक भी है दूसरे किसान भी जिन्होंने ऋण नहीं लिया है वह भी बीमा करा सकते हैं. जहां तक बीमे के छोटे किसान का विषय है इसमें छोटे बड़े किसान का विषय नहीं है इसमें एक ही चीज है जो ऋण लेगा, प्रीमियम देगा बैंकों के माध्यम से अथवा अकेले पृथक से वह बीमित किसान की श्रेणी में आयेगा. हमने 2013-14 के संदर्भ में अपने उत्तर में कहा है कि बीमा के क्लेम देने का कार्य प्रगति पर है इसमें लगभग 74-75 करोड़ रूपया हमारे विदिशा जिले में तथा लगभग 154 करोड़ रूपया रायसेन जिले के किसानों को मिलना है इसमें 78 हजार किसान विदिशा जिले के, 90 हजार किसान हैं रायसेन जिले के, यह सारे किसान इसका लाभ लेंगे. जैसे ही इसमें एस.एल.आर. की रिपोर्ट जायेगी, इसमें कृषि विभाग के प्रतिवेदन में कुछ त्रुटियां थीं उसको ठीक कर लिया गया है इसमें भारत सरकार से पैसा आना है, राज्य सरकार ने अपने बजट में प्रावधान कर दिया है हमने इसमें 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- बजट जैसे ही पास होगा और यहां जैसे ही समारोह होगा, इसके बाद में महामहिम के दस्तखत के बाद में यह पैसा चला जायेगा, किसानों के खाते में इस पैसे को पूरे प्रदेश के बीमित किसानों के पैसे उनके खाते में पहुंच जायेंगे.

श्री वीरसिंह पंवार--धन्यवाद मंत्री जी.

प्रश्न संख्या (16)--..

निजी कॉलोनियों का ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण करने के संबंध में

16. (*क्र. 2196) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि निजी कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित कराया जाकर निजी कॉलोनी निर्माण हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के तहत् प्रावधान है? (ख) खरगौन जिले में ऐसी कितनी निजी कॉलोनियां हैं जो ग्राम पंचायत सीमा में आती हैं? उनकी सूची दी जावे? (ग) बड़वाहा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसी कितनी निजी कॉलोनी हैं, जो विगत 5 वर्षों के भीतर ग्राम पंचायतों को सौंपी गई हैं? उनके कॉलोनाईजर का नाम एवं भूमि का सर्वे नंबर सहित कॉलोनीनाईजर के द्वारा कॉलोनी में क्या-क्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है? निजी कॉलोनी ग्राम पंचायत को सौंपने की समस्त प्रक्रिया सहित जानकारी दी जावे? क्या यह सही है कि निजी कॉलोनी को ग्राम पंचायत के हस्तान्तरण के पूर्व कॉलोनी पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिये? यदि हां तो कॉलोनी में क्या-क्या मूलभूत सुविधा होना चाहिये? कस्बा पंचायत, बड़वाहा ग्राम पंचायत, सिरलाय-बावड़ीखेड़ा की विगत 5 वर्षों में सौंपी गई निजी कॉलोनी के हस्तान्तरण सहित जानकारी दी जावे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है. ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्य पूर्ण कर लिया जाने बाबद् प्रतिवेदन प्रेषित करने तथा आवेदक के निवेदन व ग्राम पंचायत की सहमति के आधार पर कालोनी को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जाने की अनुमति प्रदान की गई है. ग्राम पंचायत, सिरलाय बावड़ीखेड़ा में विगत 5 वर्षों में कोई कालोनी पंचायत को हस्तांतरित नहीं की गई है.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, परंतु हम देख रहे हैं कि कई गांवों में भी अब कालोनियां बनने लग गई हैं और कालोनियां बनने के साथ में कभी कभी क्या होता है कि कोई कालोनी या तो पूरी व्यवस्थायें करता है, परंतु कई कालोनियों में व्यवस्थायें नहीं हो पाती हैं, तो मैं यह चाहता हूं कि हमारे यहां जो 1-2 कालोनियां बनी हुई हैं, वह कितनी पंचायतों में हैंडओवर हो गई है और कितनी नहीं हो पाई है और जहां पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाईं, क्या वहां पर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कालोनाइजर को जो हैंडओवर कर दी है, भोपाल से किसी अधिकारी को भेजकर उनकी क्या जांच करायेंगे ?

श्री रामपाल सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक सोलंकी जी ने जो प्रश्न किया था 5 वर्षों में हमने 7 कालोनी, 2 कालोनी का अभी और पता चला है 9 कालोनी हमने ग्राम पंचायतों को दी हैं और कुल जो है, माननीय विधायक जी का जो सवाल है आपके खरगोन जिले में लगभग 80 निजी कालोनियां स्थापित हैं उनमें जो नियम और निर्देशों का रहते हैं मूलभूत सुविधायें पूरी उपलब्ध अगर कराई हैं, उसके बाद यह कालोनियों में अगर कोई और भी गड़बड़ी माननीय

विधायक जी बताते, यदि मूलभूत सुविधायें नहीं कराई हैं और किसी तरह की कालोनी हस्तांतरण में कोई अनियमितता की है, तो निश्चित रूप से हम जांच करायेंगे.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी--मैं वही कह रहा हूं कि आप तो भोपाल स्तर से एक अधिकारी को भेजकर जांच क करा दें , सब क्लीयर हो जायेगा.

श्री रामपाल सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपाल से अधिकारी भेजकर हम जांच करायेंगे.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी--धन्यवाद.

प्रश्न संख्या (17)--..

बालाघाट जिले में खैरलांजी तहसील के ग्राम गुडरूघाट से अतिक्रमण हटाया जाना

17. (*क्र. 3177) श्री के. डी. देशमुख : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील के गुडरूघाट ग्राम में खसरा नं. 274/3, रकबा 2.68 शासकीय भूमि पर राजेश चौव्हान गुडरूघाट ने अतिक्रमण किया है? (ख) यदि हां तो तहसीलदार खैरलांजी, जिला बालाघाट द्वारा अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां. (ख) प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 26-5-2014 को बेदखली आदेश पारित कर दिया गया है. अतिक्रामक को एक माह के भीतर बेदखल किया जा सकेगा.

श्री के.डी.देशमुख--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि अतिक्रामक को एक माह के भीतर बेदखल किया जा सकेगा, यह 1 महीना की जो तारीख शुरू हुई है, तो यह तहसीलदार ने अतिक्रामक को जो नोटिस दिया है, बेदखली का आदेश पारित किया है, उस दिन से शुरू होगा कि आज से शुरू होगा क्या तहसीलदार के संज्ञान में जिस दिन आया, उस दिन से शुरू होगा ?

श्री रामपाल सिंह--बस, अब क्या पूछना है, इतना ही काफी है.

श्री के.डी.देशमुख--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गुडरूघाट का मामला है.

अध्यक्ष महोदय--बेदखली कब तक कर देंगे ?

श्री के.डी.देशमुख--मैं एक चीज और कहना चाहता हूं.

श्री रामपाल सिंह--उन्हें पूरा पूछ लेने देते हैं अध्यक्ष महोदय.

श्री के.डी.देशमुख--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तहसीलदार ने जानबूझकर ऐसे दबंग व्यक्ति पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं किया, इस आदमी ने अपने मिल के चारों ओर 2 एकड़ 68 डिसीमल भूमि पर दीवाल बनाकर कब्जा करके रखा है और 10 साल से कब्जा करके रखा है. आम जनता उस गांव की परेशान है, मैंने स्वयं पत्र लिखा तहसीलदार को, एस.डी.एम. को पत्र लिखा, कलेक्टर को पत्र लिखा मगर इस तहसीलदार ने उस दबंग आदमी के खिलाफ आज तक कोई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की है और जब मैंने विधान सभा प्रश्न किया, तो कल तहसीलदार वहां पहुंचा और अतिक्रामक को बोला अभी 5 फुट दीवाल तोड़ दे, नहीं तो मर जाउंगा, विधान सभा में मामला लग गया है. 500 मीटर दीवाल में से उस अतिक्रामक ने बस 5 फुट दीवाल तोड़ा है तो इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूरी दीवाल में लगता क्या है, जे.से.बी.मशीन से हटाने में बस एक ही घंटे का काम है. वह दबंग व्यक्ति जिसने 10 साल से कब्जा करके रखा है, तहसीलदार ऐसे आदमी को क्यों संरक्षण दे रह है ?

श्री रामपाल सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, साथी हैं, लोकसभा से भी भ्रमण कर यहां आये हैं, उनकी चिन्ता वाजिब है, मैं उस पर कार्यवाही करूंगा अध्यक्ष महोदय, अगर उन्होंने तहसीलदार ने आज की तारीख तक पूरी दीवाल अतिक्रमण नहीं हटाया होगा तो हम उस तहसीलदार को भी निलंबित कर देंगे.

अध्यक्ष महोदय--सदस्य महोदय, धन्यवाद दे दीजिये उन्हें.

श्री के.डी.देशमुख--दीवाल का क्या होगा, तहसीलदार तो हट जायेगा.

श्री बाबूलाल गौर--यह इन्होंने अच्छा पूछा.

श्री रामपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, इसको क्लीयर कर दूं, जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं, हमने जवाब में दिया था 1 महीने में तोड़ेंगे, विधायक जी ने अभी जिद की है तो हमने आज की तारीख में उसको तोड़ दिया है, मेरा निवेदन यह है कि वह कह रहे हैं 5 फुट दीवाल तोड़ी है, अगर पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया होगा, तो हम तहसीलदार को निलंबित करेंगे.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न संख्या-18.

श्री के.डी. देशमुख -- अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात कर रहे हैं ..

अध्यक्ष महोदय -- उनका आ जाने दें. आप उन्हें धन्यवाद दे दीजिये.

श्री के.डी. देशमुख -- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद किस बात का अभी दूं. (हंसी) सवाल दीवाल का है, आज तक मैं सदन को जानकारी दे रहा हूं..

अध्यक्ष महोदय -- दीवाल और तहसीलदार दोनों जायेंगे. आप बैठ जाइये.

श्री के.डी. देशमुख -- अध्यक्ष महोदय दीवाल टूटना चाहिये. कितने दिन में, एक महीने का टाइम दिया. मैं पूछ रहा हूं कि वह कितने दिन में टूट जायेगी.

श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, कितने दिन में? मैं अभी कह रहा हूं कि आज की तारीख तक अगर नहीं टूटी होगी, तो वह टूट ही गयी.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- भाऊ, अब तो धन्यवाद दे दो. (हंसी)

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि का उद्योगों को अवैध हस्तांतरण

18. (*क्र. 3452) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले की मैहर तहसील स्थित के.जे.एस. सीमेंट की किस-किस ग्राम में किस अराजी क्रमांकों की कितने रकबे की भूमियां, किस-किस नाम पर खसरा पंचशाला में दर्ज हैं? (ख) मैहर तहसील के ग्राम बेलदरा, गिरगिटा, कटिया/मिघट, लखवार, अमिलिया कलां में सुंदर कोल के नाम कितने रकबों की, किस क्रमांकों की अराजी का भूमि स्वामित्व है? (ग) क्या यह सत्य है कि एक अप्रैल, 2012 से प्रश्नतिथि तक सुन्दर कोल के द्वारा उक्त भूमियों को के.जे.एस. सीमेंट को विक्रय का है? अगर हां तो ग्रामवार/भूमि क्रमांकवार/भूमि के रकबोंवार/दिनाकवांर/भूमि की विक्रय राशिवार जानकारी दें? (घ) क्य यह सत्य है कि प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' में उल्लेखित भूमियों की जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर, सतना के द्वारा सुन्दर कोल, ड्राईवर के.जे.एस. सीमेंट के नाम की भूमियों को के.जे.एस. सीमेंट के नाम पर हस्तांतरित कर दिया है? अगर नहीं, तो कौन-कौनसे प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर के समक्ष लंबित हैं?

श्री रामपालसिंह मंत्री राजस्व विभाग

(क) जानकारी का परिशिष्ट ''अ'' पुस्तकालय में रखा गया है।

(ख) ग्राम गिरगिटा में कुल रकबा 3.261 है0, ग्राम लखवार में 0..425 है0, तथा अमिलिया खुर्द में 3.187 है0 सुन्दर कोल के नाम दर्ज हैं। विस्तृत जानकारी का परिशिष्ट ''ब'' पुस्तकालय में रखा गया है।

(ग) प्रश्नाधीन अवधि में अमिलिया खुर्द रकबा 12.217 है0 का बैनामा रू. 5,50,03,500/–कीमत लेकर दस्तावेज क्रमांक–2820 दिनांक 18.12.2013 से श्री सुन्दर कोल पिता रामस्वरूप कोल द्वारा के.जे. एस.सीमेन्ट लिमिटेड मैहर के पक्ष में पंजीयन किया गया है। विस्तृत जानकारी का परिशिष्ट ''स'' पर है।

(घ) जी हां। भूमि स्वामी सुन्दर कोल द्वारा मौजा अमिलिया खुर्द तहसील मेंहर की आराजी न 81 रकबा 0.345 हैक्टेयर, मौजा लखवार तहसील मैहर की आराजी न. 81/2 रकबा 0.079 हैक्टेयर, आराजी नं. 82/2 रकबा 1.541 हैक्टेयर आराजी नं. 81/1 रकबा 0.052 हैक्टेयर, आराजी नं. 821प रकबा 1.028 हैक्टेयर, आराजी नं. 81/1 रकबा 0.026 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 85/5प रकबा 0.514 हैक्टेयर एवं मौजा गिगरिटा तहसील मैहर की आराजी नं. 23 रकबा 0.052 हैक्टेयर, आराजी नं. 24 रकबा 0.941 हैक्टेयर, आराजी नं. 20/1 रकबा 0.020 है0, आराजी नं. 21/1 रकबा 0.540 है0 आराजी नं. 20/2 रकबा 0. 020 है, आराजी नं. 21/2 रकबा 0.540 है0 आराजी नं. 20/3 रकबा 0.020 है0, आराजी नं. 21/3 रकबा0.0540 है0 आराजी नं. 20/5 रकबा 0.100 है0, आराजी नं. 28/5ख रकबा 0.400 है0 एवं आराजी नं. 29/5/ख रकबा 0.012 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 7.220 है0 भूमि विक्रय की अनुमति का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिनमें अनुविभागीय अधिकारी का जांच प्रतिवेदन हेतु अपेक्षित है।

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी -- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में शासन ने जो माना है कि जो गलती हुई और संबंधित जो भी उद्योगपति था, उसने कूट रचित दस्तावेजों से अपने ड्राइवर के नाम अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन हस्तांतरण कराई और हस्तांतरण उपरांत उस जमीन को अपने ड्राइवर से अपने नाम करवा लिया. मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे, यह अवगत करा दें.

श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के प्रावधानों के तहत कलेक्टरों को यह अधिकार रहते हैं कि आदिवासी भाइयों की जमीन नाम करने के आदेश रहते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, निर्देश हैं कि उसमें भूमिहीन न हों और उसके बाद विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा है कि एक आदिवासी से दूसरे आदिवासी जो सुन्दर कोल पिता रामस्वरुप कोल ने जमीन खरीदी और जमीन खरीदकर के.जे.एस.सीमेन्ट लिमिटेड, मैहर के पक्ष में रजिस्ट्री कर दी. तो इसमें जो भी माननीय सदस्य चाहे उस ढंग से हम जांच करा सकते हैं. अगर कोई गड़बड़ी है, तो निश्चित रुप से जांच करायेंगे और मध्यप्रदेश में आदिवासियों के लिये पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, माननीय चौहान साहब काम कर रहे हैं और उनके हितों से अगर कोई खिलवाड़ करेगा, तो हमारा विभाग भी और सरकार अनुमति नहीं देगी. अ्गर उनके साथ जरा भी कोई गड़बड़ की गयी है, तो निश्चित रुप से हम वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी -- अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मामला कलेक्टर से संबंधित है. तो जो भी वरिष्ठ अधिकारी जायें, वह भोपाल से जायें साथ में लेजिसलेचर का भी कोई व्यक्ति उसमें समाहित हो, जिससे कि जांच निष्पक्ष हो सके.

श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपके माध्यम से आग्रह कर दिया है कि निश्चित रुप से कोई गड़बड़ी की है, तो हम भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी भेजेंगे और भी जो सुझाव देंगे , माननीय विधायक जी हैं, तो उनको भी पूरी जांच से अवगत करायेंगे. आप कोई और तथ्य दें, तो उस पर भी हम निश्चित रुप से कार्यवाही करेंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी -- अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जांच में कोई न कोई लेजिसलेशन से भी साथ में जायें.

अध्यक्ष महोदय -- कोई विधायक.

श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, आदेश आप कर सकते हैं, आप निर्देश हमें दे दें, हम भेज देंगे विधायक जी के साथ. आप अगर अनुमति देंगे, बाकी मैं समझता हूं कि जरुरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है.

सफाई कर्मियों की कार्य के दौरान मृत्यु की जांच

19. (*क्र. 3832) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत एक वर्ष के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के कितने सफाई कर्मचारियों की मृत्यु कार्य करते समय हुई है? (ख) क्या यह सही है कि दिनांक 17-6-2008 को भोपाल के कोटरा सुलतानाबाद क्षेत्र में सीवर मेन होल सफाई कार्य के दौरान दो सफाई कर्मियों की मृत्यु हो गई थी? (ग) प्रश्नांश ''क'' और ''ख'' के प्रकाश में क्या कोई जांच की गई थी? यदि हां तो किसके द्वारा तथा उक्त जांच में किसे व किस आधार पर दोषी पाया गया था? (घ) क्या यह भी सही है कि उक्त घटना में जो अधिकारी अवकाश पर था उसे ही दोषी करार कर दिया गया था, तो इसके लिये कौन दोषी है? क्या जांच में लापरवाही बरती गई है? यदि हां तो इसका कौन दोषी है? शासन द्वारा उक्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी व कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विगत एक वर्ष के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल परिक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई है. (ख) जी हां. (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में मजिस्ट्रियल जांच एवं विभागीय जांच की गई थी, जिसमें श्री आर. के. दीक्षित, उपयंत्री को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमति के अवकाश पर रहने के लिये दोषी पाया गया. (घ) जी नहीं. मजिस्ट्रियल जांच एवं विभागीय जांच के आधार पर ही कार्यवाही की गई है. अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री के.के. श्रीवास्तव -- अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से प्रश्न किया था कि एक कर्मचारी, जो अवकाश की छुट्टी देकर के जाता है आकस्मिक आवकाश, यह उसका अधिकार है. उसको कोई घर में काम है, तो वह अवकाश की छुट्टी देकर ऑफिस में रिसीव कराकर जाता है और वह घर चला जाता है. कोई घटना घटने के बाद फिर उसको कहा जाता है कि तुमने सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली थी...

अध्यक्ष महोदय -- आप प्रश्न पूछिये.

श्री के.के. श्रीवास्तव -- अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि यह उस अधिकारी के खिलेफ कार्यवाही करने का क्या औचित्य है, जो छुट्टी लेकर चला गया. यही प्रश्न है मेरा. जो अधिकारी छुट्टी लेकर घर चला गया, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का औचित्य बनता

है. यह ईएनसी ने भी कहा है कि कोई औचित्य नहीं बनता है उनके खिलाफ जांच करने का. आर.के.दीक्षित के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी है, वह अनुचित है. इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूनः जांच उसमें करवायें और जिस अधिकारी ने कूट नीति से गलत तरीके से उसको कहा कि तुम्हें अनुमति नहीं थी. बाद में पूरे उसने कागज, दस्वतावेज बनाये हैं. इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही हुई है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वरा जिस आर.के.दीक्षित के बारे में बात की जा रही है, यह बिना छुट्टी लिये आर.के.दीक्षित चले गये थे. इन्होंने विधिवत छुट्टी नहीं ली और इसलिये उनको दोषी पाया गया है और असंचयी तरीके से इनकी एक वेतन वृद्धि रोकी गयी है. कोई ऐसा बड़ा पनिशमेंट नहीं दिया गया है. बिना छुट्टी के गये हैं तो इतना तो पनिशमेंट तो दिया ही जा सकता है.

श्री के. के .श्रीवास्तव --माननीय अध्यक्ष महोदय, अवकाश की छुट्टी दी है उसके बाद अगर उनकी छुट्टी अस्वीकृत थी तो उनको फोन करके सूचना देना चाहिये थी तो वे घर नहीं जाते .

अध्यक्ष महोदय-- मजिस्ट्रियल जांच हुई है इस मामले की.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले- अध्यक्ष महोदय उनका अवकाश स्वीकृत नहीं था. अधीक्षण यंत्री ने जांच की और उसमें यह पाया कि यह बिना छुट्टी के गये हैं.

श्री के.के. श्रीवास्तव- मजिस्ट्रियल जांच में ईएनसी ने कहा है . जिला मजिस्ट्रियल भोपाल के जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन सहायक यंत्री के संबंध में इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया. किंतु जो उप यंत्री मुख्यालय पर नहीं थे तथा अवकाश पर थे उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाना उचित दर्शाता है यह जांच प्रतिवेदन निष्कर्ष स्वीकार योग्य उचित प्रतीत नहीं होता. यह ईएनसी की रिपोर्ट है.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्नकाल का समय हो चुका है . मंत्री जी

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच भी हो चुकी है और मजिस्ट्रियल जांच में यह पाया गया है.

श्री के.के. श्रीवास्तव-- उसको औचित्यहीन बताया है, ईएनसी ने.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- अध्यक्ष महोदय, अब मुझे जबाव ही नहीं देने देंगे तो कैसे चलेगा.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्नकाल समाप्त

(प्रश्नकाल समाप्त)

नियम 167(क) के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय -- निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

1. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
2. श्री कमलेश्वर पटेल
3. श्री रामनिवास रावत
4. श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी
5. श्री दुर्गालाल विजय
6. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
7. श्री प्रदीप अग्रवाल
8. श्री संजीव छोटेलाल उइके
9. श्री विश्वास सारंग
10. श्री केदारनाथ शुक्ल

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में प्रदेश में यह "व्यापम का सच" नाम की एक पुस्तक वितरीत की जा रही है. इस पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल का मौने है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के भवन का चित्र है. इस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं है. केवस मुद्रक लिखा है विजन पब्लिकेशन, भोपाल . इसका पता भी नहीं है, न फोन नंबर है. और इसका प्रकाशक भी कोई नहीं है. माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मौने की छपी हुई किताब में सरकार के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और विधानसभा जो आपकी अभिरक्षा में है, आपके

संरक्षण में है, विधासभा के महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें छपे हुये हैं इसमें सरकार और विधानसभा की व्यवस्था के प्रति प्रश्नचिह्न लग जाता है.

अध्यक्ष महोदय-- आप क्या चाहते हैं.

श्री रामनिवास रावत-- मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है.

अध्यक्ष महोदय-- यह स्थगन का विषय नहीं है.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय स्थगन का विषय है. क्या किसी के मोनो का इस्तेमाल किया जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय-- किसी किताब में छपा है इसको लेकर के स्थगन कैसे आयेगा. स्थगन प्रस्ताव तो किसी घटना पर आता है. स्थगन अविलंबनीय लोक महत्व की घटना पर आता है आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं. किसी किताब पर कैसे स्थगन आ जायेगा.

श्री रामनिवास रावत-(XX)इसलिये स्थगन आयेगा.

अध्यक्ष महोदय-- यह विषय यहां का नहीं है. आप किसी अन्य प्रकार से अन्य जगह इसकी शिकायत कर सकते हैं, यदि कोई प्रावधान हो तो.

श्री रामनिवास रावत- क्या यह आपराधिक कृत्य नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- स्थगन घटना पर होता है या किताब पर होता है.आप यह बता दीजिये आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं.

श्री रामनिवास रावत--सरकार की व्यवस्था संचालन आपके हाथ में है, विधानसभा के काजग इसमें छप रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- कोई नियम में तो आये. तो लेने को तैयार हैं, आप आपने नियम ढूंढा स्थगन का . किताबों पर भी स्थगन लेने लगेंगे तो 1000 छप रही हैं.

श्री रामनिवास रावत-- क्या व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मोनो से किताब छापना आपराधिक कृत्य नहीं है.

अध्यक्ष महोदय--यहां पर आपराधिक प्रकरणों की विवेचना नहीं होती आप कृपा करके जो उसका सक्षम फोरम हो वहां पर जायें.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, सक्षम फोरम यह भी तो है.

अध्यक्ष महोदय-- यह नहीं है.

श्री रामनिवास रावत-- (XX).

अध्यक्ष महोदय-- विधानसभा की चर्चायें यहां पर नहीं की जाती है. बैठें.

श्री सुंदरलाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय, आप यह बता दें कि विधानसभा में किन किन विषयों को नहीं लिया जा सकता है. यह बहुत गंभीर विषय है.

पत्रों का पटल पर रखा जाना

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2012-2013

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति (कुंवर विजय शाह) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उप धारा (1) (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 पटल पर रखता हूं.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि प्रदेश का कोई विषय नहीं जिस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती है.

अध्यक्ष महोदय-- आपने क्या दिया?

श्री सुन्दर लाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय, आपसे क्षमा चाहता हूं. आपने कहा कि यह विषय विधानसभा में नहीं उठाया जा सकता.

अध्यक्ष महोदय-- मैंने यह कहा कि यह स्थगन में नहीं आता किसी अन्य नियम में लाईये. आप किसी अन्य फोरम पर जाईये.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- फोरम मतलब बाहर जाना हो गया.

अध्यक्ष महोदय-- किसी दूसरे नियम में आप लायेंगे तो देखेंगे. (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, आप सभी के संरक्षक हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जायें. (व्यवधान)

श्री कमलेश्वर पटेल-- अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की गोपनीयता भंग हुई है.

अध्यक्ष महोदय-- इस बारे में कक्ष में बात करिये.(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, आप मार्गदर्शन दे सकते हैं. अगर हम अनभिज्ञ हैं. (xx).

अध्यक्ष महोदय-- आप मार्गदर्शन मानते कहां हैं. अभी यह मार्गदर्शन है कि कृपया बैठ जायें और माननीय रामनिवास रावत जी को अपना ध्यानाकर्षण पढ़ने दें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- हम आपसे मार्गदर्शन (xx) मांग रहे हैं. कृपया दे दें. पूरा सदन भी जान जायेगा और हम भी जान जायेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- यह मेरा काम नहीं है. आपने जिस नियम में दिया है उसमें यह नहीं आता. कृपया रावतजी को अपना ध्यानाकर्षण पढ़ने दें. यह भी लोक महत्व के विषय हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- तिवारी जी, रावतजी के ध्यानाकर्षण में क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- आपको तो हर चीज में व्यवधान ही लगेगा.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)-- अध्यक्ष महोदय, आपसे सदस्य निवेदन कर रहे हैं. अगर यह विषय स्थगन में नहीं आता तो आसंदी से अनेक बार जो स्थगन में नहीं आता, उसको आपने ध्यानाकर्षण में, नियम 139 में लिया है. आप जिस नियम के तहत इसमें चर्चा कराना चाहें, उस पर करा लें.

अध्यक्ष महोदय-- आपके सुझाव पर विचार कर लेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे-- हां, आप विचार कर लें और किसी भी नियम के तहत चर्चा में ले लें. इतनी प्रार्थना है.

अध्यक्ष महोदय-- आपके सुझाव पर विचार कर लेंगे.

श्री बाबूलाल गौर-- आपकी आवाज इतनी कम है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- आपको जवाब नहीं देना है. जवाब उन्हें देना है. उन्हें समझ में आ रहा है.

श्री बाबूलाल गौर-- आपकी बैटरी डाऊन हो गई है.

श्री रामनिवास रावत-- कभी डाऊन नहीं होगी. कोई दूसरा मंत्री होता तो गति को बढ़ा देता.

समय 1137 बजे **ध्यानाकर्षण की सूचनाएं.**

श्री रामनिवास रावत (सदस्य)

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्राम पंचायत गसवानी में राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण हेतु राशि 14.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.8.13 को प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत को कार्य एजेंसी बनाया गया। ग्राम पंचायत गसवानी द्वारा ग्राम पंचायत की मीटिंग में चर्चा उपरांत दिनांक 15.12.13 को उपयंत्री विजयपुर द्वारा ले आउट दिए जाने के पश्चात पंचायत भवन प्रांगण में निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया। दिनांक 26.01.14 को आयोजित ग्राम सभा में सर्व सम्मति से उक्त भवन का निर्माण पंचायत भवन प्रांगण में कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया, तत्पश्चात भवन का निर्माण निर्वाध रूप से चलता रहा जिसका समय समय पर रू 2.88 लाख का मूल्यांकन संबंधित उपयंत्री द्वारा किया गया है अभी तक निर्माण में लगभग 3.50 राशि व्यय की जाकर काफी निर्माण कार्य कराया जा चुका है। इसी बीच किसी व्यक्ति की शिकायत पर नायब तहसीलदार एवं पटवारी ने स्थल निरीक्षण कर निर्माणाधीन स्थल को सभी दृष्टियों से उपयुक्त बताया, तत्पश्चात दिनांक 31.5.14 को विशेष ग्राम सभा लेने हेतु प्रभारी पी.एस.ओ. कृष्णपाल सिंह जादौन को नोडल अधिकारी बनाया गया। ग्राम सभा का आयोजन हुआ जिसमें नोडल अधिकारी विलंब से पहुंचे और सचिव से प्रासिडिंग बुक प्राप्त कर बिना प्रस्ताव पारित कराए प्रोसिडिंग बुक को अपने साथ विजयपुर ले गए। दिनांक 3.6.14 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयपुर द्वारा सरपंच को पत्र दिया जिसमे निर्देश दिये गए कि पंचायत भवन का निर्माण कार्य गसवानी स्थित गढ़ी में कराया जावे। दिनांक 31.5.14 की प्रोसिडिंग बुक वापस प्राप्त होने पर पता चला कि प्रोसिडिंग बुक में प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है एवं निर्णय किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है जो कि प्रोसिडिंग में अंकित अलग अलग हस्तलिपि से सिद्व होता है। इस प्रकार अभी तक राजीव गांधी भवन का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत से अधिक होने, राशि 3.50 लाख व्यय होने, कार्य की गुणवत्ता ठीक होने, स्थल उपयुक्त होने के बाद भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा निर्माण स्थल परिवर्तित किए जाने के निर्देश देने के कारण एवं कार्य बंद होने से ग्रामवासियों में शासन के प्रति रोष व्याप्त है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) - अध्यक्ष महोदय,

"ग्राम पंचायत गसवानी में स्वीकृत राजीव गॉधी सेवा केन्द्र का निर्माण सरपंच ग्राम पंचायत गसवानी द्वारा दि0 15.12.2013 को उपयंत्री से ले-आउट लेकर प्रारंभ कर दिया गया तथा कार्य निर्माण हेतु प्रथम मस्टर रोल दि0 24.01.2014 से प्रारंभ हुआ। कार्य प्रारंभ करने के दौरान ग्राम पंचायत गसवानी के नागरिकों द्वारा स्थल चयन का सार्वजनिक रूप से विरोध किया गया, तब सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत गसवानी ने दि0 26.01.2014 की ग्राम सभा में पूर्व से प्रारंभ किये गये निर्माण कार्य के स्थल चयन का प्रस्ताव ग्राम सभा पंजी में लिखा दिया, उक्त ग्राम सभा के बारे में ग्रामवासियों को समुचित रूप से सूचित नहीं किया गया। ग्रामवासियों को ज्ञात होने पर दि0 15.02.2014 को खण्ड स्तरीय अन्त्योदय मेले में ग्राम पंचायत गसवानी के लोगों ने राजीव गांधी सेवा केन्द्र के स्थल चयन हेतु ग्राम सभा आयोजित कराने का अनुरोध किया । ग्रामवासियों की मांग के आधार पर दि0 31.05.2014 को विशेष ग्राम सभा आहुत करने हेतु प्रभारी पंचायत निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर ग्राम सभा आयोजन हेतु भेजा गया। ग्राम सभा की सूचना गांव में सहजदर्शित स्थानों पर चस्पा कर एवं डोंढी पिटवाकर आमजन को दी गई। ग्राम सभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गढी गसवानी में पंचायत भवन (राजीव गांधी सेवा केन्द्र) का निर्माण कराया जाये। ग्राम सभा द्वारा चयनित स्थल पर भवन निर्माण के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विजयपुर द्वारा सरपंच एवं सचिव को दिये गये। ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण प्रभारी पंचायत निरीक्षक एंव नोडल अधिकारी द्वारा लिखा गया है जो कि पूर्णतः सही है जो किसी भी प्रकार से कूटरचित नहीं है। सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गसवानी ने ग्राम सभा के प्रस्ताव को बिना निर्माण कार्य प्रारंभ कर राशि व्यय की है जो की सरपंच से ही वसूली योग्य है। वर्तमान में ग्रामवासियों एवं आमजन में किसी प्रकार का विरोध एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।"

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, जहां पर ग्राम पंचायत का भवन बना है, वहीं यह ग्राम स्वराज भवन बनाया जा रहा है. यह भूमि राजस्व प्रलेख में पंचायत भवन और पंचायत परिक्षेत्र के लिए दर्ज भी है और जहां पर गढ़ी में वे भवन बनाने की बात कर रहे हैं, वहां प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है और वह काफी दूर है और अनुपयुक्त है. आप कह रहे हैं कि नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव लिखा गया, क्या नोडल अधिकारी को प्रस्ताव लिखने के लिए अधिकृत किया था? नोडल अधिकारी की देख-रेख में ग्राम सभा होगी, क्या नोडल अधिकारी को यह अधिकार था कि वह कार्यवाही विवरण या प्रोसिडिंग की किताब अपने साथ में ले जाए और विजयपुर में बैठकर लिखे?

अध्यक्ष महोदय, ले-आउट सब-इंजीनियर ने दिया और अपने मस्टर रोल जारी करने की बात खुद ही स्वीकार की है. मस्टर रोल सीईओ जनपद पंचायत द्वारा जारी किया गया, उसके बाद दिनांक 15.2.14 को भी मस्टर रोल जारी किये गये, दिनांक 17.2.14 में भी मस्टर रोल जारी किये गये, दिनांक 27.2.14 में भी मस्टर रोल जारी किये गये, जब इतने बार मस्टर रोल जारी किये, तहसीलदार और पटवारी ने रिपोर्ट दी कि स्थल उपयुक्त है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है. एक व्यक्ति जो जानबूझकर अपने स्वार्थ के कारण स्कूल बिल्डिंग में या स्कूल प्रांगण में यह भवन बनाना चाहता है. जब प्रथमतः एकमात्र एक या दो-चार पंचायतें पूरे प्रदेश में होंगी, जहां पंचायत प्रांगण के लिए जमीन आरक्षित होगी. उनमें से एक है कि राजस्व प्रलेख में पंचायत भवन और पंचायत प्रांगण के लिए जमीन आरक्षित है. वहीं पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनना चाहिए तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप वहीं भवन बनाने के निर्देश प्रदान करेंगे? दूसरा, मैंने उल्लेख किया कि नोडल अधिकारी क्या प्रोसिडिंग लिखने के लिए अधिकृत किया था? तीसरा, आप कह रहे हैं कि दिनांक 26.1.14 की सूचना नहीं दी गई, पूरा प्रदेश जानता है कि शासन के स्थायी निर्देश हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ग्राम सभा बुलाई जाएगी और आप उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि इसकी प्रापर सूचना नहीं दी गई, पूरा प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्र का हर नागरिक, मतदाता जानता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ग्राम सभा होगी ही. उसके बावजूद भी सूचना दी गई और

आप कह रहे हैं कि सूचना नहीं दी गई. आप क्या चाहते हैं, इसमें मेरा कहना है कि आप न्याय करें, इस पूरी घटना का विवरण दिखवाएं. मंत्री जी हंस रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा बनाया हुआ जवाब पढ़ रहे हैं? इन चीजों को आप खुद भी जानते हैं जो मैं कह रहा हूं और दिनांक 26. 1.14 का प्रस्ताव निरस्त नहीं किया गया और दूसरा प्रस्ताव पारित कर लिया, ऐसी स्थिति में खुले दिल के साथ और नियम-कानून के साथ क्या कार्यवाही करेंगे, यह बता दें?

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है , नोडल अधिकारी ने प्रोसीडिंग नहीं लिखी है. वह तो केवल उसके पर्यवक्षेण के लिए और सुपरविजन के लिए था. अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत छोटा है कि पंचायत भवन कहां बने. एक स्थान जहां पर पुराना पंचायत भवन था वह 1975 में बना था. उसी पंचायत भवन के बाजु से नया पंचायत भवन बन रहा है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. एक दूसरा पक्ष है वह कह रहा है कि गढ़ी में बनाएं. सिर्फ एक छोटे से पंचायत भवन के लिए विवाद है. अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे. हम तो सोचते है कि ग्राम स्वराज कैसे आएगा, भगवान जाने समझ में नहीं आ रहा है. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, आपकी मंशा भी समझ रहे हैं. उसमें करीब 3 लाख रूपया व्यय भी हो चुका है. अब वहां पर विवाद है कि ग्रामसभा, जो ये हमारे चार दिवस ग्रामसभाओं को आयोजित करने के हैं, उस तारीख को ग्राम सभा आयोजित हुई थी. और ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ. अब दूसरे पक्ष ने कहा कि हमें सूचना नहीं मिली और इस कारण से दूसरे पक्ष के आग्रह के आधार पर गांव गांव में सूचना चस्पा की गई, सभी को बताया गया कि हां भाई इस तारीख को ग्रामसभा है और जब दुबारा ग्रामसभा हुई तो उन्होंने स्थान परिवर्तन करने का कहा. अब हम ऐसे विवादास्पद विषयों के लिए भोपाल से एक अधिकारी भेज कर हम वहां पर पूछ लेंगे, निष्पक्ष रूप से कि गांव के लोग कहां पर चाहते हैं, ग्रामसभा में तो वहां पर स्वीकृति दे दी जाएगी और पंचायत भवन बनवा दिया जाएगा. बहुत छोटा सा विषय है.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, विषय छोटा नहीं है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और मंत्री जी सही भी कहना चाहते हैं लेकिन सही कह नहीं पा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय- आप उनसे चर्चा कर लें और उसका निराकरण कर लें.

श्री रामनिवास रावत-अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा और मंत्रीजी भी जानते हैं कि नोडल अधिकारी को प्रोसीडिंग लिखने का अधिकार नहीं होता और आपने अपने जवाब में ही लिखा है कि प्रभारी पंचायत उप निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा ग्रामसभा का कार्यवाही विवरण लिखा गया है और ग्राम सभा का उपस्थिति विवरण सचिव द्वारा लिखा गया. प्रस्ताव क्रमांक सचिव द्वारा लिखा गया. और ग्रामसभा का केवल ठहराव , नोडल अधिकारी उसको घर ले गया और घर ले जाकर उन्होंने उसको लिखा , लोगों की उपस्थिति पहले से ही थी और घर ले जाने के बाद लिखा. इसमें स्पष्ट उद्देश्य परिलक्षित होता है कि क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया. मेरा निवेदन है कि इसमें 3 लाख 50 हजार रूपये व्यय हो चुके हैं. मैं तो यह चाहता हूं कि आप आ जाएं , आप को दौरे के लिए आमंत्रित कर रहा हूं. आपका स्वागत भी करूंगा. आपको जगह भी दिखाऊंगा. आगर आप अपने मुंह से खड़े होकर यह कह दोगे कि अनुपयुक्त है तो पूरे के पूरे पैसे रामनिवास रावत जमा करेगा.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी आप इनके साथ चर्चा कर निराकरण कर लें.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात मैं समझ रहा हूं. चूंकि उसमें राशि व्यय हो चुकी है और मैं यह दिखवा लूंगा कि नोडल अधिकारी की प्रोसीडिंग में यदि हैण्ड रायटिंग है तो ये गलत बात है और हम इसकी भी जांच करा लेंगे. दूसरा यह कि हम यहां से अधिकारी भेज कर... अब इतने छोटे से काम के लिए हम श्योपुर, विजयपुर तक जाएं , बहुत बड़ा भवन बनेगा तब आपके यहां आयेंगे. आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए दूसरी स्वीकृतियां दे रहे हैं. मैं माननीय सदस्य से यह कहा चाहता हूं कि हम वहां पर एक सामंजस्य

बनाने का प्रयास करेंगे और यदि सामंजस्य नहीं बना तो फिर जो नियम है और जो नीति है उसके अनुसार हम काम करेंगे.

अध्यक्ष महोदय—ठीक है.

श्री रामनिवास रावत- अध्यक्ष महोदय, यही तो बात है. अधिकारियों ने ही तो यह सब किया है.

अध्यक्ष महोदय—उन्होंने कहा है कि वे यहां से अधिकारी को भेज रहे है.

श्री रामनिवास रावत- अधिकारियों ने ही तो किया है. अधिकारी हमारी उपस्थिति में बात करें. नोडल अधिकारी का आप कह रहे हो, आपने ही उत्तर दिया है कि उसने लिखी है.

श्री गोपाल भार्गव—आपकी उपस्थिति में हम करवायेंगे. आपकी उपस्थिति में स्थान निर्धारण भी करवायेंगे और जांच भी करवायेंगे,आपकी उपस्थिति में स्थान निर्धारण भी करवायेंगे और जांच भी करवायेंगे.

श्री रामनिवास रावत- जो अधिकारी स्थल परिवर्तन करने की बात कह रहा है ..

अध्यक्ष महोदय-अब कृपया ये बात समाप्त करें. आपका विषय आ गया.

श्री रामनिवास रावत—मैं यह कह रहा हूं कि थोड़ा सा गंभीरता से दिखवाएं. क्या होगा राजीव गांधी भवन पड़ा रहेगा. कोर्ट जाएँगे. कम से कम आप इसको राजनीतिक.. इच्छा पूर्ति के लिए ...

अध्यक्ष महोदय—आप वरिष्ठ सदस्य हैं ,आपकी बात आ गई. उन्होने कुछ आश्वासन दिया है.

श्री रामनिवास रावत- मेरी बात आ गई, माननीय मंत्री जी भी, मै जो चाह रहा हूं वे कहना चाहते हैं लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है , वे कभी किसी के दबाव में नहीं रहते , आज पहली बार उनको दबाव में देख रहा हूं. हिम्मत वाले होते हुए भी और नियमानुसार कार्य करने की बात करते हुए भी. ..

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, जो नियमानुसार होगा उसको वहीं पर बनवा देंगे.

अध्यक्ष महोदय—नियमानुसार कर देंगे.

(2) जबलपुर जिले में भू-माफिया द्वारा आदिवासियों की भूमि सस्ती दर पर खरीदी जाना

श्री सुशील कुमार तिवारी (पनागर)—

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जबलपुर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से कई कतिपय भू- माफियाओं के गिरोह द्वारा आदिवासियों की जमीन सस्ती दर करीब 80 से 90 हजार रूपये प्रति एकड़ बहला फुसलाकर क्रय की गई है। जबकि उसकी वास्तविक कीमत 40 से 45 लाख रूपये प्रति एकड़ है तथा अभी तक लगभग 800 से 900 एकड़ आदिवासियों की जमीन उल्लेखित भू-माफियाओं द्वारा क्रय करने की प्रक्रिया निरंतर विगत एक से डेढ़ वर्षों से अनवरत चल रही है। आदिवासियों के विरूद्ध उक्त आर्थिक शोषण में शामिल गिरोह एवं इसमें संलिप्त अधिकारियों के कार्यकलापों से प्रशासन के प्रति स्थानीय जनता में आत्याधिक रोष व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) (दो) के अनुसार किसी ऐसी जनजाति के जिसे कि राज्य सरकार ने उस संबंध में अधिसूचना द्वारा, उस पूरे क्षेत्र के लिए, जिसको कि यह कोड लागू होता है या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (एबारीजनल ट्राइब) होना घोषित किया हो, किसी भूमिस्वामी का अधिकार – खण्ड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जाएगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जाएगा और न ही अंतरणीय होगा।
2. जबलपुर जिले में आदिम जनजाति सदस्य के नाम पर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज भूमियों के गैर आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय किये जाने की अनुमति उक्त प्रावधान के तहत देते समय आदिम जनजाति सदस्य को दिया गया प्रतिफल प्रचलित गाईड लाईन के अनुसार पर्याप्त हो और आदिम जनजाति सदस्य के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो, इस बात को विशेष ध्यान रखा जाता है।
3. अनुमति दिये जाने की शर्तों में यह अनिवार्य रूप से लेख किया जाता है कि पंजीकृत बैनामा निष्पादन के समय पंजीयक / उप पंजीयक द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावेगा कि आवेदक आदिवासी को प्राप्त होने वाली राशि वर्तमान गाईड लाईन में प्रश्नाधीन भूमि की कीमत से कम न हो अर्थात गाईड लाईन के अनुसार उप पंजीयक की जांच उपरांत निर्धारित कीमत अथवा अनुबंध अनुसार राशि जो अधिक हो, का बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट आवेदक आदिवासी को उप पंजीयक के समक्ष प्रदाय किये जाने पर ही विक्रय की अनुमति मान्य होगी। आवेदक आदिम जनजाति सदस्य को संपूर्ण राशि उप पंजीयक के समक्ष कास्र्ड बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट

की शर्त अनिवार्य रूप से अंकित की जाती है, जिससे पूर्ण राशि आदिम जनजाति सदस्य के बैंक खाते में ही जमा हो।

4. अनुमति दिये जाने के पूर्व प्रत्येक प्रकरण में आदिम जनजाति सदस्य को समक्ष में आहूत किया जाकर आदिम जनजाति सदस्य एवं गैर आदिम जनजाति सदस्य दोनों के मूल फोटो पहचान पत्रों का अवलोकन किये जाने के उपरांत उभयपक्ष के शपथ पूर्वक कथन दर्ज किये जाते हैं। जिसमें खुले न्यायालय में यह पूछा जाता है कि भूमि विक्रय के लिये आदिम जनजाति सदस्य पर कोई दबाव तो नहीं है।
5. न्यायालय कलेक्टर जबलपुर से अनुमति देते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि आदिम जनजाति सदस्य के पास जीवन यापन हेतु संहिता 1959 की धारा 165 में उल्लेखित अनुसार 5 एकड़ सिंचित अथवा 10 एकड़ असिंचित भूमि अनिवार्य रूप से शेष बचना चाहिए।
6. आदिम जनजाति सदस्य की भूमि गैर आदिम जनजाति सदस्य को अंतरित किये जाने की अनुमति राजस्व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करके संबंधित क्षेत्र के अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने के उपरांत प्रदान की जाती है। अतः व्यथित पक्षकार/ शिकायतकर्ता द्वारा खुले न्यायालय में आपत्ति भी प्रस्तुत की जा सकती है यदि प्रकरण में किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो आपत्तिकर्ता के पक्ष को ध्यान में रखकर विधिवत न्यायोचित आदेश पारित किया जाता है। तदोपरान्त भी आदेश से परिवेदित पक्षकार अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है।
7. उक्त कार्यवाही खुले न्यायालय में होने से शासन एवं प्रशासन के प्रति स्थानीय जनता में कोई रोष एवं असंतोष व्याप्त नहीं है।

श्री सुशील कुमार तिवारी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा अभी 6 मिनट पहले ही हमें जवाब दिया गया. इस जवाब से मैं सहमत नहीं हूँ. लगभग 2 हजार एकड़ जमीन आदिवासियों की लगभग 500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है. इसमें माननीय मंत्री जी ने दो पेज का जो उत्तर दिया है, आपको बता देना चाहता हूँ कि भू-राजस्व संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है और यह पता नहीं कहां से जो उत्तर आया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो बताया गया है, आदिवासियों की जमीन के लिए पर्याप्त उसके संसाधन इकट्ठे रहते हैं किन्तु मेरे पास सूचना के अधिकार के सारे प्रमाण मौजूद है और मैं यह बताना चाहता हूँ, पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ..

अध्यक्ष महोदय—आप सीधे प्रश्न पूछ लें.

श्री सुशील कुमार तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, उसको पूरा जीरो कर दिया गया है, एक तरफ से पूरी उसकी जमीन क्रय कर ली गयी है. लगभग 20 से 25 लोगों ने गिरोह बना के इस जमीन का क्रय किया गया है. इसके सारे प्रमाण मेरे सामने मौजूद हैं और एक एक व्यक्ति ने 150-150 एकड़ जमीन खरीदी है. जिस धारा 165(5) की धारा (2) का जो उल्लेख कर रहे हैं,इस उत्तर में ऐसा कुछ भी नहीं है . माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका वाचन करना चाहता हूँ. खण्ड-एक के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों में किसी एक व्यक्ति को जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी में अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी के ऐसी अनुज्ञा के बिना जो लेखबद्ध किये जाने के कारणों से दी जाएगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंध में किसी व्यवहार के परिणाम न तो अंतरित किया जाएगा न ही अन्तरणीय होगा. यह केवल 165 (5) की धारा 2 के अंतर्गत है, माननीय मंत्री जी ने यह जो दो पेज का उत्तर दिया है, मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं हूँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी इस सदन के

माध्यम से जांच होनी चाहिए और यह बहुत बड़ा घोटाला है. आदिवासियों को भूमिहीन किया जा रहा है.

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन जो नियम है वह तो बना हुआ है. आपने भी पढ़ दिया, हमने भी पढ़ दिया.धाराओं के अंतर्गत कलेक्टरों को अधिकार..

श्री सुशील कुमार तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, दो पेज का जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें है क्या?

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य कृपया उत्तर आ जाने दें.

श्री रामपाल सिंह-- माननीय अध्यक्ष जी, यह तो नियम प्रक्रियाओं से सब बंधे हुए हैं. जिले के अन्दर धारा के अंतर्गत अनुमति के अधिकार दिये हुए हैं, सुनवाई करते हैं और पूरा परीक्षण करते हैं, जो आदिवासी हैं उनसे पूछते हैं, कितनी जमीन बची है क्या है पूरा और उसके बाद उसकी अनुमति के कलेक्टर को पॉवर दिये गये हैं. माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है. इस तरह की जानकारी जबलपुर से हमको जो अभी प्राप्त हुई है, विलम्ब से हमको यह ध्यानाकर्षण प्राप्त हुआ है और फिर भी जानकारी जो अभी हमको मिली है. कुल 1365 प्रकरण कलेक्टर कार्यालय में विचाराधीन है, डेढ़ वर्ष में 605 प्रकरण स्वीकृत किये हैं और इस तरह 417 प्रकरण लम्बित हैं. रकबा और सब जानकारी हम बुलायेंगे लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय विधायक जी की जो चिन्ता है वह मैं समझ रहा हूँ. कहीं न कहीं ऐसी बात आयी होगी जिससे उनको यहां तक आना पड़ा है . मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि अगर इस तरह के कोई प्रमाण और इस तरह की कोई गड़बड़ियां, वहां पर कोई गिरोह काम कर रहा है तो मध्यप्रदेश में यह अपनी सरकार है , ऐसे गिरोहों के खिलाफ तो सख्त कार्यवाही करती है आप बतायें उसके खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे और इस तरह की कोई अनियमितता हुई है तो वल्लभ भवन के

सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाएंगे . मैं माननीय विधायक जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस तरह की और भी कोई गड़बड़ियाँ होती हैं तो निश्चित रूप से आप बतायें उसमें भी हम सीधी कार्यवाही करेंगे.

श्री सुशील कुमार तिवारी-- माननीय मंत्री जी,आपके द्वारा यह बताया गया कि कोई न कोई बात होगी ,बात तो यह है कि सरकार की बदनामी हो रही है.

अध्यक्ष महोदय-- आप सीधा प्रश्न कर लें. उन्होंने कहा है कि वह जीएडी से अधिकारी भेजकर जांच करा लेंगे.

श्री सुशील कुमार तिवारी-- यदि जाँच हो रही है तो उसकी समय सीमा भी बताई जाए कि कितने समय में जांच हो जाएगी और किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की जाए और उसमें हमारे विधानसभा के एक सम्मानित विधायक को भी उस जांच में रखा जाना चाहिए.

श्री रामपाल सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि हम सब लोग जो आपकी भावना है उसको समझते हैं, हम भी चाहते हैं अच्छे काम करें , सेवा का काम करें और व्यवस्थाओं में सुधार जरूरी है और इसके लिए आपने जो जांच की बात कही है, हम तीन महीने के अंदर इसकी जांच कराएंगे.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के आदिवासियों की जमीन जो भू-राजस्व में यह प्रावधान है कि उनके बेचने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए..(व्यवधान)....

श्री हर्ष यादव--- अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल में 2000 एकड़ भूमि आदिवासियों से गैर आदिवासियों ने ली..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी ने जांच कराने का बोल दिया है. बात समाप्त हो गई प्रस्तुतकर्ता सदस्य सहमत हैं.

समय- 12.02 बजे **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम से तैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री केदारनाथ शुक्ल(सभापति)-- अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रथम से तैंतीसवें प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं.

समय- 12.02 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय-- आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकायें प्रस्तुत की हुई मानी जाएँगी.

समय- 12.03 बजे **वक्तव्य**

मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन में नवीन पदों की स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय--- अब श्री सरताज सिंह लोक निर्माण मंत्री, मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन में नवीन पदों की स्वीकृति के संबंध में वक्तव्य देंगे.

लोक निर्माण मंत्री(श्री सरताज सिंह)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15 जुलाई 2014 को विधानसभा में संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में विभाग से संबंधित नीतिगित निर्णय लिया गया है कि मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधीन गठित मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में दो मुख्य अभियंता के पद तथा एक तकनीकी सलाहकार एवं एक प्रबंधन सहायक का पद शामिल करते हुए कुल चार अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्येदव कटारे)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो वक्तव्य की प्रति आई है वह बहुत संक्षिप्त है और मंत्री जी ने जो पढ़ा है वह बहुत बड़ा वक्तव्य है . ऐसा लगता है

कुछ औऱ होगा. मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि जो भी पद सृजित कर रहे हैं उनकी व्यापम से भर्ती नहीं करायें क्योंकि व्यापम के माध्यम से (xx) चल रहा है .

अध्यक्ष महोदय—यह कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. अब अनुदान की मांगों के बारे में प्रस्ताव आएगा.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं आपने अनुमति दी तो बोलने तो दीजिये .

अध्यक्ष महोदय-- अनुमति दी है तो विषय पर बोले , इस पर आप प्रतिक्रिया इसमें व्यापम शब्द कहाँ आया है.

श्री सत्यदेव कटारे--- तो हम विषय़ से बाहर कहाँ गये हैं. हमें यह बताइए कि हम कोई सलाह नहीं देंगे कि भर्ती कैसे करें. फिर यह लाये क्यों.

अध्यक्ष महोदय--- इसमें व्यापम शब्द कहाँ आया.

श्री रामनिवास रावत--- इसमें पदों की भर्तियाँ कैसे करेंगे यह बतायें.

श्री सत्यदेव कटारे-- क्या हम सुझाव भी नहीं देंगे क्या. आप आसंदी से कभी भी खड़े होकर रोक देते हैं. मेरा कहना है कि इनकी सरकार यह वायदा करे कि इनकी भर्तियाँ व्यापम के माध्यम से नहीं की जाएंगी, अध्यक्ष महोदय, जो यह मंत्री जी लाए बहुत अच्छी बात है. हमें उम्मीद है कि उनके विभाग की कार्यशैली इससे बढ़ेगी और कार्यप्रणाली बढ़ाएँ, कार्य भी बढ़ाएँ. लेकिन जो भी गड़बड़ियों की शिकायतें आती हैं, जब सदन में दूसरे सदस्य बोलते हैं, आपके दल के विधायक बोलते हैं, तब सरकार की सच्चाई सामने आती है, उसको ध्यान में रखें और उसको ध्यान में रखते हुए आगे कार्यवाही करें.

12.06 बजे

वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) मांग संख्या-11	**वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार**
मांग संख्या- 43	**खेल और युवक कल्याण**
मांग संख्या- 51	**धार्मिक न्यास और धर्मस्व.**

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए एक हजार चौतीस करोड़, उन्नीस लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण के लिए एक सौ एक करोड़, बयालीस लाख, सतावन हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए अठानवे करोड़, चार लाख, आठ हजार रूपये
	तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय - अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार क्रमांक
श्री रामनिवास रावत	1
कुंवर विक्रम सिंह	2
श्री हर्ष यादव	3
श्री बाला बच्चन	5
श्रीमती शीला त्यागी	9
श्री कमलेश्वर पटेल	10
श्री जितू पटवारी	11
श्री आरिफ अकील	13

मांग संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण
श्री आरिफ अकील	1
श्री बाला बच्चन	2
श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)	3
श्री जितू पटवारी	4
कुंवर विक्रम सिंह	6
श्री हर्ष यादव	7
श्री लाखन सिंह यादव	8

मांग संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
श्री आरिफ अकील	1
कुंवर विक्रम सिंह	2
श्री बाला बच्चन	3
श्री लाखन सिंह यादव	4
श्री हर्ष यादव	5

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार मंत्री के अनुदानों की मांग संख्या 11, 43 एवं 51 पर चर्चा हेतु कार्यमंत्रणा समिति ने एक घंटे का समय निर्धारित किया है तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित किया है—

भारतीय जनता पार्टी	43 मिनिट
इंडियन नेशनल काँग्रेस	14 मिनिट
बहुजन समाज पार्टी	02 मिनिट
निर्दलीय	01 मिनिट

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा(मुंगावली)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11, 43 एवं 51 का विरोध और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ. मांग संख्या 51, आपका बजट बहुत कम है. 98 करोड़ के बजट में इतना बड़ा विभाग संभालना ठीक नहीं है, मेहरबानी करके आप बजट बढ़ाने की कोशिश करें.

अध्यक्ष महोदय, मुझे समाचार पत्रों से जानकारी मिली थी कि आपने चार्ज लेने के बाद में प्रदेश के सभी मंदिरों, धार्मिक ट्रस्ट और इनकी भूमि का और संपत्ति का रजिस्टर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, इस हेतु मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस विभाग को गंभीरता से लिया है. (मेजों की थपथपाहट) कृपया यह सुनिश्चित करें कि मंदिरों और ट्रस्टों की भूमि व संपत्ति का दुरुपयोग न हो, देखरेख करने वालों के हितों का भी ध्यान रखें और संपत्ति से प्राप्त लाभ, इन संपत्तियों की आय बढ़ाने और सामाजिक कार्यों व गाँव के या नगर के विकास में यह पैसा लगे. पुजारियों का सम्मान रहे और उनको ठीक से मानदेय मिले. आपने अमरकंटक, महेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मंडला, बैतूल, पन्ना, दतिया, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, मंडलेश्वर और मंदसौर को पवित्र नगर घोषित किया है, मैंने आपके विभाग के आदेश देखे हैं. यह जरूर है कि इस विवरण में आपने घोषणा के आदेश तो सब लगा दिए हैं लेकिन पवित्र नगर से आशय क्या है और पवित्र नगर

का क्या लाभ उन नगरों को मिलेगा, इसका कोई वर्णन नहीं है. पूरे के पूरे नगर को पवित्र घोषित करने का कोई मतलब नहीं है यदि उस नगर में शराब, मांस मदिरा और अंडों की दुकानें हैं, यह सब खुलेआम बिक रहे हैं या वैश्यावृत्ति का मोहल्ला भी है तो उस नगर को पवित्र नगर घोषित करने का कोई मतलब नहीं है.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाह रही हूँ. मेरे विभाग के अधिकारी नहीं आए हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- अध्यक्ष महोदय, पवित्र नगर या तो कुछ मंदिर और उसके आसपास का एरिया घोषित किया जाए. आपके विभाग की विवरण पुस्तिका में पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर के यात्रा नियम तो बना दिए पर मेरा आप से अनुरोध है कि मंदसौर में हिंगलाजगढ़ का बहुत प्रसिद्ध किला है और वहाँ का हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर भी है, उसकी भी सुध लेने का कष्ट करें और आप जाकर किला देखें कितना सुन्दर है और मंदिर कितना विशाल है. कंबोडिया के अंगकोरवाट के विशाल मंदिर को देखने के लिए आपने तीस हजार रुपये प्रति व्यक्ति के अनुदान का प्रबंध किया है, उसके लिए आपको बधाई पर मैं आप से अनुरोध करूँगा कि कंबोडिया का बहुत अच्छा और सुन्दर मंदिर है, विधायकों को भी इसका लाभ दें और एक विधायकों का दल कंबोडिया जाए, यह भी मेरा आपको सुझाव है.

अध्यक्ष महोदय, खेलकूद की मांग संख्या के बारे में मेरा आप से यह अनुरोध है कि आपने प्रत्येक गाँव में, बेहतर होता कि इस विवरण पुस्तिका में उन सब आदेशों की प्रतियाँ होतीं जिसमें आपने प्रत्येक गाँव में खेल के मैदान के लिए भूमि आरक्षित करने के लिए आपके विभाग ने निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों की प्रतियाँ अगर आप इस रिपोर्ट में लगाएँगे तो सारे विधायकों को पता लगेगा और वे अपने अपने गाँव में उस भूमि को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे.

12.12 बजे

{उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए}

उपाध्यक्ष महोदय, माइक व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए मेरा समय बढ़ाया जाए. खेलकूद विभाग के लिए मेरा आप से अनुरोध है....

उपाध्यक्ष महोदय-- अगर आपका माइक ठीक नहीं है तो आप दूसरे स्थान से बोल लें, समय का माइक से कोई ताल्लुक नहीं है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- यह पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं खेलकूद विभाग की मांगों पर आप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो विभिन्न खिलाड़ियों ने उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं और मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमियों की जो उपलब्धियाँ हैं वह आपके विवरण में है इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूँ लेकिन यह जो प्रत्येक गाँव में खेल का मैदान है, इसको बहुत गंभीरता से आपको लेना चाहिए क्योंकि गाँवों में बहुत अतिक्रमण है. जैसे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है बरखेड़ा पिपरई में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुव्हल हो गया है, भूमि सुरक्षित हो गई है लेकिन अतिक्रमण नहीं हट रहा है तो गाँव में बहुत सी भूमि है जिन पर अतिक्रमण है, उन सबको हटाकर, उन सबको खेल का मैदान घोषित करने का कष्ट करें और इस निर्देश का सख्ती से पालन कराएँ.

उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में आप अच्छे स्टेडियम बनाना चाहती हैं, इसमें एकरूपता लाना चाहती हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई दूँगा, आप एक ही डिजाइन चाहती हैं. लेकिन अगर कोई सांसद या विधायक 10,20, 100 करोड़ रुपये और कहीं से लाए तो उसको डिजाइन के लिए आप, उसके कंसलटेंट को, उसके ऑर्किटेक्ट को भी, आपके ऑर्किटेक्ट के साथ बैठकर कोई अच्छा स्टेडियम हर जो वित्तीय साधन है उसके अनुसार उस डिजाइन को बनाने के लिए निर्देश देने का कष्ट करें. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आप से यह भी अनुरोध है कि आप अगर खेल के मैदान हर गाँव में

दे रही हैं तो हर गाँव में आप क्रिकेट का किट, वॉलीवाल, बास्केटबॉल, यह चीजें भी आप हर गाँव में आपके बजट से उपलब्ध कराने का कष्ट करें और इसके लिए आपका बजट बहुत कम है, इसके बजट को आप बढ़ाने का कष्ट करें.

उपाध्यक्ष महोदय, खेलकूद के मामले के अलावा मैं रजिस्ट्रार फर्म सोसायटीज के बारे में भी बोलना चाहूँगा कि आपका रजिस्ट्रार, फर्म सोसायटीज को आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसको ज्यादा स्टाफ देने की जरूरत है और आपके जो विभागीय, संभागीय रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी के जो अधिकारी हैं उनके कार्यालयों को भी अधिक सुविधाएँ और अधिक स्टाफ देना चाहिए क्योंकि सैकड़ों की संख्या में समितियाँ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और हो रही हैं, उनके रेग्युलेशन के लिए, उनकी मॉनटरिंग के लिए, यह बहुत जरूरी है कि ज्यादा स्टाफ हो, कंप्यूटरायजेशन हो और खासतौर से रजिस्ट्रार और संभागीय रजिस्ट्रार निष्पक्ष रहें यह करना बहुत जरुरी है क्योंकि मैं खुद भी इसका विकटिम हूं. हम लोग मध्यप्रदेश क्रिकेट एशोसिएशन के मेंबर बने और आपके ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने एक फिलिन्दी शिकायत पर हमारे वोटिंग अधिकार छीन लिये हमको कोर्ट में जाकर वह अधिकार प्राप्त करना पड़ा है. अब वह फिर पीछे पड़ गया है, आप समझते हैं कि इंदौर में जो मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है होलकर की विश्व प्रसिद्ध टीम है उसकी अपनी सालों से रेपूटेशन है जिसमें कि सी.के. नायडू, जगदाले जैसे लोग विश्व क्रिकेट के स्टालवाट्र्स रहे हैं उसको संभालने वाले मेनन और संजय जगदाले यह बहुत बड़े क्रिकेटर हैं अगर आपका ज्वाइंट रजिस्ट्रार का व्यक्ति उनके कार्यालय में जायेगा और उनको humiliate करेगा, अभी किया भी है उनसे 40 साल का रिकार्ड मांग रहा है. तमाम् फर्म सोसायटी में गड़बड़ियां हो रही हैं उनकी तो फिक्र नहीं है लेकिन एमपीईए जैसी प्रतिष्ठित संस्था का 40 साल का रिकार्ड मांग रहे हैं और उसके लिये समय भी नहीं दे रहे हैं वे कह रहे हैं कि 20 तारीख को मैं आऊंगा आपको देना पड़ेगा. यह खिलाड़ियों का और खेल संगठनों का आपको सम्मान रखना पड़ेगा. They should be no politics in sports at the same time

they should be more sportsman sprit in politics. इस सिद्धांत के अनुसार कम से कम खिलाड़ियों की इज्जत, खेल संगठनों की इज्जत आपका रजिस्ट्रार एवं फर्म्स सोसायटीस करे. एक दागी संगठन मध्यप्रदेश बास्केट बॉल एसोसिएशन की फर्म्स सोसायटी रजिस्ट्रार ने इन्कवायरी की है इसका नाम बदलने का आदेश किया है. इसको भी इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अधीन कर दिया है. इंदौर डिवीजन क्रिक्रेट एसोसिएशन न केवल बास्केट बॉल पर कब्जा करना चाहता है, मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर भी करना चाहता है. आप एक ऐसा आदेश पारित कर दें कि हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग जितने एसोसिएशन हैं उन सब का अध्यक्ष इंदौर संभाग का क्रिकेट का अध्यक्ष होगा और प्रदेश स्तर के सभी का अध्यक्ष होगा.

अब मैं आपकी मांग संख्या 11, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पर आना चाहता हूँ. अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में उद्योगों का लाना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आपके पास इन्फास्ट्रकचर नहीं है, समुद्र तट नहीं है आपके पास बिजली भी पर्याप्त नहीं है और वित्तीय कठिनाइयां भी हैं. आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 में राज्य की सकल घरेलू उत्पादन में द्वितीयक क्षेत्र उद्योग का योगदान 2004-05 में 27.15 था जो बढ़कर 2011-12 में 28.99 प्रतिशत हो गया जो कि कम है और 2012-13 में तो यह घटकर 27.82 प्रतिशत हो गया है जो कि चिन्ताजनक है. यह मैं आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार भी 2012-13 में 47414 थे, 2013-14 में 44924 रोजगार निर्मित हुए जो कि 5.54 प्रतिशत कम हैं यह भी चिन्ताजनक है निर्देश देने का कष्ट करें कि रोजगार ज्यादा बढ़ने चाहिये.

उपाध्यक्ष महोदय,पीथमपुर बामोर में 136, मंडीदीप में 18, देवास में 8 मालनपुर में 13 उद्योग बंद हुए हैं. यह इकाइयां बंद हुई हैं यह चिन्ता की बात है इकाइयां बढ़नी चाहिये और बंद इकाइयों को चालू करें इसका निर्देश देने का कष्ट करें. हथकरघा उद्योग में भी पिछले वर्ष की तुलना

में बनाये गये कपड़ों में कमी हुई है, इसमें रोजगार उपलब्ध कराने वाले कारीगरों की वृद्धि जरुर हुई है.

उपाध्यक्ष महोदय, 2009 में "मंथन" एक एक्सरसाइज हुई थी. उसमें यह कहा गया था कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की भूमिका का समुचित उपयोग होगा. मेरा आपसे अनुरोध दलौदा, जावरा और महिदपुर शुगर मिल थे इनकी भूमि को आप औद्योगिक क्षेत्र घोषित करें. को-आपरेटिव सोसायटी के पास हो तो अपने पास लें. दलौदा में तो आपके परिवार के शेयर भी थे. इन भूमियों को भू-माफिया हड़प रहा है. इसी प्रकार पिपल्या मंडी, पिपलौदा, ताल, आलोट, जावरा और अन्य शहरों में जिनिंग फेक्ट्री की भूमि भू-माफिया ले चुका है.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात के लिये सहमति व्यक्त करता हूँ लगातार हम कोशिश कर रहे हैं मैंने प्रश्नकाल में भी इस बात को उठाने की कोशिश की थी. प्रश्न के माध्यमों से मैंने विगत सत्रों में भी इसका निवेदन किया है. निश्चित रुप से दलौदा, महिदपुर और जावरा शुगर मिल के बारे में...

उपाध्यक्ष महोदय—आपका सुझाव माननीय मंत्रीजी के संज्ञान में आ गया है, कार्यवाही में भी आ गया है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—जी हां आपने भी इस मामले को उठाया था. जिनिंग फेक्ट्री की भूमियां भी सब भू-माफियाओं के कब्जे में चली गई हैं इसकी आप इंक्वायरी करवाइये कि कितनी जिनिंग फ्रेक्ट्री थीं, प्रदेश में कहां-कहां भूमि थी वह भू-माफियाओं से छीनकर उद्योग विभाग में लेने का कष्ट करें.

श्री दिलीप सिंह परिहार-- उपाध्यक्ष महोदय, पीपल्या मंडी में भी ऐसा हुआ कि जिनिंग फेक्ट्री में.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम के इम्पोरियम व प्रदर्शनियों में बिक्री में वृद्धि हुई है. इसके लिये आपको बधाई देता हूँ. रेशम उद्योग अधिकांश एससीएसटी, बीपीएल के लिये है वह 35 जिलों में है इसे अन्य जिलों में भी करें.

उपाध्यक्ष महोदय—रेशम उद्योग ग्राम उद्योग में आता है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—उपाध्यक्ष महोदय, जी. मेरा अनुरोध है कि खादी उत्पादन में 2012-13 में 357 लाख का उत्पादन हुआ है 555 कातिन बुनकरों को लाभ हुआ है, 2013-14 में 424 लाख की खादी का उत्पादन और 300 ही मजदूरों को लाभ मिला है. यह कमी है इस कमी को भी दूर करने का कष्ट करें. 11 जुलाई के माध्यम से मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था. रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में जो गारंटर एक्प्लाइट करता है जीप खरीदकर उसका उपयोग वह करता है इनके नाम पर उसको रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने का कष्ट करें.

उपाध्यक्ष महोदय, अशोक नगर में मुंगावली के पास बेतवा नदी में उस तरफ तो खूब सारे उद्योग हैं. जे.के सीमेंट है रिफायनरी भी है लेकिन बेतवा के इस किनारे पर, जहां अथाह पानी है मुंगावली अशोक नगर जिले में उद्योगीकरण ज्यादा से ज्यादा हो यह मेरा अनुरोध है इस बारे में मैंने आपको पत्र भी लिखा है . मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी पांच सहायक कंपनियां भी हैं एकेवीएन इसको उद्योगपतियों और अधिकारियों ने मिलकर काफी लूटा है. इस पर भी कार्यवाही करने का कष्ट करें और भविष्य में न लूट पायें. एसईजेड बनायें. राज्य उद्योग निगम में ग्वालियर पोटरीज बहुत फेमस था आज भी पसंद करते हैं उसको रिवाइव करें और अन्य को भी रिवाइव करें. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के बारे में अनुरोध है कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा है इसके नाम पर कुछ भी खरीदो, कुछ भी कमीशन लो, कितना भी घटिया माल दो, यह सब शिकायतें होती

रही हैं. मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह सब नहीं होगा. उपाध्यक्ष महोदय आपने बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

डॉ. मोहन यादव (उज्जैन दक्षिण)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11, 43 और 51 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र कालूखेड़ा जी ने धर्मस्व विभाग पर कुछ बातें कही हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना काम माननीय मंत्रीजी के नेतृत्व में इस साल हुआ है इतना कभी नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से रामेश्वरम, जगन्नाथ पुरी, द्वारिका, वैष्णो देवी, तिरुपति इत्यादि स्थानों पर ट्रेन चलाई गई, 98000 यात्रियों को लाभ पहुंचाया गया है. इन यात्राओं के माध्यम से 31 करोड़ 34 लाख का व्यय किया गया विगत दो वर्षों में 182 ट्रेनों का संचालन किया गया. चालू वित्तीय वर्ष में 2014-15 में 80 करोड़ के बजट का प्रावधान इसमें किया गया है. यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसके माध्यम से हम अपने यहां के 60 वर्ष से ऊपर के निवासियों को जो आयकर दाता नहीं हैं इसके माध्यम से उन्हें देश की एकात्मता से परिचित कराते हैं. मैं इस विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के लिये मुख्यमंत्रीजी और मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा. 145 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये 2013-14 के बजट में 6.60 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है. चालू वित्तीय वर्ष में इस पर शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये 4 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2014-15 के लिये किया गया है. यह न तो केवल धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की है इसी के साथ-साथ हमारे पास पर्यटन विकास निगम के माध्यम से भी अलग से इसमें फंड देते हैं तो धार्मिक पर्यटन पर सरकार कितना ध्यान दे रही है यह इससे ही परिलक्षित हो जाता है धार्मिक न्यास और विभाग के माध्यम से जो पुजारी, सेवादार इन सारे लोगों के लिये भी प्रतिमाह मानदेय बढ़ाया गया है जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें 500 से बढ़ाकर 1000 रुपया

प्रतिमाह, जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है उन्हें 350 से बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह, जिनके पास 5 एकड़ से 10 एकड़ तक की भूमि है उनको 260 से बढ़ाकर 520 रुपये प्रतिमाह की दर से विभाग द्वारा मानदेय दिया जा रहा है. जो वर्ष 2013-14 में 8.58 करोड़ शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के मानदेय के लिये वितरण किया गया है. मैं इसमें दो चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा, ये सरकार इसलिये भी प्रशंसनीय है माननीय मंत्री जी कि कर माध्यम से हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ और वर्तमान का हमारा जो भारत है, इसका सांस्कृतिक स्वरूप बहुत बड़ा था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बनाये रखने के लिये इस विभाग के माध्यम से एक जो बड़ा उल्लेखनीय कार्य हुआ उसकी तरफ माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अतीत के प्रभाव में हमारे से इस देश के कई हिस्से कटते गये और वो दूर होते रहे और आज वह दूसरे देश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हमारे अपने समान इस सांस्कृतिक प्रभाव को मानने वाले एक दूसरे से आस्मीयता रखने वाले चाहे वह कम्बोडिया , श्रीलंका , पाकिस्तान हो इन देशों से हमारे संबंध बनाये रखने के लिये एक अतिथि योजना चालू की गयी है। इस योजना से इन स्थानों पर सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा संबंध है वह चाहे अंगोरकोठ का मंदिर हो जो एक एतिहासिक मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ऐसे कंबोडिया के मंदिर में दर्शन करने के लिये अगर कोई यात्री जाना चाहता है तो उसमें सरकार अपने माध्यम से तीस हजार रूपये तक का अनुदान अगर व्यय पत्रक पर्यटन विकास निगम में वह प्रस्तुत करता है तो अपने जीवनकाल में एक बार विदेश यात्रा पर जाता है तो उसे अनुदान सरकार के माध्यम से दिया जाता है। इतना ही पाकिस्तान जहां ललकाना साहब और हिंग्लाज माता का मंदिर जहां भी कोई यात्री अपने जीवन काल में एक बार जाना चाहता है तो वहां भी तीस हजार रूपये का अनुदान देने की पात्रा की गयी है। हमको मालूम है कि श्रीलंका से हमारे ऐतिहासिक रूप से क्या संबंध है, लगभग 17 लाख साल पुराना हमारा महाभारत का काल, जो रामायण का काल रहा है उसको जीवंत करने के लिये ,

भगवान राम की लीलाओं को देखने के लिये सीता माता के मंदिर को देखने के लिये और अशोक वाटिका को देखने के लिये अगर कोई अपने जीवन काल में एक बार जाना चाहता है तो उसको भी पर्यटन विकास निगम के माध्यम से तीस हजार रूपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसी के लिये शासन ने जो बजट रखा है वह वर्ष 2013-14 में 62.40 लाख का बजट था और चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 16 लाख का इस योजना में अलग से बजट रखा गया है। जिसके माध्यम से हम इन योजनाओं को बढ़ावा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो जो यह हिस्से हमारे देश से कट गये हैं उनसे आज नहीं तो कल हमारी आत्मीयता बनती रहेगी तो हमारा अखंड भारत का सपना साकार करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बाते और जोड़ना चाहता हूं सिंहस्थ को लेकर के लगभग 900 करोड़ की मंजूरी सरकार के माध्यम से दी गयी है, जिसमें 300 करोड़ से उज्जैन और उज्जैन के आसपास तमाम सिंहस्थ के क्षेत्रों वाले मंदिरों के लिये शासन ने यह स्वीकृति दी है, जिसके माध्यम से अब यह खाली सिंहस्थ का मामला न रहकर यह तीर्थाटन का मामला हो गया है। पूरे देश के लिये एक नया स्वरूप तीर्थाटन के रूप में हमारे अपने धार्मिक स्थानों को देखने के लिये बनने वाला है, इसमें यह एक बहुत बड़ा योगदान है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं खेल विभाग की भी चर्चा करना चाहूंगा, खेल विभाग में तो वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से उन्नती हुई है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते जिस प्रकार से अभी काम हुए हम इसकी चर्चा जरूर करते हैं, माननीय कालूखेड़ा जी ने भी कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कहा कि इसका बजट कम है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2013 के पहले खेल विभाग में क्या होता था और वर्तमान की इस सरकार के माध्यम से खेल विभाग पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। नयी नयी अकादमिया के माध्यम से प्रत्येक खेल के बारे में कल्पना की गयी हे। जिस हाकी के बारे में आज पूरे देश में अलग ढंग का वातावरण है, ऐसे हाकी को प्रोत्साहन देने के लिये 15 जिलों में एस्ट्रोटर्फ की बात खेल विभाग के माध्यम से की गयी है। जिसके लिये वर्ष 2014-

15 में तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं इस बात के लिये भी बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार मिशन ओलंपिक 2020 की कल्पना की गयी है। क्योंकि हम ओलंपिक में मात्र कुश्ती पर ठहर रहे हैं। लेकिन कुश्ती से आगे बढ़कर के अगल अगल खेलों में चाहे वह रोइंग, केयाकनिंग, अलग अलग प्रकार की शूटिंग को, कुश्ती , बाक्सिंग,ताईक्वाडों, कराटे हो इस प्रकार के प्रत्येक खेल को महत्व देते हुए इसके बारे में जो योजना बनाई गई है, हमने खाली योजना नहीं बनाई है, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडि़यों को जोड़कर के चाहे वह क्रिकेट का मदनलाल हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे जी.एल.यादव हो अलग अलग विधाओं के खेल के खिलाडि़यों को यहां लाकर के अपने खिलाडि़यों को यहां लाकर के मार्गदर्शन देने के लिये यहां बुलाया गया है। एक करोड़, तीस लाख विद्यार्थियों को इस गर्मी की छुटिटयों में उनको अलग अलग प्रकार से ग्रीष्मकालीन खेल के इस मौके पर उनको प्रशिक्षित करने का उनको खेल से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मा तुझे प्रणाम योजना के माध्यम से यहां पर अपने बार्डर के एरिये में कितने कठिन दौर में हमारा अपना देश और बाकी हमारे जवान वहां रहते हैं। यहां पर भी खेल का माहौल बने इस माहौल को बनाये रखने के लिये इस विभाग ने अपनी विशेष योजना बनायी है। मैं कुछ अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो उपलब्धिया हासिल हुई है उसका उल्लेख खेल विभाग के माध्यम से करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने तेहरान में जाकर के कुश्ती मैं और अगल अगल क्षेत्रों में उन्नती हासिल की है, वास्तव में यह उल्लेखनीय है। मैं इंटरनेशनल शूटिंग प्रतियोगिता 27 से 30 अप्रैल 2013 वहां जर्मनी में अमित कुमार को दो स्वर्ण पदक और एक रजत पदक प्राप्त हुआ। 44 वीं ग्रांडफिक्स ऑफ शूटिंग लिबरेशन प्रतियोगिता 1 से 6 मई, 2013 इसमें अमित कुमार को एक कांस्य पदक, जूनियर इंटरनेशनल शॉटगन प्रतियोगिता शूल जर्मनी में संजय राठौर को कांस्य पदक, प्रियांशु पाण्डेय को कांस्य पदक, इंटरनेशनल जूनियर शॉटगन फिनलैंड में संजय राठौर को एक रजत पदक , प्रियांशु पाण्डेय को एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक हम इसकी लाईन में अगर

देखें तो वास्तव में ये इतना लंबा क्रम है, इसी प्रकार से ग्रांडफिक्स शूंटिग प्रतियोगिता में इटली पोरपट्टो में संजय सिंह राठौर को एक रजत पदक और प्रियांशु पाण्डेय को एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। पांचवीं ग्रांडफिक्स शूंटिग प्रतियोगिता जो फिर इटली पोरपट्टो में हुई उसमें प्रियांशु पाण्डेय को फिर एक पदक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से कुश्ती, हाकी की पता नहीं कितने अगल अलग प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है, मैं बहुत लंबी लिस्ट नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि समय सीमित है। लेकिन जिस प्रकार से खेलों पर ध्यान दिया गया है, हर गांव में खेल मैदान की कल्पना की गयी है। स्टेडियमों की कल्पना की गयी है वह काबिले तारीफ है, मैं अंत में अपने रोजगार जो एक महत्वपूर्ण विभाग है उसकी कल्पना करना चाहूंगा। उद्योग विभाग के माध्यम से वर्तमान में सरकार ने वातावरण बनाया है वह वाकई में अदभूत है। जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में माहौल बना जिसके कारण से देश भर में हर व्यक्ति का सम्मान से ऊंचा होता है। हमारे अपने राज्य मार्ग है राष्ट्रीय मार्ग हैं, इन मार्गों को औद्योगिक दृष्टि से चिन्हित करके जगह जगह जो अधिग्रहित करने की कल्पना की गयी है, और ए.के.व्ही.एन के माध्यम से चाहे वह इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर हो प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र की जो चिन्ता की गयी है वह काबिले तारीफ है। प्रदेश में जो 24 घण्टे बिजली देने का अभियान चला है वह इसी का परिणाम है। बड़े पैमाने में हमारे यहां निवेश की संभावना तलाश करके उद्योग का बहुत बड़ा एरिया इसमें जुड़ने जा रहा है। मैं दो तीन कमजोरियां भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं । हमारे यहां खासतौर पर वस्त्र का और कपास का बहुत पुराना मध्यप्रदेश से नाता रहा है लेकिन पिछले काल के प्रभाव में जो इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और रतलाम है इनमें जो काटन इंड्रस्टियां जो बंद हुई हैं यहां पर मजदूरो के जो पुराने भुगतान पेंशन, ग्रेज्युटी है बड़े पैमाने पर बाकी है जैसे उदाहरण के लिये उज्जैन में बीस हजार मजदूरों का बकाया था, लगभग 15 हजार लोग इस उम्मीद में की अब हमको पैसा मिलेगा, उन्होंने इस उम्मीद में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। पांच हजार श्रमिक आज जिंदा है और 15

हजार परिवार इस उम्मीद में बैठें है कि हमारा पेंशन , ग्रेज्युटी का भुगतान किसी प्रकार से होगा। हम यह चाहते हैं कि आज उन उद्योगों की जमीन है उन जमीनों का निराकरण कर दिया जाए, जैसे विनोद मिल उज्जैन का है अगर उसे नीलाम कर देते हैं तो 250 करोड़ रूपये का राजस्व उससे प्राप्त हो जायेगा और देनदारी मात्र 80 करोड़ रूपये है। लेकिन यह विषय आगे पढ़ता है तो यह दो विभागों के परस्पर कलह में छूट जाता है। इसी प्रकार से हुकुम चंद मिल का मामला इंदौर, सज्जन मिल मामला रतलाम का और ग्वालियर का भी है। मैं चाहूंगा कि इसी के साथ साथ इन मजदूरों का भी निराकरण हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से इन विभागों ने गति प्रगति की है यह निश्चित रूप से उन्नति करते जायेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मुकेश नायक(पवई) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के विषय पर विचार करने के लिये खड़ा हुआ हूं. 174 करोड़ रुपये का प्रावधान खेल डिपार्टमेंट के लिये हुआ है. यह अलग बात है कि जब मैं मंत्री हुआ करता था उस समय तो इतना बजट भी नहीं होता था कि जितने के होर्डिंग्स मंत्री जी ने मध्यप्रदेश में लगा दिये. मैं दो-तीन चीजों के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा. एक तो स्पोर्ट्स के बुनियादी ढांचे को लेकर, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों की पंचायत अपने बंगले पर बुलाई थी और उसमें यह आश्वासन दिया था कि मध्यप्रदेश के हर जिले में वह हाकी के लिये एस्ट्रोटर्फ लगाएंगे पालीग्रास लगाएंगे और जिस तरह राष्ट्रीय खेल को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की वे व्यवस्था करेंगे. अभी सम्मानित सदस्य ने अपने भाषण में बताया कि पूरे मध्यप्रदेश के लिये इस साल के बजट में पालीग्रास और एस्ट्रोटर्फ के लिय तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मंत्री महोदया, जानती हैं कि एक जिले में भी पालाग्रास इसमें नहीं लग पाएगा. इतना महंगा होता है तो इस तरह से तो चालीस साल लग जाएंगे मध्यप्रदेश के हर जिले में हाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिये

सबसे दुर्भाग्यजनक बात आज यह है कि एशियाई और ओलंपिक में जिन खेलों को मान्यता है उसकी मध्यप्रदेश में प्लेईंग पापुलेशन नहीं है और इसका कारण है कि हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं है और जो टूटेफूट स्टेडियम हैं उनमें उपकरणों की कमी है और इस कमी को यह बताते हुए सदन को अच्छा नहीं लगता कि जितने लोग वहां खेल खेलने जाते हैं उससे ज्यादा छोटे जिलों में रात में लोग जुआ खेलने लोग जाते हैं उनकी प्लेईंग पापुलेशन ज्यादा बढ़ गई है और स्टेडियमों का दुरुपयोग हो रहा है. मैं विनम्रतापूर्वक मंत्री जी से कहना चाहता हूं मैं स्पेसिफिक आपको बताता हूं कि जिन खेलों की प्लेईंग पापुलेशन मध्यप्रदेश में है ही नहीं जिन खेलों को ओलंपिक और एशियाई खेलों में जिनको मान्यता है. जब खिलाड़ी खेलने वाले ही नहीं हैं तो हम क्या उम्मीद करें कि दुनियां में हमारे खिलाड़ी स्पर्धा में शामिल होंगे. देश का गौरव बढ़ाएंगे. कुछ अर्जित करके आएंगे. इसकी क्या संभावना है. मुझे बताया जाए कि भोपाल और इन्दौर को छोड़कर जिमनास्टिक, साईकलिंग,फेंसिंग,बूशू,सेलिंग और घुड़सवारी के कितने खिलाड़ी हैं और कितनी टीमें हैं ? आप भोपाल को छोड़कर मुझे यह बताने की कृपा करें कि क्याकिंग,केनोईंग और वाटर स्पोर्ट्स की कितनी टीमें हमारे पास हैं ? आपके पास शूटिंग का भोपाल,इन्दौर और महू को छोड़कर कहां पर आपके पास इसकी बुनियादी सुविधाएं हैं. आपके पास आर्चरी की कहां सुविधाएं हैं मध्यप्रदेश में और जब आपके पास सुविधाएं नहीं होंगी. इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा बुनियादी ढांचा नहीं होगा आपके पास कोच नहीं होंगे. मंत्री जी जागरूक हैं इसलिये मुझे उम्मीद है कि खेल में कुछ होगा इस नाते मैं उनसे अपनी बात कह रहा हूं और जहां मुझे लगेगा मैं उनकी तीखी आलोचना भी करूंगा. मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्लेईंग पापुलेशन की बात कर रहा हूं कि हमने टी.टी.नगर स्टेडियम में बहुत सीमित साधनों में 27-28 खेलों की बुनियादी सुविधाएं बनाई थीं आज वहां जिमनास्टिक्स के जो फ्लोर्स हैं उनका क्या हाल है जरा जाकर तो देखिये. बच्चे अपने हाथ से सुई धागा से सिलते हैं उस पर चमड़ा लगाते हैं कोई देखने वाला नहीं है. स्पोर्ट्स के डायरेक्ट्रेट का यह हाल है कि महिला

खिलाड़ी वहां के अधिकारियों को लेकर कंफर्टेबल नहीं हैं. बाहर इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं उनके साथ आपके संचालनालय में जो अधिकारी बैठे हैं वह दुर्व्यवहार करते हैं. आप पता लगाईये कि खिलाड़ियों के साथ कोच किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं. मेरे पास रात को 12 बजे एक लड़के का फोन आया. हाकी खिलाड़ी का फोन आया. उसने मुझसे कहा कि मेरा कोच मेरे साथ बद्तमीजी कर रहा है. मारपीट कर रहा है. मेरा चश्मा तोड़ दिया. मैंने रात को 12 बजे आपके स्पोर्ट्स के अधिकारी को फोन लगाकर सूचना दी कि देखिये आप कंट्रोल करिये, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की जरूरत है अच्छे वातावरण की जरूरत है. प्यार और सद्भाव की जरुरत है. माता-पिता यहां उनको कोचिंग के लिये भेजते हैं वे स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर अडाप्टकिये हुए हैं. कितनी केलकुलेटेड रिस्क है आप कल्पना करिये कि वह अपना पूरा एकेडेमिक कैरियर छोड़कर खेल को अपने कैरियर के रूप में अडाप्ट करकर यहां पर आए हैं और जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो मुझे उम्मीद है कि इस पर आप जरूर तवज्जो देंगी और इसकी देखरेख करेंगी. क्रिकेट ने हमारी पूरी प्लेईंग पापुलेशन को खत्म कर दिया. क्रिकेट की एसोशियेशन अच्छी होने से क्रिकेट में पैसा अच्छा होने से क्रिकेट में ग्लैमर होने से और एज ए कैरियर खिलाड़ी क्रिकेट को अडाप्ट करता है तो उसको फाईनेंशियल एडवांटेज होता है. आज अंडर 14 खेलने वाला बच्चा एक साल में 7 से 8 लाख रुपये की इनकम करता है. 14 साल का बच्चा. अगर प्रदेश स्तर की टीम में उसका नाम आ जाए आप उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं क्रिकेट और हाकी के बड़े खिलाड़ी रहे हैं और यह सुखद संयोग है कि इस समय आप आसंदी पर हैं और इस बात को समझ रहे हैं. अंडर 14,अंडर 19,अंडर 25 जूनियर रणजी ट्राफी जिसको कहते हैं रणजी ट्राफी,दिलीप ट्राफी,इंडिया-ए,यहां तक अंडर 14 से अगर बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करे और स्टेट की टीम में आ जाए तो एक साल में 7 से 8 लाख रुपये की उसको इनकम होती है अगर वह पूरा सर्किट वह खेल ले. आज दूसरे खेलों में क्या एडवांटेज है मंत्री महोदया, क्या कारण है आप सदन में बताएं कि क्या

कारण है कि आपने कार्यकाल में एक भी उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति नहीं की. खिलाड़ियों का क्या दोष है. हम जब खेल मंत्री थे तो तीन से चार बार जो खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में पार्टीसिपेट करता था हमने उसको थानेदार बनाया, हमने उसको स्पोर्ट्स आफीसर बनाया. जिसकी शैक्षणिक योग्यता जैसी थी उसको उस लायक उसको नियुक्ति दी. हवलदार बनाया,सिपाही बनाया और वह बच्चे जहां पर तैनात हैं आज अच्छे ढंग से वे मध्यप्रदेश में काम कर रहे हैं. आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जिनको सीधी नियुक्ति देने की परंपरा थी 10 साल से बंद कर दी गई. आप उसको पुनर्जीवित करें. उसको चालू करें ताकि खिलाड़ियों में यह संदेश जाए कि एज ए कैरियर हम स्पोर्ट्स को अडाप्ट करते हैं तो हमारा भी भविष्य है. हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं. अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. क्या इंसेंटिव दिया इन दस सालों में आपने यह सदन को बताएं. एक भी उत्कृष्ट खिलाड़ी को आपने नौकरी नहीं दी. मध्यप्रदेश में हजारों की संख्या में स्पोर्ट्स आफीसर के पदखाली पड़े हुए हैं. अभी शिक्षा की अनुदान मांगों पर चर्चा है मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि कितने स्कूलों में स्पोर्ट्स आफीसर के पद ख्ग खाली पड़े हुए हैं . एक और बात मुझे कहनी है कि मध्यप्रदेश में सारे इनविटेशन टूर्नामेंट बंद हो गये. ग्वालियर का सिंधिया गोल्ड कप बंद हो गया, रूपसिंह मेमोरियल बंद हो गया. यहां का औबेदुल्लागंज गोल्ड कप हाकी टूर्नामेंट टूटाफूटा,किस ढंग से चल रहा है आप जानती हैं. मैं बात कर रहा हूं कि जिस आन,बान,शान के साथ खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते थे और इस टूर्नामेंट की जो टीमों की संख्या थी और उस टूर्नामेंट की जो उत्कृष्टता थी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं. आप केवल औपचारिक रूप से किसी इनवीटेशन टूर्नामेंट को चालू रखें यह भर पर्याप्त नहीं है. इन खेल प्रतियोगिताओं में जब खिलाड़ी खेलता था और उसको खेलता हुआ जब दर्शक देखता था तो यह कल्पना करता था कि अगले दो साल में यह बच्चा भारत की टीम में जाएगा और देश का प्रतिनिधित्व करेगा वह परंपरा टूट गई. सारे इनविटेशन टूर्नामेंट आज अंतिम सांस ले रहे हैं. दूसरी चीज हजारों क्लब थे मध्यप्रदेश

में हाकी के, क्रिकेट के, फुटबाल के, अनेक खेलों के मैं जानना चाहता हूं कि इन क्लबों को जो ग्रांट दी जाती थी वह क्यों बंद कर दी गई जो ग्रांट दी जाती थी वह क्यों बंद कर दी गई यह क्लब क्यों बंद हो गये. जब इनविटेशन टूर्नामेंट ही नहीं होंगे तो क्लब क्यों बनेंगे काहे को वे टूर्नामेंट में खेलने जाएंगे. इतने क्लब होते थे वे इनविटेशन टूर्नामेंट्स में जाते थे पार्टिसिपेट करते थे दर्शक मैच देखने जाते थे यह बंद हो गये और यही कारण है कि भारतीय शैली के पारंपरिक खेलों का आकर्षण बिल्कुल खत्म हो गया. आज जहां टूर्नामेंट होते हैं वहां दर्शक भी मैच देखने के लिये नहीं जाते हैं.

अंतिम बात मैं ट्रेनिंग के लेबल पर कहना चाहूंगा. आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास वाच नहीं है, आप खिलाड़ियों को कोई इंटेंसिव नहीं देते, प्रोत्साहन नहीं देते. तो आप किस तरह की खेल संस्कृति की कल्पना मध्यप्रदेश में करते हैं यह बताईये. आप यह उम्मीद करते हैं कि ऐसे टूटेफूटे वातावरण में हमारे खिलाड़ी तैयार होंगे.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा – उपाध्यक्ष महोदय, ये कोई आंकड़े ही नहीं लाए और कह रहे हैं कि यह नहीं है वह नहीं है फिर यह खेल हो कैसे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय – कृपया सुनें.

श्री मुकेश नायक – यह बहुत गंभीर किस्म की बात हो रही है. मैं स्वयं स्पोट्र्स यूथ वेलफेयर मिनिस्टर रहा हूं. मेरा मैदान से सीधा कई सालों तक संबंध रहा है और उस आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं. आप एन.आई.एस. कोचेस की क्या पोजीशन मध्यप्रदेश में आज है. एक साई का स्पोट्र्ससेंटर हमने बनाया और उसमें मध्यप्रदेश के कितने बच्चे हैं जरा यह बताया जाए. यह टी.टी.नगर का स्पोट्र्स होस्टल क्यों बंद हो गया यह बताया जाये. हमने जो झाबुआ में और यहां तीरंदाजी के जो केंद्र खोले थे, आर्चरी के जो सेंटर खोले थे. उनके बारे में बताया जाए क्या स्थिति है ? भोपाल में वाटर स्पोट्र्स का सेन्टर हमने शुरू किया था भोपाल में बहुत बड़ा तालाब है, सागर में भी बहुत बड़ा तालाब है, रीवा में एक जगह है जहां नदी के तट पर तैरने वाले खिलाड़ी तैयार हुए

उन्होंने नेशनल-इंटरनेशनल लेवल पर ईवेन्ट्स पर पार्टिसिपेट किया और स्पर्धाएं जीतीं. खेल के जो बुनियादी ढांचे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं उन सेन्टर्स को भी विकसित नहीं किया जा रहा है. एक भोपाल में थोड़ा सा ध्यान दिया गया है वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर बाकी किसी जिले में, भारतीय शैली के पारम्परिक खेल जो खेल औलम्पिक एवं एशियाड में मान्यता प्राप्त खेल हैं उनका भी न तो बुनियादी ढांचा है और न कोई कोच है और न ही खिलाड़ी हैं मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब गंभीर बातों के ऊपर हमारी मंत्री महोदिया ध्यान देंगी और पूरे प्रदेश की मंशा के अनुरूप यहां पर भी पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे, उनका बुनियादी ढांचा तैयार होगा, खिलाड़ी होंगे, कोच होंगे, प्रशिक्षण का प्रापर अरेंजमेंट होगा इस तरह से हम मध्यप्रदेश में खेल एवं संस्कृति की परम्परा को लेकर आगे बढ़ेंगे. आपने समय दिया इसके लिये आपका अनुग्रह.

श्री दिलीप सिंह शेखावत (नागदा-खाचरौद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांगों का समर्थन करता हूं कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. जहां 2003-4 में मात्र 8 करोड़ रूपये का बजट था, 2006 में बजट बढ़कर 40 करोड़ हो गया, आज बजट 1 करोड़ 42 लाख, 57 हजार का बजट हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है. यह 100 करोड़ का देश है मुझे दुःख होता है कि 67 साल की आजादी में जिस राजनैतिक दल का बहुत ज्यादा वर्षों तक शासन रहा 100 करोड़ के देश में आज भी पदकों के लिये तरसना पड़ता है. पदकों के बारे में डॉ.मोहन जी ने बताया है. आज मध्यप्रदेश के एक नौजवान विदेश में जाकर एक स्वर्ण पदक लेकर आता है तो यह मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है. जब मध्यप्रदेश के अंदर केवल खेल विभाग हुआ करता था आज हमने 17 अकादमियां खोली हैं, क्या यह प्रसन्नता की बात नहीं है, क्या खेलों के विस्तार करने के लिये पर्याप्त नहीं है. मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही होंगी उन कमियों को हम दूर करेंगे. मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि इतने होर्डिंग्स लग गये, जनता को मोबिलाईजेशन करने के लिये यह बहुत जरूरी होता है.

उपाध्यक्ष महोदय—उनका आशय था कि पहले विभाग का जब वह मंत्री थे बहुत कम बजट था उतनी ही सीमा में होर्डिंग्स लगते थे.

श्री दिलीप सिंह शेखावत—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर पूरे मध्यप्रदेश की बात न भी करूं मैं जिस विधान सभा में रहता हूं वहां पर एक छोटे से धाकड़ परिवार की बच्ची भी अगर बॉक्सिग में यू.एस.ए. जाती है तो यह हम सबके लिये गर्व की बात है कि हम खाचरौद की एक बच्ची को भी वहां पर भेज सकते हैं. खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम इस मध्यप्रदेश के अंदर हुए है मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा. मां तुझे प्रणाम योजना एक अद्‌भुत योजना और मैं मानता हूं कि कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो सरहद पर जा ही नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं कि वहां का वातावरण कैसा होगा, हमारे सैनिक किस स्थिति में हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं, उनमें अपने देश के प्रति जज्बा पैदा करना मैं माननीय मंत्री जी आपको साधुवाद दूंगा कि आपने मध्यप्रदेश में अद्‌भुत योजना लागू की है. केवल शहरों के अंदर खेलों के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया है आपने सुदूर ग्रामीण अंचलों के अंदर जाकर खेल मैदान बनाकर आज एक एक विधान सभा के अंदर 50—50—100—100 खेल के मैदान बनाकर उनके खेल की प्रतिभाओं को उभारने का साहसिक निर्णय लिया है. खाचरौद से संबंधित मैंने एक तारांकित प्रश्न भी लगाया था उसमें आपने उत्तर भी दिया है कि खाचरौद ब्लाक स्तर की तहसील है, लेकिन वहां पर स्टेडियम नहीं है जैसा कि मैं बता रहा हूं कि खाचरौद में बहुत उपजाऊ भूमि है खेल के लिये वहां के खिलाड़ी साधनों का थोड़ा बहुत अभाव होगा भी होगा, लेकिन वहां के खिलाड़ी चाहे मलखम हो, चाहे बॉक्सिग हो, चाहे कबड्डी हो, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है. वहां पर शासकीय विद्यालय के पीछे बहुत बड़ा ग्राऊंड है उस ग्राऊंड में अगर स्टेडियम के लिये शिक्षामंत्री एनओसी देंगे और आप खेल मंत्री उसमें स्वीकृति देंगे तो महत्ती कृपा होगी. खाचरौद में मट, व्यायामशाला, खारीमीठी बावड़ी की व्यायामशाला, बुरहानाबाद,

नरसिंहगढ़, पारदी आदि ऐसे छोटे गांव हैं जहां पर बहुत ही अच्छी व्यायामशालाएं चलती हैं और वहां पर आप खेल के साधन उपलब्ध कराएंगे तो महत्ती कृपा होगी. नागदा में एक आदिवासी एवं एक अनुसूचित जाति के विजय तथा एक राजकुमारी कोड़ी जो आदिवासी हैं वह आज जूड़ों की एक क्लास चलाती है उनकी एक रजिस्टर्ड संस्था है और मुझे आश्चर्य है और आपको भी आश्चर्य होगा कि विदेशों में जाकर के वह पदक लेकर आयी हैं उनको आप अगर साधन देंगे तो आपकी महत्ती कृपा होगी. पूरे मध्यप्रदेश में खेल संगठन है, कई खेल संगठन तो ऐसे हैं कि उनके वर्षों से चुनाव ही नहीं हुए, कई खेल संगठन ऐसे हैं जिन पर चुनिन्दा लोगों के कब्जे हैं और उसके कारण खेल जगत में जितनी क्रांति आनी चाहिये मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं हम उनसे वंचित हैं उन संगठनों पर आप ठीक से ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा. 2003 में जहां मध्यप्रदेश की तुलना भी होती थी तो बिहार जैसे प्रदेश से करते थे और कहते थे और सुना भी समाचार पत्रों में कि वगैर बिजली-पानी-सड़क के बिहार में सरकार बन सकती है तो हम क्यों नहीं सरकार बना सकते हैं, लेकिन जनता ने कहा कि इन्फ्रा स्ट्रक्चर तथा विकास नहीं करोगे तो आप लोग सरकार में नहीं आ सकते हो, हम लोग तीसरी बार इसलिये आये कि हमने प्रदेश के लिये सब-कुछ विकास किया है और जो नहीं होना था वह भी किया है इसलिये मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 6-6 इनवेस्टर मीट से इंफोसिस जैसी कम्पनी इन्दौर के अंदर आती है आज इन्वेस्टर मीट करके आज के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है. मैं मंत्री जी कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है. यहां पर सिंगल विन्डो प्रारंभ करेंगे तो जल्दी उद्योगपति यहां पर आयेंगे इससे सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का ध्यान हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ क्षेत्रों में तो औद्योगिक विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के अंदर उद्योग में पर्याप्त साधन हैं जैसे मालवा अंचल के अंदर चम्बल है, क्षिप्रा है, गंभीर है, कालीसिंध है, लेकिन आज शाजापुर, देवास, उज्जैन, नीमच एवं मंदसौर में जितना पर्याप्त औद्योगिक विकास होना चाहिये नहीं हो पा रहा है. मेरा यहां पर भारत कमरस नाम से उद्योग है

जो बंद हो गया है वहां पर लक्कीटेटर नियुक्त हो गया है, लेकिन मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि लक्कीटेटर पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष में देखा है कि लक्कीटेटर सम्पत्ति का किस प्रकार से दुरूपयोग करते हैं. भारत कमरस के उद्योगों को जल्द से जल्द उनके अधिकार का पैसा है मिले ऐसा आपसे निवेदन करता हूं. धर्मस्व विभाग के बारे में कहना चाहता हूं पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि किस प्रकार चाहे कंबोडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, जो भारत माता के अंग थे उनको आमने एक मैत्री भाव की दृष्टि से जो योजना बनायी है निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना है. खाचरौद में एक राम मंदिर है जो आपके स्टेट के समय का मंदिर है, भव्य मंदिर है सिंहस्थ के लिये आदरणीय मोहन जी ने कहा कि 300 करोड़ का प्रावधान किया है

अगर उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये आप राशि स्वीकृत करेंगे, तो कृपा होगी. मेरे नरसिंहगढ़, उमरना इन 2 मंदिरों का प्रस्ताव भी आपकी तरफ काफी समय से लंबित है अगर उस पर भी आप कृपा करें तो मेहरबानी होगी. मैं पुन: माननीय मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत शुभकामनायें देते हुए अपनी वाणि को विराम दूंगा, जयहिन्द, जय भारत.

उपाध्यक्ष महोदय--जीत पटवारी..जीतू जी, समय का ध्यान रखेंगे, दल के लिये कुल 14 मिनट आबंटित हैं, 2 माननीय सदस्यों ने ही 23 मिनट ले लिया है.

श्री जीत पटवारी (राऊ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं की और आपके आदेशों का पूरी जिज्ञासा से पालन करूंगा. मैं अपने आपको बहुत खुशनसीब समझता हूं कि वित्त मंत्री जी का भाषण बजट पर जब मुझे बोलना था, तो कोई योग संयोग ऐसा बना कि मैं बोल भी नहीं पाया और वह सुन भी नहीं पाये. आज वह भी हैं, इनकी एक बात जो याद आती थी, वह आपका जो शेर था "यह एक दुआ है खुदा से किसी का दिल न दुखे मेरी वजह से, हे ईश्वर, कुछ ऐसी नियायत मुझ पर कि सबको खुशी मिले मेरी वजह से" मुझे लगता है कि बजट के उस शेर की जितनी परिकल्पना आपने की थी, शायद पूरी हो मध्यप्रदेश की इस जनता के लिये, खेल के लिये खिलाड़ियों के लिये, बेरोजगारों के लिये....

उपाध्यक्ष महोदय--आज भोजन अवकाश नहीं होगा, माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लाबी में की गई है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

श्री जीतू पटवारी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो समय की पाबंदी के साथ मुझे बोलना है, खेल पर बहुत सारी बातें मुकेश भैय्या ने कहीं, खेल को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रोत्साहन कितना मिला, उसकी बात भी शेखावत जी ने कही.

उपाध्यक्ष महोदय--उद्योग के बारे में बातें कम आई हैं, आप उद्योग के बारे में कहें.

श्री जीतू पटवारी--जैसा आपका आदेश है, उद्योग पर ही मैं अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश सरकार ने जिस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 3-4-5 बातें ऐसी मध्यप्रदेश को निवेश मित्र राज्य घोषित किया है. औद्योगिक विकास दर 8.8 परसेंट सबसे ज्यादा देश से भी औद्योगिक विकास दर से ज्यादा बताई है. मध्यप्रदेश के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये नया एक व्यापार संवर्धन मंडल 2003 में बना है, इसका गठन किया गया है. मध्यप्रदेश में इन्वेस्टर मीट के माध्यम से कई उद्योगपतियों को बुलाने की भी बात कही है. लैंड बैंक, जल्दी से उद्योग आये, अच्छा उद्योग आये, उसको एक अच्छी लैंड मिले, इसके लिये लैंड बैंक का भी आप लोगों ने जिस तरीके से प्रोवीजन रखा है, मैं समझता हूं कि यह साब बातें जब इनकी परिकल्पना सही साबित होगी, तब इन सभी उद्योगों के कारण यहां के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा. अगर आपके आंकड़े दिये हुए, सरकार के आंकड़े दिये हुए और सरकार की बातें बताई हुई, मैं समझता हूं कि इनका और उद्योग का और उद्योग से मिले रोजगार का और बेरोजगारों का अगर हम आंकड़े का मुल्यांकन करें या तुलना करें, तो मैं नहीं समझता हूं कि मध्यप्रदेश की सरकार ने जो परिकल्पना जो उद्योगों को लेकर बातें कही हैं, जो बेरोजगारों को लेकर बातें कही हैं, वह सब सही साबित होती हैं. मध्यप्रदेश में पीथमपुर एक ऐसी जगह है, जहां

पर आज 2003 से पहले या अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जितने उद्योग लगे, उनमें से आधे उद्योग 609 उद्योग में से 200 कारखाने बन्द पड़े हैं, यह बातें आदरणीय कालूखेड़ा जी ने भी पहले बताई है. मंडीदीप के भी क्या हाल हैं, मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं. मालनपुर, ग्वालियर जहां कि माननीय मंत्री जी आती हैं, वहां 200 में से 151 उद्योगों पर ताले लगे हुए हैं, इस परिस्थिति को भी हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा.

श्री मुरलीधर पाटीदार--वह सब्सिडी के लिये लगाये थे. अपने आप बंद कर दिये बैंक का लोन न भरने की वजह से.

श्री जीतू पटवारी--इसीलिये दिग्विजय सिंह हट गये हैं. अब आप 10 साल से बैठे हो, उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बात उद्योग की, रोजगार की और बेरोजगारों की हो रही है, इसमें राजनीतिक द्वेश भाव या एक व्यक्ति सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इन बातों पर हमें कटाक्ष न करते हुए, भावनाओं को समझते हुए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. जिस तरीके से पूंजी निवेश बढ़ाने को लेकर विकास करने का ढिंढोरा पीटकर इस सरकार ने पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आभा मंडल बनाया है, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का यह भ्रमजाल जनता में भी आता है, उद्योगपतियों में भी आता है और बेरोजगार तथा रोजगार भी इसको आज तक नहीं समझ पाये. मैं किसी की बुराई या किसी बात को नेगेटिव भाव से कहने के आशय से यह बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि वित्त मंत्री जी का वह शेर मैंने इसीलिये पढ़ा था कि मेरी वजह से आप लोगों का दिल न दुखे, पर वास्तविकता यह है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर मीट 8 हुई और इन्वेस्टर मीट में 4,000 इन्वेस्टर आये और उसमें से करीब 40 करोड़ रूपया खर्चा करने के बाद 158 लोगों ने आज मध्यप्रदेश में या 158 इन्वेस्टरों ने उद्योगों ने यहां पर अपनी इस जमीन पर पैर फैलाने की या इसमें रखने की कोशिश हुई है, मैं समझता हूं कि यह एक तरह का फैलीवर है, जिस तरीके से मध्यप्रदेश में इन्वेस्टर मीट को लेकर वाहवाही लूटी

गई, जिस तरीके से उस पर खर्चा किया गया, होर्डिंग तो ठीक, क्या-क्या खाना खिलाया गया, कितना खर्च हुआ इन्दौर में फाइव स्टार फैसेलिटी के साथ उद्योगपतियों को रखा गया, मैं समझता हूं कि वह किसी से छुपा हुआ नहीं है. मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि करोड़ों के विज्ञापन छप गये, करोड़ों के होर्डिंग लग गये, पर उसके पीछे जितना रोजगार मध्यप्रदेश के युवाओं को मिलना था, वह नहीं मिल पाया, मैं इसके लिये माननीय उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि आपका ध्यान रोजगार पर आकर्षित करना चाहता हूं. मेरे पास समय कम है, इसलिये मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से विज्ञापनों पर करोड़ों रूपये खर्च करके रोजगार के योजनान्तर्गत 3 करोड़ रूपये 2013...

उपाध्यक्ष महोदय--जीतू जी, आपका एक शब्द संशोधित कर दूं "करती हूं" नहीं "करता हूं" आयेगा.

श्री जीतू पटवारी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला अवसर आया है किसी मंत्री महोदया के सामने बोलने का मुझे अवसर मिला है, इसलिये मैं कन्फ्यूज हो रहा हूं और माननीय उपाध्यक्ष जी, मैडम का इतना प्रभाव है कि एक नया सदस्य तो यूं ही घबरा जायेगा, तो दोनों बातों को एक साथ लेकर आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें अनुरोध यह है कि जिस तरीके से रोजगार की बात कही गई, 2013-14 में 300 करोड़ रूपया प्रोवीजन रोजगार के लिये रखा गया था और जिससे 2014-15 में 66 करोड़ रूपये रखा गया, क्या आप मानते हैं कि सारे लोगों को रोजगार मिला है या जो पहले रोजगार के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों में नामजद शिक्षित बेरोजगार और अर्धशिक्षित बेरोजगारों की संख्या थी, वह भी बढ़ी है उसके बाद भी 300 करोड़ जब पिछले वित्त वर्ष में था, तो इस बार 66 करोड़ क्यों रखा गया ? यह क्या सरकार इसकी ओर ध्यान आकर्षित करेगी ? मैं इसी इसमें कहना चाहता हूं कि 2014 में रोजगार कार्यालयों में करीब 20 लाख 66 हजार बेरोजगारों की संख्या अंकित की गई थी जो बढ़ी है, वह घटी नहीं है, तो इसका क्या कारण है कि आपने ढिंढोरा उद्योगों का पीटा, रोजगार

बढ़ने के, संसाधनों का भी ढिंढोरा पीटा और बेरोजगारों की संख्या आपके आंकड़ों के अनुसार बढ़ी है, मैं समझता हूं कि यह सब बातें हुई हैं. सरकारी क्षेत्र में भी नौकरियों की कमी हुई है. जिस तरीके से सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की कमी लाई 7 लाख, उन्पचास हजार नौकरियां उनकी संख्या घटकर 7 लाख, 34 हजार हो गई है, तो आपकी संख्या नौकरियों की घटी, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, आपने कहा कि हम इन्वेस्टर ज्यादा लाये, आपने कहा कि हमने उद्योग ज्यादा लगाये, आपने कहा कि हम स्वर्णिम मध्यप्रदेश बना रहे हैं, तो फिर रोजगार क्यों मिल रहा है ? इस सवाल को आपको और हमको, सबको समझना पड़ेगा. आप लोगों ने मुझे सुना, चूंकि मेरे पास 2-3-4 मिनट ही थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने थोड़े ज्यादा ले लिये इसके लिये मैं माफी चाहता हूं, धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय--नहीं, ज्यादा नहीं लिये.

श्री दिव्यराज सिंह (सिरमौर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या 11, 43, 51 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो कि उद्योग और रोजगार में बहुत ही पिछड़ा हुआ है. पहली बार भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को इस क्षेत्र से निर्वाचित किया गया. मध्यप्रदेश आज उद्योग की इकाई में काफी आगे आ रहा है खासकर मालवा और इन्दौर क्षेत्र. हमारे विंध्य में भी खनिज के उद्योग काफी लग चुके हैं. आज हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र एवं जिले में कृषि आधारित उद्योग भी शुरु हो रहे हैं. जैसे कि सोयाबीन के प्लांट. उद्योग विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2013 से प्रारंभ की गयी है. इसके अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंक से फायनेंस उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. सभी वर्गों के युवाओं को स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने के लिये बैंक से फायनेंस मिल रहा है. इस योजना के तहत विगत् वर्ष में 30 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया गया है. मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश के इतिहास में पहली बार व्यापक पैमाने पर औद्योगिक विकास के लिये 600

करोड़ से ज्यादा व्यय किया गया है. इससे हमारे प्रदेश में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ है. हमारे प्रदेश को एक औद्योगिक प्रिय राज्य का दर्जा मिल गया है. विगत् 5 सालों में प्रदेश में सौ से ज्यादा वृहद और मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें 29 हजार करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हुआ है और 20 हजार लोगों को रोजगार मिला है. उद्योग विभाग द्वारा हमारे प्रदेश में रोजगार कार्यालयों का उन्नयन करके पेसमेंट कार्यालय में बनाया गया है. इनको प्रायवेट पार्टनर्शिप के सहयोग से विकसित किये जाने का प्रस्ताव भी लाया गया है. ऑन लाइन जॉब पोर्टल, कॉल सेंटर की व्यवस्था, जो युवाओं को मार्गदर्शन और रोजगार के अवसरों की जानकारी देगा. कई रोजगार मेलों का आयोजन कराया जा रहा है, जो कि युवाओं को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं. प्रदेश में केरियर कौंसलिंग योजना 2008-09 से शुरु की गयी है, जिसके अंतर्गत 20 रोजगार कार्यालय शुरु किये गये थे. वर्तमान में 48 रोजगार कार्यालय खुल चुके हैं, जिससे मार्च,2014 तक 2 लाख 25 हाजर आवेदकों को लाभान्वित किया गया है. Today our country has the largest base of youth population and a large number of them belongs to the rural region. It is our duty to guide them and provide them proper education and jobs. आज मेरे क्षेत्र में एक भी बड़ा उद्योग नहीं है और नील गाय के प्रकोप के कारण खेती में भी पिछ्ड़ रहा है. मेरे क्षेत्र में कई कम्पनियां वीडियोकॉन, अभिजीत ग्रुप, एनटीपीसी के पॉवर प्लांट आने की बात कई सालों से चल रही है, परंतु इनका काम अभी तक शुरु नहीं हो पाया है. मैं मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में हम कृषि से संबंधित उद्योगों को लगाने के लिये प्रोत्साहन दें. मेरे क्षेत्र में दूध का उत्पादन बहुत तादाद में होता है. परन्तु वह व्यवस्थित नहीं है. मैं मानता हूं कि उसमें दूसरे विभाग का भी हाथ है, परन्तु मैं चाहता हूं कि अगर हमारे क्षेत्र में बाहर से निवेश हो तो इसको हम अच्छे तरीके से आर्गनाइज कर पायेंगे, जिससे दूध और उसके बाय प्रोडक्ट्स का हम अपने क्षेत्र में भी उत्पादन करना शुरु कर पायेंगे.

मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम अनस्किल्ड लेबर जो उद्योग में इस्तेमाल होते हैं, उसमें अगर क्षेत्रीय लोगों का 50 प्रतिशत का आरक्षण किया जाय, तो हमारे क्षेत्र के लोग जो नौकरी ढूंढने के लिये दर-दर भटकते हैं. चाहे उत्तर प्रदेश, गुजरात जाते हैं. उनको अपने ही अपने क्षेत्र में रोजगार मिलने का मौका मिलेगा.

मैं खेल के बारे में भी एक सुझाव देना चाहूंगा. मेरे क्षेत्र में एक भी स्टेडियम नहीं है. मैं मंत्री जी से एक मांग करुंगा कि मेरे क्षेत्र में एक स्टेडियम जल्दी से जल्दी खोला जाय, कृपा आप अपने बजट में इसको जोड़ें. साथ में मैं धरमार्थ के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में और खास करके हमारे विंध्य क्षेत्र में कई पुराने मंदिर हैं, बहुत बेशकीमती मूर्तियां रखी हुई हैं, उनकी हम देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, कई चोरी हो रही हैं. तो मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर हम वहां पर पुलिस प्रशासन तो लगा नहीं सकते हैं, अगर सीसी टीवी केमरा उन मंदिरों को चिह्नित करके लगा दिया जाय, जहां पर कीमती मूर्तियां हैं, तो काफी हद तक इससे हमको सहायता मिल पायेगी. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री देवेन्द्र वर्मा (खण्डवा) -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-11,43 एवं 51 के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं. मेरे पूर्व वक्ताओं ने खेल एवं युवक कल्याण, धार्मिक न्यास एवं वाणिज्य उद्योग के संबंध में अपने अपने सुझाव और अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं. खेलों से जीवन में अनुशासन और शरीर बलिष्ठ होता है, खेलों से शरीर में बुद्धि का विकास होता है और स्वस्थ बुद्धि निश्चित रुप से एक युवा और एक बच्चा अपने एक अच्छे भविष्य की कामना कर सकता है. जैसे कि माननीय नायक जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि हमारी सरकार ने खेलों की उपेक्षा की, अर्थात् हम बजट नहीं दे पाये और आज लगभग 174 करोड़ रुपये का बजट बतलाता है कि निश्चित रुप से सरकार कितनी गंभीर है. सरकार ने चिंता ही नहीं की है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में पायका जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बच्चियां भी खेल के

प्रति उत्साहित हैं. ग्रामीण क्षेत्र से भी प्रतिभाएं निकलकर आ रही हैं और साथ ही साथ हमारे मध्यप्रदेश में लगभग 16 अकादमियों के माध्यम से विभिन्न खेलों में किस प्रकार प्रतिभाओं का निखार हो, इसके प्रति सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है, अर्थात् सरकार कितनी गंभीर है, यह हमें दर्शाता है. निश्चित रुप से अगर हम पिछले 3 वर्षों के हमारे मध्यप्रदेश की खेल अकादमियों द्वारा अर्जित पदकों की बात करें, तो जहां 2011-12 में हमने कुल 234 पदक हासिल किये थे, वहीं 2012-13 में 275 और 2013-14 में 164 अर्थात् राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी खेलों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं. मैं साथ ही साथ कुछ खेलों के बारे मे सुझाव भी मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा. जब हम खेलों की बात करते हैं, तो निश्चित रुप से 16 अकादमियों पर हमारा मध्यप्रदेश पूरी तरह से निर्भर है. मेरा मानना ऐसा है कि खेल की प्रतिभायें गांव से, मोहल्लों से निकल आयेंगी, अर्थात् निचले स्तर से निकलकर आयेंगी. अगर निचले स्तर पर हम देखें, हमारा प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है, तो हमारे ध्यान में आता है तो एक खेल अधिकारी एक जिले में होता है और वह खेल अधिकारी पुलिस अधीक्षक के अधीन होता है. मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार अन्य विभाग काम करते हैं, उसी प्रकार अगर एक खेल विभाग भी अलग से बनाया जाय और उसे जिलाधीश के अंडर में, कलेक्टर के अंडर में किया जायेगा, तो निश्चित रुप से वहां पर कोई भी अगर डिप्टी कलेक्टर या इस प्रकार का एक अधिकारी देखेगा, तो निश्चित रुप से हम खेलों के साथ न्याय कर पायेंगे. इसी प्रकार खेल में अगर कोच की बात करें, तो प्रत्येक जिला स्तर पर एक कोच रहता है और वह सभी खेलों को संचालित करता है. कई जिलों में तो इस प्रकार की स्थिति है कि वह कोच भी नहीं है. मैं मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि निश्चित रुप से हम जिला स्तर पर जिला मुख्यालय पर लगभग 4-4 खेलों के उस क्षेत्र में जो प्रमुख खेल हों, वहां पर अगर उस खेल के कोच पहुंचायेंगे, तो निश्चित रुप से उस खेल के साथ हम न्याय कर पायेंगे. मेरे खण्डवा से जहां एक कृपाशंकर पटेल जैसे

अन्तर्राष्ट्रीय पहलवान निकलकर आये हैं. मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर लॉन टेनिस का कोच है. हमारे यहां मोहल्ले-मोहल्ले में गांव गांव में अखाड़े हैं लेकिन हमारे यहां कुश्ती का कोच नहीं है,

श्री बेल सिंह भूरिया-- हर खेल के अलग अलग कोच जिला स्तर पर होना चाहिये.

श्री देवेन्द्र वर्मा-- उपाध्यक्ष महोदय,मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे खंडवा जिले में कुश्ती का कोच उपलब्ध करायें और मल्लखंब में आपने 14 जिले शामिल किये हैं. हमारे यहां मल्लखंब की विद्या बहुत अच्छी है, हमारे खंडवा जिले को भी मल्लखंब में शामिल कर दें तो निश्चित रूप से हम खेलों का ज्यादा से ज्यादा विकास कर पायेंगे. जैसा कि मैंने बताया कि खेलों को जिले के अंदर कलेक्टर के अधीन करते हैं , अगर हम खेल की सुविधाओं को देखें तो स्टेडियम नगर निगम के अधीन है, इन्डोर स्टेडियम है वह भी किसी के अधीन है, जो भी खेल की सुविधायें हैं वह कहीं न कहीं विभिन्न विभागों में बटी हुई हैं इन सबको एकत्रित करते हुये मेरी मांग है कि जिला स्तर पर एक खेल विभाग का गठन किया जाये और उसके अधीन यह सारे कार्य किये जायें तो हम खेलों का विकास कर सकेंगे.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खंडवा विधानसभा क्षेत्र में हमने जितनी जनभागीदारी की है मेरा मानना है कि मध्यप्रदेश ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में कभी खेलों के लिये इतनी जनभागीदारी से राशि एकत्रित नहीं हुई होगी. हम खंडवा शहर के प्रत्येक नागरिक के पास गये हमने निवेदन किया कि खंडवा में हम स्वीमिंग पुल बनायेंगे, हमने 65 लाख रूपये जनभागीदारी से एकत्रित किये थे, इस 65 लाख की राशि एकत्रित करते हुये शासन से लगभग 65 लाख रूपये प्राप्त किये और स्वीमिंग पुल का निर्माण कराया. उसके बाद लगभग 130 लाख में वह स्वीमिंग पुल पूर्ण नहीं हो रहा है, मंत्री जी से अनुरोध है कि उसके लिये 1 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दें तो हमारा स्वीमिंग पूल पूर्ण हो जायेगा और खंडवा के प्रत्येक व्यक्ति ने जो जनभागीदारी निभाई है उसमें शासन का भी

सहयोग हो जायेगा. इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इन्डोर स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार में स्वीकृत हुआ था उसकी फ्लोरिंग और लाइटिंग बाकी है उसका भी निरीक्षण करायें और उसके लिये राशि उपलब्ध करायें, हम खेल की प्रतिभाओं की जहां बात करते हैं , खेल की प्रतिभायें कहां से आयेंगी, खेल की प्रतिभायें आगे कैसे बढेंगी, मैं बताना चाहता हूं कि मात्र 16 अकादमी में 10 खिलाड़ी खंडवा शहर के भाग ले रहे हैं, लेकिन 1 जिले से 10 खिलाड़ी भी पहुंचते हैं तो यह संख्या बहुत कम है, ऊंठ के मुंह में जीरे के बराबर है. निश्चित रूप से प्रत्येक जिले में 1000-1000 खिलाड़ी निकलकर के आयें तब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की बात कर सकते हैं. एक एक जिला मुख्यालय में मेरे खंडवा शहर में लगभग 25 एससी एसटी के छात्रावास हैं लेकिन एक भी कोच वहां पर किसी प्रकार का नहीं है. हम जिस प्रकार शिक्षा की अनिवार्यता पर जौर दे रहे हैं उसी प्रकार से खेल की शिक्षा भी अनिवार्य करेंगे और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को खेल का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से देंगे तो निश्चित रूप से खिलाड़ी निकलेंगे और आगे जायेंगे. मेरा मानना है कि सभी हॉस्टलों में खेल को अनिवार्य किया जाये, छोटे छोटे बच्चों को अगर हम खेल का प्रशिक्षण देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्मस्व विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे खंडवा जिले में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओकारेश्वर ज्योर्तिलिंग है. ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग की बात करें तो जहां हमारी सरकार ने निर्णय लेकर के महाकालेश्वर, सलकनपुर, मैहर इनके लिये शासकीय ट्रस्ट बनाने का काम किया है वहीं खंडवा के ओंकारेश्वर को छोड़ दिया गया है, वह एक प्रायवेट ट्रस्ट है जिसके कारण व्यवस्थाओं में दिक्कत आती है, लाखों करोड़ों श्रृद्धालु ओंकारेश्वर पहुंचते हैं लेकिन प्रशासन की उपयुक्त व्यवस्था के कारण वहां व्यवस्थाओं को देखने में दिक्कत आती है. मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आपने महाकालेश्वर का ट्रस्ट बनाया है उसी प्रकार से ओंकारेश्वर

में भी ट्रस्ट बनाते तो निश्चित रूप से आने वाले सिंहस्थ में वहां की व्यवस्थाओं में ऐतिहासिक सुधार हो सकेगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने खंडवा शहर के लिये ग्रोत सेंटर स्वीकृत किया है लगभग 40 करोड़ रूपये की राशि उसके लिये स्वीकृत की है लेकिन उस ग्रोत सेंटर में जो जमीन के रेट तय किये हैं वह 150 रूपये स्कवायर फिट के रखे हैं जिसके कारण उद्योगपतियों में व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है. उस रेट को अगर नीतिगत करेंगे , कुछ कम करेंगे तो अच्छे उद्योग धंधे वहां पर आयेंगे.खंडवा शहर में खंडवा जिले में सबसे अधिक डायवर्सन टेक्स है जो कहीं न कहीं त्रुटिवश है इस डायवर्सन टेक्स की विसंगति दूर करेंगे तो खंडवा जिले को फायदा होगा. उपाध्यक्ष जी आपने मुझे अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओंकारेश्वर का जो मामला है वह मेरी विधानसभा क्षेत्र का है. विधानससभा क्षेत्र का नाम ही मांघाता विधानसभा क्षेत्र है. मेरा सुझाव है कि ओंकारेश्वर ट्रस्ट की जितनी जमीन है हजारों एकड़ जमीन है उसको लीज पर कलेक्टर देंगे तो उसकी आय बढ़ जायेगी. जो अभी तक हो नहीं रहा है. दूसरा सुझाव है कि जबट्रस्ट बनेगा और शासकीय अधिनियम के तहत जब एक्ट में आयेगा तो इसमें स्थानीय विधायक को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाये.

श्री वेल सिंह भूरिया-- मैं आदिवासी क्षेत्र की बात करना चाहता हूं. धार झाबुआ आदिवासी क्षेत्र है यहां पर तीरंदाज का खेल परिसर सरदारपुर जिला धार में हो जाये तो अच्छा रहेगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपने बोलने के लिये नाम तो दिया नहीं. आपकी बात आ गई है.

श्री सुदर्शन गुप्ता (इंदौर-1)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11,43 एवं 51 का समर्थन करता हूं तथा कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं

मंत्री जी का ध्यान औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं और अपनी ओर से कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला उद्योग केन्द्र के अधीन समस्त औद्योगिक क्षेत्रों का AKVN में विलय का शासन का प्रस्ताव है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिये. इससे उद्योगपति परेशान होंगे. क्योंकि आये दिन AKVN द्वारा प्रीमियम की राशि बढ़ा दी जाती है और यदि कोई उद्योगपति एक या दो वर्ष तक किसी कारणवश, बीमार हो जाये और उद्योग नहीं चला पाता है तो AKVN तुरंत जमीन की लीज को समाप्त कर देता है. और मजबूरी में उद्योगपति को अपना उद्योग बंद करना पड़ता है. AKVN का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है जबकि जिला उद्योग केन्द्र का उद्देश्य लघु उद्योंग का बढ़ावा देना है, इसी हेतु इनकी स्थापना भी हुई है अतएव जिला उद्योग केन्द्र से लघु उद्योगों को बढ़ावा और लाभ मिलता रहे इसलिये इसको यथावत जारी रखा जाना चाहिये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला उद्योग केन्द्रों को अधोसंरचना विकास हेतु मजबूत बनाना चाहिये जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा उद्योगपतियों से प्रति वर्ष संधारण शुल्क वसूला जाता है , किंतु उसकी राशि कोषालय में जमा हो जाती है, जिला उद्योग केन्द्रों के पास संधारण के लिये किसी प्रकार की कोई राशि नहीं रहती है. वहां की जो समस्यायें होती हैं उन समस्याओं को हल करने के लिये बजट नहीं होता है. मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याये हैं उसके लिये अलग से जिला उद्योग केन्द्रों के लिये राशि का आवंटन करें.नये उद्योग को मिलने वाली छूट और रियायत के लिये गठित जिला स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं उसकी नियमित बैठकें नहीं होती हैं और उसका नुकसान नये उद्योगपतियों को उठाना पड़ता है इसलिये

इस समिति की नियमित बैठकें होनी चाहिये. मेरे इंदौर में लगभग 2 वर्ष हो गयें हैं इस समिति की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है.

माननीय उपाध्यक्ष महोद, इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर, औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड़, और पोलो ग्राउन्ड औद्योगिक क्षेत्र अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं जिसमें मुख्य रूप से मूलभूत सुविधायें सड़क, पानी, ड्रेनेज, पीने का पानी, सुरक्षा आदि की व्यवस्थायें और उसके कारण अनेक श्रमिकों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है , इन जिला उद्योग केन्द्रों को नगर निगम से तालमेल बैठाकर के वहां के श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिये प्राथमिकता देना चाहिये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस फायर विग्रेड की व्यवस्था बहुत कम होती है आये दिन वहां पर आगजनी की घटनायें होती रहती हैं . फायर विग्रेड के पहुंचने में काफी विलंब होता है जब तक पूरी इन्ड्रस्टीज जल कर के खाक हो जाती है. पिछले दिनों लगातार इस तरह की घटनायें हुई हैं. इस तरफ विभाग को ध्यान देना चाहिये.

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र को मास्टर प्लान में सर्वे नंबर 104 में प्रस्तावित 40 मीटर रोड को समाप्त करके उद्योग बसाये जाने की योजना है. अगर यह रोड समाप्त कर दिया गया तो लगभग 500 उद्योग और उद्योगपतियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. श्रमिकों को कठिनाई का सामना करना पडेगा औऱ वहां से निकलने वाले भारी वाहन है उनको भारी तकलीफ उठाना पडेगी. चूंकि यह मास्टर रोड मास्टर प्लान में स्वीकृत है तो इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है अन्यथा यह भविष्य में लोकायुक्त का विषय बनेगा इसलिये मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह रोड़ किसी हालत में समाप्त नहीं होना चाहिये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी के साथ अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है इस और भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये. माननीय उपाध्यक्ष महोदय सबसे ज्वलंत

समस्या जो इंदौर की है , इंदौर की जो बंद मिले हैं उनके मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिये, इंदौर के हुकुमचंद मिल,राजकुमार मिल, और भंडारी मिल के मजदूर काफी परेशान हैं. वह मिलें जब बंद हुई थीं तब वे मजदूर जवान थे .उपाध्यक्ष महोदय, मिलें जब बंद हुई थी, तब वे मजदूर जवान थे. किन्तु अब वह मजदूर बूढ़े हो चुके हैं. उसमें से कई मजदूर मर चुके हैं. लेकिन उनके परिवारों को न्याय नहीं मिला है. उनके परिवारों को राशि नहीं मिली है. मैं मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि उन मजदूरों के पक्ष में न्याय करें. धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- श्री मनोज अग्रवाल जी.. कृपया 3 मिनट में अपनी बात कहिएगा.

श्री मनोज कुमार अग्रवाल(कोतमा)-- उपाध्यक्ष महोदय, तैयारी तो ज्यादा थी..

उपाध्यक्ष महोदय-- उसको कॉन्साईज कर लीजिएगा.

श्री मनोज कुमार अग्रवाल-- ठीक है. आज मेरे जीवन का अविस्मरणीय और ऐतिहासिक क्षण है कि इस प्रजातंत्र के मंदिर में पहली बार मैं किसी चर्चा का हिस्सा बन रहा हूं इसलिए आपका और पूरे सदन का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और संरक्षण चाहूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय,किसी भी देश या प्रदेश की प्रतिष्ठा, उसका निर्माण, उसके औद्योगिक नीति और औद्योगिक परिस्थिति पर निर्भर करता है. हम सब चाहते हैं कि मध्यप्रदेश एक सशक्त औद्योगिक प्रदेश में रुप में जाना जाये लेकिन परिस्थितियां और परिदृश्य बिलकुल विपरीत है. हमारे पास भू-गर्भ में इतनी प्रचुर मात्रा में सम्पदा है लेकिन हम उद्योग स्थापित करने में बिलकुल नाकाम हैं. हमारे यहां पर कोयले की बड़ी-बड़ी खदानें हैं. मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां लाखों टन कोयला रोज निकलता है लेकिन एक भी सहायक उद्योग वहां पर स्थापित नहीं हैं. चूंकि शासन का ऐसा कोई नियम, परिपत्र या बंदिश नहीं है कि वहां पर सहायक उद्योग स्थापित हो.

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग बढ़ाने की सरकार की इच्छा है. सरकार का विज़न है. लेकिन उस विज़न में एक कमी है जो मंत्रीजी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में एक ब्लेंकेट पॉलिसी

नहीं चल सकती. इतना बड़ा प्रदेश है कि यहां पर जो औद्योगिक नीति हो वह एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए. आपकी जो औद्योगिक नीति है वह शासन का विज़न है. वह सरकार की सोच है. लेकिन विंध्य में अलग जरुरत है, मालवा,निमाड़,बुंदेलखंड, बघेलखंड में अलग जरुरत है. सबकी भौगोलिक परिस्थिति अलग है. वहां पर क्या संसाधन है उसके हिसाब से नीति बननी चाहिए तब हम उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत सारे ताप विद्युत गृह बन रहे हैं. वहां से उसकी फ्लाई एश निकलती है लेकिन हम उस फ्लाई एश का उपयोग ब्रिक्स बनाने में नहीं करते. हमारा उद्योग विभाग इस पर नहीं सोचता है कि इनको संरक्षण चाहिए. यह बहुत एक लघु उद्योग है. शासन को ऐसा परिपत्र निकालना चाहिए कि जहां भी थर्मल पॉवर स्टेशन्स हैं,वहां पर लाल ईंटों का उपयोग नहीं होगा और जितने भी शासकीय, अर्द्ध शासकीय और सार्वजनिक उपक्रम के जितने भी संस्थान हैं वह अपने निर्माण कार्य में फ्लाई एश का ही उपयोग करेंगे और जितने थर्मल पॉवर स्टेशन्स हैं, वह फ्लाई एश ब्रिक्स प्राथमिकता से लघु उद्योगों से बनवायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इन्टरप्रियोनर नहीं खोज रहे हैं. मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इन्टरप्रियोनर खोजने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए और जिस तरह से हमारा जो प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था उसी तरह से जिले और ब्लाक स्तर पर इस तरह के प्रबोधन कार्यक्रम कराना चाहिए. हम उधार के निवेश से प्रदेश का भला नहीं कर सकते. हमको अपने पास के संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा. हमारी जो संपदा भू-गर्भ में है, उसका पूरा उपयोग करना पड़ेगा. मुझे कहने में खेद होता है कि शासन के पास ऐसी कोई भी नीति नहीं है जो इन्टरप्रियोनर को प्रमोट करे.

उपाध्यक्ष महोदय, जितने जिला उद्योग केन्द्र (DIC) हैं वह सब्सिडी सेन्टर हो गये हैं. वह डाटा फीलिंग सेन्टर हो गये हैं. वह केवल आंकड़ें भरते हैं. वहां पर जितना स्टाफ है वह सिर्फ यह देखता है कि सब्सिडी किस तरह से शेयर की जाये. किस तरह से डाटा भर कर मंत्रीजी को दे दिये जायें. जमीनी हकीकत में वह मूर्तरुप ले सके ऐसा कुछ भी नहीं होता है.

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक उद्योगों की हालत नहीं सुधरेगी हम बीमारु राज्य से बाहर नहीं आ सकते. हम जब तक उद्योगों को सशक्त नहीं करेंगे. जब तक गुणवत्ता नहीं लायेंगे तब तक हमारी तकनीकी शिक्षा भी नहीं बढ़ेगी. क्योंकि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाला स्टुडेंट एब्जार्ब कहां होगा !

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शहडोल जिले में और अनूपपुर जिले में, जहां की कोतमा विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पर रिलायन्स कंपनी इतना बड़ा CBM यानि कोल बेड मिथेन प्रोजेक्ट चला रही है. जहां जहां कोयला होता है वहां भू-गर्भ में कोयले की परत के नीचे जो गैस होती है उसको मिथेन गैस बोलते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- कोकिंग कोल..

श्री मनोज कुमार अग्रवाल-- कोई भी कोल. जहां कोल होता है उसकी परत के नीचे गैस होती है. उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है. कोल बेड मिथेन गैस का इतना बड़ा करोड़ों-अरबों रुपये का प्रोजेक्ट है, उसको कंपनी बाहर लेकर जा रही है. उस गैस का उपयोग पॉवर बनाने में और बाकी चीजें बनाने में किया जा सकता है लेकिन उस कंपनी वहां रोजगार का, उद्योग की कोई योजना नहीं है जो कि गलत है. शासन को इस विषय में सोचना चाहिए कि जहां भी हमारी भू-गर्भ की संपदा है, उसका उपयोग किया जाता है तो यह उन कंपनियों का दायित्व बनता है कि वहीं पर उसको उपयोग करे. अगर नहीं पूरा नहीं कर सकती हैं तो अंशः में करे. सौ प्रतिशत नहीं कर सकते तो आधा करे लेकिन करे. जिस तरह फ्लाई एश के लिए मैंने कहा तो इसके लिए भी शासन को परिपत्र

निकालना चाहिए कि जहां जहा थर्मल पॉवर स्टेशन्स हैं,वहां पर फ्लाई एश ब्रिक्स को हमको प्रमोट करना है.

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एकल खिड़की प्रणाली के संबंध में कहना चाहता हूं कि जो युवा पढ़कर निकलते हैं. इंजीनियर बनते हैं. एमबीए करते हैं उनका अगर सपना है. उनको उद्यमी बनना है. आप स्वयं सोचिये. एक भी उदाहरण इस प्रदेश में नहीं है कि उसको एकल खिड़की का लाभ मिला हो. एकल खिड़की एक एकस्ट्रा खिड़की हो गई. उस एकल खिड़की से कुछ भी नहीं होता है. मैं मंत्रीजी के संज्ञान में भी इस बात को लाना चाहता हूं कि एकल खिड़की को भी आप इतना सशक्त करें और वह दिखे, परिलक्षित हो, एपीयरेन्ट हो. दिखना चाहिए. उसे पता चलना चाहिए कि हां कुछ हो रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्वेस्टर्स मीट की बात करता हूं. मुझे भी एक बार जनवरी 2008 में इन्वेस्टर्स मीट में जबलपुर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था. वहां पर आदरणीय कुमार मंगलम बिड़ला गेस्ट ऑफ ऑनर थे. आप स्वयं देखिये कितनी इन्वेस्टर्स मीट होती है. कितने लोग जमीनी हकीकत में आते हैं. शासन कोशिश कर रहा है लेकिन क्यों नहीं आते. उसका कारण सिर्फ यह है कि हमारे यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है. इन्फ्रास्ट्रक्चर तभी होगा जब हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे. आज सीहोरा और कटनी क्षेत्र में निम्न स्तर का लौह अयस्क है. हम वहां पर क्यों नहीं स्टील इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना कर सकते हैं. दुनिया में ऐसी तकनीकी है कि निम्न किस्म के आयरन ओर को उन्नयन किया जा सकता है. धन्यवाद.

इंजीनियर प्रदीप लारिया(नरयावली)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, खेल और व्यायाम हमारे जीवन के लिए कितने अनिवार्य हैं यह हम सब जानते हैं. स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. जब राजतंत्र था उस समय जो राजा

या राजा से जुड़े हुए लोग होते थे वह भी सब खेलों से जुड़े होते थे. हमारे यहां आज जो खेल खेले जाते हैं चाहे वह तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो,तीरंदाजी हो, कुश्ती हो, पहलवानी हो वह खेल राजा के लिए अनिवार्य होते थे.उस समय वे राजा के लिए अनिवार्य होते थे और जो राजा या राजतंत्र से जुड़े जो लोग थे, वे उसमें निपुण होते थे, वे सफल राजा कहलाते थे. उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक कहावत थी - "खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब." लेकिन आज वर्तमान युग में जहां पढ़ने-लिखने से तो नवाब बन ही रहे हैं. लेकिन खेलने-कूदने से भी बन रहे हैं, हम सबके सामने प्रमाण हैं, चाहे सचिन तेंदूलकर की बात कर लें, चाहे महेन्द्र सिंह धोनी की बात कर लें, चाहे पीटी ऊषा, चाहे सानिया नेहवाल की बात कर लें. आज हम देखते हैं कि विविध क्षेत्रों में खेल के माध्यम से ही अपने आपको लोहा मनवाया है. मुझे इस बात की खुशी है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने जिस तरह से खेल के क्षेत्र में काम किया है. माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से खेल के क्षेत्र में काम किया है. निश्चित तौर पर हम सबके लिए एक उपलब्धि है. अभी श्री मुकेश नायक जी कह रहे थे कि खेल के क्षेत्र में इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी हुई है और जब वे खेल मंत्री थे, उनके समय जितना बजट होता था, आज उतने के होर्डिंग खेल विभाग के माध्यम से लग रहे हैं. मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वर्ष 2003 में खेल का बजट लगभग 3 या 4 करोड़ रुपए का हुआ करता था, आज 174 करोड़ रुपए का खेल का बजट है.

उपाध्यक्ष महोदय - श्री मुकेश नायक जी ने तो आपकी प्रशंसा ही की है, वह अपनी सिर्फ पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि उनका बजट कम था.

श्री मुकेश नायक - आपकी सरकार ने बहुत प्रगति की है. पूरे मध्यप्रदेश के लिए खेल का बजट 174 करोड़ रुपए और एक आईएएस अधिकारी के घर छापा पड़ता है तो 300 करोड़ रुपए निकलते हैं, आपने क्या कोई कम प्रगति की है?

इंजी. प्रदीप लारिया - आप इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि खेल के प्रति माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री कितनी संवेदनशील हैं और उसी का परिणाम है कि चाहे राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हों, लगातार मध्यप्रदश को सफलता मिलती जा रही है. हॉकी, हम सब जानते हैं कि यह देश की शान हुआ करती थी. कभी दादा ध्यानचंद जी, जिनके नेतृत्व में कई वर्षों तक हॉकी के क्षेत्र में हम विश्व विजेता रहे हैं. हॉकी के कारण भारत को पहचाना जाता था. मुझे इस बात की खुशी है कि वर्ष 2007-08 में ग्वालियर में खेल अकादमी का प्रारंभ हुआ. उसी का परिणाम है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने खेल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में ध्यान दिया है और हॉकी के जूनियर खिलाड़ियों की जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मध्यप्रदेश की जो महिला हॉकी है, उसने कांस्य पदक जीता और उसमें मध्यप्रदेश की 6 महिला हॉकी खिलाड़ी थीं. (मेजों की थपथपाहट).. यह निश्चित तौर पर मध्यप्रदेश के लिए उपलब्धि है.

उपाध्यक्ष महोदय, जो विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, हमने राष्ट्रीय स्तर पर तो दक्षता हासिल की है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्ष 2011-12 में 9 स्वर्ण, 11 रजत, 13 कांस्य पदक कुल मिलाकर 59 पदक जीते गये. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2012-13 में 14 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य पदक जीते गये और वर्ष 2013-14 में 4 स्वर्ण, 5 रजत, 11 कांस्य पदक जीते गये. जहां तक हमारी उपलब्धियां हैं, लगभग 17 खेल अकादमी मध्यप्रदेश की सरकार ने खोलने का काम किया है. मैं माननीय मंत्री महोदया जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो बुन्देलखण्ड का क्षेत्र है, उसका मुख्यालय सागर है और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कोई भी अकादमी खास तौर पर सागर में नहीं खुली है. वहां पर खेल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. निश्चित तौर पर वहां अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां भी कोई खेल अकादमी खोल दें, जिससे वहां से भी अच्छे खिलाड़ी निकल सकें. मेरा निवेदन है कि सागर में खेल गतिविधियां बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण हुआ है. लेकिन हम देखते हैं कि जो खेल के मैदान खेल के लिए आरक्षित रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अन्य प्रयोजन के लिए भी खेल के मैदान दे देते हैं. मेरा आपसे निवेदन है कि खेल के मैदान वैसे ही कम हैं, इसलिए उनको खेल तक ही सीमित रखा जाय. अन्य गतिविधियों के लिए उनको नहीं दिया जाय. जो वहां स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स है, उसमें सुविधाओं की कमी है, उसको भी पूरा कर दें. सागर में स्वीमिंग पूल नहीं है. अच्छे तैराक वहां पर निकल सकते हैं. जब मैं सागर का महापौर था तो नगर निगम और खेल एवं युवक कल्याण विभाग के माध्यम से एक स्टेडियम वहां पर प्रारंभ करने की बात हुई थी. उसमें 25 लाख रुपए की राशि नगर निगम ने जमा भी कर दी थी. शेष राशि खेल एवं युवक कल्याण विभाग को देना थी. लेकिन वह बीच में योजना बंद हो गई, जिसके कारण स्वीमिंग पूल नहीं खुल पाया. मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सागर में स्वीमिंग पूल खुल जाय, जिससे हमारे तैराकी के खिलाड़ियों को एक साधन उपलब्ध हो सके. हमारे सागर का जो बैडमिंटन कोर्ट है, वह बैडमिंटन कोर्ट बढ़िया वुडन का कोर्ट बन गया है. वहां पर सिंथेटिक फर्श भी डल गया है लेकिन वहां एक समस्या है कि बरसात का पानी सीधा उस वुडन कोर्ट में भर रहा है. लगभग 60-70 लाख रुपए की राशि से वहां पर काम हुआ था, आप इसको दिखवा लें, नहीं तो वह वुडन कोर्ट बेकार हो जाएगा. वहां पर जो छत का काम है वह ठीक हो जाय. उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र पटेल (इछावर) - उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश युवाओं का देश है. आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा युवा कहीं रहते हैं तो वह हमारे भारत वर्ष में रहते हैं. आज 66 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम के युवाओं की है. यह जो विभाग है इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है. खेल एवं

युवक कल्याण विभाग, जिसमें एक तरफ खेल की बात की जाती है और दूसरी ओर युवाओं के कल्याण की बात की जाती है. हमारे देश के भविष्य के निर्धारण में युवा सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं. अभी हाल ही में देखा गया है कि राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल मुक्त बाजार व्यवस्था के कारण प्रदेश में फैला. मजदूर, क्लर्क, प्रबंधक, इंजीनियर, फार्मासिस्ट की जरूरत इन कंपनियों का आ पड़ी. इन कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देशी शिक्षण संस्थाओं की भरमार हो गई. जहां डिग्रीधारी तो तैयार कर दिये गये, लेकिन उन डिग्रियों को लेने के लिए 80 से 90 हजार रुपए और कहीं -कहीं 1-1 लाख रुपए तक का सालाना खर्च युवाओं के ऊपर आया और बाद में वे युवा बेरोजगार के रूप में घूम रहे हैं. वर्ष 2008 में प्रदेश में युवा नीति लागू करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की. लेकिन उस युवा नीति का फायदा आज तक युवाओं को इस प्रदेश में देखने को नहीं मिला है. खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन आज हमें देखने में आता है कि बहुत से युवाओं की आत्महत्या के मामले में प्रदेश का नम्बर बहुत ऊपर आता है. इन सबके लिए हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा, जिससे युवा क्रिएटिव वर्क में लगे, प्रदेश के विकास में लगे और खेलों के विकास में लगे.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद भी राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहा हूं तो बहुत मेरा खेलों से जुड़ाव रहा है. प्रदेश में विरले ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर खेलने को मिला है. अभी हॉकी की बात की गई, पिछले 3 वर्षों में किसी भी हॉकी खिलाड़ी को विक्रम एकलव्य अवार्ड नहीं मिला है. जहां पर मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में एस्ट्रोटर्फ की बात की थी कि हमारे हर जिले में एस्ट्रोटर्फ हो, वे एस्ट्रोटर्फ अभी तक नहीं लगे हैं. अगर 2-3 करोड़ रुपए का प्रावधान एस्ट्रोटर्फ के लिए किया जाएगा तो जैसा नायक जी ने बताया कि लगभग 40-50 साल लग जाएंगे. हालैंड जैसे एक छोटे से देश में जहां 800 एस्ट्रोटर्फ हैं और उसी के कारण वहां की हॉकी ऊपर गई है. हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है. लेकिन हॉकी की विडम्बना हम भोपाल में देख सकते हैं. भोपाल में हॉकी का एक नाम था.

लगभग एक समय 80 से ज्यादा क्लब हॉकी के रजिस्टर्ड थे. लेकिन धीरे-धीरे क्लब कल्चर खत्म हो गया और भोपाल से या मध्यप्रदेश से हॉकी खिलाड़ी निकलना कम हो गये. अभी बहुत सी अकादमियों की बात की गई, लेकिन अकादमियों में हमारे मध्यप्रदेश के कितने मूल लोग उन अकादमियों में हैं यह देखना होगा. हम प्रतिभा को निकालने के लिए हर जिले स्तर पर खेलों को रिकगनाईज करना पड़ेगा, हर जिले की अपनी प्रतिभाए होती हैं , अलग अलग विधाओं में वे प्रतिभाएं होती हैं, उन प्रतिभाओं को चिन्हित कर कर उसी खेल मे उनको बढ़ावा देने का प्रयास करना होगा. बार बार बातें आती हैं कि बजट बढ़ गया. उपाध्यक्ष जी,आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे रूपये का अवमूल्यन हुआ है ,महंगाई बढ़ी है. तो निश्चित रूप से हर विभाग का बजट बढ़ना स्वाभाविक है, चाहे प्रदेश का बजट हो, चाहे देश का बजट हो. हर वर्ष बढ़ा हुआ बजट ही मिलता है. यहां पर इस बार 174 करोड़ रूपये की खेल विभाग की बात की गई. हमारे यहां लगभग दो ढाई करोड़ युवा हैं ,तो अगर ऐसा देखा जाएगा तो एक युवा के हिस्से मे तो 60 रूपये भी नहीं आते हैं. तो उस हिसाब से तो यह बहुत कम बजट कहा जाएगा. इतने कम बजट में हम कभी भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते. क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी देश का पूरे विश्व में होता है और युवाओं को हम जब तक ओलेम्पिक में, या वर्ल्ड कप गेम्स में नहीं निकालेंगे और युवाओं को छोटी उम्र से , जैसा कि चाईना में, जापान में, रशिया में किया जाता है. कम उम्र से हम बच्चों को चिन्हित नहीं करेंगे ,शिक्षा विभाग से मिल कर कोई योजना नहीं बनायेंगे तब तक प्रदेश का हमारा कोई भी खिलाड़ी औलेम्पिक या वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगा. भोपाल में औबेदुल्ला गोल्ड कप की बात मुकेश जी ने भी कही. ये एक बहुत बड़ा नामी टूर्नामेन्ट हमारे यहां होता था. उसके हाल हमारे मंत्री जी को पता है कि किस स्थिति में है. उनमें प्रयास करना चाहिए., कि वह टूर्नामेन्ट नई उँचाईयों पर आए ताकि प्रदेश की हमारी खेल प्रतिभाएं निकल कर आएँ,. अभी प्रदेश में भर्ती सूचना केन्द्र के माध्यम से मात्र 184 खिलाड़ी सशस्त्र बलों में पहुंचे हैहैं. हमारी

कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा खेलों को बढ़ावा दिया जाय और खिलाड़ियों को स्टायपण्ड की व्यवस्था दूसरे विभाग के द्वारा की जाय. ताकि वे खेल में अपना केरीयर बना सकें. क्योंकि युवा चाहता है कि उसका केरीयर सिक्युअर हो और जब तक उसका केरीयर सुरक्षित नहीं होगा तब तक वह खेल की तरफ नहीं बढ़ पाएगा. और एडवेन्चरस गेम में , मध्यप्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर इनको डेवलप किया जा सकता है. हमारे इच्छावर विधान सभा में कठोतिया गांव है जोकि भोपाल से लगा हुआ है वहां पर भी एडवेन्चरस गेम्स को बढ़ावा दिया जा सकता है. उत्कर्ष खिलाड़ी की नौकरी की बात नायक जी ने कही है. मैं एक बात और कहा चाहता हूं कि जो संविदा खेल प्रशिक्षक जो नियुक्त किए गए हैं उनको नियमित किया जाय और उनका जो वेतन है उसको बढ़ाया जाय.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें उद्योगों के बारे में कहना चाहूंगा. इछावर विधान सभा भोपाल से लगी हुई विधान सभा है और इछावर विकास खंड में जोकि सीहोर जिले में आता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसी जिले से आते हैं. वहां पर अभी तक किसी भी उद्योगों की स्थापना नहीं हुई है. हमारे यहां काफी संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं. और जो मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार योजना की बात की थी ,लेकिन बैंकों से ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. मेरा आदरणीय उद्योग मंत्री जी निवेदन है कि इछावर भोपाल से लगा हुआ क्षेत्र है वहां पर कोई ऐसा उद्योग लगाया जाय ताकि वहां के युवा जो कृषि पर आधारित हैं उनको रोजगार मिल सके. हमारा खेती किसानी वाला क्षेत्र है. वहां पर डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है. दूध की प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएँगे तो निश्चित रूप वहां की खेती भी सुधरेगी और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा. उपाध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्रीमती नीना विक्रम वर्मा (धार)- उपाध्यक्ष महोदय, मैं विभाग की सभी मांगो का समर्थन करते हुए अपनी बात रख रही हूं. यह अपने आप में सत्य है कि उद्योग किसी भी राष्ट्र और प्रदेश की

प्रगति और विकास की पहचान होते हैं. केवल राजस्व प्राप्ति ही नहीं वरन् रोजगार के असीमित अवसर भी उद्योग ही प्रदान करते हैं. प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या और खासकर शिक्षित युवाओं के लिए ,उद्योग उनके सुनहरे भविष्य के लिए एक आवश्यक और सशक्त माध्यम है. हम पूरी तरह अकेले कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते. अतः मध्यप्रदेश सरकार ने उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है. अनेक उद्योग समिट की हैं ,इन्वेस्टर्स को सीधे सकारात्मक संदेश दिए हैं और इसके अंदर यदि हम एकल विण्डो सिस्टम चालु कर दें तो शायद हमें इसमें और भी कई पाजीटिव सन्देश मिलेंगे. इसके परिणामस्वरूप उद्योग के विकास की दर हमारी 8.8 जोकि देश की विकास दर है उससे कहीं अधिक है . मुख्यमंत्री युवा स्वराज हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 12,13-14 और 16-17 तक मार्जिन मनी , व्याज की अनुदान गारंटी शुल्क , गारंटी सेवा शुल्क, कार्यालयीन व्यय सेमिनार, कार्यशाला आदि के मद में 676.28 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है. इसके प्रस्ताव ,परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करके आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है. इससे युवाओं को अपने स्वयं के रोजगार सृजन करने में काफी सहयोग मिलेगा. सतत बिजली, जमीन और श्रमिकों की उपलब्धता , श्रमिकों के शान्ति के वातावरण इसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इन्वेस्टर्स को हमने अपनी ओर आकर्षित किया है. एन.डी.ए. सरकार ने देश का पहला SEZ (SPECIAL ECONOMIC ZONE) मेरी विधान सभा पीथमपुर में प्रारंभ हुआ था. आज वहां एक और दवाई का SEZ बना हुआ है. तेजी से विकसित होते हुए औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में शासन नें नर्मदा से पानी लाकर उद्योंग और नागरिकों को उपलब्ध करान का निर्णय लिया है. मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के प्रयासों से उसे जल्दी ही मूर्तरूप मिलेगा. पीथमपुर, बाम्बे-दिल्ली इण्ड्स्ट्री कॉरीडोर में भी सम्मिलित हो गया है. अतः इसे आधुनिक सुविधा और विकसित करने के लिए औद्योगिक नगर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है. जेठान के पास उज्जैनी गांव में भी एक इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र विकसित हुआ है.

जिसका तेजी से विकास हो रहा है , इन सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की मैं बहुत आभारी हूं और मेरा एक निवेदन है कि तेजी से बढ़ते हुए उद्योग जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए कोई उचित सुविधा या साधन नहीं है. उनके रहने के लिए न आवास हैं ,न बस स्टेण्ड और न ही वहां पर कोई अच्छा अस्पताल है. सारी जमीन AKVN के पास है. नगर पालिका चाह कर भी वहां कोई विकास के कार्य नहीं कर सकती. अतः मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि जन प्रतिनिधि और AKVN के माध्यम से नगरपालिका के अधिकारियों के साथ बैठ कर अगर हम उद्योंगो और श्रमिको के विकास के लिए एक व्यवस्थित प्लान तैयार करें ताकि नागरिकों को और जनता को अधिक से अधिक सुविधाएँ देने का हम प्रयास कर सकें. माननीय मंत्री जी आपसे एक और निवेदन है कि आपने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 6- करोड़ की राशि का प्रावधान किया है और पुजारियों को भी उनका मानदेय बढ़ा करके आपने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की है. इसके साथ मेरा एक सुझाव है कि मंदिरों की तालाब और जमीनें काफी मात्रा में अतिक्रमण में आ गई हैं उन्हें एक योजनाबद्ध तरीके से मुक्त कराने का प्रयास किया जाय तो पुजारियों को काफी सहयोग होगा. माननीय मंत्री जी, खेलों में आपकी विशेष रूचि है ,आपकी रूचि को देख कर के, आपने पहले भी खेल विभाग में प्रशंसनीय कार्य किया है. आपके मार्गदर्शन में हमारा खेल विभाग और आगे बढ़ेगा. मेरा आपसे निवेदन है कि धार के अंदर एक केन्द्र का साईन्स सेन्टर चल रहा है उसके अंदर होस्टल भी है और एक मध्यप्रदेश का STDA सेन्टर है. वहां पर खिलाड़ियों के लिए होस्टल की सुविधा तो है लेकिन उनसे पास मेस और डायनिंग हॉल नहीं है. अगर आप वहां मेस और डायनिंग हॉल की राशि इसी बजट में स्वीकृत करेंगी तो खिलाड़ी और मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करेंगे. उपाध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री रामपाल सिंह (ब्योहारी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. खेल से स्वस्थ्य शरीर एवं स्वस्थ्य मस्तिष्क का निर्माण होता है. साथ ही खेल से हमको अनुशासन सीखने को मिलता है. खेल और युवा कल्याण विभाग खेल का संचालन करते हुए संभाग,जिला एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित करते हैं. किन्तु चिन्ता का विषय यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से खेलों के संबंध में , खेलों के प्रति पतन हुआ है निश्चित ही यह शोचनीय विषय है. क्योंकि ग्रामीण अंचलों में खेलों के प्रति एक अच्छी सद्भभावना और एक जागरुकता पैदा करने की जरूरत है. आज हमारे हायर सेकण्ड्री स्कूल और हाई स्कूल जिनमें भी खेल अधिकारी नियुक्त हैं, ग्रामीण अंचलों में उन्हें कोई भी नहीं जानता, वहां के लोग उनको सिर्फ पी.टी.आई. बोलते हैं. एक तो खेलों की सामग्री की पर्याप्तता नहीं और न ही खेल के संबंध में खेल अधिकारियों द्वारा उन्हें कुछ बताया जाता है. ग्रामीण अंचलों में इतना ज्यादा खेल मैदान का अतिक्रमण है, उतना शायद कहीं नहीं है. चूंकि उस तरफ जब खेल में इन्ट्रेस्ट नहीं होगा तो उसके अतिक्रमण में इन्ट्रेस्ट नहीं होगा. मैं चाहता हूं कि इनको संरक्षित किया जाना चाहिए. खेल मैदानों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय—रामपाल जी एक मिनट में समाप्त करें.

श्री रामपाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त करूंगा. भोपाल स्थित टी.टी.नगर स्टेडियम में कार्यरत बाक्सिंग कोच एवं अन्य कोच को मानदेय कम मिल रहा है, उसको बढ़ाया जाय और उन्हें नियमित किया जाना चाहिए, परंतु इसका बजट में उल्लेख नहीं है. ब्यौहारी में हमारे स्पोट्र्स सेन्टर का निर्माण कार्य स्वीकृत था, जिसका कार्य प्रगति पर है, उक्त कार्य की निविदा 60.58 लाख स्वीकृत की गई थी, किंतु प्रशासनिक स्वीकृति 54 लाख प्रदान की गई है, जिसके कारण समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो सका. उपरोक्त कार्य हेतु शीघ्र आवश्यक राशि प्रदान करने की कृपा करें. ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद.

श्री राजेश सोनकर (सांवेर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11, 43, 51 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. इतिहास साक्षी है कि जब भी इस देश में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं तो उसका कारण युवा ही रहा है. मध्यप्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश की युवाओं को, युवा तरूणाई को, युवा ताकत को खेलों से जोड़ने का एक मिशन बनाया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं. इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं. मध्यप्रदेश के युवाओं ने मध्यप्रदेश ही नहीं वरन् देश और प्रदेश में मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है. मध्यप्रदेश के युवा खिलाड़ियों द्वारा देश और प्रदेश में कांस्य पदक, रजत पदक और स्वर्ण पदक जीतकर मध्यप्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है. मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय खेल मंत्री महोदय को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हाकी को गोद लेने का निर्णय लिया. निश्चित रूप से मध्यप्रदेश में हाकी के क्षेत्र में से ऐसे कई महान खिलाड़ी पैदा हुए हैं, जिन्होंने मध्यप्रदेश का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है. चाहे वह पद्मश्री शंकर दादा हों, चाहे आदरणीय गुरू बख्श हों, चाहे आदरणीय मीर रंजन नेगी हों, निश्चित रूप से हाकी को गोद लेने के कारण मध्यप्रदेश में निकट भविष्य में अच्छे हाकी के खिलाड़ी सामने आएंगी, ऐसी मेरी आशा है. माननीय खेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि खेल एवं युवक कल्याण विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो खेल अकादमियां खोली गई हैं, चाहे वह हाकी की हो, क्रिकेट अकादमी हो, कुश्ती अकादमी हो, बैंडमिन्टन और तीरंदाजी की अकादमी हो, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ऐसी अनेकों अकादमियां संचालित हो रही हैं. मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले बजट में इंदौर में भी एक ऐसी अकादमी खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उसके लिए शायद अभी कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए हैं. मैं मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें. चूंकि इंदौर एक बड़ा संभागीय मुख्यालय है. इंदौर में भी

बहुत सारी खेल प्रतिभाएं हैं, जो इस खेल अकादमी की वजह से सामने आएंगीं. अध्यक्ष महोदय, माननीय खेल मंत्री महोदय को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्यप्रदेश में खेलों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, वह सराहनीय है. महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सशक्तीकरण के लिए महिलाएं जिस भी क्षेत्र में काम करती हैं, उस क्षेत्र में उनके शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के लिए जो वीरांगना योजना चलाई गई है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं. जिस प्रकार से मध्यप्रदेश के छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में ..

उपाध्यक्ष महोदय—राजेश जी दो मिनट में समाप्त करें.

श्री राजेश सोनकर—जी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा. मैं नया सदस्य हूं और पहली बार बोलने का प्रयास कर रहा हूं. वरिष्ठ सदस्यों का समय कम कर दीजिएगा.

उपाध्यक्ष महोदय—आप तीन मिनट में समाप्त करें.

श्री राजेश सोनकर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को जिस प्रकार से प्रोत्साहित करने का काम खेल विभाग कर रहा है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं आदरणीय खेल मंत्री महोदय से एक बात का और निवेदन करना चाहता हूं चूंकि मैं इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र से आया हूं और मेरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रेवती में पिछले दिनों खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा वहां स्टेडियम के लिए स्थल का चयन किया गया था, वहां के जिला प्रशासन की ओर से भी आवेदन दिया गया था, राजस्व मंत्री जी के पास भी शायद उसका आवदेन गया है. मैं राजस्व मंत्री महोदय और खेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यथाशीघ्र उस पर निर्णय लेकर हमारे रेवती गांव में स्टेडियम बनाने की कृपा करें. क्योंकि इंदौर एक ऐसा मुख्यालय है और रेवती गांव यह एक ऐसा स्थान है जो इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में आता है, जहां लाखों जनता निवास करती है. वहां पर कोई भी खेल का मैदान

नहीं है. वह इंदौर शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र हैं, जहां सांवेर तहसील, देपालपुर तहसील और इंदौर तहसील के भी बहुत छोटे छोटे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों का उसका लाभ मिल सकता है. वह एक ऐसा स्थान है कि अगर वहां प्रशिक्षण के लिए इंदौर जिले और उसके बाहर से भी खिलाड़ी आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं. अच्छे चिकित्सालय, अच्छे स्कूल, अच्छे डिग्री कालेज, प्रोफेशनल कालेज भी वहां उपलब्ध हैं. अगर वहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई स्पर्धाएं होती हैं तो उन स्पर्धा के खिलाड़ियों को रूकने,ठहरने और खाने के लिए वहां छोटे-बड़े अस्पताल हैं. वहां पर अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड और रेल्वे स्टेशन मात्र एक या दो किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाना प्रस्तावित है. एयरपोर्ट मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है. मैं यह कहना चाहता हूं यदि वहां पर स्टेडियम का निर्माण होता है तो वहां के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वह बहुत उपयुक्त स्थान होगा. इसके अलावा मेरा आखरी सुझाव उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो पायगा योजना है, 2014-15 में बंद होने वाली है, इसका नाम राजीव गांधी खेल योजना रखने का निर्णय हुआ है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पायगा योजना का नाम इस देश के किसी ऐसे महान खिलाड़ी के नाम पर रखा जाय, जिससे हमारी भावी पीढ़ी है, उनको प्रेरणा मिले. माननीय राजीव गांधी बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन खिलाड़ियों को उनके नाम से कोई प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मैं नहीं समझता हूं. ध्यानचंद जी हैं, सी.के.नायडू जैसे कई महान खिलाड़ी इस देश में पैदा हुए हैं, अगर उनके नाम से यह योजना रखी जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले खिलाड़ियों को उससे प्रेरणा मिलेगी. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद.

श्रीमती चंदा गौर (खरगापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11 के कटौती प्रस्ताव के संबंध में अपनी बात रख रही हूं. टीकमगढ़ जिले में रोजगार एवं उद्योग की बहुत कमी है,

जिससे युवा बेरोजगार परेशान हैं. रोजगार योजनाएं जो शासन द्वारा चलाई जा रही हैं. जिसमें खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने हेतु बैंक लोन देने के लिए सहमत नहीं होती है. ऐसी व्यवस्था कराई जाए, जिससे हितग्राहियों को लोन मिल सके और वह अपना रोजगार कर सकें.

2.04 बजे {अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में अहार लड़वाई क्षेत्र में गन्ने की फसल ज्यादा होती है. इसलिए मेरे उस अहार लड़वाई क्षेत्र में यदि लघु शक्कर मिल खोल दी जाएगी तो काफी बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा. अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखूंगी. पंचायत, क्रीड़ एवं खेल अभियान पायगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों के स्तर पर खेल कार्यक्रम कराए जाते हैं, उसमें खेल प्रभारियों द्वारा भारी अनियमितताएं की जाती हैं. खिलाड़यों को भोजन एवं आवागमन की कठिनाईयां उठाना पड़ती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं, जो प्रदेश से लेकर देश विदेशों में अपना नाम करती हैं. इसलिए मेरी विधानसभा में नगर बल्देवगढ़, नगर खरगापुर, नगरे पलेरा में स्टेडियम बनाए जाने हेतु माननीय मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा वास्तव में विकास में पीछे है, इसलिए आपके संरक्षण चाहते हुए मंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे यहां स्टेडियम की इस मांग एवं सुझाव को आवश्यक रूप से पूरा करें, साथ ही शासकीय भूमि पड़ी हैं, उसका भी ध्यान रखें. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद.

श्री के.के. श्रीवास्तव(टीकमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11,43 और 51 का समर्थन करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में खेल की दिशा में जितना अधिक कार्य हुआ है उतना इसके पूर्ववर्ती सरकारों के समय कभी नहीं हुआ. यहां पूर्व खेल मंत्री, वरिष्ठ सदस्य उन्होंने भी स्वीकार किया कि जितना बजट अभी है, बहुत

अच्छी बात है, इतना बजट तो कभी हमें मिला ही नहीं और जितना यहां खेलों के विज्ञापन पर खर्च हुआ उससे कम हमारा बजट हुआ करता था. इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों में खेलों के प्रति कहीं रुचि नहीं रही और यही कारण है कि खेलों में उस समय से जो दुर्गति हुई है, एक समय देश की यह स्थिति थी कि ओलम्पिक में हम क्वालीफाई नहीं कर पाये. हमें शर्मिन्दगी महसूस होती थी. आज मध्यप्रदेश में 17 एकेडिमियां खुली हैं, विभिन्न खेल के क्षेत्रों में हमने उत्कृष्ट प्रदर्शन किये हैं. रांची में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें हम 103 पदक लेकर के आये हैं . अध्यक्ष महोदय, एक आईएएस अधिकारी के घर में 300 करोड़ छापे में मिलता है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो भ्रष्ट अधिकारियों के यहां छापे डालकर के उनके घरों को राजसात कर जनहित में उनको समर्पित कर उन घरों में शैक्षणिक केन्द्र खोलने का प्रयास कर रही है,यह पहली मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. खेलों में हमने उत्कृष्ट उन्नति की है.हमारी सरकार हाकी के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न सुविधाएँ देकर के आगे लाने का प्रयास कर रही है. हमने मध्यप्रदेश राज्य हाकी एकेडमी बनायी, महिलाओं की हाकी एकेडमी हमने बनायी और दोनों एकेडमियों ने पूरे देश के अन्दर राष्ट्रीय स्तर पर खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अच्छा काम किया है. हाकी की नर्सरी के रुप में टीकमगढ़ को जाना जाता है .वरिष्ट सदस्य माननीय मुकेश जी नायक ने कहा, पहले जो टूर्नामेंट हुआ करते थे, आज उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ. यह परिस्थिति जो पहले समय में कटौती हुई है उसकी वजह से बनी है. एक समय दमोह में तमदनी स्मृति हाकी टूर्नामेंट हुआ करता था. टीकमगढ़ में अखिल भारतीय स्तर का वीरसिंह हाकी टूर्नामेंट 1956 से हम संचालित कर रहे हैं . पिछले दस वर्ष से मैं उसकी आयोजन समिति का सचिव हूँ. देश के 16 टूर्नामेंटों में इसकी गिनती आती है और वह टूर्नामेंट वहां होता है. हाकी का बी ग्रेड का टूर्नामेंट है. मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि देश में चार सबसे महत्वपूर्ण गोल्ड कप उस हुआ करते थे,यादवेन्द्र कप लखनऊ,सिंधिया गोल्ड कप ग्वालियर, बेटिन कप मुम्बई, और औब्दुल्ला कप, यह चार एक समय जो देश के महत्वपूर्ण हाकी के टूर्नामेंट हुआ करते थे, टीकमगढ़ की भगवंत क्लब ने इन चारों टूर्नामेंट पर अपना कब्जा किया था. टीकमगढ़ हाकी की नर्सरी के रुप में जाना जाता है. 92 वां हाकी टूर्नामेंट हृ हम लोगों ने पिछले वर्ष संचालित किया. लगभग 15 से 20 लाख रुपये हम लोगों को उसमें खर्च करना पड़ता है .हम लोग जनभागीदारी के माध्यम से धन इकट्ठा करते हैं . लेकिन अब समिति की परिस्थितियां नहीं है. अध्यक्ष महोदय, मैं यहां आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वहां केन्द्र सरकार में सांई सेंटर खोला हुआ है, वहां हाकी की नर्सरी, हाकी की कोचिंग चल रही हैं वहां बेसबाल की कोचिंग भी सांई सेंटर के माध्यम से संचालित हो रहा है.हमारे यहां के 6 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर हाकी में महत्वपूर्ण स्थान लेकर सम्मिलत हैं.मैं चाहता हूँ कि वहां पर जो सांई सेंटर है, अच्छी व्यवस्थाएँ हैं. माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि टीकमगढ़ के अन्दर एस्ट्रोटर्फ की व्यवस्था की जाए. हमने पिछले वर्ष अखिल भारतीय वीरसिंह हाकी टूर्नामेंट किया और वूमेंस हाकी टूर्नामेंट भी

स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर पिछले वर्ष आयोजित किया है.दोनों में लगभग ढाई-तीन लाख रुपये नगद पुरस्कार देते हैं इसलिए हाकी की दिशा में भी मध्यप्रदेश ने खूब काम किया है.

अध्यक्ष महोदय—क्षेत्र की समस्याएं एक मिनट में बता के कृपया बात समाप्त करें.

श्री के.के.श्रीवास्तव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि हमारे टीकमगढ़ में एस्ट्रोटर्फ बिछा दिया जाए, केन्द्र सरकार के अधीन वह सांई सेंटर में प्रक्रियाधीन है,थोड़ा प्रयास यहां से होगा तो वह हो जाएगा. दूसरा,हाकी में एक बहुत बड़ा नाम मेजर ध्यानचंद जी का है. टीकमगढ़ में उन्होंन् कोचिंग भी दी है.उनके भाई केप्टन रुपसिंह जी और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी उस हाकी के मैदान पर खेलने आये हैं . मेजर ध्यानचंद जी इस देश की वह शख्सियत हैं जिन्होंने विदेश में जाकर हिटलर के सामने भी, कहीं न कहीं उनको जादूगर कहा जाता है, सदन की तरफ से उनके लिए यह प्रस्ताव जाना चाहिए कि उनको भारत रत्न दिया जाए.मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि इस प्रस्ताव के लिए सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार के पास आवाज जानी चाहिएि कि उनको भारत रत्न मिले. माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल सामाजिक सरोकारों से संबंधित मामला है, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग ने भी निश्चित रुप से कहीं न कही बहुत काम किया है और हमारी सरकार ने बच्चे के आगमन से लेकर उसकी सारी चिन्ताएँ की हैं हमारे बुन्देलखण्ड में होन,व्यान, सौंठ,विश्वार, दादरे, पासरी, पढ़ाई, लिखाई, गणवेश, साइकिल, भोजन, विवाह-निकाह, प्रसवकाल की छुट्टियां यह सारी कुछ दी है और यहां तक जब बुढ़ापा हो जाता है तो उस समय तीर्थदर्शन की बहुत महत्वकांक्षी योजना दी है और मैं चाहता हूँ कि बहुत से गरीब क्षेत्रों में रहते हैं जो अपने पूर्वजों के अस्थि संस्कार के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए रीवा के आगे चाकघाट होकर के इलाहाबाद में प्रयाग तक नहीं पहुंच पाते, गरीब लोगों के अस्थि विसर्जन की भी चिन्ता अगर हमारा धर्मस्व विभाग कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि टीकमगढ़ पिछड़ा जिला है , हमारी भाभी जी चन्दा गौर जी भी यहां बोल रही थीं उन्होंने भी कहा है, मैं चाहता हूँ कि वहां पीतल की बहुत अच्छी कलाकारी होती है, विदेशों में भी उसकी प्रदर्शिनियां हुई हैं उसके बारे में ध्यान दिया जाए और टीकमगढ़ में मधुबन एक औद्योगिक क्षेत्र हैं जो अविकसित है उसको लिया जाए, 52 हेक्टेयर भूमि दी गई है केवल सीमांकन नहीं हुआ है, कलेक्टर द्वारा भूमि दे दी गई है उसको सम्मिलित करके शीघ्र उद्यमियों को बांट दिया जाए, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री आशीष शर्मा(खातेगांव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11,43 और 51 का समर्थन करता हूँ और आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि यह आज मध्यप्रदेश में परिलक्षित हो रहा है कि पिछले 10-15 वर्षों में जो खेल विभाग की अनदेखी हुई थी,आज मध्यप्रदेश में खेल का वातावरण निर्मित्त हुआ है और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं होती थी वे प्रतिभाएँ चाहे तैराकी के माध्यम से, चाहे तीरंदाजी के माध्यम से, चाहे कबड्डी, खो-खो अन्य तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो सरकार की विभाग की योजना है, युवा अभियान योजना उसके अंतर्गत यह प्रतिभाएँ पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, विकासखण्ड स्तर पर चयनित होकर आ रही हैं और इस मध्यप्रदेश के खेल विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके देश में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रही हैं. इस सरकार ने निश्चित तौर पर खेलों को आगे बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है. चाहे युवा अभियान योजना हो, चाहे बालिकाओं के लिए चूंकि आज हमें देखने में आ रहा है कि महिलाओं पर और बालिकाओं पर कई तरह के अपराध समाज में बढ़े हैं. इस विभाग ने जो वीरांगना योजना चलाई जिसमें दस वर्ष से अधिक की बालिकाओं को और युवतियों को प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा के गुढ़ सिखाकर उन्हें किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए

सक्षम किया जाता है. मैं खुद भी ऐसे एक-दो प्रशिक्षणों में गया हूं. वास्तव में बालिकाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने का काम विभाग कर रहा है यह बहुत सराहनीय योजना है ,इसे सभी जिलों एवं विकासखंडों में लागू करना चाहिए ताकि मध्यप्रदेश की बालिकायें आत्मनिर्भर हो सकें और अपनी आत्मरक्षा कर सके. मैं बताना चाहता हूं कि युवा अभियान के अंतर्गत जो खेल प्रतिभायें होती हैं उसमें पांच तरह के खेलों को शामिल किया गया है . मैं चाहता हूं कि इसमें फुटबाल औऱ खो-खो को भी स्थान दिया जाये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन खेलों में युवाओं की रुचि रहती है यदि आप इन दो खेलों को इसमें शामिल करेंगे तो इस अभियान में चार चांद लग जाएंगे. माँ तुझे प्रणाम इस तरह की योजना है जिसमें सरहद पर जाकर ,सरहद की परिस्थितियों को , सैनिकों की परिस्थितियों को युवाओं को दिखाने का काम किया जाता है इस योजना का अभी और विस्तार किया जाये और इसमें तहसील स्तर तक के युवाओं को भी सरहद पर जाने वाले अभियानों का हिस्सा बनाया जाये. साथ ही मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन माँग इस माध्यम से रखना चाहता हूं . हमारे क्षेत्र में नेमावर को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा हासिल है, वहाँ पर सोयाबीन औऱ कपास का प्रचुर उत्पादन होता है . मैं मंत्री महोदया से मांग करना चाहूंगा कि वहाँ पर कॉटन व सोयाबीन से जुड़े उद्योगों को लगाने में प्राथमिकता दी जाये .कन्नौद व खातेगांव दो बड़े सेंटर हैं . यहाँ पर कन्नौद में स्टेडियम बना हुआ है उसके विकास के लिए राशि आपके माध्यम से मिलना चाहिए और खातेगांव के स्टेडियम के लिए भी आपके द्वारा राशि मिलना चाहिए. नेमावर माँ नर्मदा का नाभिस्थल है यहाँ पर बाबा सिद्धनाथ का अति प्राचीन मंदिर है इस मंदिर के विकास के लिए आपके द्वारा कार्य होना चाहिए एवं नेमावर को पवित्र क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हो जाये तो बड़ा अच्छा होगा.

अध्यक्ष महोदय—कृपया समाप्त करें.

श्री आशीष शर्मा--- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर एक सतनगरी करके स्थान है जिसे बाबा जामवंत की प्राचीन गुफा के रूप में जाना जाता है उसके विकास के लिए भी अगर आपके द्वारा राशि घोषित की जाएगी तो अच्छा होगा और एक बात औऱ कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि देवास जिले में बागली और खातेगांव ऐसे क्षेत्र हैं , जहाँ पर बड़ी संख्या में वनवासी परिवार निवास करते हैं इसलिए तीरंदाजी की जो अकादमी जबलपुर में चल रही है उसका फीडर सेंटर यदि देवास में बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार(नीमच)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या के समर्थन में औऱ कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. मैं मुख्यमंत्री जी औऱ खेलमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि खेल को प्रोत्साहन देने के लिए आपने अनेक योजनायें बनाई एवं खिलाड़ी भाईयों ,बहनों को प्रोत्साहित करके एक अभिनव काम किया है. खेल के मैदान में हर कोई नहीं खेल सकता है जो खेल के मैदान में खेलता है , पसीना बहाता है, वह लोहे के चने चबाने का काम करता है और लोहे के चने हर कोई नहीं चबा सकता है इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग खिलाड़ी होते हैं वह बहुत आगे बढ़ते हैं . चाहे राजनीतिक ,सामाजिक या अन्य क्षेत्र में काम करते हों. हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कहीं न कहीं खेल के मैदान में जाना चाहिए . जो खेल के मैदान में जाते हैं उनमें स्पोर्टसमैन स्प्रिट पैदा होती है. न वह हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न गरीब होता है, न अमीर होता है. खेल के मैदान में खेलने वाले भाई औऱ बहन केवल खिलाड़ी होते हैं और खेल को प्रोत्साहन देने के लिए खेलमंत्री जी अनेक योजनायें बनाई हैं. माँ तुझे सलाम, माँ तुझे प्रणाम् यह जो योजना बनी है,इसमें हमारे भारत के आसपास से लगी हुई जो सीमा है उन सीमाओं के दर्शन करने का यदि अवसर किसी ने दिया है तो मध्यप्रदेश की सरकार और उनके खेलमंत्री जी ने दिया है. इस

योजना में 15 वर्ष से 35 वर्ष का युवा जब अपने सीमादर्शन के लिए जाता है और वहाँ जाकर सीमा की स्थिति देखता है कि किस प्रकार बंगलादेश है, किस प्रकार चीन है , किस प्रकार पाकिस्तान है और वहाँ की जमीन को जब वह प्रणाम् करके आता है तो उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न होती है . स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे "मेरे साहसी युवकों और युवतियों यह विश्वास रखो कि आप ही सब कुछ हो ,महान कार्य करने के लिए धरती पर आए हो , चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडर होकर खड़े हो जाना , सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी". आज मध्यप्रदेश में खिलाड़ी भाईयों के कदम सफलता चूम रही है और मध्यप्रदेश की सरकार उन्हें अनेक अवसर दे रही है. मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि अमित कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया. कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण रजत,कांस्य पदक हमारी मध्यप्रदेश सरकार के नेतृत्व में प्राप्त किये हैं. मैं उनको बधाई व शुभकामना देता हूं. हर गांव में सरकार ने खेल के मैदान सुरक्षित किये हैं . मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिलाधीश को यह निर्देश दें कि जहाँ भी बच्चे खेल के मैदान में स्कूलों में खेलते हैं अगर वहाँ अतिक्रमण है तो उसको अतिक्रमणमुक्त कराया जाये जिससे कि खेल के मैदान में बच्चे फुटबाल,हाकी ,क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि खेल खेले और मध्यप्रदेश का नाम रोशन कर सके. आज हम देखते हैं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा अनेक प्रतियोगिताये आयोजित कराई हैं. नीमच में उन प्रतियोगिताओं में मुझे भी जाने का अवसर मिला है . मुझे खेल से विशेष प्रेम है क्योंकि मैं भी प्रातः 4 बजे उठकर 24 वीं एथेलेटिक प्रतियोगिता में दौड़ा और अंतर विश्वविद्यालय तक मैंने फुटबाल रिप्रेजेन्ट किया इसलिए मैं जानता हूं कि खेल का कितना महत्व है. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो बालक और बालिकायें नेशनल खेलते हैं जो यूनिवर्सिटी अंतर विश्वविद्यालय खेलते हैं उन्हें कहीं न कहीं नौकरी में भी आप प्रोत्साहन दे.

अध्यक्ष महोदय , इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जीरन तहसील है वहाँ पर खेल का मैदान सुव्यवस्थित हो और वहाँ स्टेडियम को आप व्यवस्थित बनायें . युवक एवं खेल कल्याण विभाग ने 10 बीघा जमीन नीमच में अधिग्रहण की है वहाँ हाकी खेलने हेतु एस्ट्रोटर्फ बनाया जाये क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब खेल पंचायत बुलाई थी उस समय घोषणा की थी. अध्यक्ष महोदय, नीमच में 9 लड़कियाँ एम. पी. हाकी में खेली थी.

अध्यक्ष महोदय--- कृपया समाप्त करें.

श्री दिलीप सिंह परिहार--- उद्योग के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नीमच में औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण हो गये हैं . नये औद्योगिक क्षेत्र खोलने के लिए आप परमीशन दे . औद्योगिक कारीडोर का विस्तार नीमच में होने वाला है औऱ हमारे यहाँ जो सीसीआई सीमेन्ट फैक्टरी थी, वह वर्षों से बंद पड़ी है . कहीं न कहीं उसको प्राइवेट में देकर औऱ उसे पुनः प्रारंभ कराया जाये , इससे आपको दुआएं मिलेंगी औऱ कई लोगों को रोजगार मिलेगा.नीमच में लघु उद्योग हेतु कनावटी में बैरागी कालेज के पीछे एक जमीन पड़ी हुई थी,उस संबंध में बेरोजगारों ने आवेदन लगाये थे, आपके विभाग ने जमीन आवटंन भी की थी, यदि उसमें कहीं कोई कमी हो तो उसे आप विस्तार देकर पूरा करने का काम करें.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धर्मस्व विभाग के ब्ारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ माँ भादवा माता का मंदिर है ,बीस भुजा माता का मंदिर है , वहाँ कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति आता है उसको फायदा होता है, उसका मास्टरप्लान बना है तो आप वहाँ धार्मिक न्यास के द्वारा कुछ राशि देने का काम करें , पुजारियों का वेतन बढ़ाया क्योंकि वह भगवान के पास रहते हैं, अर्चक हैं. आपने जो मानसरोवर या अन्य यात्रायें देता हूं उसके लिए धन्यवाद देता हूं ,आपने उसमें 30 हजार का प्रावधान किया है. अध्यक्ष महोदय,आपने बोलने का अवसर दिया उसके धन्यवाद.

श्री सुखेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है.इतनी बड़ी घटना आज के पेपर में छपी है. यह सोचने की बात है, यह महत्वपूर्ण विषय है.

अध्यक्ष महोदय--- कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा.यह कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है. (समाचार पत्र दिखाये जाने पर) पेपर नहीं दिखा सकते हैं , रख दीजिये आप. यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है. किसी अन्य विषय के रूप में उठायें.

जितू पटवारी--- यह विषय पर ही है. मेरा अनुरोध है कि आज जिस तरह से सदस्यों के संज्ञान में आया है तीन चार दिन से हम देख रहे हैं कि पुलिस विभाग में जिस तरीके से चरित्र संबंधी मामले सामने आ रहे हैं.अगर सदस्य कोई बात कहना चाहता है तो मैं समझता हूं कि उसकी बात को सुना जाये.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, यह कोई बात नहीं है. किसी भी समय कोई बात नहीं की जा सकती है. अखबार में पढ़कर आप कोई भी प्रश्न उठा देते हैं. मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि कोई भी समाचार आया और आप पेपर दिखाकर कहेंगे कि मुझे यह मामला उठाना है तो यह बात ठीक नहीं है.

श्री के के श्रीवास्तव--- जितू भाई बजट पर चर्चा चल रही है.

अध्यक्ष महोदय--- श्रीमती ऊषा चौधरी का ही लिखा जाएगा.

श्री सुखेन्द्र सिंह-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- उनको बोलने दीजिये .

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया

श्रीमती ऊषा चौधरी(रैगांव)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11,43 और 51 का विरोध करती हूं और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करती हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग जगत में हमारा सतना जिला काफी आगे बढ़ा हुआ है लेकिन रैगांव विधानसभा में कोई भी

कुटीर उद्योग नहीं है और रोजगार के अभाव में हमारे क्षेत्र के लोग इस समय महाराष्ट्र,बिहार और गुजरात की ओर पलायन कर रहे हैं . इसलिए वहाँ पर ऐसा कुटीर उद्योग खोला जाए जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेल पर चर्चा करना चाहती हूं . हमारे सतना जिले में खेलकूद की व्यवस्था तो है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब तबके के खिलाड़ी हैं वे छोटे छोटे मैदानों में अपना खेल का मैदान बनाकर खेल की प्रतिभा को उजागर करते हैं. ऐसे लोगों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था नहीं है मैं चाहती हूँ कि हर विधान सभा क्षेत्र में विधायकों को किट की व्यवस्था की जाए, प्रतिवर्ष कम से कम 20 से 25 किट उनको दी जाए तो उन बच्चों की प्रतिभा उजागर हो. उनको सामग्री मिले तो खेल में वे आगे बढ़ सकें.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धर्मस्व के उसमें बोलना चाहती हूँ कि रतलाम जिले में एक जावरा विधान सभा है, जहाँ पर एक हुसैन बाबा की मजार है, वहाँ पर पूरे मध्यप्रदेश से मानसिक रूप से बीमार लोग दुआ के लिए आते हैं और काफी समय तक वहाँ पर पड़े रहते हैं तथा उनके परिवार के लोग कभी कभी तो सालों उनको छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर वहाँ मेमोरी हॉस्पिटल बनवा दिया जाए ताकि दुआ के साथ उनकी दवा भी हो सके और उनका रखरखाव हो सके.

अध्यक्ष महोदय, सतना जिले में एक भरहूत पहाड़ है, जहाँ पर पुरातत्व, वहाँ पर काफी कीमती मूर्तियाँ निकाल कर विदेशों में बेच दी गई और वहाँ का रखरखाव नहीं है, अगर उस भरहूत पहाड़ में बौद्ध स्थली का स्थान बना दिया जाए तो वहाँ की जो खनिज संपदा है, जो मूर्तियाँ हैं उनकी सुरक्षा हो सकेगी.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री रामेश्वर शर्मा(हुजूर)-- (माननीय सदस्य श्री मुकेश नायक जी के अपने आसन से उठकर बाहर जाने पर) मुकेश नायक जी, आइये, आइये. बैठा लें साहब, इन्होंने बहुत तारीफ की थी. अब मुझे कुछ तारीफ करनी है आइये. (श्री मुकेश नायक अपने आसन पर आकर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय-- श्री रामेश्वर शर्मा कृपया अपनी बात प्रारंभ करें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- बड़ी मित्रता है मुकेश जी की और रामेश्वर शर्मा जी की... (व्यवधान)..

श्री रामेश्वर शर्मा-- बिल्कुल मित्रता है,..(व्यवधान)..और दिग्विजय सिंह जी को भी पता थी हमारी दोस्ती.

अध्यक्ष महोदय-- आप अपनी बात करें.

श्री रामेश्वर शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं मध्यप्रदेश सरकार की मांग संख्या 11, 43 एवं 51 के समर्थन एवं कटौती प्रस्तावों के विरोध में कुछ अपनी बात कहना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय, अभी जैसी कि चर्चा चल रही थी माननीय मुकेश नायक जी ने बताया कि वर्ष 2004 का जो बजट था, आज उतना विज्ञापन का बजट है. उस समय सही है कि इनका बजट 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में था, आज 174 करोड़ रुपये का बजट है. उस समय यह भी सही था कि मध्यप्रदेश में एक टीटी नगर स्टेडियम था. आज लगभग 95 स्टेडियम हैं. उस समय यह भी था कि उस समय दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे. आज मध्यप्रदेश में 117 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं. (मेजों की थपथपाहट) उस समय यह भी सही था कि इन्होंने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश में हमने खेल को कितना प्रोत्साहन दिया, क्या दिया भाई मुकेश नायक जी, जब आपने खेल युवा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय आए तात्या टोपे जो भारत की सेनानी संपदा

है, जिसने आजादी के लिए संघर्ष किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. उस समय मुकेश नायक जी ने तात्या टोपे स्टेडियम का नाम बदल करके राजीव गाँधी रख दिया, मैं उस समय पार्षद था, मैंने उसका विरोध किया और स्वयं श्रीमती सोनिया गाँधी जी ने मुझे चिट्ठी लिखी, माफी मांगी और तात्या टोपे स्टेडियम का नाम परिवर्तित किया गया. (मेजों की थपथपाहट) यह उस समय खेल था. उस समय खेल पर यह राजनीति हो रही थी. मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने बोट क्लब का भी उल्लेख किया. अध्यक्ष महोदय, जब बोट क्लब बनकर तैयार हो रहा था, मध्यप्रदेश की सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही थी. दिल्ली की सरकार उस समय, सुश्री उमा भारती, मध्यप्रदेश में खेल के कईं स्थान लाना चाहती थी. तब वह बोट क्लब का निर्माण हुआ. आपको मालूम है, आप शायद मंत्री भी थे, उस समय मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने जाकर उस बोट क्लब को तोड़ा गया, क्या यह खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का आपका काम था? उस समय हमने विरोध किया और वह केन्द्र सरकार की राशि थी फिर बाद में 2005 में खेल प्रतिभाओं का सम्मान, तो यह कहते हैं कि 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका निर्माण किया और बोट क्लब को हमने फिर से चालू किया, यह है खेल प्रतिभाओं का सम्मान, यह है खेलों का काम. हम खेल में राजनीति नहीं करना चाहते. पहले आप खेल में राजनीति करते थे. अब हम खिलाड़ियों को स्वतंत्र रूप से खेलने का सुअवसर देते हैं और वह खेलते हैं. पहले खिलाड़ी अगर खेलने जाए तो उन्हें बिना आरक्षण के, उनको जनरल बोगी में घुसेड़ दिया जाता था, जाओ बैठो, दिल्ली उतर जाओ, कोई लेने आएगा, कहो तो जैसे मालगाड़ी में बिठा दिया, वैसे वहाँ पर सब्जी भाजी लेने आने वाला ट्रक में उनको बिठाकर स्थान पर छोड़ दिया जाता था. आज हम खिलाड़ियों का आरक्षण करते हैं, उनको बिठाते हैं और सुविधा से हमारे अधिकारी उनके साथ जाते हैं. मैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, हमारी मंत्री महोदया को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ (मेजों की थपथपाहट) कि खेल प्रतिभाओं को जो निखारने का काम किया है, मध्यप्रदेश के

खिलाड़ी, खेल में भी पुरस्कार लेकर आएँगे, मध्यप्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम भी कमाएँगे और मध्यप्रदेश के खिलाड़ी, मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं में भी जाएँगे. यह अवसर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया. आप कह रहे हैं हमने सीधे खिलाड़ियों का चयन किया. कौनसा चयन किया, 98 में किसकी सरकार थी, उसको आपने बंद किया है, जबकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी और मंत्री महोदया के नेतृत्व में आज हमने उसको ओपन किया अब खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, वह भी सरकारी सेवाओं में जा सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश की राजधानी में हमारे यहाँ एक टीटी नगर स्टेडियम है और एक छोटा स्टेडियम हम बॉबे अली ले सकते हैं, एक अगर छोटा और स्टेडियम ले लें तो हम ऐशबाग स्टेडियम ले लेते हैं. लेकिन भोपाल में क्रिकेट का कोई स्टेडियम नहीं है. माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा है, बरखेड़ा नाथू में अगर क्रिकेट का एक स्टेडियम बनाया जाए, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ. मैं महेन्द्र सिंह जी कालूखेड़ा की एक बात का समर्थन करना चाहता हूँ कि आज गाँव का हम विस्तार करना चाहते हैं, गाँव की प्रतिभाओं में भी हम हों, हम गाँव में पैदा हुए, गाँव से पैदा होते हुए, लड़ते लड़ते आज इस स्थान पर आए हैं. मैं चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश के गाँव के मैदान में जो बच्चा पैदा हो रहा है, वह भी बंबई की पिच पर जाकर खड़ा हो और पाकिस्तान के खिलाफ छक्का लगाकर हिन्दुस्तान का पुरस्कार ले. (मेजों की थपथपाहट) लेकिन आज उसको खेलने के लिए मैदान नहीं है. वहाँ जो खेल मैदान, हमारे रजिस्टर में तो वे अंकित हैं लेकिन उन पर अतिक्रमण है. यह सदन निवेदन करना चाहता है कि प्रत्येक गाँव में कम से कम ढाई एकड़ से पाँच एकड़ के बीच में भूमि आरक्षित हो. वहाँ के खिलाड़ियों को मौका मिले. वहीं पर स्पोर्ट क्लब मिले.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्री रामेश्वर शर्मा-- जैसा आप बोलें.

अध्यक्ष महोदय-- एकाध दो मिनिट में समाप्त कर दें.

श्री रामेश्वर शर्मा-- एकाध दो मिनिट मतलब आप मिनिटों को, उधर उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे उन्होंने कहा 14 मिनिट का समय दिया है और 23 मिनिट हो चुके हैं. तब माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा था. आप जैसा कहें.

अध्यक्ष महोदय-- और भी विभाग हैं...

श्री रामेश्वर शर्मा-- मैं तो उस पर बोल रहा हूँ मैंने जो नाम लिया है इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ..

अध्यक्ष महोदय-- आप कितना समय लेंगे.

श्री रामेश्वर शर्मा-- अध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी कृपा पर है.

अध्यक्ष महोदय-- 2-3 मिनिट में समाप्त कर दीजिए.

श्री रामेश्वर शर्मा-- आप जितना दें. अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश की राजधानी को हम विकसित करना चाहते हैं. हम ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को भी निखारना चाहते हैं तो गाँवों में खेल के मैदान भी तैयार किए जाएँ, उनको भी खेलने के सुअवसर प्रदान किए जाएँ और इसके लिए एक संयुक्त टीम बनाई जाए, जिसमें राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और खेल विभाग, इन तीन विभागों की संयुक्त टीम वहाँ पर काम करे. हर गाँव में जब तक खेल मैदान आरक्षित नहीं होगा तब तक गाँव के नौजवान का विकास नहीं होगा क्योंकि खेलों की जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, जो हमारे गाँव के नाम पर, खेलने आ जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी कभी उसमें भी शहर के लड़के गाँव के नाम पर प्रमाण पत्र लेकर खेलने आते हैं, वह ठीक नहीं है इसलिए गाँव की खेल की प्रतिभाओं को निखार दिया जाए. उनको भी खेलने के सुअवसर दिए जाएँ. मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है यहाँ पर मैंने लगभग 62 गाँवों

में खेल मैदान तैयार करवाए हैं. खेल मैदानों के लिए जमीन आरक्षित करवाई है. मैं माननीय मंत्री महोदया से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उन गाँवो में भी खेल के मैदान तैयार किए जाएँ, वहाँ भी खिलाड़ी खेलकर आगे बढ़े. मध्यप्रदेश का नाम रोशन करेगा क्योंकि मध्यप्रदेश में जिस तरह खिलाड़ियों और युवाओं को तरजीह दी है, यह मध्यप्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी है. हमने जब दिल्ली में श्रीमान् अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार थी, तो अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार में भोपाल के अन्दर साई स्पोर्ट क्लब का सौ एकड़ भूमि पर अगर निर्माण किया है तो वह भी भारतीय जनता पार्टी की देन है जो राजधानी में आज है. (मेजों की थपथपाहट) यहाँ पर एक नहीं, तीन तीन बड़े बड़े नेश्नल खेल होते हैं. जहाँ पर हजारों बच्चों का प्रशिक्षण होता है इसलिए खेल के मामले में हम राजनीति नहीं करना चाहते. हम खिलाड़ियों को खेलने का सुअवसर पैदा करना चाहते हैं और इसमें हमें सबका सहयोग भी चाहिए. हम खिलाड़ियों को सहयोग भी करें. जगह जगह उनको, हमारा स्वेच्छा अनुदान निधि है. उस अनुदान निधि में हम कुछ राशि खिलाड़ियों को, गाँवों की टीमों को दें. जिससे गाँवों की टीमों पर किट मिल सके. उन बच्चों को भी खेलने का सुअवसर प्राप्त हो सके. मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ कि जिस तरह दर्शनों की यहाँ पर बात हुई, हमने विचार नहीं किया था, लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी की सरकार पर कहते हैं, एक दल के अध्यक्ष कहते थे कि अब तो दल में भी फूल छाप काँग्रेसी हो गए हैं, यह बात आती थी. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि दल में नहीं दिल में फूल छाप काँग्रेसी हो गए (मेजों की थपथपाहट) जो बुजुर्ग माँ बाप वर्षो से बेटे की प्रतीक्षा करते थे, धन के अभाव में जीते थे या बेटे के समय के अभाव में जीते थे शिवराज सिंह जी चौहान ने भी उनको सरकारी खर्चे से तीर्थ दर्शन करा दिये हैं इसलिये बुजुर्ग मां-बाप ने भी दिल से शिवराज जी को आशीर्वाद दे दिया है और इसलिये वह योजना सफल हो गई और घर-घर में शिवराज जी को आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो गया है. हिन्दुस्तान की आजादी में सिंधु दर्शन का भी बहुत बड़ा उल्लेख है हम लैह, लद्दाख और

बाबा अमरनाथ की गुफाओं तक जाते हैं तो इसमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसलिये सिंधु दर्शन भी इस यात्रा में जोड़ा जाये यह मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ क्योंकि हजारों लोग सिंधु दर्शन करना चाहते हैं. सिंधु दर्शन को जायेंगे वहां पर भी भारत की एकता अखंडता के बारे में विचार करेंगे. एक और प्रार्थना करना चाहता हूं जो पुजारियों को जो वेतन है वह कम है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिये, मंदिरों को सुव्यवस्थित करने के लिये विशेष पैकेज चलाये जायें और कुछ मंदिर जो पर्यटन विकास के अधीन लिये गये हैं ऐसे और भी बड़े-बड़े स्थान हैं जिनको विकास की योजना में जोड़ सकते हैं. हमारी सरकार न तो खेल में राजनीति करना चाहती है, न धर्म में राजनीति करना चाहती है बल्कि हमारी सरकार मध्यप्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिये काम करना चाहती है और उज्जवल भविष्य के काम के लिये आप सबका जो सहयोग मिलता है और नौजवान जब मैदान में दौड़ता है जब वह मैदान जीतकर आता है जब वह मैदान में स्वर्ण पदक लेकर आता है तो वह भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता नहीं होता है वह किसी दल का नेता कार्यकर्ता नहीं होता है बल्कि वह मध्यप्रदेश की धरती का बेटा होता है उसको पुरस्कार मिलता है तो पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है इसलिये प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिये प्रदेश को ताकतवर बनाने के लिये प्रदेश के नौजवान को हिम्मत देने के लिये हम सब को नौजवानों के साथ खड़े होना चाहिये. जो योजना मंत्री महोदय ने रखी है मैं उसका समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी योजनाओं में हमें और सहयोग करना चाहिये और अधिक से अधिक नौजवानों को खेलने का मौका मिले. धन्यवाद.

श्री सुखेन्द्र सिंह – अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर.

अध्यक्ष महोदय—नहीं कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है. समय नहीं है.

श्री सुखेन्द्र सिंह – अध्यक्ष महोदय, इनफॉरमेशन है. यह पेपर में इतनी बड़ी खबर छपी है. इस पर थोड़ा सा आप गौर करें.

अध्यक्ष महोदय—यह रिकार्ड में नहीं आयेगा..

श्री सुखेन्द्र सिंह—(XXX)

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जावरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है. वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार, खेल एवं युवक कल्याण, धार्मिक न्यास...

अध्यक्ष महोदय—यह अखबार आप सदन में नहीं पढ़ सकते हैं, कृपया करके कोई वरिष्ठ सदस्य उन्हें समझायें वे अखबार पढ़ रहे हैं. माइक से अखबार पढ़ रहे हैं यह क्या ठीक बात है. आप बैठ जाइये, सदन की नियम-प्रक्रियायें समझिये.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम खेल में राजनीति नहीं करना चाहते और राजनीति में खेल नहीं करना चाहते हैं इसीलिये आज तक जो खिलाड़ियों के लिये नहीं हो पाया है वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में हुआ है. यह एक सुखद संयोग है कि सम्माननीय मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी के कुशल नेतृत्व में खेल एवं युवक कल्याण विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश भर में कार्य किये गये हैं वे विगत वर्षों में नहीं हो पाये हैं न विगत शासनकाल में हो पाये. माननीय मुकेश नायक जी ने यहां पर व्यक्त किया था कि आपके समय जो विज्ञापन लगाये जा रहे हैं उतना भी बजट उनके समय नहीं हुआ करता था. यह उनके लिये दुर्भाग्य की बात है और हमारे लिये सौभाग्य की बात है कि आज लगातार बजट बढ़ने के साथ साथ खेल गतिविधियों का क्रियान्वयन भी मध्यप्रदेश में होने लगा है.

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर प्रदेश स्तर तक छोटे खेल मैदान से लेकर स्टेडियम तक के बारे में चर्चायें की गई हैं. जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय व अन्तरार्ष्ट्रीय प्रतियोगिताओं

में मध्यप्रदेश के खिलाड़ी भाग लेने लगे हैं. हॉकी की टीम जर्मनी में जाकर न केवल मध्यप्रदेश का नाम रोशन करती है वरन पूरे देश भर को गौरवान्वित करती है.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय, यह भी एक सुखद संयोग है कि उस हॉकी की महिला टीम में 6 खिलाड़ी तो माननीय मंत्री महोदय के यहां से ही अर्थात् ग्वालियर से थीं. खेल प्रतिभाओं को और अधिक प्रोत्साहित किया जाये. जितना बजट रखा गया है उस बजट के माध्यम से जो संभावना है वह थोड़ी कम महसूस होती है इस बजट को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है. ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान के बारे में जो नीति आयी है जब तक ग्रामीण क्षेत्र में भूमि को चिह्नित नहीं किया जाता वहां पर चारागाह की भूमियां भी समाप्त सी हो रही हैं उन भूमियों को चिह्नित करते हुए भाई रामेश्वर शर्मा जी ने अच्छा सुझाव दिया है कि राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और खेल विभाग एक संयुक्त नीति समन्वय के माध्यम से बनाये. खेल की बात आती है तो हमें अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब हम पढ़ने जाया करते थे उस समय हमारे शिक्षक स्कूलों में कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी खिलाया करते थे. टेबिल टेनिस और बेडमिंटन की वहां व्यवस्था हुआ करती थी. खेल मैदानों को चिह्नित करने के लिये एक समन्वय की नीति बनाते हुए कुछ ऐसी कार्य योजना निश्चित की जाये ताकि प्रत्येक विकासखंड के अन्तर्गत आऩे वाली ग्राम पंचायत मुख्यालयों के साथ ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल मैदानों को निश्चित किया जाये. मेरे जावरा विधान सभा क्षेत्र में लगातार स्वीमिंग पूल की मांग की जाती रही है यदि वहां स्वीमिंग पूल प्रदान किया जाता है तो हमारे क्षेत्र को वह सुविधा मिल सकेगी. साथ ही एक स्टेडियम की मांग भी की जाती रही है. शासकीय महाविद्यालय का जो बड़ा खेल मैदान है जैसे अभी मैंने समन्वय की बात की है तात्कालिक समय में मैं वहां जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष था वहां से हमने प्रस्ताव भिजवाया था तब खेल विभाग ने संभवत: उसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी लेकिन यह कहा गया था कि

शिक्षा विभाग उस भूमि को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करे तब जाकर के खेल विभाग के द्वारा वहां पर राशि दी जा सकती है तब वहां स्टेडियम बनाया जा सकता है. मेरा निवेदन है कि शासन एक है शासकीय व्यवस्था एक है मंत्रिमंडल में बैठकर नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है. सामान्य सी बात है भूमि कहीं उड़कर नहीं चली जायेगी. मेरा निवेदन है कि या तो शासकीय महाविद्यालय में स्टेडियम की स्थापना की जाये या हायर सेकेण्डरी स्कूल का भी एक बड़ा खेल मैदान है वहां पर भी यह कार्यवाही की जा सकती है.

अध्यक्ष महोदय, ब्यावरा शुगर मिल विगत कई वर्षों से बंद पड़ी है. वहां पर शासन के द्वारा सहकारी समिति बना दी गई थी. सहकारी समिति ने भी उसे चलाने की कोशिश की. सहकारी समिति के माध्यम से अंश पूंजी इकट्ठी की गई, दुग्ध समिति के माध्यम से अंश पूंजी इकट्ठी की गई. अभी संयोग से महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा जी भी सदन में उपस्थित हैं. काफी प्रयास किये थे लेकिन वह मिल प्रारंभ नहीं हो पायी. यही स्थिति महिदपुर की शुगर मिल की भी है, यही स्थिति बलौदा शुगर मिल की भी है. निवेदन यह है कि उद्योग विभाग उसे अपने अधीन ले ले सहकारी समिति का परिसमापन करते हुए उद्योग विभाग उस शुगर मिल को प्राप्त कर ले. शुगर मिल और शुगर मिल में जो मशीन है उसका उपयोग किया जाये देख लें.

अध्यक्ष महोदय—आपने अपना सुझाव दे दिया, अब आप बैठ जायें.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे लगी हुई जो भूमियां हैं उन भूमियों को भी औद्योगिक क्षेत्र में लिया जाये उद्योग विभाग के अन्तर्गत लिया जाये और लघु और कुटीर उद्योग लगाये जाने के लिए उन भूमियों का उपयोग किया जाये. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- माननीय मंत्री जी ।

वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार मंत्री(श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया):- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि यह बहस 12.15 बजे शुरू हुई और अभी पौने तीन बज गये हैं । मैं चाहती हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने आज इस सदन में तीनों विभागों के ऊपर बोले हैं उनको मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूं तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद हमारा जो उद्योग विभाग है वह थोड़ा सा बड़ा विभाग है, उसके लिये भी थोड़ा सा समय दें तो कृपा होगी और जितना खेल में रूचि पूरा सदन रखता है अगर उसके लिये भी थोड़ा सा समय मिल जाये तो हम लोग आपके आभारी रहेंगे। रहा धर्मस्व विभाग तो उसके लिये भी थोड़ा सा समय दिया जाये। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति उसी से ही जुड़ी है।

अध्यक्ष महोदय:- आपसे अनुरोध है कि सभी सदस्यों की भावनाओं को समाहित करते हुए जितने संक्षेप में बोल सकती हैं उसको करें।

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:- आपके माध्यम से चर्चा में 20 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। इसमें हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा जी ने अपने बजट भाषण में बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपने तीनों विभागों को चर्चा में लिया था, मैं आपकी आभारी हूं कि जिस तरह से आपने धर्मस्व की बात करी मंदिरों और ट्रस्टों की, भूमि की बात करी, उनके देखरेख की बात करी, पुजारियों का सम्मान रहे उसकी बात कही, यही वजह है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि मैं इस विभाग में काम करना चाहती हूं। क्योंकि थोड़ा सा पुण्य भी मिलेगा, परन्तु जो काम हमें इस विभाग में करना है उस काम की शुरूआत ही नहीं हुई, अभी 6 महीने हो गये हैं और हमें आगे जाकर साढ़े चार साल में बहुत काम करना है। माननीय सदस्य ने पवित्र नगर की बात भी करी थी इसमें में रूचि लेकर जरूर आपको इसके ऊपर एक चिट्ठी लिखने वाली हूं, ताकि हम जो भी पवित्र नगर की घोषणा करते हैं, उस पर हम अमल करें । हिंग्वागर मंदिर मंदसौर में आपने कुछ इसके ऊपर जिक्र किया था, इस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। आपने एक और अच्छा सुझाव दिया

था कि अंकोरवाठ में जरूर सदस्यों को भेजा जाए। हम लोग पुराने दिनों में ट्रिप्स करते थे, माननीय आप भी तब हमारे साथ एक सम्माननीय विधायक थे, हम लोग बाहर जाते थे और मैं समझती हूं कि आपने जो कहा जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट के लिये आज हम विदेश जाते है निवेशकों से मिलने, उसमें भी मैंने सुझाव दिया अपने विभाग को दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि हम अपने विधान सभा से उसमें एक दो सदस्यों को भी लिया जाए, जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट में निवेशकों के पास जाते हैं। इसमें हम सिर्फ हालीडे करने के लिये नहीं जा रहे हैं। अंकोरवाठ का जो सुझाव माननीय महेन्द्र सिंह जी ने दिया है वो जरूर ली जायेगी। आपने गुना स्टेडियम की भी बात कही मैंने आपसे विशेष इस पर बात की है। आपने कहा था कि खेल में राजनीति नहीं होना चाहिये। मैं समझती हूं कि सबसे ज्यादा राजनीति खेल एसोसिएशन्स में ही होती है। इसमें सारे लोग आज पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जगत से ही अध्यक्ष विराजमान हैं। महेन्द्र सिंह जी व्यक्तिगत रूप से बात इस सदन में नहीं करना चाहिये, मैं चौदह महीने खेल विभाग की मंत्री थी तब मैं किसी भी एसोसिएशन की अध्यक्ष बन सकती थी, पर मैं नहीं बनी मैं चाहती थी कि मैं एक रोल मॉडल की तरह पूरे प्रदेश को बताना चाहती थी कि पालिटिक्स हमें छोड़ना चाहिये और जो पॉलिटिकल व्यक्ति है उसको भी अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहिये। पालिटिक्स और पालिटिकल लोगों को एसोसिएशन्स में रहना नहीं चाहिये। इसमें अपने आप सुधार आ जायेगा।

आपने उद्योग में कहा कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो बजट, नो बिजली आर्थिक सर्वे में कई इंडिकेटर्स आ रहे हैं। मैं 6 महीने से इस विभाग की मंत्री हूं, मैं समझती हूं कि जिस तरह से मेरे विभाग के अधिकारियों ने पिछले दो तीन साल से ताबड़तोड़ तरीके से काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय है, मैं आज उनका एक अंग हूं। जैसे मैं आज मदद आप लोगों से चाहती हूं तो मैं अलग हटकर नहीं चाह रही हूं। मैं अपने मध्यप्रदेश के लिये, इंडस्ट्री के लिये कुछ चाह रही हूं ताकि इस मध्यप्रदेश में हम रोजगार और बेहतरीन तरीके से लायें। आपने एक अच्छा सुझाव दिया जो जिनिंग

फैक्ट्रीस् हैं, उनकी लिस्ट लें और उन लिस्टों में से जो फैक्ट्री भू-माफिया आपरेट करता है, उसको मैं जरूर करूंगी, मैं अपने विभाग के अधिकारियों से जरूर पूछूंगी उन जिनिंग के बारे में । मध्यप्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसलिये समय लगता है हर चीज को देखने के लिये, डॉ मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के बारे में बात कही थी और मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी बात कही थी और अपना जो संस्कारित इतिहास है उसकी भी बात कहीं थी, उसमें अंकुरवाठ की बात भी कही थी। उसमें एक बात और अच्छी चीज जोड़ी कि जो पाकिस्तान में जो हिंग्लाज माता का मंदिर है और ननकॉना साहेब है उसकी लिये भी हम लोग प्रयासरत हों और इसके लिये भी हम अपने लोगों को वहां भेज सकते हैं तो उसकी भी परमीशन हो जाये। बंद हुई मिलों के मजदूरों के पेंशन की बात हुई और यह जो प्रकरण लिक्वडेशन और बीआईएफआर में प्रचलित है इसीलिये हम इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पायेंगे। हमारे बहुत ही समाजसेवी मुकेश नायक जी यहां नहीं हैं उन्होंने जिस तरह से आज खेल विभाग को क्रिटिसाईज किया. मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शुरुआत में उनको एकनालेज करने वाली थी कि टी.टी.नगर स्टे स्टेडियम विक्रम वर्मा जी और उन्हीं की देन है. पर जिस तरह से आक्रोष की तरह उन्होंने अपना प्रजेंटेशन दिया मैं थोड़ी सी दुखी हूं क्योंकि आप आज होर्डिंग्स की बात करते हो आज बच्चे अपनी वजह से गोल्ड मेडल लाकर हमने तो प्रोत्साहन दिया पर जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई एक स्पोर्ट्समेन की तरह से क्या हम उनको धन्यवाद नहीं दे सकते. क्या हम उनको प्रोत्साहन नहीं दे सकते. क्या उनको पसंद नहीं आएगा कि पूरे भोपाल में जो अपना केपीटल है वहां एक उनकी अलग से होर्डिंग लगी है जो लोग कह सकते हैं कि हां बेटा तुमने बहुत बढ़िया किया साउथ अफ्रीका में. इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड लेकर आए. हमारी सबजूनियर्स हाकी की बच्चियां सिर्फ 12-13 साल की हैं आज उनको हम प्रोत्साहन देने के लिये होर्डिंग्स लगाते हैं कि आज नेशनल चैंपियन हो आप. सबजूनियर्स नेशनल चैंपियन हो और आपने एक बार नहीं सबजूनियर्स नेशनल नहीं जीता वरन् कई बार जीता.

माननीय मुकेश नायक जी अब पधारे हैं वह तो एक समाजसेवी का ऐसा वक्त था जहां मुकेश नायक जी एम.एल.ए. नहीं थे मंत्री नहीं थे. हम लोगों को कहा जाता था कि वे धार्मिक चीजों में बहुत रुचि लेते हैं और कथा वाचन करते हैं तो मैंने सोचा कि आज जो शब्द निकलेंगे वह बहुत अच्छे प्रोत्साहित शब्द निकलेंगे क्योंकि धार्मिक चीज में अगर हम देखते हैं तो कभी हम कटाक्ष नहीं करते. हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं हम मंत्री की बातनहीं कर रहे हैं हम विभाग की बात नहीं कर रहे हैं. उनके समय में टी.टी.नगर स्टेडियम स्थापित हुआ मैं वहां दौड़ने के लिये जाती हूं और मैं देखती हूं कि उन्होंने जो आज स्थापना की है उसी की नींव से इतनी चीजें बाहर निकली हैं. मैं एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी हूं मुकेश जी, पर जिस तरह से आपकी आज की प्रस्तुति थी मुझे बड़ा दुख है क्योंकि जो मैंने अपने पहले के कार्यकाल में और जो आज मेरे बच्चों को प्रोत्साहित किया है उसी आधार पर मैंने यह सोचा कि आज क्रिकेट पूरे देश में है परंतु आज हमें लेना चाहिये ऐसा इंडियन खेल जिसे हम प्रोत्साहित करें इसीलिये हमने हाकी की खेल अकादमी शुरू की. हमने महिला अकादमी शुरू की और आप देखों को 2007 में वह शुरु की. कितना समय लगता है साई को अपना काम करने के लिये पर आपकी जो महिला हाकी अकादमी ने सिर्फ 6 साल में ऐसी ख्याति प्राप्त की कि जहां जूनियर वर्ल्ड कप में 34 ईयर्स में हमने कभी कोई मेडल नहीं जीता आज हमारी 6 बच्चियां उस टीम में थीं जो मेडल लेकर आईं उस जूनियर वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में, तो आपको तो हमें धन्यवाद देना चाहिये. माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिये कि 6 साल में हमने इतना काम किया कि सबजूनियर्स में भी जीत रहे हैं, जूनियर्स में भी जीत रहे हैं, सीनियर्स में भी जीत रहे हैं. मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि दुख की बात आएगी पर एक और चीज माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी इस पूरे विधान सभा सदन में कि हम अपने गरीब बच्चों की तरफ भी देख रहे हैं. हमारे शूटिंग अकादमी में एक मनीषा कीर है, मैं कई बार उससे मिली हूं. जब मैंने उससे पूछा कि बेटी तुमने शूटिंग कैसे ली ? वह बोली मेरे पास में है. मैंने कहा मेरे पास

मतलब, गोरा गांव में मैं रहती हूं माननीय मंत्री और उस गोरा गांव में मेरे पिताजी मछली पकड़कर अपना जीवनयापन करते हैं. मेरे आज 5 बहन हैं और 3 भाई हैं. मतलब 8 सदस्य तो वही हो गये और आज हमने उसको इतना प्रोत्साहित किया है कि वह नेशनल गोल्ड मेडल विनर है. वाटर स्पोर्ट्स की मुकेश नायक जी बात करते हैं. उन्हीं के टाईम में सारी चीजें तोड़ कर चली गईं. आज हमारी नेवी चीफ को जब मैंने फोन किया कि आज हमें रोजगार देना है नेवी में. आपके माध्यम से हम वाटर स्पोर्ट्स अकादमी खोलना चाहते हैं एक लक्ष्य से और वह टारगेट है कि हम अपने बच्चों को पानी की पसंदगी करें,पानी में वह तैरें,पानी में वह अपना काम करें ताकि नेवी में जाकर अपना रोजगार लें. उनने कहा कि कितना अच्छा आईडिया है. तब हमने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की. अब वह बात करते हैं कयाकिंग,केनोईंग की, पर उनको शायद जानकारी नहीं है कि कितने गोल्ड मैडल्स, कितने सिल्वर मैडल्स और कितने नेवी की टीमों को हमारे बच्चों ने बीट किया है. हमारे बच्चों ने उनको पार करते हुए गोल्ड मैडल और सिल्वर मैडल जीते हैं. यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की. श्री दिलीप सिंह शेखावत जी ने अपनी स्पीच में मोटीवेशन की बात की. मैं दिलीप सिंह जी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि वही मैं सिखा रही थी कि मोटीवेशन की ही बात है हमारे बच्चों के लिये, अगर हम मोटीवेशन नहीं देंगे तो वह कैसे आगे बढ़ेंगे. हम भी पैरेंट्स हैं. हमारे भी बाल-बच्चे हैं. हम कैसे उनको अपनी शिक्षा में मोटीवेट करते हैं तो आज हम खेल में भी हम मोटीवेट करना चाहते हैं. थैंक्यू दिलीप सिंह जी, आपने बहुत अच्छा कहा. आपने केल मैदान,खाचरौद में ग्राउण्डण्डे डेव्लहप करवाने के लिये कहा है. हम जरूर इसमें देख लेंगे. मैं नीति पर भी आऊंगी. इसलिये खेल मैदान पर बात अभी नहीं करूंगी.

सिंगल विंडो क्लियरेंस में दिलीप सिंह जी आपने बात की थी हम बड़े पैमाने पर इसके सुधार के लिये बैठते हैं कि यह सुधार जल्दी कैसे हो. जीतू पटवारी जी ने हमारे उद्योगों की स्थिति

पर बात की थी कि 100-200 कारखाने मालनपुर,पीथमपुर में बंद हैं. 6 महिनों में मैं इसकी कोशिश करूंगी सुधार करने के लिये. हमें दौरे करने हैं, हमें देखना है कि हम कैसे प्रोत्साहित करें इन बंद कारखानों को खोलने के लिये. इन्वेस्टर्स मीट में आपने कहा था कि अनाप-शनाप पैसा बर्बाद न हो. मेरे वाच में मैं जीतू जी प्रामिस करती हूं कि ऐसा होगा नहीं.गिरिराज जी ने रीवा में कई इंडस्ट्रीज की बात की थी. माननीय अध्यक्ष महोदय ,यह सही है कि रीवा साईड में बहुत इंडस्ट्रियल लैंड है और कई उद्योगों ने लैंड खरीद कर रखा है. मुंबई जाकर उन लोगों से हम मिले हैं उनसे पूछा कि आप इंडस्ट्रियां क्यों नहीं लगा रहे हो ? आपने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया था कि मिल्क इंडस्ट्रीज में काफी गुंजाईश है काम करने के लिये यह मैंने नोट कर लिया है. स्पोट्‌र्स में आपने स्टेडियम की बात की थी.

श्री कमलेश्वर पटेल – माननीय अध्यक्ष महोदय, रीवा,सिंगरौली,सीधी से ही संबंधित है आपकी इजाजत हो तो माननीय मंत्री जी से निवेदन कर लें. हमारे यहां सिंगरौली जिले में सीधी जिले में जो उद्योग स्थापित किये गये हैं वहां विस्थापितों की बहुत समस्या है और उन विस्थापितों की समस्या के निदान के लिये प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता . इस पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिये.

अध्यक्ष महोदय – ठीक है बात आ गई आपकी. मंत्री जी बैठी नहीं हैं आप बीच में बोलने लगे. यह ठीक नहीं है.

श्री कमलेश्वर पटेल – माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में हिंडाल्को स्थापित है. वहां काफी अनियमितताएं हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है.

अध्यक्ष महोदय – कृपया बैठ जाएं यह उचित नहीं है.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया – कमलेश्वर जी मैं दौरा करके देख लूंगी.

श्री यादवेन्द्र सिंह - अध्यक्ष महोदय, मेरा जरूरी सुझाव है.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया – माननीय सदस्य लिखकर दे दें.

अध्यक्ष महोदय – आप लिखकर दे दें.

श्री यादवेन्द्र सिंह - अध्यक्ष महोदय, मेरे नागौद विधान सभा क्षेत्र में धर्मस्व शाखा में मंदिरों में जमीन 200-300 एकड़ चढ़ी है उसका मालिक है कलेक्टर अध्यक्ष. दो साल से उन मंदिरों की बोली पर रोक लगा दी है. उसमें मंदिरों का नुकसान हो रहा है विकास रुका है. 6-6-6,8-8 लाख रुपया आता है. उसके लिये फिर से बोली हो क्योंकि जमीन पड़त हो गई.

अध्यक्ष महोदय – आपकी बात आ गई. आप लिखकर दे दीजिये.

श्री शंकरलाल तिवारी - अध्यक्ष महोदय, मंदिरों की जमीनों पर कई सामंतों का कई महत्वपूर्ण लोगों का कब्जा है इसलिये वह कब्जा हटाया जाए नागौद के मंदिरों की जमीनों का.

अध्यक्ष महोदय – कृपा करके बैठ जाईये. आपकी बात आ गई.

श्री सुन्दरलाल तिवारी – कौन सामंत है नाम बताईये ना तिवारी जी.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जारी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय देवेन्द्र वर्मा जी जो खंडवा के हैं उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया था ओंकारेश्वर मंदिर के लिये उस मंदिर के ट्रस्ट का जो प्रस्ताव यह प्रक्रियाधीन है और यह शीघ्र ही इसमें सम्मिलित हो जायेगा. आपने एक और स्टेडियम जो नगर निगम के अंदर है उसमें आपने कहा था कि जनभागीदारी से 65 लाख रूपये दिये थे वहां पर स्वीमिंग पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है इसमें ज्यादा कुछ न कहते हुए यह कहना चाहता हूं कि हम ज्यादा खेल अगर और ऐड करें जो हमने अभी तक खेल अकादमिया शुरू की हैं उसको हम और सुदृढ़ नहीं कर पायेंगे अगर हमने ज्यादा कुछ लिया अपने हाथों में, पर अपने दो खेल, तीन खेल अभी हैं निकट में जो कि हम लेना चाहते हैं एक है तैराकी, एक है स्वमिंग, एक है कबड्डी एवं खोखो, एक है फुटबाल तो इसमें जरूर इस पर हम ध्यान देंगे.

श्री देवेन्द्र वर्मा—अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि स्वमिंग पूल के लिये हमने 65 लाख रूपये एकत्र करके उपलब्ध करवाये हैं.

अध्यक्ष महोदय—आपकी बात मंत्री जी ने भी कही है.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया—अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य जी मेरे पास आ जाना आपसे इस बारे में बात कर लेंगे. आपने खंडवा में ग्रोथ सेन्टर की भी बात की थी उसकी भूमि आवंटन में दरें अधिक होना उठाया था तो विभाग के द्वारा शीघ्र ही भू-आवंटन नियमों का सरलीकरण किया जायेगा जिससे उद्योगों को कठिनाई नहीं होगी.

माननीय सुदर्शन गुप्ता जी ने जिला उद्योग केन्द्रों के लिये पर्याप्त राशि की बात की थी इसमें मैं और विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग एक बैठक करके इसको देखेंगे कि कहां हमारी कमी हुई है. आपने यह भी सजेस्ट किया था कि जिला उद्योग केन्द्र के तालमेल बेटर होने के लिये अपने डीएम के साथ, अपने सब अधिकारियों के साथ जो जिले में हैं उनके साथ बैठकर आपको तालमेल बिठाना चाहिये. आपने एक और बड़ा प्रकरण सुझाया था इंदौर से सांवेर रोड़ पर एक रोड़ को आप शायद उखाड़ रहे हैं इसके ऊपर हम लोग एक उद्योग लगा रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा माननीय सदस्य आप कृपया करके हमारे पास आकर हम लोग अपने अधिकारियों के साथ इसकी छानबीन करके आपको बता देंगे कि सही बात क्या है.

माननीय मनोज अग्रवाल जी ने उद्योग की बात पहले कही कि सहायक उद्योग अपने उद्योग बने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो एरिया स्पेसिफिक है यह बहुत अच्छा सुझाव था, आप पहले एरिया स्पेसिफिक देखें आपने कहा था कि ऐसी उद्योग नीति नहीं बना सकते हैं कॉम्प्रिहेन्सिव एक बड़ी उद्योग नीति बने, क्योंकि हर क्षेत्र अलग अलग है और इसीलिये हर क्षेत्र की एरिया स्पेसिफिक चीजें नोट करनी चाहिये इनकी रिसोर्सेज नोट करनी चाहिये और उसके मुताबिक एरिया स्पेसिफिक नीतियां बननी चाहिये पर उसमें क्या होता है कि आप बहुत महीन तरीके से हम लोगों को जाना

पड़ेगा. अभी जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनायी थी उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सुधार करने की आवश्यकता है हम तथा हमारे विभाग के अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में हमें और सरलीकरण चाहिये कि किस तरह से हम निवेशे जल्दी से लायें इस पर हम जरूर काम करेंगे और एरिया स्पेसिफिक, रिसोर्स स्पेसिफिक हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे बनाने के लिये. आपने एक और अच्छा सुझाव दिया था थर्मल प्लांट के लिये मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे प्रमुख सचिव पॉवर के भी हैं इसकी उनको अच्छी जानकारी होगी इसके बारे में कि फ्ला-एश के लिये हम कितना यूस कर सकते हैं, कैसे हम यूस कर सकते हैं और क्या हम सही सरक्यूलर जारी कर सकते हैं कि फ्ला-एश के ऊपर जो भी आज थर्मल पॉवर स्टेशन हैं वह क्या उसकी ब्रिक्स बना सकते हैं नहीं यह जानकारी उनसे लूंगी अगर सरक्यूलर बन सकता है जरूर बनाऊंगी.

इंजीनियर प्रदीप लारिया जी ने बहुत कुछ स्पोर्ट्स के बारे में और प्रशंसा भी की थी मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने एक और चीज कही थी कि बजट का बड़ा होना चाहिये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यह होना चाहिये, क्योंकि हमें कई काम करने हैं, जो कि बजट के अभाव में हम नहीं कर पा रहे हैं.

बुंदेलखंड एवं सागर स्पेशली आपने कहा था कि वहां अपार संभावनाएं हैं इसीलिये कोई अकादमी खोलनी चाहिये. सागर में आपने स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की बात की थी और गतिविधियां भी स्पोर्ट्स अकादमी में होनी चाहिये, स्वमिंग पूल भी नहीं है उसमें 25 लाख रूपये जमा किये थे नगर निगम ने अभी तक नहीं हुआ, बेडमिन्टन कोर्ट पानी गिरने से खराब हो सकता है इसीलिये आप कुछ करें. आपने शुरूआत में ही कुछ कहा था खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. मैं तो इसको मेटीवेशन के तौर पर इसको ले रही हूं, क्योंकि पुराने दिनों में यह सही था और मेरी मां भी यही कहती थीं तुम घुड़सवारी करती हो तुम्हारे पैर टूट जायेंगे तो मैं क्या करूंगी तो

हम लोगों को कहा जाता था कि आप घर पर ही रहो और अपनी पढ़ाई करो और आज की तारीख में बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न हो गया है हम तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं जो एक मिलियन डॉलर-दो मिलियन डॉलर उनकी सेलरी होती है तो हम भी चाहते हैं मध्यप्रदेश से हमारे ऐसे खिलाड़ी भी हों जो कि कम से कम एक करोड़ अर्न करें, दो करोड़ अर्न करें और इसीलिये माननीय मुकेश नायक जी मैं कहूंगी कि शिवेन्द्र सिंह जी को भी जो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं हमने उनको भी हाकी में विक्रम अवार्ड दिया है तथा उनको भी यहां पर मौका दिया है काम करने का. बुंदेलखंड में स्वमिंग पुल नहीं हैं स्वमिंग पुल निर्माण का कार्य आवास एवं पर्यावरण विभाग को हस्तान्तरित किया गया है माननीय विधायक जी आप उनके साथ बात कर लें.

माननीय शैलेन्द्र पटेल जी ने राष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी की बात की थी वह खुद राष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा था कि हमको और प्रोस्ताहन मिलना चाहिये. औबेदुल्ला खान गोल्ड कप ऐसे जो सिंधिया गोल्ड कप है मैं सात साल तक सांसद थी उस समय में मैंने बहुत कोशिश की थी कि सिंधियां गोल्ड कप को उसी तर्ज पर दिया जाये. औबेदुल्ला खान गोल्ड कप बहुत राजनीति है यह भोपाल वासियों को पता है ऐसे में हम खेल करें वह कैसे होगा जिस तरह से औबेदुल्ला खान गोल्ड कप में हम कोशिश करने के लिये हम इसे फिर नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर हम करना चाह रहे हैं तो आज हम प्रवेन्ट होते हैं इसको करने के लिये तो हमारी सोच है कि इसको हम वापस एसोसिएशन को दें और वह ही करें और हम उनको प्रोत्साहन राशि दे दें. पर मैं शैलेन्द्र पटेल जी को बधाई देती हूं कि आज हमारे सदन में एक नेशनल हाकी खिलाड़ी भी है मैं बहुत बधाई देती हूं कि आप समझोगे कि मेरी समस्या क्या है और मुझे कितना काम करना है. इच्छावर विधान सभा में आपने कहा था कि कोई उद्योग नहीं है स्वरोजगार योजना के तहत आप कुछ करिये और डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट की भी अपार संभावनाएं हैं. मीना वर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि सम्मानित विधायक ने खेल विभाग के लिये हमारी प्रशंसा की श्रमिकों के लिये आप ध्यान देना

चाहती हैं और हमारा भी ध्यान इसी पर है हम अपने विभाग के अधिकारियों से जो श्रम लेबर लॉ हैं उसके ऊपर भी कोशिश हो रही है उसका सरलीकरण करने के लिये श्रमिकों की मदद करने के लिये और आपने जो धर्मस्व में अतिक्रमण की बात की थी उसमें हम बिल्कुल सचेत हैं कि उसमें बहुत सारा अतिक्रमण हो रहा है.

रामपाल सिंह जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पतन की बात की थी मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहती हूं कि मैं इस छोटे से विभाग को 2005 के दिसम्बर महीने में लिया था और 14 महीने के बाद में मैं निकल गई थी उसमें हमारी एक ही कोशिश थी कि ग्रामीण से हम प्रतिभाओं को निकालें और संवारे और इसी वजह से वह पाईका बना, क्योंकि हमारा जो खेल अभियान था जो हमने ग्रामीण खेल क्रीड़ा अभियान के नाम से जाना जा रहा था उन दिनों में 2006 की बात है तो हमारे पंचायत मंत्री माननीय मणिशंकर अय्यर ने बहुत पसंद किया उन्होंने हमारे विभाग के अधिकारियों को कहा था आप प्रजेन्टेशन करने के लिये आयें यह बात माननीय मुकेश नायक जो कहना चाहती हूं, क्योंकि वह उन दिनों में धर्म में थे तो उस समय माननीय शंकर अय्यर जी के पास हमारा पूरा विभाग गया पूरा प्रजेन्टेशन हमने किया उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने पंचायत स्तर पर पाईका नाम करके इसको पूरे भारत में लागू किया अब हम उस पाईका को कैसे अपने जिलेवाईज लायें इसमें हमारे माननीय सदस्य भी मदद करें इस साल से राजीव गांधी खेल अभियान से वह जाना जायेगा.आज पाइका खतम हो रहा है 2014 में और मैं तो कहती हूं कि विधायक अपने-अपने विधान सभा में कृपया रूचि लें कि जो डी.एस.ओ. है, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स आफिसर है, जो एस.पी. है, जहां पैसा आता है स्पाइका का अध्यक्ष महोदय, वह देखें कि उसका सही क्रियान्वयन हो क्योंकि हम लोग डायरेक्ट्रेट में बैठकर, या मैं अपने वल्लभ भवन में बैठकर हम लोग सारे जिलों में और सारे विधान सभाओं में काम नहीं कर सकते, न पैनी नजर रख सकते हैं, तो मेरा तो आग्रह है हर स्म्मानीय विधायक को इस विधान सभा में कि प्लीज, मेरी मदद करें क्योंकि मैं चाहती हूं कि

ग्रामीण क्षेत्रों से हमारी प्रतिभायें आयें, जैसे मनीषा कीर हमारे यहां आई है, जैसे हमारा एक नौका चलाने वाला 10 किलो मीटर से साइकल करके अपने गांव से आता है नौका चलाने के लिये और आज उसको भी गोल्ड मैडल और कई मैडल्स उसने जीते हैं. हम चाहते हैं कि ग्रामीण से हमारे लोग आयें, इसीलिये हमने वह युवा खेल अभियान बनाया था, इसीलिये पाइका बनी और इससे अगर आप मानीटर कर सकते हो और आप बता सकते हो कि हमारा डी.एस.ओ. काम नहीं कर रहा है या कहीं और हमारे खेल मैदान में अतिक्रमण हो रहा है, तो मैं बहुत आपकी आभारी रहूंगी. राजेश सोनकर जी ने आज माना कि हमारे हाकी में हम लोगों ने जो गोद लिया है महिला हाकी और अपने पुरूष हाकी में, अच्छी बात है अच्छा किया है इन्दौर खेल अकैडमी को खोलने के लिये बात की है. रेवती गांव में जमीन चयन की गई थी वह इन्दौर स्टेडियम के लिये क्यों नहीं हो सकता है और पाइका का नाम चेन्ज हुआ है, वह उसकी बात भी करी थी. माननीय चन्दा गौर जी ने खरगापुर के लिये रोजगार की कमी की बात बताई, खरगापुर विधान सभा के पाइका जो ठीक से नहीं चल रहा है, उसकी भी बात बताई, स्टेडियम बनाने की बात भी करी, टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2013-14 में स्वरोजगार योजनान्तर्गत 730 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत की गई है, इस वर्ष 1 हजार, 12 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, माननीय सदस्या इस ओर ध्यान अगर दे सकती हैं. के.के.श्रीवास्तव साहब ने एक हमारी जो हमने कांट्रीब्यूशन की है, अपने खेल विभाग में, उसकी मानते हुए टीकमगढ़ एस्टोटर्फ की बात करी है और ध्यानचंद जी को भारत रत्न की बात करी है. हम लोग प्रयासरत् हैं और भारत सरकार भी प्रयासरत् है कि माननीय ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिले, वह उनकी नीति है, इसलिये हम इसमें कुछ हिस्सा नहीं ले सकते हैं. धर्मस्व में आज अस्थि विसर्जन की बात आपने करी इलाहाबाद के लिये, हम इसके ऊपर जरूर देखने का प्रयास करेंगे. टीकमगढ़ नगर के समीप मधुबन में 33 हैक्टर शासकीय भूमि हस्तांतरित होकर उद्योग क्षेत्र हेतु प्राप्त हुई है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जायेगा माननीय श्रीवास्तव साहब, आपके लिये.

आशीष शर्मा जी ने वीरांगना की प्रशन्सा की, आत्मनिर्भरता की प्रशन्सा की, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आशीष जी कि आपने पूरे सदन को बताया कि हम क्या चाह रहे हैं इस वीरांगना योजना के माध्यम से. युवा अभियान के अंतर्गत खो-खो शामिल करा जाये, कबड्डी और खो-खो में हम ध्यान दे रहे हैं कि यह दो भारतीय खेल हैं, इनको कैसे शामिल किया जा सकता है. नेमावर में आपने कहा था कि सोयाबीन और कपास उद्योग की इंडस्ट्री बनाई जाये, क्योंकि अपार संभावनायें हैं, इसमें भी हम ध्यान देने वाले हैं. मंदिर के विकास के लिये बजट का अभाव है, वह तो हमें पता ही है, हम कोशिश कर रहे हैं ए.सी.एस. फाइनेन्स से और हमारे माननीय एफ.एम. से कि हमें थोड़ा सा और बजट मिल जाये. देवास जिले में तीरंदाजी का फीडर सेंटर दिया जाये, इसकी भी आपने मांग की है. माननीय दिलीप सिंह परिहार जी ने स्पोर्ट्समेन स्प्रिट की बात करी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि यह भी आपने पूरे सदन को बताया. मां तुझे प्रणाम की आपने प्रशन्सा की कलेक्टर को कहा जाना चाहिये कि खेल मैदान के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, इसीलिये जल्दी से इसकी कार्यवाही हो और 10 बीघा जमीन आपके हाकी एस्ट्रोटर्फ लगनी चाहिये यह भी आपने बात करी. श्रीमती उषा चौधरी जी ने सतना की बात करी, कुटीर उद्योग वहां रैगांव में खोला जाये, खेल सतना में ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ी और खेल सामग्री का अभाव है और आपने यह भी सजेस्ट किया वह बहुत ही अच्छी बात है मैं अपने खेल विभाग के अधिकारियों को जरूर इस बारे में बताउंगी कि विधायक को भी क्रिकेट के 25-25 किट्स देने चाहिये, ताकि वह भी अपने क्षेत्र में सही जगह पर बांटें. रतलाम जावरा में आपने कहा कि एक हुसैन बाबा का मजार है, वहां उसकी सुरक्षा करने की जरूरत है और मंदिर भी हैं, जो पहाड़ में हैं, उनकी भी सुरक्षा हो जाये. रामेश्वर शर्मा जी को मैं कैसे बधाई दूं ? आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुती की हमारे खेल विभाग की और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं. आपने क्रिकेट स्टेडियम की बात करी थी और हमारा ध्यान अवगत कराया था कि सी.एम. साहब ने एक घोषणा की है भोपाल में, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमें पता है इसके

बारे में और हम इसमें जैसे ही हमें बजट मिलेगा, इसके लिये हम एक इन्टरनेशनल स्तर पर, चूंकि आज भोपाल हमारा कैपिटल है और कैपिटल होने से हमें गर्व है कि हम आज तरह-तरह की अकैडमीज यहां शुरू कर रहे हैं और वह भी जो आज उनकी पहचान भारत सरकार में बन रही है. भारत सरकार के खेल विभाग देखने के लिये यहां आ रहे हैं कि हम कैसे इसका संचालन कर रहे हैं और कैसे हमने खोला है, तो क्रिकेट की एक स्टेडियम का एक बहुत बड़ा अभाव है और हमें इस त्रुटि को जल्दी से जल्दी ठीक करना है, बजट हमें लानी है, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को जरूर पूछूंगी कि हमें अगर इस बजट के लिये इस इन्टरनेशनल स्टेडियम के लिये ऐसा ही बजट मिल जाये. माननीय शर्मा जी, आपने एक और सुझाव दिया था और वह था कि सिंधु दर्शन के लिये आप विशेष ध्यान दें और पुजारियों के वेतन की कमी की भी आपने बात की थी. माननीय रामेश्वर शर्मा जी, सिंधु दर्शन योजना प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही इसके नियम बनवाये जायेंगे. लास्ट में डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय जी ने जावरा की बात करी थी खेल मैदानों को विकसित करने की बात करी थी, स्वीमिंग पुल और स्टेडियम की बात करी थी, जावरा शुगर मिल और 2 और शायद शुगर मिल्स हैं वहां महिदपुर शुगर मिल और एक और है, उसकी बात करी थी.

श्री बहादुर सिंह चौहान--माननीय मंत्री जी, महिदपुर शुगर मिल की बात करी थी मेरे क्षेत्र का महिदपुर.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया--वह विधान सभा की कार्यवाही में आ ही जायेगी और मैं उसकी पूरी रिपोर्ट निकाल लूंगी और इसमें आपने लघु और कुटीर उद्योग की भी बात करी थी. माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस पर बहुत जोर दिया है कि छोटे-छोटे उद्यमियों को भी आज मदद किया जाये और छोटे-छोटे लघु उद्योगों को भी मदद किया जाये, अब माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कितना समय देंगे ?

अध्यक्ष महोदय--रजनीश सिंह जी, वॉलीबाल के बारे में एक बात बताना चाहते हैं, कृपा करके सुन लें.

श्री रजनीश सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने अभी हाल ही में इन्दौर में ग्रामीण खेलों का आयोजन किया, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कानीवाड़ी की टीम वॉलीबाल प्रतियोगिता में इस प्रदेश में प्रथम आई और आपने माननीय मंत्री महोदया, 2 लाख रूपये का इनाम भी मेरे उस ग्रामीण क्षेत्र कानीवाड़ा टीम को दिया. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रामीण इलाके में वॉलीबाल प्रतियोगिता आयोजित होते रहती है, हमें माकूल स्थान नहीं है, हम माननीय मंत्री महोदया से प्रार्थना करना चाहेंगे कि...

अध्यक्ष महोदय--आपकी बात आ गई अब बैठें.

श्री रजनीश सिंह--एक स्टेडियम की व्यवस्था हो, ताकि ग्रामीण प्रतियोगिताओं को खेलों का एक अनुभव प्रदर्शन करने का मौका मिले और आपके माध्यम से दूसरा निवेदन यह है कि सिवनी जिला हाकी के मामले में बहुत अव्वल है और वहां पर भी नेशनल गेम आयोजित हों...

अध्यक्ष महोदय--अब आप ज्यादा बात नहीं करिये. आपने वॉलीबाल का बोला, अब कृपा करके बैठ जाइये, इसीलिये मैं समय नहीं देता.

श्री रजनीश सिंह--मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वहां पर एस्ट्रोटर्फ का ग्राउन्ड बन जाये.

अध्यक्ष महोदय--रजनीश सिंह जी, यह बात उचित नहीं है. कृपा करके बैठ जायें. बीच में मैंने उनको इंटरप्ट करके आपको कहा, आप फिर नई बातें करने लगे, आप बैठें.

श्री रजनीश सिंह--जी, धन्यवाद.

श्री रणजीत सिंह गुणवान--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे एक निवेदन है.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानीय विधायक जिनके पिता जी एक बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि मैं ज्यादा प्रशन्सा करूं, तो कम है. मैं उनको कहना चाहती हूं कि जब मैं खेल विभाग के ऊपर चर्चा करूंगी, तो उस समय आप देख लोगे कि मेरी मन्शा क्या है और उसी के हिसाब से फिर आप अपनी जो मांगें हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं.

श्री रजनीश सिंह--धन्यवाद मंत्री महोदया.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया--थोड़ा सा उद्योग पर हमारे सम्मानीय सदस्यों ने कम बोला तो इसीलिये उद्योग अब एक ऐसा विभाग है, जिसमें हमें सारे सदन की सपोर्ट चाहिये. तो इसीलिये मैं थोड़ा सा अगर ज्यादा बोलूं तो आप माइंड न करें. अध्यक्ष महोदय, एक तो आपके मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के मेरे माननीय साथी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं सदन में उपस्थित माननीय सदस्य गण की मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने अनुमति दी इस बजट पर बात करने की. मध्यप्रदेश के समग्र आर्थिक विकास हेतु निवेश को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य वाणिज्यिक उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है. विभाग द्वरा औद्योगिकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में स्थापित किया गया है. मध्यप्रदेश देश में तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था वाले राज्यों में शुमार हो गया है. प्रदेश में निवेश का माहौल बना है. प्रदेश की पहचान निवेश मित्र राज्य के रुप में बनी है. वर्ष 2005-06 से 2013-14 तक प्रदेश की औसत औद्योगिक विकास दर 8.08 प्रतिशत रही है, जो कि देश की औसत विकास दर से ज्यादा है.

प्रदेश के सर्वांगीण व समुचित औद्योगिक विकास हेतु मध्यप्रदेश उद्योग संवर्द्धन नीति,2010 यथा संशोधित 2012 लागू की गयी है. प्रदेश में 20 अप्रैल,2013 से मध्यप्रदेश निवेश

क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम,2013 लागू किया गया है. प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने तथा प्रदेश को व्यापार के एक प्रमुख केन्द्र के रुप में स्थापित करने के उद्देश्य से दिसम्बर,2013 में मध्यप्रदेश व्यापार संवर्द्धन मंडल का गठन किया गया है. विभाग में समयबद्धता एवं पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए 6 विभागीय सेवाओं को लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी..

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, कितना समय लेंगी.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया -- अध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा.

अध्यक्ष महोदय -- अभी 3 विभाग और लेना है.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया -- अध्यक्ष महोदय, आपने ढाई घण्टा दिया सब विधायकों को.तो मुझे 40 मिनट तो मिल जाय.

अध्यक्ष महोदय -- आपको 40 मिनट हो गये. 10-15 मिनट में समाप्त करें.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया -- अध्यक्ष महोदय, वह तो मैं विधायकों के जवाब दे रही थी. अध्यक्ष महोदय, हो नहीं पायेगा, क्योंकि उद्योग के संबंध में अभी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट आ रही है.

अध्यक्ष महोदय -- अन्य विषय भी हैं और सभी को आज लेना है. यदि आपको सहयोग हो.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया -- अध्यक्ष महोदय, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित किया गया है. मुझे यह बताते हुए अत्यन्त गर्व हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट तृतीय का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और 8 से 10 अक्टूबर,2014 को ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है. मैं आपके माध्यम से सबको इनवाइट करना चाहती हूं, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, सब हमारे सदन के विधायक गण हैं. आप सबको मैं आमंत्रित

कर रही हूं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 8 से लेकर 10 अक्टूबर,2014 तक है और कृपया आप हमें सपोर्ट दें. आप आकर हमें मदद करें. इसके लिये मैं बहुत आभारी रहूंगी. इस समिट में हम इस बार वृहद परियोजना के साथ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रदेश में पूंजी निवेश कर रोजगार सृजन के लिये आमंत्रित एवं आकर्षित कर रहे हैं. प्रदेश में निवेश में वृद्धि तथा सर्वांगीण विकास होकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु नीतियों में सरलीकरण एवं संशोधन किया जा रहा है. हमारी ग्लोबल इवेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिये देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने सहमति प्रदान की है. समिट के सफल आयोजन के लिये शासन द्वारा निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की समीक्षा निरन्तर की जा रही है. मेरे विभाग द्वारा भी प्रति सप्ताह निवेशकों के साथ बैठक आयोजित की जाकर उनके प्रकरणों की क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है. एमपी ट्रायफेड द्वारा निवेशकों के प्रस्ताव के निराकरण हेतु सिंगल विंडो एजेंसी के रुप में कार्य सम्पादित किया जा रहा है. निवेश प्रस्तावों का ऑन लाइन निराकरण करने हेतु कई सदस्यों ने इसके बारे में कहा था. इसीलिये मैं पढ़ना चाह रही हूं कि निवेश प्रस्तावों का ऑन लाइन निराकरण करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम निजी एजेंसी के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जिसमें 7 विभागों की 15 सेवाओं को शामिल किया जायेगा. प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 6100 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 186 औद्योगिक क्षेत्र तथा 8500 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 545 से अधिक औद्योगिक विकास केन्द्र पार्क स्थापित किये जायेंगे. इसके अतिरिक्त लैंड बैंक की स्थापना की गयी है, जिसमें शासकीय भूमि को सम्मिलित किया गया है. लैंड बैंक के अंतर्गत लगभग 19 हजार हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गयी है, जो विभिन्न औद्योगिक इकायों को उनकी आवश्यकतानुसार आवंटित की जायेगी. जिसमें से लगभग 7 हजार हेक्टेयर भूमि विभाग को हस्तांतरित हो गयी

है. निवेशकों को औद्योगिक भूमि आवंटन में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम,2008 का सरलीकरण किया जा रहा है.

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि लैंड एलाटमेंट के भी जो रुल्स हैं, उसका भी सरलीकरण और उसको भी ठीक से बनाने के लिये हमारे विभाग के अधिकारी इसमें प्रयासरत् हैं. मध्यप्रदेश का पहला एसईजेड, इन्दौर में 1113 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया गया है. विकसित भूमि 593 हेक्टेयर है. यहां से वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक रुपये 9600 करोड़ का निर्यात किया गया है. राज्य शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केन्द्रों में अधोसंरचना के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है. प्रदेश में 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 27 स्थानों पर लगभग 7675 हेक्टेयर भूमि पर चरणबद्ध रुप से रुपये 3022 करोड़ की लागत से सर्व सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना बनाई गई है, जिसमें से एक औद्योगिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क, इन्दौर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. महत्वपूर्ण चीज दिल्ली, मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर डीएमआईसीडीसी जिसको हम कहते हैं. उस परियोजना के अन्तर्गत विक्रम उद्योग पर ही इकॉनॉमिक कॉरीडोर इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ग्रीनफील्ड इंटिग्रेटेड टाउनशिप, पीथमपुर जल प्रदाय योजना हेतु भू अर्जन हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. मैं यह भी बताना चाहती हूं कि कल जापान के एम्बेसेडर आ रहे हैं. इसी बात पर चर्चा होगी और इसी बात पर निवेश हम कैसे ला सकते हैं जापान से उसी बात पर चर्चा उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा होगी. राज्य स्तरीय इनवेस्टमेंट कॉरीडोर की 6 परियोजनाएं अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो गये हैं. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति,2011 अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन की स्थापना हेतु मुरैना से लेकर शिवपुरी और ग्वालियर से होते हुए गुना राज्य स्तरीय इनवेस्टमेंट कॉरीडोर अन्तर्गत ग्राम पड़ोरा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी में स्थल का चयन किया जा चुका है. प्रदेश में अब तक 800 से अधिक वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित

हुए हैं, जिसमें रुपये 53 हजार करोड़ से अधिक पूंजी निवेश हुआहहै तथा 1 लाख 90 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5 लाख से अधिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिसमें रुपये 5200 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के साथ लगभग 13 लाख 14 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है. प्रदेश के उद्यमियों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्राधिकरण की तर्ज पर मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर ऑथॉरिटी गठित हुई है. प्रति वर्ष चयनित उद्यमी को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिये यात्रा व्यय पर अनुदान सहायता दी जा रही है. यह भी मैं कहना चाहूंगी कि मेला प्राधिकरण अपना है ग्वालियर में. इसको हम ग्वालियर ट्रेड एंड कनवेंशन सेंटर यहां बनाने जा रहे हैं. 104 एकड़ की भूमि है जिसमें ग्वालियर ट्रेड एंड कन्वेन्शन सेन्टर बनेगा और मैं सोचती हूं कि पूरे सदन का सहयोग अगर मुझे मिल जाये तो हम नोएडा में जो आज ट्रेड फेयर की तर्ज पर इंटरनेश्नल स्तर हेतु भूमि है और प्रगति मैदान में जो भूमि है उससे भी बेहतर, क्योंकि हम 3 घंटे ही आज दिल्ली से दूर है. हम भी कोशिश करना चाह रहे हैं कि हमारे ग्वालियर में एक ऐसा ट्रेड फेयर और ट्रेड एंड कन्वेन्शन सेन्टर बने ताकि नोएडा को छोड़कर के लोग हमारे यहां आयें. अपने ट्रेड फेयर गठन करने के लिये, अपनी ट्रेड बनाने के लिये.

अध्यक्ष महोदय, राज्य में 1 लाख 40 हजार से अधिक संस्थायें तथा लगभग 1 लाख से अधिक फर्म पंजीकृत हैं. फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन की व्यवस्था के सरलीकरण हेतु दिनांक 1 जून 2013 से फर्म्स एवं सस्थाओं के पंजीयन प्रकरणों की आन लाइन परीक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है. विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों , कई माननीय सदस्यों ने यहां पर यह बात उठाई है कि शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, दीनदयाल स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जा रहे हैं. अभी कैबिनेट ने प्रस्ताव

पास किया है कि इन सबका युक्तियुक्तकरण करके तीन ऐसी स्वरोजगार योजनायें बनाई जायें ताकी कन्फ्यूजन न हो, विभाग अपनी अलग अलग योजनायें चलायेंगे पर तीन ही अब स्वरोजगार योजनायें बनेंगी. जिसमें 25 हजार से अधिक युवाओं ने भाग लिया है . विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं अंतर्गत अहर्ता एवं सहायता के प्रावधानों में भिन्नताओं के कारण हितग्राहियों के समक्ष उत्पन्न भ्रम की स्थिति को दूर करने तथा उन्हें अधिकतम सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समस्त स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा स्वरोजगार योजनाओं के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये स्थानीय संसाधन एवं स्थानीय कौशल के दोहन पर विशेष बल देना, प्रदेश के भीतर और दूसरे प्रदेशों के साथ बाजारों की नेटवर्किंग की जाना, तथा उद्योग एवं औद्योगिक विकास के उन्नयन की व्यवस्था का भी कार्य किया जा रहा है. प्रदेश निरंतर औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर है. प्रदेश में मंडीदीप, पीथमपुर, मालनपुर एवं पीलूखेड़ी से औद्योगिक उत्पाद निर्यात हो रहे हैं. नवीन स्थापित औद्योगिक इकाईयों को रियायती दरों पर भूमि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता लागत, पूंजी, अनुदान, ब्याज अनुदान आदि उपलब्ध कराई जा रही है. टेक्सटाइल उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु विशेष ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है. मैं गर्व के साथ बताना चाहती हूं कि मध्यप्रदेश की टेक्सटाइल नीति देश की सर्वश्रेष्ठ टेक्सटाइल नीति में से एक है. मध्यप्रदेश में श्रमिक माहोल देश में श्रेष्ठतम है. राज्य के उद्योगों में श्रमिक दिनों की हानि लगातार गिर रही है. तथा औद्योगिक विवादों में भी प्रतिवर्ष कमी हो रही है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को आर्थिक सुविधायें प्रदान करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु जिलों का वर्गीकरण समाप्त किया जा रहा है. प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाईयों को रियायत एवं सुविधा देने हेतु नई उद्योग नीति लाने, पर भी विचार किया

जा रहा है. प्लग एंड प्ले सुविधाओं हेतु कहना चाहती हूं कि यह छोटे लघु उद्योगों के लिये है. प्लग एंड प्ले सुविधाओं के निर्माण हेतु औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा(भोपाल), तथा लेदर काम्पलेक्स, मुरार (ग्वालियर) का चयन किया गया है. इसी प्रकार से विदिशा तथा औद्योगिक क्षेत्र रिछाई (जबलपुर) में फ्लेटेड उद्योगों हेतु स्थल का चयन भी हो गया है. निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार अवसरों के अधिकतम दोहन के लिये प्रदेश में जॉबफेयर आयोजित किये जा रहे हैं. जॉबफेयर आयोजनों के अंतर्गत मार्च 2014 तक 1 लाख 80 हजार से अधिक आवेदकों को नियुक्ति हेतु चयन करवाया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय वायु सेना में 3 हजार 392 एयरमेन एवं भारतीय थल सेना में 12 हजार 744 सैनिकों का चयन भी हो गया है. इस वर्ष थल सेना की भर्ती रेलियों में शारीरिक एवं चिकित्सीय परीक्षण में चयनित 4 हजार 816 युवाओं को कॉमन इन्ट्रेंस टेस्ट परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु आगामी 19 जुलाई से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार बाजार की समझ को विकसित करने एवं रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढाने उद्देश्य से कैरियर काउंसलिंग योजना क्रियान्वित की जा रही है. इसके अंतर्गत प्रशिक्षित कैरियर काउंसलर एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षात आवेदकों को काउंसलिंग कर उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है. प्रदेश के बेरोजगारों के आन लाइन पंजीयन तथा नियोजकों को जनशक्ति की जानकारी सहजता व त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 48 जिला रोजगार कार्यालयों को , कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि जिला रोजगार कार्यालय और जो डीआईसी का कार्यालय है , मुझे याद है कि डॉ.पाण्डेय ने एक सजेशन भी दिया था तारांकित प्रश्न के समय तो आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहती हूं कि हम इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं ताकि वह दोनों एक साथ एक रूप में उस भवन में रहें, रोजगार के लिये लोग भी वहीं पर आयें, डीआईसी की भी जो

समस्यायें हैं वह वहीं पर हल हो. पर हमारी जीआई की बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं. इसीलिये बजट के अभाव में हम आज तक इस पर कुछ काम नहीं कर पाये हैं.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- आप विचार कर रही हैं इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी कृपया 5 मिनिट में समाप्त करें.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया -- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग पर चर्चा खत्म ही हो रही है. काफी संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगी. माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं तक सरल एवं सहज रूप से शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों तथा रोजगार कार्यालयों के कर्मचारियों को एक छत के नीचे बैठने का निर्णय लिया गया है.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी अभी बहुत से विभाग पर चर्चा होना बाकी है.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया-- अध्यक्ष महोदय, ढाई घंटे तो हमारे सदस्यों ने ले लिया. अध्यक्ष महोदय, अब मैं अनुदान संख्या 43 पर आती हूं खेल विभाग की. मैं इसमें मात्र समीक्षा कर लेती हूं. पूरा पढ़ूंगी नहीं.

अध्यक्ष महोदय-- खेल विभाग तो हो गया. 40 मिनिट तो आपने पहले उसी विभाग पर बोला है. आप तो कृपा करके 5 मिनिट में समाप्त कर दें ताकी दूसरे विषय आ सकें.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त कराना चाहती हूं कि खेल के प्रति जिस तरह से विधायकगणों ने अपनी रूची ली है तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहती हूं कि क्या कहते हो आप "लगे रहो मुन्ना भाई" वह बात हो गई या फिर आप कह सकते हो कि "भाग मिल्खा भाग" वही हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी , मैं सदन को एक ही चीज बताना चाहती हूं कि स्टेडियम की नीति हम बनाना चाह रहे हैं. बार बार यही बात आती है कि आपने हमें अभी तक स्टेडियम नहीं दिया, तो स्टेडियम बनाने के

लिये पैसा लगता है और वह हमारे बजट में नहीं है इसीलिये हम फाईनेन्स को जाने के पहले एक स्टेडियम नीति बनाना चाहते हैं कि पापुलेशन के हिसाब से, खेलों के हिसाब से और गोल्ड मेडेल्स के हिसाब से जिलेवार कहां पर स्टेडियम बनेंगे, कितने में बनेंगे क्या उनका स्वरूप होगा, कौन उनको चलायेगा, किसके अधीन होंगे, क्योंकि अभी तक स्टेडियम बनते थे और नगर निगम के हवाले होते थे और नगर निगम उनको सम्हालता नहीं था तो हम धीरे धीरे उनको वापस ले रहे हैं और अपने फाइनेन्स के बजट से उनकी देखरेख हो रही है तो हमें भी अगर हम आज आपके यहां पर स्टेडियम बनायेंगे तो फिर लोग वहां तैनात होने हैं, उसका बजट हमको चाहिये उसके इन्फ्रास्ट्रेक्चर की देख रेख , उसके लिये भी पैसा लगेगा तो इन सबके लिये पैसा चाहिये और हम इसके लिये कोई जादू की छड़ी नहीं चला सकते हैं. हमें पहले नीति देखनी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहती हूं कि हम 4 बिंदू पर नीति बना रहे हैं और यह बिंदू होंगे स्टेडियम जिलावार, उसके बाद मिनी स्टेडियम, उसके बाद जिला खेल परिसर जैसा मैंने ग्वालियर को विकसित किया है और उसके बाद में खेल मैदान. 2006 में हमने सब कलेक्टरों को लिखकर के कहा था कि एक दिन ऐस आयेगा जब हमें खेल के मैदान मिलेंगे नहीं कृपया आप अपने जिलेवार, विधानसभा वार खेल मैदान हर गांव के लिये आप निकाल कर रखिये, वो हुआ नहीं, खेद की बात है कि इस पर अमल नहीं हुआ. जब यह विभाग वापस मेरे पास में आया है तो मैं फिर से कलेक्टरों के लिख रही हूं कि कृपया जो 2006 में हमने कहा था कि खेल मैदान हर गांव के लिये होना चाहिये उसको आप चिह्नित करिये.हम कलेक्टरों को लिख रहे हैं कि 2006 में जो हमने कहा था कि हर गांव के लिए खेल मैदान होना चाहिए. उसको आप चिन्हित करिये. उसका रखरखाव हमें बताईये. उसकी बाऊंड्री वॉल बनाईये ताकि हम अपने खेल की गतिविधियां प्रारंभ कर दें.

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य का सुझाव था कि किट भी दिया जाये तो हमारे विधायक को वह भी दिया जायेगा.

श्री सोहन लाल वाल्मिक-- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि बेटी बचाओ अभियान के संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे दें.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया-- अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या 51 के संबंध में कहना चाहती हूं. माननीय मुख्यमंत्रीजी को जो तीर्थ दर्शन योजना है.इसमें आप लोग भी श्रवण बन सकते हैं. सिर्फ सरकार ही श्रवण न बने. आप अगर अपने जिले में और अपनी विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो आप अपने स्तर पर लोगों को भेज सकते हैं. क्योंकि हमने खेल विभाग से युवाओं को प्रोत्साहित किया है. इसी तरह जो 60 साल के ऊपर के गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, अपंग हैं उनको भी भेजे जाने की बात जब हम करते हैं तो हम भगवान से पुण्याई लेते हैं. उनको पहुंचाने का काम हमारा काम है. लेकिन चिन्हित करने का काम आपका काम हो सकता है. इसलिए आप भी इस योजना में शामिल हो जायें और हमें मदद करिये अच्छे और बूढ़ों लोगों को भेजने के लिए जो वाकई में रामेश्वरम्,वैष्णो देवी, दूसरे तीर्थ स्थानों पर जाना चाहते हैं जहां वे जा नहीं पा रहे हैं. मैं, सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं. धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय-- मैं, पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11,43 एवं 51 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब, मैं मांगों पर मत लूंगा.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए एक हजार चौतीस करोड़, उन्नीस लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण के लिए एक सौ एक करोड़, बयालीस लाख, सतावन हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए अठानवे करोड़, चार लाख, आठ हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अनुदानों की मांग के बारे में प्रस्ताव

श्री पारस चन्द्र जैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को

अनुदान संख्या - 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए छः हजार पॉच सौ सात करोड़, इकसठ लाख, उनहत्तर हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर) के लिए दो हजार तीन सौ तिरासी करोड़, चौदह लाख, चौबीस हजार रुपये,
	तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे,उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या--27	**स्कूल शिक्षा(प्रारंभिक शिक्षा)**
सुश्री हिना लिखीराम कांवरे	1
श्री जयवर्द्धन सिंह	2
श्री रामनिवास रावत	3
कुंवर विक्रम सिंह	4
श्री शैलेन्द्र पटेल	6
श्री बाला बच्चन	7
श्री निशंक कुमार जैन	8
श्री रामपाल सिंह(ब्यौहारी)	9
श्री जितू पटवारी	10
श्री हर्ष यादव	11

श्री सचिन यादव	12
श्री रजनीश हरवंश सिंह	14
श्रीमती झूमा सोलंकी	15
श्री आरिफ अकील	16
श्री कमलेश्वर पटेल	19
डॉ गोविन्द सिंह	20

मांग संख्या--77 **स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)**

श्री उमंग सिंघार	1
श्री आरिफ अकील	2
श्री हर्ष यादव	3
श्री बाला बच्चन	4
श्री रामनिवास रावत	5
कुंवर विक्रम सिंह	6

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा होगी.

स्कूल शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांग 27 एवं 77 चर्चा हेतु कार्य मंत्रणा समिति ने एक घंटे का समय निर्धारित किया है. तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित किया है.

भारतीय जनता पार्टी	43 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	14 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	02 मिनट
निर्दलीय	01 मिनट

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कृपया समय का विशेष ध्यान देंगे.

श्री सुन्दर लाल तिवारी(गुढ़)--अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं. वर्तमान में हमारे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा किस स्थिति में है यह किसी से छिपा नहीं है. अगर हम इसका मूल्यांकन सदन के अंदर से ही कर सकते

हैं. सदन में मंत्रीगण से लेकर जितने सदस्यगण बैठे हैं, मैं समझता हूं कि शासकीय विद्यालय में इनमें से किसी के भी बच्चे या पोते नहीं पढ़ रहे हैं. कोई भी आर्थिक रुप से सक्षम आदमी अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा है. यह पूरे प्रदेश का दृश्य है.

अध्यक्ष महोदय, आज शासकीय स्कूलों में मजदूर,गरीब या स्कूल में नाम लिखाकर कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले बच्चे जा रहे हैं. बाकी सभी लोग जो सक्षम हैं, वह शिक्षा प्राप्त कराने के लिए अपने बच्चों को शहरों में ले जाते हैं और शहरों में भेज रहे हैं. सरकार का खजाना खाली होता चला जा रहा है. प्रदेश के बजट की भारी भरकम रकम इस शिक्षा के क्षेत्र में लगायी जा रही है लेकिन इसके क्या कारण है इसका उल्लेख सरकार कभी नहीं करती है. मंत्रीजी से हम जानना चाहेंगे कि जब अपना जवाब दें तो यह बतायें कि आखिर शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकंडरी शालाओं से लोगों का विश्वास क्यों घटता चला जा रहा है. क्या कारण है कि लोग अपने बच्चों को इन विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते हैं. बहुत सारी स्कूलें हैं. शहरों में सीबीएसई की स्कूलें, सरस्वती स्कूलें हैं और लोगों की व्यक्तिगत स्कूलें भी हैं. गांव में शासकीय स्कूल के बगल में अगर कोई निजी स्कूल खुली है तो निजी स्कूल में बच्चों की संख्या अच्छी रहती है और शासकीय स्कूलों में संख्या लगभग नगण्य रहती हैं.

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आगे आऊंगा कि शासकीय स्कूलें बंद की जा रही हैं. उनके स्थान परिवर्तित कर दिये जाते हैं क्योंकि वहां बच्चे नहीं मिलते. मंत्रीजी आपने अपने विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में कुछ दायित्वों के बारे में कहा है. इसमें लगभग 19 दायित्व आपने बताये हैं. इन 19 दायित्वों को समय की कमी के कारण पढ़ पाना संभव नहीं है. अध्यक्ष महोदय, का सख्त निर्देश है कि समय का ध्यान रखें. मैं यह कहना चाहता हूं कि इन 19 दायित्वों में एक भी दायित्व का निर्वहन हमारी सरकार नहीं कर रही है. एक भी दायित्व का जमीन पर क्रियान्वयन नहीं दिख रहा. और वही कारण है कि आज शासकीय स्कूलों की हालत पूरी तरह बद से बदतर हो चुकी है.हम

आगे चलें, इनफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो इस बात का मूल्यांकन सरकार करे कि स्कूल में बच्चे शिक्षा तो नहीं पाते हैं, लेकिन स्कूल से बीमारी लेकर अपने घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इस बात का भी माननीय मंत्री जी को मूल्यांकन करना चाहिए, मैं यह अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं. बिल्डिंग है नहीं, जहां बिल्डिंग है वहां पर पानी टपक रहा है वहां जानवर जैसे बच्चे बैठा करते हैं. शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है. पीने के पानी कोई व्यवस्था नहीं है.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा - आपके बच्चे वहां पढ़ते नहीं है, इसलिए आपको मालूम नहीं है, वहां सब है, शौचालय हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं वहीं होगा.

श्री जतन उइके - माननीय मैं 14 साल मास्टर रहा हूं, आदरणीय सदस्य इस बात की सच्चाई को जानते हैं, यकीनी तौर पर कहा जाय तो पूरे प्रदेश में तकरीबन 60 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय वाकई में नहीं हैं और शौचालय हैं तो पानी नहीं है.

अध्यक्ष महोदय - कृपया बैठ जाएं. माननीय सदस्य को बोलने दें.

श्री बहादुर सिंह चौहान - अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी से पूछना चाह रहा हूं कि आपके बच्चे शिशु मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यह पूछना चाहता हूं?

श्री सुन्दरलाल तिवारी - नहीं, मेरे बच्चे शिशु मंदिर में नहीं पढ़े हैं.

अध्यक्ष महोदय - आप उनका उत्तर न दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष महोदय, बहादुर सिंह चौहान जहां से आते हैं, वह मेरी बहन कल्पना पारुलेकर की सीट है और यह जिस सीट पर बैठे हैं, वह भी मेरी बहन कल्पना पारुलेकर की सीट है. (हंसी)...

श्री सुन्दरलाल तिवारी - आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? या आप अपने मन की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - आपका छोटा भाई हूं, आपसे आशीर्वाद ले रहा हूं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - आप अपने मन की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - आप कृपया अपनी बात कहें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - उस सीट पर ज्यादा बोलने वाले की जमानत जप्त हुई है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - मैं जानता हूं कि उस पक्ष के सभी लोगों की यह दिल में इच्छा है कि भविष्य में मुझे यहां आने का अवसर न मिले. यह मैं जानता हूं. (हंसी)..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - जो ज्यादा बोलते थे, उनकी जमानत जप्त हुई है, उस सीट पर कम बोलो, अन्यथा अगली बार आपकी भी जमानत जप्त हो जाएगी.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - (व्यवधान)..(xx).

एक माननीय सदस्य - तिवारी जी अंतिम अवसर मानकर तो इतना नहीं बोल रहे हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - नहीं, वहां आने वाले हैं हम लोग, अगली बार उधर बैठेंगे.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - मेरा निवेदन है कि विषय पर चर्चा हो और तिवारी जी, जो स्कूलों को सरकारी किया गया है, उन्हीं पर आप बात करें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - उसको भी बताएंगे. गौर साहब आप सुनिएगा.

श्री मुरलीधर पाटीदार - उनको शौचालय सहित सरकारी किया है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - आप सुन तो लीजिए. अध्यक्ष महोदय, शेजवार साहब ने कुछ बात कही, कहने के पहले मैं यह बोलूंगा कि एक सरस्वती स्कूल है मध्यप्रदेश में, अगर आपने शासन को दिया हो तो उस स्कूल का नाम बताइएगा?(xx).

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - मैंने तो कोई बात ही नहीं की. मैंने तो यह भी नहीं कहा कि जितने भी मास्टर थे, सब तिवारी थे, मैंने क्या कहा बताओ तो आप?

श्री सुन्दरलाल तिवारी -आपको मालूम ही नहीं, हमारे गांव में 70 प्रतिशत तिवारी हैं. (हंसी)..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - आपका पूरा समय इसी में निकल जाएगा.

श्री के.के.श्रीवास्तव - अध्यक्ष महोदय, कोई और इनके गांव में रह ही नहीं पाया. (व्यवधान)..

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी नहीं पूछा कि उसके जो प्रिंसिपल साहब थे वे इनके कौन लगते थे?

श्री सुन्दरलाल तिवारी - वह भी बताएंगे.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - आप बताओगे तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन हम कहां पूछ रहे हैं कि कुल कितने स्कूल थे, कितने सौ मास्टर उसमें बाद में भरे गये, मैंने यह भी इनसे नहीं कहा कि वह स्कूल एक कमरे में चलता था कि दो कमरे में चलता था?

श्री सुन्दरलाल तिवारी - अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी, माध्यमिक शालाओं का है, उसकी दुर्दशा इस सदन में बताना एक-एक करके शुरू किया जाएगा तो मुझे लगता है कि रात्रि हो जाएगी. लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि कम से कम जिलों में कुछ चिह्नित स्कूलें कर लें और उनको एक मॉडल स्कूल के रूप में वे भी गांव में हों, जिनको आप यह कह सकें कि यह स्कूल हमारी है और सारी की सारी सुविधाएं इस स्कूल में हैं. लैब आपके किसी स्कूल में है ही नहीं. केवल परीक्षा के समय उनको नम्बर दे दिया जाता है. लाइब्रेरी किसी स्कूल में है ही नहीं. 10-5 परसेंट कोई सौभाग्यशाली विद्यालय हों तो नहीं कह सकते हैं तो मेरा यह कहना है माननीय मंत्री जी.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - तिवारी जी, आपको अपने जमाने की याद आ रही है.

श्री विश्वास सारंग - उस समय स्कूल में लाइब्रेरी भी होती थी परन्तु उसमें किताबें नहीं होती थीं.

श्री मुरलीधर पाटीदार - आजकल प्रेक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं, सब कम्प्यूटर पर हो जाते हैं.

4.00 बजे {सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.}

श्री सुन्दरलाल तिवारी -सभापति महोदय, ये लोग सही सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, ये फोटोकापी कराकर आए हैं. अभी मैंने 10 लोगों का भाषण सुना तो ये शुरू करेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने यह योजना लागू की, मंत्री जी ने यह योजना लागू की और जब अंतिम लाईन आएगी तो बोलेंगे, "लेकिन मेरे क्षेत्र में इस चीज का अभाव है, इसलिए माननीय मंत्री जी इस चीज को आप हमारे यहां प्रदान कर दें तो हमारे यह चीज खुल जाय. " इनके पास यह एक प्रोफार्मा है. अगर इतना विकास हुआ है तो अंतिम लाईनों आप यह बार-बार क्यों कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में यह दे दिया जाय, इसका अभाव है.

श्री के.के. श्रीवास्तव - सभापति महोदय, विकास की कोई सीमा नहीं है, विकास कितना भी जा सकता है. विकास हुआ है और भी विकास की संभावना है हम तलाशते हैं और विकास की मांग करते हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - अभी इनका भाषण निकाल लिया जाय तो अंतिम 10 लाईन में यह केवल अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगेंगे.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -सभापति महोदय, इनके जमाने के विकास की बात बताना चाहता हूं, यह मध्यप्रदेश दो स्टेट में बंट गया था, एक रीवा राज्य कहलाता था और दूसरा बचे हुए जिलों का एक प्रदेश था और ये रीवा के युवराज थे. (हंसी)..अब हालांकि यह बात अलग है कि अब क्या हैं मुझे नहीं मालूम? ये बीच-बीच में कभी-कभी याद करते हैं. जैसे कल यह कह रहे थे, माननीय

अध्यक्ष महोदय के बारे में बता रहे थे कि मेरे पूज्य पिताजी इस विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे हैं. वास्तव में तिवारी जी के लिए सम्मान की बात है कि वे इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और हम सब के लिए सम्मान की बात है. लेकिन दूसरी तरफ मैं यह नहीं कहूंगा(xx) . एक बात यह भी है कि ये उनके लड़के हैं. (हंसी)..

सभापति महोदय - शेजवार साहब, अब यह तय करें रीवा के युवराज आपकी तरफ हैं कि इनकी तरफ हैं?

श्री रामनिवास रावत - सभापति महोदय, वह अपमान की बात निकाल दें.

सभापति महोदय - तिवारी जी, शुरू करें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - सभापति महोदय, इसमें असलियत कुछ भी नहीं, यह तो मनोविनोद के लिए है. सभापति महोदय, मैंने जो बातें कहीं है उसमें कहीं कोई असलियत नहीं है. यह तो मनोविनोद के लिए है. (व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी -सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि जो मूलभूत ढांचा हमारे शिक्षा का है, उसमें सुधार लाने का प्रयास करें. अभी यही काम नहीं हो पाया है और हम बढ़-चढ़कर बातें कर रहे हैं. अब विद्यालय को दिवालें नहीं पढ़ाएंगी.

सभापति महोदय - समाप्त करें तिवारी जी, आपका समय हो गया.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - सभापति महोदय, अभी तो शुरू भी नहीं कर पाया, शेजवार जी हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं. मेरा सारा समय मंत्री जी से काटा जाय क्योंकि उन्हीं के लोग यह सब बोल रहे हैं. सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि अब जब किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है. जो हमारा आरटीई कानून बना, अगर उसके मानक से हम देखें कि प्रदेश में शिक्षकों की कितनी कमी है तो लगभग 41 प्रतिशत शिक्षकों प्रदेश में कमी है. अब अगर आरटीई के मानक से 41 प्रतिशत

शिक्षक हमारे प्रदेश में कम हैं तो फिर शिक्षा प्रदेश में कैसी हो रही है, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं?

श्री विश्वास सारंग - सभापति महोदय, ये आंकड़ें कहां से लाए? यह फर्जी आंकड़े यहां पर पेश कर रहे हैं. यह कहीं के आंकड़ें ही नहीं हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - यह सरकार की दी हुई किताब है.

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—सभापति जी, आज भी इनकी नियुक्ति किए हुए टीचर साल साल भर नही जाते हैं. (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी- यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश के बाद मध्यप्रदेश का नंबर है. (व्यवधान) 2014 की रिपोर्ट यह बता रही है कि तीसरी कक्षा से पांचवी कक्षा के बच्चे जिनको साधारण गणित का घटाना भी नहीं आता.

सभापति महोदय—तिवारी जी , समाप्त करें, काफी समय आपको हो गया है.

श्री सन्दरलाल तिवारी—सभापति जी ,मुझे बोलने ही नहीं दिया गया. (व्यवधान) हमारे तीसरे दर्जे से पांचवे दर्जे के बच्चे का राष्ट्रीय औसत वह 40.60 है और मध्यप्रदेश का है 23.01 ये वास्तविक तस्वीर है. तीसरी से पांचवी तक के बच्चे साधारण घटाना नहीं जानते. यह 2012 की रिपोर्ट है. (व्यवधान) आगे मेरा कहना है..मेरे समय में यह देख लिया जाय कि कितना समय इन्होने सत्ता पक्ष के लोगों ने बर्बाद किया है. ये सच्चाई सबके सामने नहीं आने देना चाहते. मेरा कहना है कि प्राथमिक शिक्षा की मध्य प्रदेश में पूर्णरूपेण अव्यवस्था है और जिस प्रदेश में शिक्षा की हालत अच्छी नहीं होगी वह प्रदेश उन्नति नहीं करेगा विकास नहीं करेगा. तो सभापति जी मेरा यह कहना है ..

सभापति महोदय—पाण्डे जी आप शुरू करें.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय(जावरा)- सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27 और 77 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—मेरा यह कहना है कि प्राथमिक शिक्षा की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान देना चाहिए और जब पहली से लेकर आठवीं तक शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा.

सभापति महोदय-तिवारी जी समाप्त करें, पाण्डेय जी ने बोलना शुरू कर दिया है. अब तिवारी जी जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जाएगा.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- (X X X)

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय- सभापति महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं शिक्षा की जितनी अनिवार्यता है (व्यवधान)

....

(x x x) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

एक माननीय सदस्य—सभापति जी,इतना व्यवधान हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है. (व्यवधान)

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय- अगर शिक्षित होते तो निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, संस्कार भी प्राप्त हो जाते और अगर संस्कार प्राप्त हो जाते तो ऐसी स्थिति सदन के समक्ष उपस्थित नहीं होती. (व्यवधान)

सभापति महोदय—तिवारी जी, आप जो बोल रहे हैं वह लिखा भी नहीं जा रहा है, पाण्डेय जी को बोलने दीजिए. तिवारी जी आप बैठ जाईए.

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय- सभापति महोदय, निश्चित रूप से तात्कालिक समय में .विगत वर्षों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता तो आज इस तरह का दृष्य हमें निश्चित रूप से नहीं मिलता. प्रशिक्षित होना, शिक्षित होना, शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है और अगर शिक्षित होते

तो संस्कार भी निश्चित रूप से आ जाते और अगर संस्कार आ जाते तो इस तरह की स्थितियां सदन के समक्ष उपस्थित नहीं होती. माननीय सभापति महोदय,

सभापति महोदय—पाण्डेय जी, आप विषय पर बोलें.

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय- सभापति जी मैने नाम लिया नहीं. तिवारी जी मेरे बड़े भाई हैं ,मैं उनके संदर्भ नहीं कह सकता. शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है. सभापति महोदय, मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस तरह के प्रायास किए हैं , यदि इस तरह के प्रयास निरन्तर किए जाते तो जिस शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में ,जिस शिक्षा के स्तर के बारे में आज हम ही आरोप लगा रहे हैं . जिन्होंने पूरा ढांचा जर्जर कर दिया था ,जिन्होंने मध्यप्रदेश में इस तरह की स्थिति ला दी थी , बहुत खराब है, बहुत खराब है, कुछ नहीं है. पालक घबरा गए थे और तब शासकीय स्कूलों की ओर निश्चित रूप से लोग नहीं जाते थे. लेकिन कई स्थानों पर इस तरह की स्थितियां भी रहीं हैं . सभापति महोदय, मैं स्वयं अपना उदाहरण दू. पहली कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी शिक्षा शासकीय शिक्षण संस्थाओं में, शासकीय महाविद्यालय तक हमने अध्ययन किया है. तब भी कमियां रहा करती थीं, लेकिन आज कमियों को सुधारते हुए ,शिक्षा के स्तर को सुधारते हुए मुख्यमंत्री जी ने पहला जो काम किया है. टोल फ्री कॉल योजना प्रारंभ की. इस योजना के माध्यम से अब, मोबाईल पर शिक्षक स्कूल में पहुंचा है या नहीं पहुंचा , मोबाईल पर उसकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है. इससे चाहे शिक्षकों में भले ही थोड़ी घबराहट हो लेकिन उनकी उपस्थिति शतप्रतिशत होने लगी है और सभापति जी, जब उनकी उपस्थिति शतप्रतिशत होने लगी तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा ही. (व्यवधान) सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आओ स्कूल चले आओ अभियान प्रारंभ किया था. यह मुख्यमंत्री जी का अभिनव प्रयास था. आओ स्कूल चले हम अभियान उन्होंने प्रारंभ किया था और उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने , तिवारी जी आओ स्कूल चले हम

अभियान के बारे में सुन लें. मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को आव्हान किया था कि इसके लिए वे प्रेरक बनें. छात्र छात्राओं को स्कूल ले जाने के लिए वे प्रेरक बनें. उन्होंने 0755-257000 एक नंबर दिया था. उस नंबर से मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेश को जोड़ने का काम किया था. पूरा प्रदेश जुड़ा था. हजारों की संख्या में प्रेरक बने थे और स्वयं सेवी संस्थाएं भी सामने आई थीं, संगठन सामने आए थे और उसका यह सुखद परिणाम रहा कि आज शासकीय स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होने के साथ साथ में ,बल्कि उत्सुकता है, प्रसन्नता है. खुशी के साथ वे वहां पर पहुंचते हैं और सभापति महोदय लगातार ,अगर पिछले वर्षों का हम अध्ययन करें , देखें तो हाईस्कूलों में जो उन्नयन किये जाने के कार्य किये गए ,वर्ष 2008-09 मे 448 हाईस्कूलों का उन्नयन किया गया और 30 हायर सेकण्ड्री स्कूलों का उन्नयन किया गया. वर्ष 2010-11 में 341 हाईस्कूलों का उन्नयन करने के साथ साथ में 50 हायरसेकण्ड्री स्कूलों का उन्नयन किया गया . वर्ष 2011-12 में 603 हाईस्कूलों का और 160 हायर सेकण्ड्री स्कूलों का उन्नयन करने का काम किया गया. इसी के साथ साथ वर्ष 2012-13 में 100 हाईस्कूलो का और 300 हायरसेकण्ड्री स्कूलों का उन्नयन किया गया. और वर्ष 2013-14 में 100 हाई स्कूलों का और 300 हायरसेकण्ड्री स्कूलों का उन्नयन करने का काम शिक्षा विभाग के द्वारा ,माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय पारस जी जैन, हमारे शिक्षा मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में किया गया है. सभापति महोदय, जहां शिक्षकों की कमियां थी, आज शिक्षकों की कमी की बात प्रतिपक्ष के लोग उठाने की कोशिश करते हैं. पहले किस तरह की स्थितियां थीं. पहले शिक्षाकर्मी किस तरह के रखे गए थे. शिक्षाकर्मियों का वेतन किस तरह का रखा गया था. कितने वेतन पर वे किस तरह की शिक्षा दिया करते थे.अभी माननीय गौरीशंकर जी शेजवार ने एक उदाहरण दिया था कि गंगा जी का उद्गम कहां से होता है, तो गंगा जी अमरकंटक से निकलती हैं 300 रूपए तो निरीक्षक ने पूछा कि भैया इस तरह की शिक्षा दे रहे हो, इस तरह की पढ़ाई करवा रहे हैं तो शिक्षा कर्मी यह कहते थे कि जितना वेतन मिलेगा, वैसी ही शिक्षा दी

जाएगी. आज शिक्षा का स्तर सुधरा है और शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जा रही है, उसके लिए उत्कृष्ट विद्यालय की कल्पना को साकार करने का काम विभाग द्वारा किया गया है. आज जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय लगातार अपनी सेवाएं देकर उत्कृष्ट शिक्षा देने का काम कर रहे हैं. सभापति महोदय, शासकीय स्कूलों की तरफ छात्र, छात्राओं का रूझान बढ़े और इसके लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण करने का काम विभाग द्वारा किया जाता है. विगत् 3-4 वर्षों की बात मैं करना चाहता हूं. वर्ष 2009-10 में लगभग 18 लाख छात्र, छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया, वर्ष 2010-11 में 19 लाख 23 हजार, 554 छात्र, छात्राओं को, 2011-12 में 20 लाख, 82 हजार 573 छात्र, छात्राओं को, 2012-13 में 23 लाख, 10 हजार, 500 छात्र, छात्राओं को और 20-13-14 में 24 लाख, 17 हजार, 203 छात्र, छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया. इस प्रकार 1 करोड़, 5 लाख, 33 हजार, 830 निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण पूरे प्रदेश भर में किया गया है और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से शिक्षा को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है.

सभापति महोदय—आप अपनी विधानसभा की चर्चा कर लें, सुझाव दे दें.

श्री राजेन्द्र पांडेय—सभापति जी, अभी तो शुरूआत की है, थोड़ा सा और निवेदन कर दूं. इसी के साथ साथ निशुल्क सायकिल प्रदाय योजना भी विभाग के द्वारा शुरू की गई. वर्ष 2009-10 में 2 लाख, 2 हजार छात्राओं को, 2010-11, 2 लाख, 8 हजार 48, 2011-12 में 5 लाख, 8 हजार, 718, वर्ष 2012-13 में 5 लाख, 7 हजार, 590 और वर्ष 2013-14 में 5 लाख, 22 हजार, 833 सायकिल वितरण करने का काम शासन के द्वारा किया गया. इस प्रकार शासकीय स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है. लगभग 19 लाख, 49 हजार, 189 सायकिलों का वितरण किया गया है. यह संख्या पड़ौस के गांव में पढ़ने जाने वाले छात्र, छात्राओं की है. अब तिवारी जी कह रहे हैं कि स्कूल वीरान पड़े हैं, स्कूलों में छात्र, छात्राएं नहीं हैं, यह जो एक करोड़ पाठ्य पुस्तकों का वितरण

हुआ, 19 लाख से अधिक सायकिलों का वितरण हुआ तो छात्र, छात्राओं की संख्या का अनुमान निश्चित रूप से तिवारी जी जैसे हमारे मित्र कर सकते हैं. इसी के साथ साथ हायर सेकंडरी स्कूलों में अध्ययनरत 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कम्प्युटर क्रय करने के लिए 25 हजार रूपए की राशि प्रति छात्र के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. लगभग 9544 छात्र, छात्राओं ने इसका लाभ लिया है. यदि इस तरह की योजनाओं के बारे में मैं विस्तार से कहना चाहूं तो निश्चित रू से काफी बात हो सकती है, लेकिन अभी जो हमारा शासन है वह एस.सी.,एस.टी. के परिवार से जुड़े छात्र, छात्राओं के लिए भी काफ प्रयास कर रहा है और इसके लिए 20 नवीन प्रि-मैट्रिक छात्रावास प्रारंभ करने की योजना प्रस्तावित हुई है और 10 आश्रम शालाएं भी खोली जाना प्रस्तावित किया है.

श्री बाला बच्चन—माननीय पांडेय जी अभी जो होस्टल्स में एस.सी.,एस.टी. के स्टुडेंट्स रहते थे, उन सबको हटाने का निर्देश आपके शासन ने दे दिया है, उसको वापिस करवाईये. बड़ी दिक्कत में बच्चे पड़ गए हैं. भोपाल में इसको लेकर परसों बहुत बड़ा एजीटेशन भी हुआ है.

श्री राजेन्द्र पांडेय—यह नीतिगत् बात है, हमारे मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—आपने बोलने के लिए नाम नहीं दिया? इसमें तो बोलना चाहिए.

श्री बाला बच्चन—आदिम जाति कल्याण विभाग आएगा, तब बोलेंगे.

श्री राजेन्द्र पांडेय—सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री शिवराज सिह जी चौहान के नेतृत्व में यह सारे कार्य कर रही है और यह सुखद संयोग है कि शासन पर जब शिवजी की कृपा हो. स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे माननीय पारस जी हों और पारस जिसको छू ले तो लोहा भी सोना बन जाता है. ऐसा काम पूरे मध्यप्रदेश में हो रहा है. मेरी भी विधानसभा क्षेत्र में काम हों, क्योंकि तिवारी जी ने अभी इस तरह की बात की है, मैं इसलिए इस मांग संख्या के

समर्थन में अपने क्षेत्र की कोई मांग नहीं कर रहा हूं. मैं निजी रूप से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा. मुझे आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद.

श्री गोविन्द सिंह पटेल (गाडरवारा)—माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग की मांग संख्या 27 और 77 के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार रख रहा हूं. आज मैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, तब से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है और सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का रूझान भी बढ़ा है. मैं 2003 और आज की 2014 की स्थिति बताना चाहता हूं. 2003 में अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, चबूतरों पर स्कूल लगते थे, अगर भवन थे भी तो खपरैल के थे कि बरसात में पानी गिरे तो बच्चों को शिक्षक छुट्टी देकर घर भेज देते थे. कई गांव में जहां भवन नहीं थे, लेकिन आज की स्थिति में कोई भी ऐसा गांव नहीं है, जिसकी शाला प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या हाई स्कूल, हायर सेकंडरी हो सब में अच्छे भवन, सब भवनों में शौचालय, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में किचन सेट बने हैं जहां बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है. अब हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल के भवन अच्छी लागत के बनेंगे, सवा करोड़ की लागत के बनेगें. जबकि पहले यह एक स्वप्न था. पहले शाला भवनों को बनाने के लिए विधायक निधि, कहीं पाठ्य पुस्तक निगम से निवेदन करते थे, लेकिन आज हर जगह चाहे गांव में देखो, चाहे शहरों में देखो, जगह नहीं बची है, भवन या अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था स्कूलों के अंदर की जा रही है. सरकार की इच्छा है कि सबको शिक्षा और सुलभ शिक्षा सबको प्राप्त हो, यह मध्यप्रदेश सरकार की कल्पना है और उसके लिए स्कूल चलो अभियान चल रहा है और 16 तारीख को प्रेरकों के माध्यम से पूरे प्रदेश में स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला स्कूलों में कराया गया और शाला त्यागे बच्चों का भी दाखिला स्कूलों में हुआ. पहले स्कूलों में बच्चे जाने से डरते थे, लेकिन सुविधायुक्त स्कूल होने से और उनका रूझान बढ़ाने के लिए मध्याह्न

भोजन दिया जाता है, जिससे गरीब परिवार के बच्चे यदि मध्यांतर की छुट्टी में घर जाते थे तो उनके मां बाप मजदूरी करने जाते थे, इसलिए फिर बच्चे स्कूल नहीं आते थे. इसलिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था चलाई गई, जिससे बच्चे स्कूल में भोजन करें और दिन भर पढ़ाई करें.

सभापति महोदय—अपनी विधानसभा की बात करें.

श्री गोविन्द सिंह पटेल—सभापति महोदय, अभी तो शुरू हुआ हूं. थोड़ा सुन तो लें, मेरी बात तो आ जाए. आपसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा समय सदस्यों को देना चाहिए, अपनी बात करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं. मध्याह्न भोजन से बच्चों का स्कूल जाने की ओर रूझान बढ़ा है. गरीब बच्चों के पास पहिनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, किताबों के लि पैसे नहीं होते थे, उनको निशुल्क गणवेष और निशुल्क पाठ्य पुस्तकें पहली से लेकर 12 वीं तक पहली जुलाई को वितरित की जाती है. जो पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम में नहीं छपती हैं, उसकी राशि उनके खातों में दी जाती है और उसकी व्यवस्था की जाती है, शिक्षकों की जो कमी है, उसको भी संविदा के द्वारा भर्ती की जा रही है. पहले तो शिक्षाकर्मी को 500 रूपए मिलते थे,500 रुपया महीना मिलता था जो कि गंगाजी को अमरकंटक से निकालते हैं लेकिन अब उनको अध्यापक का दर्जा दिया है उनका वेतन भी 4500 से 8500 रुपया किया गया है जो कि सम्मानजनक उनको वेतन दिया जा रहा है जिससे शिक्षा में गुणवत्ता भी आयी है. बाकी शिक्षा के क्षेत्र में नये शाला भवन बनना, छात्रावास बनना, आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावास बनाये जा रहे हैं जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे उनमें रहें और उसमें पढ़ाई कर सकें.सभापति महोदय, विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है इसका कहीं अंत नहीं होता है. सरकार ने खूब हाई स्कूल, हायर सेकण्ड्री स्कूल, मिडिल स्कूल दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर पर खोले लेकिन इसके बाद भी बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव से आज भी आवश्यकता है जैसे पहले दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आते थे, कहीं कहीं जीरो परसेंट परिणाम आते थे लेकिन आज वह परिणाम सुधरे हैं. 70-80 परसेंट तक भी शासकीय हायर सेकण्ड्री, हाई स्कूलों के

परीक्षा परिणाम आते हैं जो कि शिक्षा में जो सरकार ने प्रयास किया है उसमें सुखद परिणाम आये हैं. पहले बच्चियां आठवीं पास होने के बाद यदि गांव में हाई स्कूल नहीं तो बैठ जाती थीं तो वे बच्चियां स्कूल जा सकें तो उनको साइकिलें दी जाती हैं अब तो बच्चों को भी साइकिलें दी जाती हैं जो नवीं या ग्यारवीं क्लास दूसरे गांव में पढ़ने बच्चे बच्चियां जाते हैं उनको साइकिल दी जाती है ताकि पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़े. गांव की बेटी योजना चलायी जा रही है. पहले जो बारहवीं में टॉपर लड़की होती थी उसको उस योजना का लाभ मिलता था लेकिन अब तो प्रथम श्रेणी में जितनी भी बच्चियां आती हैं सबको गांव की बेटी योजना का लाभ मिलता है.

माननीय सभापति महोदय,मैं माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक शाला से हाई स्कूल उन्नयन के कुछ स्कूल हैं जिनके नाम मैं बता देना चाहता हूँ, नेवाओर, बेतपोन, रमपुरा, दहलवाड़ा,झाइनखेड़ा,रिछावोर, मारेगांव, अमाड़ा, बैहरागढ़ ग्वारी, जामगांव, पुवांरिया, बेंगवाकलां, मढ़गुला, कन्यासांईखेड़ा, किसानीगाडरवारा, स्टेशनगाडरवारा. अब कुछ हाई स्कूल से हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन की मैं बात करना चाहता हूँ, बमौरीकलां, पिपरियाकलां, मेहरागांव, मिड़वानी, आड़ेगांवकला,शहाबंद, बसौरिया, पचामा, सिंगपुरछोटा, तेंदूखेड़ा, कांगड़गांव, गांगईरायपुर, कन्यासांईखेड़ा, कन्यासालेचोका और मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूँ जो अतिथि शिक्षक हैं जो कि शिक्षकों की कमी के कारण बरसों से मदद कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनको या तो संविदा में भर्ती में उनको वरीयता मिले या उन्हें नियमित भी कर दिया जाए क्योंकि वे बात भी करते हैं और उनको अनुभव भी है तो इसी निवेदन के साथ सभापति महोदय, आपने समय दिया,बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री गिरीश गौतम(देवतालाब)—माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात को माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग का समर्थन और कटौती प्रस्ताव के विरोध में प्रारम्भ करने के लिए खड़ा हूँ. मैं तीन भागों में अपनी बात को कहना चाहता हूँ. एक तो बजट के समर्थन के लिए कुछ समय चाहूंगा.

दूसरा कुछ सुझाव देना चाहता हूँ और तीसरी मांग करना चाहता हूँ.अभी जो कटौती प्रस्ताव के पक्ष से जो हमारे वक्ता खड़े हुए और जिनका तिवनी का जो सवाल आया कि तिवनी के स्कूलों को, और उन्होंने यह उठाया कि साहब यह सरकारी स्कूलों में किसी के बच्चे नहीं जाते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग जो यहां विधानसभा के भीतर हैं, खासतौर पर जो हमारी उम्र के लोग होंगे उसमें से अधिकांश लोग, शासकीय स्कूलों से पढ़कर के आये हैं . शासकीय स्कूल से पढ़कर हायर सेकेण्ड्री किया, बीएससी किया, एमएससी किया, और लॉ किया. हमें विचार यह करना पड़ेगा कि प्रायवेट स्कूल क्यों खुले? तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस सदन को कि 1993 से लेकर 2003 के बीच में जो सरकार रही हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी जो शिक्षाकर्मी आये, उन शिक्षाकर्मियों के खुद का स्तर इस तरह का है कि वे शिक्षाकर्मी में भर्ती हो गए, खुद एबीसीडी लिखना नहीं जानते. मैं मनगवां विधानसभा से जब विधायक 2003 में बना तो मैंने एक स्कूल में देखा,उन्हीं के गांव के जो ओपनर साहब अभी चले गए,उनके गांव का एक लड़का शिक्षाकर्मी में भर्ती हुआ एक ग्राम सु सुजवार में वहां जाकर के पढ़ाने गया स्कूल में , वहां के एक ठाकुर साहब ने उनसे पूछा कौन सा क्लास पढ़ाओगे,क्या पढ़ाओगे तो उसने कहा कि हमसे तो कुछ नहीं बनता, हमको तो भर्ती कर लिया है, नाम लिया उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि उन्होंने हमको भर्ती कर दिया, हम स्कूल में चले आए तो बोले क्या पढ़ाओगे तो बोले हमसे कुछ नहीं बनता तो बोले अच्छा भाई इसको हल बैल दे दो, ये चलकर के हमारा हल जोते, सारा दिन उससे ठाकुर साहब ने हल जुतवाया और शाम को वह लौटा लिया और बहाने से भागकर के अपने गांव चला आया फिर उसका परिवर्तन कर दिया गया और मैं समझता हूँ कि इसी कारण से यह जो बार बार कह रहे हैं प्रायवेट स्कूल खुल गए, प्रायवेट स्कूल की तरफ गया काम, वह इसी कारण से हुआ है और इस कारण से तमाम् सारी परेशानियां आयी हैं पर मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस सरकार के आने के बाद, अभी हमारे भाई राजेन्द्र पाण्डेय जी ने यह कह दिया कि हम कोई मांग नहीं करेंगे, मैं आपसे

कहना चाहता हूँ, मांग हम करेंगे क्योंकि हमारी सरकार ने यह जिन स्कूलों के उन्नयन की हम बात करते हैं इनको जूनियर से हाई स्कूल किसने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ही यह हाईस्कूल हुए हैं, जूनियर स्कूल हुए हैं, प्रायमरी स्कूल खोले गये हैं. हमारी सरकार ने यह तय किया कि एक किलोमीटर से ज्यादा किसी बच्चे को हम पढ़ने ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे प्रायमरी के भीतर से, पांच किलोमीटर से ज्यादा हम हाई स्कूल नहीं जाने देंगे, आठ किलोमीटर से ज्यादा हम हायर सेकेण्ड्री नहीं जाने देंगे, उन तमाम् सारे स्कूलों की व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है तो मैं कहना यह चाहता हूँ , जरुर थोड़ी सी खामियां हैं,पहम यह सब जानते हैं कि जिस तरह नींव खड़ी होती है उस तरह महल, भवन खड़ा होता है उसी तरह से प्रायमरी शिक्षा है, यदि हमारी प्रायमरी शिक्षा कमजोर होगी तो स्वाभाविक तौर पर उसमें खड़ा होने वाला समाज, आने वाला भविष्य ठीक नहीं होगा और इसके चार भाग है. एक भाग वही विद्यार्थी है जो बच्चा आता है, स्कूल में भर्ती होने आता है वह है जिसे हम बीज कह सकते हैं और बीज में खाद पानी देने का कामि शिि शक्षा ही करती है जिससे बड़ा पेड़ पैदा होता है भविष्य और काफी फलदार पेड़ पैदा होता है . दूसरा भाग हमारा शिक्षक है, हमारा शिक्षक कुम्हार की भूमिका अदा करता है जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को काली मिट्टी या कच्ची मिट्टी को चाक में चढ़ाकर उससे मूर्ति तैयार करता है और जब मूर्ति रख दी जाती है तो उसकी हम पूजा करते हैं उसी तरह से शिक्षक का काम है कि वह शिक्षा पढ़ाकर के हमारे उस बच्चे को भगवान की तरह या पूज्य के योग्य बनाता है या आदशर्श पैदा करता है , तीसरा भाग हमारा जो उसके सुरक्षा का काम करते हैं,चौथा भाग हमारी सरकार का है जो व्यवस्था करती है और वह व्यवस्था इन्होंने की . मैं 2003 के पहले की याद दिलाना चाहता हूँ, तमाम् गांव के भीतर हम दौरा करते थे, कहीं भी स्कूल भवन नहीं था और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब हम 2014 में खड़े हैं , कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसका भवन नहीं बना हो इस प्रदेश के भीतर, मैं आपसे यह निवेदन

करना चाहता हूँ , यह हमारी सरकार की उपलब्धि है इसलिए हम इस बजट का समर्थन करते हैं. मैं तमाम् सारे सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो स्कूल की बात आयी है इनके जमाने में हाईस्कूल का उन्नयन नहीं होता था. क्यों नहीं होता था, प्रायवेट स्कूल खोलकर एक घर से 44-44 आदमियों को सरकारी करते थे इसलिए उनको स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं थी.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—गिरीश भैया, ये लोग हाईफाई होते थे इसलिए हाईस्कूल की चिन्ता नहीं करते थे.

श्री गिरीश गौतम-- हाईफाई नहीं थे, घर की भर्ती करना था.

श्री बाला बच्चन—सैकड़ों की संख्या में हाई स्कूल से हायर सेकण्ड्री होते थे, मिडिल से हाई स्कूल होते थे, ऐसा नहीं है, निरन्तर प्रक्रिया है, उस समय भी बहुत हुए है.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—आज भी भवन नहीं है, आज भी शिक्षक नहीं है, जीरो बजट में खोल दिया.

श्री रामकिशोर दोगने—सभापति महोदय, आज भी अतिथि शिक्षकों से पढ़ाया जा रहा है. (व्यवधान)

श्री कमलेश्वर पटेल—कांग्रेस सरकार ने जो व्यवस्था बनायी थी,वही व्यवस्था चल रही है, प्रभारी प्राचार्य के भरोसे स्कूल चल रही है, विषय विशेषज्ञ नहीं है.सब कामचलाऊ सरकार चल रही है.

श्री मनोज पटेल—पहले भी स्कूल खुलते थे, उन्नयन होता था पर वे इनके प्रायवेट स्कूल ह्म हुआ करते थे .

श्री गिरीश गौतम—स्कूल खुलते थे जीरो बजट में, अभी पिछली केबिनेट में 2002 के जो शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूल थे जिनको आप देते थे उनका हायर सेकण्ड्री या हाई स्कूल में उन्नयन कर लिया था वह सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था,वह इसी सरकार ने पिछले हफ्ते के अन्दर

उन सब को शासकीय घोषणा की है,आवंटन दिया है. आप जाकर के घोषणा कर देते थे, जीरो बजट में खुल जाता था कहीं कुछ नहीं होता था कोई भवन नहीं रहता था .अब हमारी हाईस्कूल खुलती है ,हमारी हायर सेकेंडरी खुलती है, हमारी जूनियर स्कूल खुलती है तो उसके साथ बिल्डिंग का पैसा भी सेंक्शन किया जाता है. आपकी सरकार और इस सरकार में यह फर्क है.

श्री कमलेश्वर पटेल-- सर्व शिक्षा अभियान के तहत गांव गांव में स्कूल खोले गये थे.

श्री गिरीश गौतम-- हाँ खोले गये थे इसलिए कहीं बिल्डिंग नहीं थी.

श्री सचिन यादव—मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति यह सारी केंद्र सरकार की देन है. कांग्रेस पार्टी की देन है.

श्री गिरीश गौतम-- सभापति महोदय, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं. अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत हमारे बच्चों को जो बीपीएल कार्डधारी हैं, उनको भी प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है. मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इन प्राइवेट स्कूलों में जो भर्ती के नियम बनाये गये, प्राइवेट स्कूलों में टारगेट ,यह चार तारीख को मेरा प्रश्न था उसके जवाब में स्कूल की तरफ से आया था उसमें यह था कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल हैं ,कई स्कूल हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं. उसमें टारगेट 50 है उसकी पूर्ति केवल 1 करके की गई है . 50 में से 1 भर्ती हुआ, 36 में 2 भर्ती हुए. यह 4 जुलाई का मेरा प्रश्न था. मेरा आग्रह यह है कि बहुत अच्छी योजना है हमारे उन लोगों को प्राइवेट स्कूल में मौका मिलना चाहिए .केवल मेरा उसमें सुझाव यह है कि जिस तरह से स्कूल चले हम का नारा हम देते हैं. हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाने के लिए ड्राइव करते हैं उसी तरह से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि उन बीपीएल कार्डधारी बच्चों को भी ढूंढकर उनकी पात्रता के आधार पर स्कूल में ले जाकर के भर्ती करायें, यह मेरा सुझाव है. दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो अतिथि शिक्षक अभी भर्ती हो रहे हैं ,यह अभी आ गया है कि माइनस पेंशन पर अतिथि शिक्षक भर्ती किये जाएंगे. कोई शिक्षक यदि, 40

हजार 38 हजार वेतन पा रहा है . उसकी पेंशन 18 हजार बनी , 20 हजार उसका शेष बचा तो 18 हजार माइनस करके 20 हजार में उसे अतिथि शिक्षक रखा जा रहा है .मेरा आग्रह है कि आज हमारे काफी पढ़े लिखे नौजवान हैं , जो चार-पांच हजार रुपये में काम करने को तैयार हैं तो यदि चार-पांच हजार में लोग काम करने को तैयार हैं तो 20 हजार हम देकर के क्यों अतिथि शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं. इसलिए उस पर रोक लगाई जाए ,यदि वह कोई शिक्षक रिटायर हो गया है तो उसे भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है. हमारे नये नौजवान हैं उनको अवसर दें इससे नये लोगों रोजगार मिलेगा और वह ठीक से पढ़ाने का भी काम करेगा. सभापति महोदय, तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि पहले हमारे जमाने में बागवानी शिक्षा अनिवार्य थी आजकल उसको बंद कर दिया गया है उसको भी अनिवार्य किया जाये तो उचित होगा. मैं दो-तीन मांग करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, आपको टोकना नहीं पड़ेगा. सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं का कस्तूरबा गांधी छात्रावास , फरहदा एक गांव है, मऊगंज विकासखंड में, यह इसमें फरहदा के नाम से भी मंजूर है , आपके जमाने में तीन चार साल पहले कोई रहे होंगे , उन्होंने तिकड़म करके उसका स्कूल का जो भवन बना वह भवन किसी दुग्गमा में खोल दिया गया और वह बार-बार ऑर्डर होता है कि उसको बदलकर के दुग्गमा ले जाया जाये, मैं बार-बार आपत्ति करके उसको रोक देता हूं तो मेरे उसमें दो आग्रह है कि हमारे कस्तूरबा गांधी फरहदा के लिए भवन का पैसा दे दे और दुग्गमा में भवन बना हुआ है तो वहाँ दूसरा खोल दे यह मेरी मांग है. दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ जिन स्कूलों का उन्नयन किया है, जूनियर से हाईस्कूल करना है,मैं कुछ नाम बता देता हूं उनको जोड़ लेने की कृपा करेंगे. नईगढ़ी ब्लॉक में हमारा माढ़व है ,डिहियापड़ान है ,पुर्वा है, जिलेहड़ी है,मऊगंज में सूजी है, सरईसेगर है, रामपुर है, छुहिया है . रायपुर कर्चुलियान में सिरसा है,कांटी है, पथरहा है.इनको हाईस्कूल में उन्नयन करना है और दो जो हाईस्कूल आपने खोले थे उनका पांच साल पूरा हो गया है . नईगढ़ी में शिवराजपुर है और मऊगंज में खैरा है इन

हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी करने की मैं मांग करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इनको जोड़ने का काम करेंगे. अभी खेल मैदान की बड़ी बात हो रही थी मेरे क्षेत्र में दो बढ़िया मैदान हैं एक नईगढ़ी में और एक देवतालाब में . हायर सेकेंडरी स्कूल का बड़ा मैदान है उसको मिनी स्टेडियम में खेल परिसर के रूप में बढा़ने का काम करेंगे मैं इसी आशा, विश्वास के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए कटौती प्रस्तावों का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा(मुंगावली)-- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27 और 77 का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. माननीय सभापति महोदय, आजकल प्राइमरी स्कूल और हाईस्कूलों में गुणवत्ता की समस्या है . गुणवत्ता वहाँ ठीक होनी चाहिए. ड्रॉपआउट रेट कम होना चाहिए और साक्षरता का प्रतिशत बढ़ना चाहिए यह शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रमुख चैलेंजेस हैं. अभी हमारी राष्ट्रीय साक्षरता दर 74 परसेंट है औऱ मध्यप्रदेश की साक्षरता दर 70 परसेंट है. राष्ट्रीय पुरुष साक्षरता दर 82 परसेंट है और मध्यप्रदेश पुरुष साक्षरता दर 80 परसेंट है . महिला साक्षरता में राष्ट्रीय साक्षरता दर 65 है और मध्यप्रदेश में 60 परसेंट है और खासकर अनुसूचित जाति की पुरुष साक्षरता 72 परसेंट और महिला की सिर्फ 43 परसेंट है . कुल 58 परसेंट अनुसूचित जाति में है औऱ अनुसूचित जनजाति में पुरुष की साक्षरता 53 परसेंट है और महिला की 28 परसेंट है यह दोनों बहुत चिंताजनक हैं. इसको ठीक करना होगा.क्योंकि साक्षरता बढ़ाने से हमारे देश की दो प्रमुख समस्याओं का निदान हो सकता है एक जनसंख्या वृद्धि औऱ दूसरा भ्रष्टाचार का. यदि केरल और तमिलनाडु में 95 प्रतिशत साक्षरता है तो वहाँ फर्टिलिटी रेट कम है. इसका मतलब यह है कि यदि आप लोगों को केरल औऱ तमिलनाडु की तरह साक्षर कर दें तो जनसंख्या समस्या अपने आप हल हो जाएगी. दूसरी समस्या भ्रष्टाचार की है इसके लिए लोगों में अवेयरनेस लाना होगा, लोगों को बोलना सिखाना पड़ेगा, लोगों को गलत चीज का विरोध करना सिखाना पड़ेगा. पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम में एडल्ट एजुकेशन में इसको लिया जा सकता है .

इस पर भी जोर दिया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके. साक्षरता के कारण हमारी यह दो प्रमुख समस्यायें हल होती हैं . जब केरल और तमिलनाडु कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है राष्ट्रीय औसत से कम है और इसको राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर ले जाना चाहिए. एक बात और है कि शिक्षा के सुधार के लिए कोठारी कमीशन बना, सैम पित्रोदां का नॉलेज कमीशन बना. यह हालत है कि तांगा चलाने वाला या स्कूटर चलाने वाला भी कोशिश यह करता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े सरकारी स्कूल में ना पढ़े. क्योंकि उसको आपकी स्कूलों की गुणवत्ता पर विश्वास नहीं है. इसको ठीक करने के लिए ,एक इवान इलीफ साहब हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी समाज को स्कूलों से मुक्त करो. कई लोग यह बोलते हैं कि यदि आपके प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूल न भी हों तो भी बच्चे पढ़ सकते हैं , बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ आप एक काम कर दीजिये . बीपीएल, एससीएसटी के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में कर दीजिये और जितने भी अध्यापक हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इन सब लोगों को आप रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी से सोसायटी बना कर इनके स्कूल खुलवा दीजिये एंड लेट दैम काम्पीट विथ सरस्वती शिशु मंदिर और दूसरे क्रिश्चियन स्कूल्स और निजी स्कूलों से उनको काम्पीट करने दीजिये ताकि जो लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वह भी काम्पीटीशन में आएं और पढ़ायें तो स्कूलों की जरूरत ही नहीं है . आपका सारा बजट बच जाएगा. यह स्थिति आ गई है. सभापति महोदय, हमारी शिक्षा में शोषित , पीड़ित लोगों के लिए कुछ नहीं है . गुणवत्ता तो कम है ही.ऑल फ्रायरे साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है डेमोक्रेसी ऑफ द ऑपरेस्ट एंड सेलीब्रेशन ऑफ अवेयरनेस . इसमें उन्होंने बताया है कि हमारी शिक्षा पद्धति में शोषित, पीड़ित तबके के लिए कुछ भी नहीं है. एक गुन्नार रेडेल साहब हैं जिनको उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा पर नोबल पुरस्कार मिला है उऩ्होंने हमारी स्कूलों शिक्षा पद्धति को औपनेवेशिक शिक्षा पद्धति बताया है . तो इतनी सब आलोचनाओं के बाद भी अगर हम इसको ठीक

करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा. आप बच्चों को मध्याह्न भोजन क्यों देते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे आकर्षित हो स्कूलों में आएं. लेकिन उसके बाद भी ड्रॉप रेट बहुत है . स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बहुत है और बच्चों को भोजन बहुत खराब मिलता है , बहुत घटिया क्वालिटी का मिलता है ऐसा कि आप खा नहीं सकते. यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है क्योंकि जब तक आप स्कूलों को इन्टरेस्टिंग नहीं बनाओगे तब तक बच्चे टिकेंगे नहीं. न्यूजीलैंड में एक सिल्विया स्टर नाम की महिला है उसने मावरी जाति के बच्चों को उनकी लोकल भाषा में, डायलेक्ट में, गाकर बच्चों को पढ़ना सिखाया तो जब तक आप स्कूल्स को इंट्रस्टिंग नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा और बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमारा इतना करोड़ों रुपये का खर्चा हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को, खासतौर से एक और बात पर मैं जोर देना चाहूँगा कि आप 35 हजार शिक्षक भर्ती कर रहे हैं. मेहरबानी करके यह ट्रांसफर समस्या, मैंने की थी, जब मैं शिक्षा मंत्री था, अध्यापकों की बहुत भीड़ होती थी, हर गाँव में अध्यापक नेता है, सरपंच, वगैरह सब, उनका बड़ा प्रेशर होता था तो सैकड़ों लोग मेरे मकान पर ट्रांसफर के लिए खड़े रहते थे. मैंने समझा कि मैं शिक्षा में क्या सुधार करूँगा, मैं तो ट्रांसफर मिनिस्टर बन गया. मैंने सिर्फ एक तीन लाइन का ऑर्डर निकाला, मैंने देखा कि जो गृह जिले में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे देने को तैयार रहते हैं क्योंकि वह अपने गाँव में पोस्टिंग करा लेते हैं और उनको न किराया देना पड़ता है न खाने का खर्चा होता है, लाख, दो लाख, तो मैंने एक ऑर्डर किया कि हर व्यक्ति अपने गृह जिले में पोस्ट हो जाएगा, एक तीन लाइन का आवेदन दीजिए और जितने लोग थे उन सबको हमने गृह जिलों में पोस्ट कर दिया और जिले के अधिकार हमने जिला पंचायत को दे दिए. अगर आप यह करेंगे तो कोई भी यहाँ भोपाल आने का कष्ट ही नहीं करेगा. आज सैकड़ों अध्यापक यहाँ घूमते फिरते हैं. लड़कियों की शादी हो जाती है वे अपने पति के यहाँ जाना चाहती है आप पोस्ट नहीं कर पाते हैं. यहाँ के कर्मचारी उनको भाव ही नहीं देते हैं तो मेहरबानी करके आप

35 हजार शिक्षकों की भर्ती रोक दीजिए. हर टीचर को उसके गृह जिले में भेज दीजिए और रिक्रूटमेंट में करप्शन खत्म करने के लिए, व्यापम से आप शिक्षा लीजिए. इसके लिए मैंने क्या किया था कि ग्राम वाइज विज्ञापन निकाला था, स्कूल वाइज विज्ञापन निकाला था और जिस बच्चे को हाइएस्ट मार्क्स मिला उसको टीचर बना दिया. गाँव के टीचर को गाँव में आप बनाएँगे तो एक सोशल प्रेशर होगा, अल्टीमेटली लोगों में अवेयरनेस आ रही है. हो सकता है कि वह शाम को अपना खेत और दुकान देखे पर दिन में उसे पढ़ाना पड़ेगा.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर-- उसमें भी उसी गाँव के तो वह वहाँ जाते ही नहीं. जैसे सचिवों की स्थिति आई है फिर वह वहाँ गाँव का नेता बन जाता है इसलिए वह संभव भी नहीं है...(व्यवधान)..

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- सोशल प्रेशर बनाने की जरूरत है...(व्यवधान)..बाहर का है तो वह 12 बजे आता है 3 बजे ट्रेन या बस से चला जाता है. दो शिक्षक होते हैं तो एक का आवेदन दूसरे के पास तैयार रहता है 15 दिन एक शिक्षक पढ़ाता है, कोई आ गया तो वह आवेदन दे दिया तो इसको ठीक करने के लिए आप भर्ती में लोकल कर दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी पढ़े लिखे बच्चे कम थे तो उत्तर प्रदेश और बिहार, अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ टीचर बन गए थे. आप स्टटे वाइज रिक्रूटमेंट करेंगे तो कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे और सब बाहर के लोग आकर रिक्रूट हो जाएँगे तो आप गाँव के बेस्ट टेलेंट को वहाँ स्कूल में दीजिए जिसके सबसे ज्यादा नंबर हैं, तो यह ट्रांसफर समस्या हल करें और रिक्रूटमेंट रोक कर हर टीचर को उसके गृह जिले में भेजें. यह आपको मेरा सुझाव है. धन्यवाद, जयहिन्द.

श्री मुरलीधर पाटीदार(सुसनेर)-- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा विभाग की मांग संख्या 27 एवं 77 का जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और विपक्ष के द्वारा लाए हुए कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूँ.

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है. अगर हम किसी देश की, समाज की, तरक्की कुछ साल के लिए चाहते हैं तो हमें अच्छी खेती को बढ़ावा देना चाहिए. अगर हम चाहते हैं कि इन सबकी तरक्की कुछ दशक के लिए हो, तो अच्छे बगीचों को बढ़ावा देना चाहिए और हम चाहते हैं कि इन सबका विकास जन्म जन्मान्तर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक होता रहे तो अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए. यह वह सदन है जहाँ निश्चित तौर पर इस दिशा में माननीय शिवराज जी प्रयास कर रहे हैं. अभी आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पर है तो स्कूल चलो अभियान पर है. वह स्वयं जा रहे हैं, जिस जिले में भी भ्रमण कर रहे हैं एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि स्कूल चलो अभियान कहाँ कैसा चल रहा है, हमारे माननीय मंत्री जी भी, राज्य मंत्री और पूरा शिक्षा विभाग का महकमा इसी अभियान में लगा हुआ है और निश्चित तौर पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 99 प्रतिशत बच्चे इस साल स्कूलों में प्रवेश ले ही लेंगे उसमें कहीं कोई शंका कुशंका वाली बात ही नहीं है. एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि विभाग कई हैं लेकिन यह ऐसा विभाग है इसमें 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं. याने मध्यप्रदेश शासन के सब विभाग एक तरफ और शिक्षा विभाग अपने आप में एक तरफ इतना बड़ा है कि केवल हम 12 वीं तक की अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ बच्चे हमारी स्कूलों में प्रवेश लेते हैं पहली से 12 वीं तक. मैं इस सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को एवं राज्य शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ. शिक्षा विभाग से जुड़ा पूरा महकमा वह भी इसका हकदार है. सभापति जी, 2008 से 2014 तक 1592 माध्यमिक शालाओं का और 840 हायर सेकंडरी का उन्नयन किया.

सभापति महोदय—पाटीदार जी, अब अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ सुझाव दे दें.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- सभापति जी, मेरा निवेदन है कि मैं अन्य सदस्यों से इसमें 5 मिनिट का समय ज्यादा लेना चाहूँगा.

सभापति महोदय-- बहुत सदस्य हैं.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- मैं सभी माननीय सदस्यों और हमारे माननीय मंत्री जी से निवेदन कर लूंगा कि इसके लिए मेरे को 5 मिनिट का अतिरिक्त समय दें.

सभापति महोदय-- आप पहले अपने सुझाव दे दीजिए. वह ज्यादा बेहतर रहेगा.

श्री मुरलीधार पाटीदार-- सभापति जी, मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस व्यापम की बात, हमारे माननीय सदस्य जिसका विरोध करते रहते हैं. मैं उसी पर आना चाहता हूँ. 42 हजार शिक्षकों की और उसके पहले भी लगातार भर्ती होती रही है. जब 1995, 1998, 2003 के पहले जो भर्तियाँ होती थीं तो मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ कि अभी हमने प्रमोशन की लिस्ट बनवाई तो जनपदों में उनके वह आदेश ही नहीं मिले, रिकार्ड ही गायब था. जनपद, जिला पंचायत जिन्होंने भर्ती की वह रिकार्ड ही गायब था इसीलिए ऐसी परिस्थिति बनी कि निचले स्तर पर दबाव नहीं बने, भ्रष्टाचार न हो, व्यापम के माध्यम से लगातार भर्ती हो रही है. सभापति महोदय, जो एसटीएफ जाँच कर रही है यह हमारे लिए फक्र की बात है कि अगर कहीं कमी है, जहाँ इन्सान है वहाँ कहीं न कहीं विसंगति होती है और उस विसंगति को दूर करने का पूरी सरकार प्रयास कर रही है. मैं निवेदन करना चाहूँगा हर स्कूल का अपना भवन है, बाउंड्री वॉल है और टॉयलेट भी है, एक सदस्य ने कहा कि टॉयलेट नहीं है, मैं हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि थोड़ी साफ सफाई की ओर अगर और ध्यान रहेगा तो चार चाँद लग जाएँगे. सरकार ने 102 मॉडल स्कूल खोले. 102 ब्लाक में 102 मॉडल स्कूल खुले हैं निश्चित तौर पर इन मॉडल स्कूल्स में बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है. जिला स्तर के उत्कृष्ठ विद्यालय अपने आप में उत्कृष्ठ हैं. ब्लाक स्तर पर भी उत्कृष्ठ विद्यालय हैं. मेरा यहाँ विनम्र आग्रह है कि मॉडल स्कूल प्रदेश के सभी ब्लाकों में खोले जाएँ. मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही खोले जाएँ. सभी ब्लाक मुख्यालय पर खोले जाएँ, जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के हैं. इसी प्रकार से मैं एक और बात की तरफ आपका

ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ कि कोई योजना ऐसी नहीं है जो हमारे माननीय शिवराज जी के द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा लागू नहीं की गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ओपन स्कूल में 2003 में....

सभापति महोदय-- पाटीदार जी, एक मिनिट में अपने सुझाव दे दीजिए.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- सभापति जी, ओपन स्कूल के माध्यम से 2003 में मात्र 31 हजार छात्र दसवीं में बैठते थे, 2013 में जिनकी संख्या 1 लाख 18 हजार है. इसी प्रकार से 12 वीं में 13 हजार जिनकी संख्या थी, 2003 में जिनकी संख्या 62170 हो गई, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है. इसके अलावा 2003 के पहले गुरूजी, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से भर्ती होती थी, माननीय शिवराज जी ने सबका एक कॉमन महकमा बनाया. सबका अध्यापक पदनाम सम्मान के साथ दिया और यही नहीं उस समय जिनका वेतन पाँच सौ रुपये से एक हजार रुपये था. आज उनका वेतन चौदह हजार रुपये से लगाकर अट्ठाईस हजार रुपये तक है. सभापति जी, पिछले साल, 2000 करोड़ का बजट प्रावधान एकमुश्त दिया और हर साल एक एक बजट का 2016 तक करने का प्रावधान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया. सभापति जी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ कि विभाग प्रमोशन उतनी सक्रियता के साथ नहीं कर रहा है. सभी अध्यापक संवर्ग और शिक्षक संवर्ग का प्रमोशन किया जाए और वरिष्ठ अध्यापकों के लिए 17 साल में प्रमोशन की नीति नहीं बनना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारी सक्रियता या गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है. यहाँ सदन में सभी माननीय सदस्य मौजूद हैं मेरा निवेदन है कि हम जिस गाड़ी से आए उस सबका बीमा है लेकिन अध्यापक संवर्ग का अभी तक बीमा नहीं किया जाना कहीं-न-कहीं प्रश्न चिह्न खड़ा करता है. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बीमे के बारे में वे हमें आश्वस्त करें. पुरुष अध्यापक 17 साल से एक ही स्थान पर नौकरी कर रहे हैं वे अपने मां-बाप की सेवा करना चाहते हैं उन पुरुष अध्यापकों को

जिन्दगी में कम से कम एक बार अपने घर आने का मौका मिलना चाहिये. उसमें विभाग की ओर से यह बहानेबाजी नहीं होना चाहिये गांव के स्कूल खाली हो जायेंगे. ऐसा नहीं है गांव में फिर नई भर्तियां हो जायेंगी. मिडिल स्कूलों में 1996 के बाद से प्राचार्यों के पद नहीं भरे गये हैं इस पर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिये इससे शिक्षा विभाग में कसावट आयेगी. 8 वीं और 5 वीं की परीक्षा जब तक बोर्ड की नहीं होगी हम गुणवत्ता में कहीं-न-कहीं पीछे रहेंगे. आपने बोलने का समय दिया इसके लिये धन्यवाद.

श्री जितू पटवारी (राउ)—माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शिक्षा के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद. हमारे सदन के साथी, ब्यूरोक्रेसी के लोग व दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग. शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा सार्थक न हो तो मैं नहीं समझता कि यह सदन के समय के सदुपयोग के लिये ठीक रहेगा. जब हम परिवार में बच्चे को बड़ा करते हैं उसको अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं तो चरित्र की शिक्षा के मामले में पूरा परिवार चिन्तित रहता है और मैं समझता हूँ कि सरकार भी चारित्रिक शिक्षा बच्चे को मिले इसके लिये चिन्तित रहती होगी. इसकी कमी प्रदेश और देश में देखने को मिल रही है. जो छोटी-छोटी घटनायें बच्चों से संबंधित होती हैं या बच्चों के द्वारा होती हैं उससे हमें इस बात का अहसास होता है कि चारित्रिक शिक्षा को लेकर प्रदेश में किस तरह की अनियमितता या लापरवाही का वातावरण बना हुआ है.

सभापति महोदय, स्कूल चलो अभियान के तहत अभी मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार ने पूरी ताकत से जितनी पब्लिसिटी हो सकती थी करने की कोशिश की, मुख्यमंत्रीजी भी कई जगह गये, शिक्षा मंत्रीजी भी गये. हम सब विधायकों को भी निर्देश थे हमने भी कोशिश की. परन्तु इसका कितना फायदा प्रदेश के बच्चों को हुआ. पिछले साल जब स्कूल चलो अभियान नहीं हुआ था और इस साल हुआ क्या इससे हमें कुछ फायदा हुआ और इसमें कितना खर्च हुआ? इसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिये थी वह थोड़ी कम दिखती है और यह इस बात से पता चलता है कि स्कूल में

शिक्षकों की कमी है. 80 प्रतिशत स्कूलों में विषय के संदर्भित शिक्षकों की कमी है. मैं समझता हूं मुरलीधर जी इस विषय में मुझसे बेहतर बता सकते हैं. मेरी विधान सभा में ऐसी 20 जगह हैं जहां पर भौतिक विषय के 10 बच्चे हैं पर वहां पर बच्चों के लिये शिक्षक नहीं हैं. 4-5 स्कूलों में, अलग-अलग, छोटे-छोटे 5-5, 10-10 विषय पर बच्चे होते हैं पर शिक्षक नहीं होते हैं. ऐसा कुछ वातावरण बने कि 10-10 बच्चे हों तो 30 बच्चे एक स्कूल में करके शिक्षक अपाइंट हो शिक्षा मंत्रीजी का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. साथ ही शिक्षकों से कितना काम करवाते हैं आप.

4.57 बजे

सदन के समय में वृद्धि

स्कूल शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

सभापति महोदय-- स्कूल शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय मैं समझता हूं. मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई.

श्री जितू पटवारी—माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता रहा था कि आप शिक्षकों से कितना काम लेना चाहते हैं. शिक्षकों से निर्वाचन का काम करवाते हैं, हम सब राजनीतिक वातावरण में काम करने वाले लोग हैं, मुरलीधर जी शिक्षा कर्मी ही थे, शिक्षाकर्मी कांग्रेस की देन थी, ठीक हैं जहां भी हैं जिस जगह भी हैं ठीक जगह पर हैं.

सभापति महोदय, बड़ी गंभीर बात यह है कि शिक्षकों से हम इतना काम लेते हैं कि उनका जो मूल काम है उससे हम भटक जाते हैं. 80 प्रतिशत स्कूलों में प्रायमरी के बाद, मिडिल स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नकल के माध्यम बच्चों का रिजल्ट सुधारने के लिये शिक्षक छूट देते हैं. यह ईमानदारी की बात है कोई एलिगेशन नहीं है.

श्री मुरलीधर पाटीदार—कपिल सिब्बल जी ने परीक्षायें तो बंद करवा दीं.

श्री जितू पटवारी—सभापति महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि शिक्षा का जो स्तर होना चाहिये उसमें हमें गंभीर होने की आवश्यकता है. विधान सभा में जितने ब्यूरोक्रेटस बैठे हैं यह तो अपनी जगह कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस हैं पर क्लर्क रेंक के या जो प्यून हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं. ईमानदारी की बात यह है कि इतने विधायक हैं बताइये किसी एक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो. मुख्यमंत्रीजी भोपाल के मॉडल स्कूल में पढ़े हुए हैं उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं. आप शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करें और शिक्षा के लिये हम अपने आपको बेइमानी के साथ पेश करें तो इसके लिये हम सब दोषी हैं.

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूँ. मेरे भाव किसी को क्रिटीसाइस करने के नहीं हैं पर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये हम सब को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे. मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि गांव-गांव में प्रायवेट स्कूल खुल रहे हैं. आने वाले समय में यह देखने में आयेगा कि हम चाहे कितना भी खर्च करे, सरकार को एक न एक दिन सरकारी स्कूल बंद करना पड़ेंगे. इस तरह का वातावरण बन रहा है. मेरा अनुरोध है सरकार को इस ओर पहल करनी चाहिये. ब्यूरोक्रेटस यहां बैठे हैं वे अगर इस बात पर गहराई से विचार करेंगे तो कहीं न कहीं इस बात का आभास होगा कि यह सच है कि आने वाले समय में हमें ओर ज्यादा, पूरी ताकत से, ईमानदारी के साथ और खासकर समाज में वे लोग जो ऊंचे दर्जे पर बैठे हैं जिनको लोगों

ने सम्मान दिया है वे भी बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ायेंगे तो शिक्षा के सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी. धन्यवाद.

डॉ. कैलाश जाटव (गोटेगांव)—माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरीके से मध्यप्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने काम किया है और जिन योजनाओं पर काम चल रहा है वह स्थिति बताती है कि आज कांग्रेस की क्या हालत हो गई है. वर्तमान समय में हम शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा कर रहे हैं मैं इसके समर्थन में हूं और मध्यप्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं का समर्थन करता हूँ.

सभापति महोदय, वर्तमान स्थिति में माननीय मंत्री महोदय को मैं कुछ विषय से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो सरकार की योजनायें है वे आपकी अधिकारिक बैठकों में तो बहुत बढ़िया हैं, संभाग स्तर पर भी बढ़िया हैं लेकिन संभाग स्तर से जब यह जिला स्तर पर पहुंचती हैं वहां से यह लचर होना शुरु होती हैं. बात बहुत कड़वी कर रहा हूँ लेकिन यह शिक्षा का विषय है इसको राजनीति से न जोड़ा जाये और मैं उन अधिकारियों को भी सीधा यहां से संबोधित कर रहा हूँ.

सभापति महोदय—आप अधिकारियों को सीधे संबोधित न करें आप सदन को ही संबोधित करें.

डॉ. कैलाश जाटव—सभापति महोदय, सदन के माध्यम से बात वहीं जाती है. मेरा यह कहना है कि जिन योजनाओं को हम ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर रहे हैं वहां कि वर्तमान में जो स्थिति हमने देखी है उस स्थिति में जिन स्कूलों का निर्माण कार्य हो रहा है उन स्कूलों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय मंत्रीजी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा. वहां पर जो टायलेट्स हैं वे सिर्फ कुछ खास शिक्षकों के लिये ही खोले जाते हैं बच्चों के लिये नहीं खोले जाते हैं. बहाना यह दिया जाता है कि वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं है इसलिये बच्चों को टायलेट्स इस्तेमाल नहीं करने दिये जाते हैं. इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक स्कूल में एक सफाई कर्मचारी जरुर रखा

जाये. ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहां पर पहले पीटी टीचर होता था आजकल पीटी टीचर स्कूलों में कहीं पर नहीं है.गणित और संस्कृत टीचरों की भी हमारे स्कूलों में भी कमी है। यह देखने में भी आ रहा है कि स्कॉउट गाईड की व्यवस्था की भी हमारे स्कूलों में बहुत कमी है, या कहीं पर है ही नहीं। हमारे सरकारी स्कूलों की जो जमीनें हैं वह ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण के क्षेत्र में आ रही है। वहां के शिक्षक लोग वहां के ग्रामीणों से लड़ाई झगड़ा करते हैं इसलिये बॉऊंडीवाल की व्यवस्था मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है। स्कूल भवन का जो निर्माण होना चाहिये जिस तरीके का वहां निर्माण कार्य होना चाहिये, वह भी नहीं हो रहा है। स्कूल का जो पहुंच मार्ग है जो गांव से जो स्कूल तक का मार्ग है वह भी कच्ची होने के कारण बरसात में काफी दिक्कत आती है। उसके ऊपर ध्यान देंगे तो गोटेंगाव विधान सभा के लिये काफी अच्छा होगा। गोटेगांव विधान सभा में हमारा एक ऐतिहासिक स्कूल है जो वर्तमान में उत्कृट विद्यालय है, आप उस तरफ आयेंगे तो देखेंगे वह बिल्कुल जर्जर हालत में है। उसकी व्यवस्था और गुणवत्ता का अगर ध्यान रखा जाए तो वह स्कूल बहुत अच्छा हो सकता है। रानी दुर्गावती बालिका विद्यालय है उसकी उन्नयन कर हाईस्कूल कर दें। श्रीनगर स्कूल को अगर हाईस्कूल कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं जैसे हमारे माननीय कांग्रेस साथियों ने बोला है, एक उदाहरण के तौर पर हमारी देवसर विधान सभा है यहां पर दो शासकीय विद्यालय कंजी और बंधा हैं। यहां पर 15 वर्षों से हमारे (xx) शिक्षक जो भर्ती हुए थे, वहीं शिक्षक आज भी हैं, वह स्कूल नहीं जाते हैं इसकी जांच करवा लें। माननीय सभापति जी एक और जानकारी देना चाहता हूं, जिस समय कांग्रेस चुनाव में जाती थी उस समय उस समय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होती थी। क्योंकि चुनाव शिक्षकों के माध्यम से होता था। आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद्।

सभापति महोदय:- देखिये कोई शिक्षक किसी पार्टी का नहीं है,शिक्षक शिक्षक ही है, यह विलोपित किया जाए।

श्री लोकेन्द्र सिंह (मांधाता) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27 और 77 के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जबसे मध्यप्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, इस सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा रही है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिये और उसके लिये लगातार प्रयास किये गये। एक किलोमीटर पर प्रायमरी स्कूल, तीन किलोमीटर पर मीडिल स्कूल, पांच किलोमीटर पर हाई स्कूल और आठ किलोमीटर पर हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की योजना बनाई गई और कई जगह खुल गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि ईधर से बातें हो रही थी कि शिक्षा में कमी हो रही है, उसमें गुणात्मक सुधार नहीं हो पा रहा है परनिशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यह केन्द्र सरकार से लागू हुआ है। सब पढ़ना चाहिये और कोई पढ़ने से वंचित न हो, यह भावना अच्छी है, इसमें एक विसंगति आयी है जिसमें पहली क्लास से लगाकर के आठवीं तक कास्टरों की भी फुर्सत कर दी, शिक्षकों को भी फुर्सत में डाल दिया वह इसलिये डाल दिया कि पहली क्लास से लगाकर के आठवीं क्लास तक कोई परीक्षा नहीं होगी। भोपाल से शताब्दी चली और दिल्ली में जाकर के रूकेगी आठवीं तक। फिर नवमीं में जायेगी फिर तकलीफ आयेगी इसलिये शिक्षा में गुणात्मक सुधार कहां से होगा। न मास्टर पढ़ाना चाहता है, बच्चे भी सोचते हैं कि बिना पढ़े पास हो रहे हैं। सभापति महोदय, इससे गुणात्मक सुधार नहीं आ सकता है। यह जो अधिनियम लाया गया है इस अधिनियम में बहुत बड़ी विसंगति है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिये स्वल्पाहार की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गयी है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें।

श्री लोकेन्द्र सिंह:- सभापति महोदय यह अधिनियम कांग्रेस की देन रही है। बच्चा पढ़गा होशियार होगा तो फिर हमारे कहने पर नहीं रहेगा, आदिवासी भाईयों के लिये भी ऐसी योजनाएं लायें। हमारा एक निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा है, आपने कहा है

कि पहले पांचवीं की और आठवीं की बोर्ड की परीक्षा होती थी। बच्चों में पढ़ने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये, उसका रिजल्ट जाना चाहिये और अगर रिजल्ट नहीं आयेगा तो फिर भोपाल से चली गाड़ी दिल्ली जायेगी पर जम्मू जाने में अटक जायेगी। नवमीं क्लास का रिजल्ट बेकार हो रहा है। अभी आपको नहीं अखरेगी पालकों को भी नहीं अखरेगी पर आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम आने वाले हैं। आने वाले समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज में कौन जायेगा। कामर्स कौन पढ़ेगा, अच्छे क्षेत्र में कौन जायेगा,

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया:- जीतू भाई यहां मेज थपथपा रहे हो,कांग्रेस की शिक्षा का जो कानून, अधिकार बना है।

सभापति महोदय:- सिसौदिया जी, आप सीधे न करें।

श्री कमलेश्वर पटेल :- सभापति महोदय, यूपीए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शिक्षा के लिये दी है, हमारी सरकार ने जो योजनाएं दी है अगर उसमें कमी है तो आप उसका सुधार लो।

श्री लोकेन्द्र सिंह :- योगेश्वर जी आप भी स्कूल चलाते हो, प्रायवेट स्कूलों मे आज भी पाचवीं और आठवीं की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं ले रहे हैं। यह आपकी दिल्ली में आपकी सरकार ने किया है। ...(व्यवधान)...

श्री जीतू पटवारी :-जीतू पटवारी जी आप अपनी सीट से बोलें, दूसरे की सीट से न बोलें।

श्री लोकेन्द्र सिंह :- जीतू पटवारी जी तो कटारे जी की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। ये यहां से उठे वहां चले गये अब थोड़ी देर बाद कटारे जी की कुर्सी पर चलें जायेंगे तो वहां से बोलना शुरू कर देंगे।

श्री लोकेन्द्र सिंह :- सभापति महोदय, यह विषय गंभीर है, कमी है। उस कमी के लिये मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी

हो सके क्योंकि अब सरकार हमारी है, इसलिये हम जल्दी से जल्दी निर्णय करायें कि पांचवीं और आठवीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिये, प्रतिस्पर्धा होना चाहिये तब शिक्षा विभाग में अच्छे परिणाम आयेंगे। सभापति महोदय, स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी उसमें वर्ष 2013 से 14 के बीच में 45 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती की गयी है। वह स्कूलों में जाने लग गये हैं। पर मेरा एक निवेदन है कि हमको भी कठोर होना पड़ेगा शिक्षा मंत्री जी यह आपसे निवेदन है। हाजरी भर कर शिक्षक चला जाये और दूसरा आ जाये यह अब चलने वाला नहीं है। इसलिये आपके बी आर सी और बी ई ओ जन शिक्षक इनको सख्त से सख्त निर्देश दिये जायें कि जो शिक्षक अगर बराबर नहीं आयेगा तो उसका वेतन रोक दिया जाये, ज्यादा हो तो उसको निकाल दिया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं, मेरे यहां पर जो डूब क्षेत्र है वहां पर मॉडल स्कूल है वहां पर शिक्षकों की कमी है, उसको पूर्ण करायें और मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में गड़बड़ीमाल, जलवागुजूर और पावाखेड़ी ऐसा गांव है जहां पर हाई स्कूल का उन्नयन किया जाना आवश्यक है, उसके अलावा मिडिल स्कूल से हाईस्कूल में उन्नयन करने के लिये मेरे यहां बिजोरामाफी, गोराड़िया, सरलिया, रोहणी ऐसे नो प्रपोजल आये हैं, उनका मिडिल स्कूल से हाईस्कूल से उन्नयन करेंगे। मेरा एक और निवेदन है कि हाईस्कूल हो या हायरसेकेण्डरी स्कूल हो वहां पर सरकार की तरफ से एक भृत्य लगना ही चाहिये ताकि वह अपनी ड्यूटी करें, भृत्य नहीं होने के कारण तकलीफ आती है। सरकार की तरफ से एक एक हायरसेकेण्डरी स्कूल और हाई स्कूल में भृत्य की पदस्थापना होनी चाहिये, मिडिल स्कूल में भी हो सके तो अच्छा होगा। आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद् ।

श्री राजेन्द्र मेश्राम(देवसर) – माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं. मैं देवसर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं. देवसर विधान सभा क्षेत्र में आज से 10 साल पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी एक ही परिवार के 10-10 टीचर आज तीन स्कूलों में हैं. वह विद्यालय में नहीं जाते हैं. अटेंडेंस साल में एक बार होती है और पूरी तनख्वाह घर बैठे लेते हैं.

सभापति महोदय – आप यह लिखकर मंत्री जी को दे दें.

श्री रामकिशोर दोगने(हरदा) – माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27,77 का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करते हुए बताना चाहता हूं कि शिक्षा रूपी चाबी जो हर क्षेत्र में लगती है. शिक्षा से ही हर चीज का विकास होता है. व्यक्ति अगर प्रशासनिक क्षेत्र में जाए,राजनैतिक क्षेत्र में जाए,शासकीय सेवा में जाए या व्यवसाय के क्षेत्र में जाए. शिक्षा होगी तो वह निश्चित ही उन्नति करता है. मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छा से अच्छा हो सके सरकारों को करना चाहिये. मेरा सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि शिक्षा का क्षेत्र सब तरफ उन्नति,प्रगति और विकास लाता है इसलिये इस पर विशेष ध्यान देते हुए बजट प्रावधानों को ज्यादा से ज्यादा करके आगे बढ़ाए. जैसा पूर्व वक्ता तोमर जी ने बताया कि शिक्षा में पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा होना चाहिये. मैं भी स्कूल संचालित करता हूं क्योंकि जब तक हम जनरल प्रमोशन से आठवीं तक बच्चे को भिजवा देते हैं और बच्चा अपना नाम भी नहीं लिख पा रहा है गिनती भी नहीं लिख पा रहा है कुछ कर भी नहीं पा रहा इसलिये बहुत जरूरी है कि जगह-जगह ब्रेक होंगे तो निश्चित ही बच्चों की उन्नति और विकास होगा.

स्काउट और एन.सी.सी. भी हमारे स्कूलों में होती है और उस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता. उस पर विशेष ध्यान दें जिससे खेल,स्काउट और एन.सी.सी. ऐसे क्षेत्र हैं जिससे बच्चे का मानसिक विकास होता है. हमारा प्रदेश और देश कृषि प्रधान है लेकिन हमारे यहां कृषि विषय बहुत कम स्कूलों में है. मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हर स्कूल में अनिवार्य रूप से कृषि विषय होना चाहिये. प्रेक्टिकल की समस्या आती है पर हर गांव में खेत लगे हुए हैं स्कूलों से इसलिये प्रेक्टिकल में कभी समस्या नहीं आएगी और कृषि विषय अनिवार्य रूप से हर स्कूल में चालू होना चाहिये क्योंकि हमारा प्रदेश पूरा कृषि प्रधान प्रदेश है और हम लोग भी 80 परसेंट कृषि क्षेत्र से ही आते हैं

मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने क्षेत्र पर आना चाहूंगा. मेरे क्षेत्र में स्कूलों की बहुत सारी समस्याएं हैं.बिल्डिंगों की समस्याएं हैं. पूर्व में भी मैं बता चुका हूं. मंत्री जी से आश्वासन मिल गया है. मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी

माध्यमिक शालाएं जिनको हम हाई स्कूल करना चाहते हैं. हाईस्कूल के लिये हमारे यहां बोरपानी

,कायदा

,रातामाटी

,चंद्रखाल,कचनार,लोधीढाना

,पटाल्दा

,जामन्याखुर्द,बड़झिरी

,रोलगांव,धौलपुरकलॉ

,सुंदरपानी

,बड़वानी

,भगवानपुरा

,प्रतापपुरा

,साल्याखेड़ी

,जामली

,पानतलाई,नांदवॉ

,धनवाड़ा

,रातातलाई,नादरा

,गोंदागांवकलॉ

,लछोरा

,महूखाल,कासरनी

,मन्याखेड़ी

,लोनी,जटपुरामाल,रामटेकरैयत,अमाखाल,कड़ौलाराघो,लोध्याखेड़ी,बड़नगर,कायागांव,आदमपुर,नवीन कुल्हार,हंडिया,कुकरावत. हायर सेकेंड्री के कुछ स्कूल हैं- खामापड़वा

,नयापुरा,बालागांव,रेसलपुर,बाजनिया,टेमागांव,बोरी,,छीपाबड़,खमलाय,पहटकलां,पलासेनेर और सारंगपुर. ऐसे 12 स्कूल हैं. कोई ज्यादा स्कूल नहीं हैं जिले में इतने स्कूल होना चाहिये और हैं इसलिये मांग कर रहे हैं.

मेरा यह निवेदन है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास होगा प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा इसलिये पुन: मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ध्यान दें और विशेषकर मेरा तो यह अनुरोध है कि सबसे ज्यादा बजट शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिये जिस क्षेत्र से सब चीजें निकलती हैं. रोड अगर नहीं मिलेगा तो चल जाएगा लेकिन शिक्षा नहीं होगी तो नहीं चल पाएगा. सभापति महोदय, आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री दिलीपसिंह परिहार (नीमच)—माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्य 27 एवं 75 के समर्थन में तथा कटौती प्रस्तावों के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं. सरकार एवं सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी तथा हमारे शिक्षामंत्री सम्मानीय पारस जी जैन, सम्मानीय राज्यमंत्री दीपक जी जोशी की वजह से आज शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में तथा सुदूर गांवों में पहुंचे हैं यही नहीं मजरे-टोले में भी विद्यालय खुल रहे हैं इसकी प्रशंसा आज पूरी गांव की जनता तथा मजरे टोले की जनता भी कर रही है इसके लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं. हम सब जानते हैं कि चाहे मध्यान्ह भोजन हो, चाहे निशुल्क सायकिल वितरण हो, ड्रेस वितरण हो, या गांव की बेटी की योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं की वजह से आज सरकार को दुआएं मिल रही हैं और उन दुआओं की वजह से सरकार दिन दौनी रात चौगनी तरक्की करती हुई बढ़ रही है. अभी हमने देखा कांग्रेस के समय में जीरो बजट के स्कूल खोले गये थे आज इसलिये कांग्रेस जीरो हो गई है और मध्यप्रदेश की सरकार ने लगातार गांवों एवं मजरे-टोलों में स्कूल खोले हैं और तीसरी बार सरकार बनाकर जनता ने उन्हें हीरो बना दिया है. यह फर्क पड़ता है इस सरकार का, जो लोग काम करते हैं वह निश्चित ही आगे बढ़ते हैं हम यह चाहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने का सभी को अधिकार है. चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे पन्नी बीनने वाला हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे महल में रहने वाला हो, हमारी सरकार ने सबको शिक्षा और अभी स्कूल चलो अभियान चला सम्मानीय दीपक जी जोशी नीमच जिले में आये जो झोपड़ी में रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं उनको भी वहां पर पुस्तकें वितरित की गई उनको भी वहां बुलाया गया और 10 हजार लोग उस कार्यक्रमों में आये. कुछ सामाजिक संगठन लगे उन सबने देखा कि स्कूल चलो अभियान किस प्रकार होता है, कोई भी बच्चा शब्द ज्ञान अथवा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे ऐसी हमारी सरकार की मंशा है और उस मंशा में हम कामयाब होते दिख रहे हैं. मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा कि सरकार की वजह से ही आज गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही

है और गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है तो लोगों में संस्कार आते हैं इसलिये शिक्षा बहुत अनिवार्य है शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य विनम्र भी बनता है. मैं यही कहूंगा कि आज जो उत्कृष्ट विद्यालय चल रहे हैं उन उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से अच्छे बच्चे परसंटेज के आधार पर पढ़ लिख रहे हैं और मध्यप्रदेश के बच्चे 85 प्रतिशत अंक ला रहे हैं उनको सरकार ने लेपटॉप देने का काम किया है यह अभिनव प्रोत्साहन की योजना है मैं इस अवसर पर यही कहूंगा मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं नीमचि जिले में एक शिक्षा का प्रशिक्षण संस्थान है डाइट माननीय मंत्री जी नीमच में एन.सी.टी.ई से मान्यता दिलवाना है, क्योंकि जब लक्ष्मण सिंह गौड़ साहब सदन में शिक्षामंत्री थे उस समय उन्होंने भूमि-पूजन किया था तब पारस जी जैन साहब हमारे प्रभारी मंत्री थे तब डाइट की बिल्डिंग का लोकार्पण किया था. वहां डाइट में स्टॉफ है, बिल्डिंग बनी हुई है सारी मान्यता प्राप्त होने की स्थिति में है. प्रायवेट स्कूल के कॉलेज संचालकों ने जो डीएड और बीएड कराते हैं उन्होंने कहीं न कहीं इनको रोक रखा है आज वह एक एक लाख रूपये लेकर जो बच्चों को शिक्षा देते हैं डीएड और बीएड में और हमारे शासकीय विद्यालय में डीएड नहीं हो रहा है. मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे नीमच में जो डाइट की बिल्डिंग है उसमें पूरे कर्मचारी हैं उनको आप मान्यता दिलवायेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बालिकाएं-बच्चे आपको दुआएं देंगे और दुआएं बहुत काम करती हैं.

मैं अक्सर कहता हूं कि

"क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिये जो जीता है मिलता जहां
का प्यार उसे जो गरीब के आंसू पीता है. "

आप गरीब बच्चों एवं बच्चियों को डीएड- बीएड की शिक्षा प्राप्त हो इसके लिये लिये उसकी मान्यता दिलाने का काम करें. आज हम देखते हैं कि 5 हजार में डीएड होता है वहां पर प्रायवेट कॉलेज वाले एक एक लाख रूपये लेते हैं यह काम नीमच जिले की प्रथम प्राथमिकता का है आप इसे

करने की कृपा करेंगे, साथ ही मेरे हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जिसे जीरन में जो तहसील है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तहसील घोषित किया है. आप प्रभारी मंत्री जी थे, आपके प्रयास से वह तहसील बनी है, वहां कन्याओं के लिये हायर सेकेंड्री बिल्डिंग नहीं है, माननीय आपसे निवेदन है कि झीलन में आप बिल्डिंग दें. करैय्या महाराज में हायर सेकेंड्री स्कूल नहीं है, आप उसमें उन्नयन करने की कृपा करें. वहां भादवा माता का स्थान है, जहां आप भी जाते हैं हमारे मंत्री जी भी जाते हैं, वहां हमारे भादवा माता में भी हाई स्कूल खोलें, क्योंकि वहां भादवा माता का बहुत ही महत्व है, किसी को यदि लकवा मार जाये, वह वहां आये तो कंधे पर बैठकर जाता है और पांव पर चल कर आता है, ऐसा स्थान है, इसलिये वहां पर हाई स्कूल खोलने की कृपा करें. इसके साथ ही चंपी, जमुनिया और जवासा में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह हमारे हाई स्कूल खोलने के लिये आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, आप तो नीमच जिले से भलीभांति परिचित हैं, इसलिये नीमच सिटी में हमारे कामर्स के पद नहीं हैं, वहां बच्चे कामर्स शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक गांव है दारू, दारू पीने वाला दारू नहीं, गांव का नाम है दारू, जहां आप भी गये हैं जहां आप भी गये हैं, तो उस दारू में भी यदि आप हायर सेकेंड्री स्कूल की बिल्डिंग देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा. जमुनियाकला माननीय मंत्री जी, हायर सेकेंड्री हाई स्कूल के अतिथि शिक्षकों का आदेश देने की भी कृपा करें, क्योंकि जो लोग पढ़े-लिख लेते हैं, अच्छे परसेंटेज में आते हैं, उन अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है, इसलिये मैं इस अवसर पर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 2013-14 में 42 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती की, पुन: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को, माननीय सभापति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, भारत माता की जय.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (पुष्पराजगढ़)--माननीय सभापति महोदय, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा इस सदन में लिया जा रहा है. निश्चित ही पूरा सदन इस विषय पर चिंतित है कि पूरे मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा किस तरह से होना चाहिये और कहां-कहां विसंगतियां हैं, इस पर

भी माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को रखा है. माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरीके से मध्यप्रदेश में शिक्षा दो भागों में विभाजित होकर एक हमारे शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की शिक्षा और दूसरी तरफ हमारे अशासकीय विद्यालयों में जो दिया जा रहा है, वह शिक्षा 2 तरीके से शिक्षा है. माननीय सभापति महोदय, शासकीय विद्यालयों की प्राथमिक शालाओं में जो अध्ययन कराये जाते हैं, जो शिक्षण पद्धतियां हैं, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं कबाड़ से जुगाड़ में शिक्षा. कबाड़ से जुगाड़ और शिक्षा खेल-खेल में शिक्षा यह पद्धतियां हैं प्राथमिक शालाओं की, उस समय अर्द्धशासकीय विद्यालयों में अशासकीय विद्यालयों में हमारे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय के हैं, वह ए, बी, सी, डी पढ़ते हैं. हमारे कवार्ड के बच्चे कबाड़ से जुगाड़ पढ़ रहे हैं शासकीय विद्यालयों में और अशासकीय विद्यालयों में इंग्लिश पढ़ते हैं और वही जब आगे चलते हैं माननीय सभापति महोदय, अशासकीय विद्यालयों में बच्चे टेबलों पर बैठकर शिक्षा अध्ययन करते हैं और हमारे बच्चे अपने कथड़ी में दबाकर के हाथ में और पट्टियां लेकर के बैठते हैं. माननीय सभापति महोदय, वहां आज भी यह स्थिति है. आज यह शिक्षा जिस तरीके से गांवों में दुराव चल रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर देखें कि शिक्षा किस तरीके से आज भी पेड़ पौधों के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं. हम आज पूरे प्रदेश की शिक्षा के लिये चिन्तन कर रहे हैं कि हमारी प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिये ? हमारे प्रदेश की शिक्षा स्थिति को कैसे सुधारा जाये ? वे बच्चे जो अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् हैं, उनको कैसे शिक्षा मिलना चाहिये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा पुष्पराजगढ़ 2004-05 से सर्वशिक्षा अभियान के कुछ भवनें बनाई गई हैं, जिसमें माध्यमिक शाला 33 भवन, प्राथमिक शाला के भवन 33, माध्यमिक शाला के 14 भवन, ई.जी.एस. के 20 भवन, अतिरिक्त कक्ष 80 भवन और बालिका शौचालय 35, इस तरीके से साढ़े 4 करोड़ लगभग की यह राशि उन भवनों में खर्च की गई है. कोई प्लिंथ लेबल में है, कोई डोर लेबल में है, कोई आधे में

बना हुआ है, आज लगभग 200 भवनें सर्वशिक्षा अभियान के पुष्पराजगढ़ विधान सभा में अपूर्ण हैं 10 वर्षों से. मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करता हूं कि इन भवनों को पूर्ण कराने की कृपा करें, चूंकि यह प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है.

सभापति महोदय -- आप जो भवन बता रहे हैं, आप लिस्ट मंत्री जी को दे दें.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को -- लिस्ट मैं दूंगा. एक विभाग ने लिखा, हमने भी कई बार लिखा. यह जानकारी विभाग वालों के पास क्या नहीं है. सभापति महोदय, जब हम राशि सेंक्शन कर रहे हैं, भेज रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं, पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है. आप यहां से सेंक्शन कर रहे हैं. लिस्ट हर महीने भेजी जा रही है. इसके बाद भी उसमें काम पूरा नहीं हो रहा है. मैं चाहता हूं कि आज इसका बजट में प्रावधान कर लिया जाय, क्योंकि बच्चे, कोई अतिरिक्त कक्ष है, मध्यामिक शाला, प्राथमिक शाला है, ईजीएस भवन हैं, बालिकाओं के शौचालय हैं. साथियों ने कहा कि बड़ी ये सारी व्यवस्था की है, मैं सबको आमंत्रित करता हूं पुष्पराजगढ़ के उस जंगल, पहाड़ में. मां नर्मदा जी के दर्शन भी कराऊंगा और इन प्राथमिक विद्यालयों को भी दिखाऊंगा.

सभापति महोदय -- आप मंत्री जी यह लिस्ट दे दीजियेगा. कृपया एक मिनट में समाप्त करें.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को -- सभापति महोदय, दे दूंगा. मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि आज जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षा के स्तर में जो गिरावट हुई है, इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिये. हमारी नींव बहुत कमजोर है. शिक्षा की नींव प्राथमिक शिक्षा है. यह जो हमारे अपूर्ण भवन हैं, यदि बन जायेंगे, तो बच्चों को लाभ मिलेगा. इसलिये मेरा निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिये. अशासकीय विद्यालयों की तरह हमारे शासकीय

विद्यालय का भी स्तर अच्छा होना चाहिये, क्योंकि जब प्रतिस्पर्द्धा में बच्चे बैठते हैं, तो एक ही प्रश्न पत्र होता है. एक बच्चा वह जो हमारे कानवेंट में पढ़ता है और दूसरा हमारा शासकीय विद्यालय किसी कोई हायर सेकेण्डरी, हायस्कूल का अध्ययन करता है, तो दोनों का एक ही पेपर होता है. इसलिये मेरा निवेदन है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देते हुए जो अपूर्ण भवन हैं, उनको तत्काल पूर्ण किया जाय. आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं.

श्री दिलीप सिंह शेखावत (नागदा-खाचरौद) -- सभापति जी, चूंकि मेरे जिले के ही मंत्री जी हैं और जैसा कहते हैं कि अगर मां का घर हो और मामा परोसने वाला हो तो निश्चित रुप से सारी समस्याओं का निदान करता है. कई बार दुख इस बात का होता है कि पूरे सदस्यों ने, कइयों ने कहा कि..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- सभापति महोदय, यह कहावत है कि कुम्हार फूटी हण्डी में ही खाता है. (हंसी)

श्री बहादुर सिंह चौहान --- आपकी बात की मैं पुष्टि करता हूं.

श्री दिलीप सिंह शेखावत -- बहादुर सिंह जी, नहीं. मैं यह कहूंगा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता. इसलिये कई बार मन में यह विचार आता है कि देश को आजाद हुए 67 साल हो गये और अगर आज भी जनता का चुना हुआ जन प्रतिनिधि अगर यह कहता है कि हम फिसड्डी हैं, तो फिर मन में आश्चर्य होता है कि जिस जनता ने आपको चुना है, क्या उस जनता पर आप प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहे हो. ..

श्री कमलेश्वर पटेल -- फिसड्डी का एवार्ड स्मृति ईरानी जी ने अभी दिया दिल्ली में. स्मृति ईरानी जी ने दिया है प्राथमिक शिक्षा में.

श्री दिलीप सिंह शेखावत -- पटेल साहब, अगर बोलने लगूंगा तो 2003 के पहले यह स्थिति थी कि जहां स्कूल था वहां छत नहीं थी. जहां छत था वहां टीचर नहीं था. जहां

टीचर था तो वहां पर टाट पट्टी नहीं थी. यह स्थिति थी मध्यप्रदेश की. इस मध्यप्रदेश में कई विद्यार्थी रोते थे, इसलिये रोते थे कि हम इसलिये फेल हो गये कि अगर शिक्षक पढ़ाते तो शायद हम पास हो जाते.

श्री कमलेश्वर पटेल -- उस समय की पढ़ाई का स्तर अच्छा था. वहीं से निकलकर आज सरकारी नौकरी में हैं, अच्छे अच्छे पद पर हैं.

श्री दिलीप सिंह शेखावत -- सभापति जी, यह व्यवस्था देनी पड़ेगी कि (xx) अगर ऐसे लोगों को बोलने का शौक हैं, तो सभापति जी, एक्सट्रा टाइम दे दिया जाय. मैं बहुत ज्यादा बोलने के मूड में इसलिये नहीं था कि आदरणीय पारस जी जिस तत्परता के साथ में अपने विभाग को संचालित कर रहे हैं..

श्री कमलेश्वर पटेल -- सभापति महोदय, अगर सत्ता पक्ष के साथियों को सच सुनने का वह नहीं है ..

सभापति महोदय -- कृपया आप बैठिये.

श्री दिलीप सिंह शेखावत -- सभापति जी, जिस प्रकार से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और आज यह मैं नहीं कह रहा हूं. मैं शनिवार को मेरे क्षेत्र में गया था, बीते हुए शनिवार को. मैं आपको नाम भी बता रहा हूं आक्या गांव, वहां साइकिल बांटने के लिये गया था. लेकिन सीना गर्व के साथ जब फूला कि उस विद्यालय के प्राचार्य ने यह कहा कि मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले एक शासकीय विद्यालय के 90 परसेंट अंक आये हैं , यह गर्व की बात है. मैं आक्या गांव का नाम भी बता रहा हूं. और प्राचार्य ने यह भी कहा कि इस विद्यार्थी को गणित में 100 में से 100 अंक मिले तो फिर सीना और फूला, इसलिये मित्रों अगर कोई कमी होगी तो कमी को दूर करेंगे लेकिन आने वाले समय में मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बना के रहेंगे, किसी भी कीमत में. सभापति महोदय, बहुत विनम्रता के साथ में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय

लोकेन्द्र सिंह जी मुझे बता रहे थे कि पुराने समय का एक विधान है कि अगर 6 वीं कक्षा में या पहली कक्षा में कोई भर्ती नहीं होता है, उम्र बढ़ जाती है तो उसकी अगली कक्षा में उसको एडमीशन मिल जाता था, तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रकार के नियम में निश्चित रूप से परिवर्तन करना चाहिये.

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से विनम्रता के साथ मे निवेदन करना चाहता हूं कि एक जमाना था जब संविदा शिक्षक आने वाले कल के भविष्य को संवारते थे लेकिन तिल तिल करके जिंदगी को जीते थे 500-700 रूपये उनको मिला करते थे. इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके जीवन को संवारने का काम भी मध्यप्रदेश की सरकार को करना चाहिये यह बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा . मंत्री जी मेरे जिले के हैं. इसलिये ज्यादा कुछ न कहते हुये आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया उसके आपको भी धन्यवाद.

श्री के.के.श्रीवास्तव (टीकमगढ़) --माननीय सभापति महोदय,मैं मांग संख्या 27 एवं 77 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. सभापति महोदय, हम पहले से किसी को छेड़ते नहीं है और जब कोई हमें छेड़े तो छोड़ते नहीं हैं.

सभापति महोदय-- आप विषय पर बोलिये.

श्री के.के.श्रीवास्तव-- विषय पर ही बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं. जब हमारे ऊपर ऊंगली उठाई जायेगी तो हकीकत बतानी पडेगी.

श्री रजनीश सिंह -- सभापति महोदय के के श्रीवास्तव जी हमेशा धमकियां देते हैं. कभी छेड़ने की बात करते हैं कभी बाहें चढ़ाते हैं.

सभापति महोदय-- आप विषय पर ही बोलें.

श्री के.के.श्रीवास्तव-- सभापति महोदय, शिक्षा की अनुदान मांगों पर ही बात कर रहा हूं.

सभापति महोदय-- छेड़ा छाड़ी की बात छोड़कर विषय पर आयें.

श्री रजनीश सिंह -- सभापति जी धन्यवाद आपने हमारी बात पर गौर किया.

श्री के.के.श्रीवास्तव--सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि 2003 के पहले की परिस्थितियां क्या थी . 2003 के पहले स्कूलों में भवन नहीं हुआ करते थे, मास्टर नहीं हुआ करते थे, टेवल कुर्सी नहीं हुआ करती थीं, टाट-पट्टी नहीं हुआ करती थी, टाटपट्टी है तो मटका नहीं है, मटका है तो, घंटी नहीं है, घंटी नहीं है तो घंटा नहीं है. मास्टर नहीं,विद्यार्थी नहीं, स्कूल महुंआ के पेड के नीचे चलते थे.

माननीय सभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कहा गया. आपरेशन ब्लेक बोर्ड वह भी फेल , सर्व शिक्षा अभियान वह भी फेल, सारा सिस्टम फेल और आपने शिक्षाकर्मियों की भर्ती करके बेचारों को तिल तिल मरने के लिये छोड़ दिया था उसको भी सम्हालने वाली सरकार मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने उनके जीवन को संवारा है.

माननीय सभापति महोदय, आज मध्यप्रदेश में जो परिस्थितियां हैं . आज प्रति 1 किलोमीटर पर प्रायमरी स्कूल, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर के बीच में हाई स्कूल 8 से 10 किलोमीटर के बीच में हायर सेकेन्डरी स्कूल की व्यवस्था मध्यप्रदेश की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे शिक्षा मंत्री पारस जी के हाथ में दी है. मैं समझता हूं कि जिन्होंने अपनी छात्र राजनीति से ही भाई दीपक जोशी जी जो राज्य मंत्री हैं छात्र राजनीति से आये हैं शिक्षा के माध्यम से जहां से उन्होंने पढ़ाई की वहीं से छात्र राजनीति प्रारंभ की है उनको यह महकमा दिया गया है. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऊपर से पहलवानी की डंडा भी शिक्षा के ऊपर चला है कि कहीं गड़बड़ी भी नहीं होने देंगे.

माननीय सभापति महोदय, मैं सुझाव देने जा रहा हूं जो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी के सम्मुख भेजना चाहता हूं. कुमरउखिरिया का उन्नयन कर हाई स्कूल में लिया जाये, मदिना हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेन्डरी में किया जाये ,टीकमगढ़ नगर में स्थित जानकी बाग

माध्यमिक शाला का उन्नयन हाई स्कूल में, सभापति महोदय, मेरे यहां सवा लाख की आबादी है और केवल एक कन्या हायर सेकंडरी स्कूल है उसमें साढ़े तीन हजार छात्राएं अध्ययन करती हैं. मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि टीकमगढ़ नगर और गुढेरा में एक नवीन हाई स्कूल

खोला जाये.

सभापति महोदय-- नवीन हाई स्कूल या कन्या हाई स्कूल?

श्री के के श्रीवास्तव-- सभापति महोदय, नवीन कन्या हाई स्कूल खोला जाये. सभापति जी, एक तात्कालिक समस्या है. मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराता हूं टीकमगढ़ नगर में एक एक्सीलेंस स्कूल है उसमें छात्रों की संख्या से ज्यादा एडमिशन हो गये थे क्योंकि टीकमगढ़ नगर के दो हाई स्कूल किसी कारण से अचानक संचालित होना बंद हो गये है. वहां के 60-70 प्रतिशत से लेकर 90-95 प्रतिशत अंक तक के लगभग 150-200 विद्यार्थी आज बिना प्रवेश के शहर में घूम रहे हैं. कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है वह शायद कल 17 तारीख को बैठक करने वाले हैं. मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से बात करें ताकि टीकमगढ़ के विद्यार्थी बिना प्रवेश के न रह जाये. वहां सारी सीटें फुल हो चुकी हैं. इसलिए आवश्यकता हो तो और सीटें बढ़ायी जाये या बगल में क्रमांक-2 स्कूल है उसमें बैठने की व्यवस्था करायी जाये. वहां 40-50 शिक्षकों का स्टाफ है. अगर इसकी व्यवस्था हो जायेगी तो 150-200 विद्यार्थी ऐसे ही नहीं भटकते रहेंगे. इसकी तत्काल चिन्ता होना चाहिए.

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग ने एक बाल सभा करने का पीरियड शुरु करने का निर्णय किया है. ताकि बच्चों में नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा आये उनमें संस्कार आये. मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने फिर से नैतिक शिक्षा और संस्कार शिक्षा पर ध्यान दिया है और बाल सभा के माध्यम से उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व की दिशा में काम किया है. धन्यवाद.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- सभापतिजी, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं. मैंने यही कहा था कि सत्ता पक्ष के जितने लोग खड़े हो रहे हैं, मांगों का समर्थन कर रहे हैं. अन्त में वे अपने क्षेत्रों की बात करने लगते हैं और सारी कमियां स्वमेव उजागर कर देते हैं. इस बात पर मंत्रीजी ध्यान दें. सचाई यही है जो अंत में बोली जाती है. वह सही दृश्य है. यह शिक्षा का वास्तविक दृश्य है.

श्री दिनेश राय'मुनमुन'(सिवनी)-- सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से अपने सिवनी विधानसभा के कुछ स्कूलों के उन्नयन का निवेदन करता हूं.

सभापति महोदय, उमैया में हाई स्कूल, जैतपुर कल,तिघर,गोरखपुर,तिलगौड़ी

,सूखामाल,बीसावाड़ी

,कलारवाकी,केवलारी,बीजादेवी,शाहगढ़,झिरी,लाटगांव,कमकासुर,उडैपानी,खुलारा और पंडोर का उत्कृष्ट विद्यालय मैं चाहता हूं कि इन स्कूलों का आप उन्नयन करें. इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन करता हूं लखनादौन नगर परिषद में वर्तमान में मेरी मां अध्यक्ष है वहां पर जो मॉडल स्कूल है वह चपरासी के हवाले है. वहां पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है. अतः निवेदन है कि इस पर आप ध्यान दें. मैं मांगों का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं.

सभापति महोदय, मेरे पास संचालक, स्कूल शिक्षा, म.प्र. का एक पत्र है. जिसमें स्कूलों में चाहे शासकीय स्कूल हों या अशासकीय स्कूल हों, में शाला विकास के नाम से राशि वसूली जा रही है. सरकार के द्वारा भी 40-50 हजार रुपया विकास शुल्क दिया जा रहा है तो फिर बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. उस पर तत्काल रोक लगायी जाये. बच्चों से इस प्रकार की फीस न ली जाये. अतः मेरा निवेदन है कि 14 मार्च 2011 का जो संशोधित निर्देश है, उसका पालन सभी स्कूलों में कराया जाये. सभापति महोदय, स्कूल निर्माण के साथ-साथ बाउण्ड्री वॉल एवं शौचालय की

स्वीकृति प्रदान करें, ऐसा मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं. क्लास के अंदर जब बच्चों को मोबाईल ले जाना माना है तो स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाओं को कैसे आप अनुमति देते हैं? हम देखते हैं आधा-एक घंटा शिक्षक मोबाईल में लगे रहते हैं, जिनकी शादी हो गई है वे कम उपयोग करते हैं, जिनकी शादी होनी होती है वे लगातार पूरा पीरियड खत्म कर देते हैं. अतः इस संबंध में आप कठोर कार्यवाही करें. ऐसे लोगों को वहां पर अनुमति न दें. प्रायवेट स्कूल में प्रतिवर्ष किताबों में बदलाव किया जा रहा है. एक-दो पन्ने किताबों में बदल देते हैं, उससे आने वाली पीढ़ी को, उनसे छोटे बच्चों को अगर उन पुस्तकों का उपयोग करना हो तो वे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत जाती है. इस संबंध में भी आप कार्यवाही करें और किताबों में बार-बार बदलाव न हो. वरिष्ठ शिक्षक कम पीरियड ले रहे हैं, जबकि वे निजी कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं. उन पर भी आप लगाम लगाएं. संविदा शिक्षकों के लिए समान वेतन की घोषणा की है वह उनको मिले. अतिथि शिक्षकों को भी उसी वेतन में रखे ऐसा मेरा निवेदन है. मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रायः-प्रायः अधिकांश स्कूलों में स्कूलों में फर्नीचर की कमी है. मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं की भी तनख्वाह बढ़ा दें. कम से कम उनको कलेक्टर रेट तो दें और मेरा निवेदन है कि मध्याह्न भोजन बंद करके उन बच्चों के गार्जियन को राशि प्रदान कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा. जो अनियमितताएं हो रही हैं जैसे भोजन में छिपकली गिरना, कहीं अशुद्ध खाना मिलना. सभापति महोदय, पांचवीं, आठवीं की शिक्षा को लेकर सभी ने बात रखी है कि उनकी परीक्षा होना चाहिए. ऐसा मेरा आपसे निवेदन है. सभापति महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया है, उस समय में मैं अपनी बात पूर्ण करते हुए समाप्त करता हूं. धन्यवाद.

श्री जयवर्द्धन सिंह (राघोगढ़) - सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं. सभापति महोदय, शिक्षा एक बच्चे के भविष्य की नींव है और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भी अगर हम मध्यप्रदेश के बारे में बात करें तो हमको Urban vs Rural, शहर और ग्रामीण में तुलना करके ही बात करनी चाहिए.

5.48 बजे {उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}

उपाध्यक्ष महोदय, अगर शहर के बारे में बात करें तो आज प्रत्येक विद्यार्थी के पास स्कूल जाने के लिए अनेक विकल्प होते हैं, अनेक प्रायवेट और सरकारी स्कूल जहां वह जा सकता है. अगर आप राघोगढ़ नगर पालिका के बारे में बात करें तो वहां भी करीब 40000 मतदाता हैं और 5 सीबीएसई स्कूल हैं. मगर जब हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करते हैं और अधिकतर उन गांवों के बारे में बात करते हैं जो शहर से दूर होते हैं, जो इस मौसम में ऐसे काफी गांव होते हैं जहां पर ठीक सड़क न हो, बारिश के समय वे एक टापू जैसे बन जाते हैं. वहां पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम एनजीओ की जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) है .पूरे भारत में और खास कर शिक्षा के बारे में नम्बर वन रिपोर्ट है और एक तरह से पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश के बारे में शिक्षा की क्या स्थिति है, उससे अच्छी तरह हमको जानकारी मिल जाती है. उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) है, इसकी जो प्रैक्टिस है और जो सोच है, वह यह है कि जो भी सरकारी योजना होती है, उसकी आउट-कम क्या है, उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है, वह उसको मेजर करती है. वर्ष 2013 की जो असर रिपोर्ट थी, उसमें दो उन्होंने जो नम्बर दिये हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. नंबर वन जो इनरोलमेन्ट की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में है , 2010 तक 3 या 4 प्रतिशत

ड्रॉप आऊट थे ,मगर दुख की बात यह है कि पिछले तीन साल में ड्राप आऊट रेट बड़ गया है. उसी के साथ साथ जो प्री प्रायमरी एजुकेशन है. जो 3 से 5 साल के बच्चे को मिलती है वहां पर 10 से 20 प्रतिशत का ड्राप आऊट रेट है. और यह बहुत गंभीर समस्या है. क्योंकि आखिर किसी भी बच्चे के लिए एक से पांच वर्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है. उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा की कमी है ,हम कह सकते हैं कि हां बुनियाद व्यवस्था में कमी है. शिक्षकों की कमी है. मगर मैं मानता हूं कि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोसायटी होती है, कम्युनिटी होती है. इसलिए आप देखोगे कि शहर में जो बच्चों का माता पिता हैं वे बच्चों की शिक्षा पर खास ध्यान देते हैं. मगर कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में माता पिता अपने बच्चो की शिक्षा पर कम ध्यान दे पाते हैं. पाण्डेय साहब ने कहा था कि इस बार बजट के भाषण में, कॉल सेन्टर के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था और हां क़ॉल सेन्टर एक अच्छी शुरूआत है. मगर कॉल सेन्टर में जो बच्चे के माता पिता हैं वे शिक्षक को फोन लगायेंगे या वे DEO को फोन लगायेंगे.मगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि फीड-बैक दो डायरेक्शन में होना चाहिए सिर्फ एक दिशा में नहीं. मेरे कहने का मतलब है. जो अध्यापक भी हैं उनको भी प्रतिदिन या प्रति हफ्ते कम से कम एक बार पेरेन्ट्स के साथ संपर्क में रहना चाहिए. क्योंकि खास कर के ग्रामीण क्षेत्र के जो पेरेन्ट्स हैं उनको भी शिक्षा के बारे में ,उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सीखना चाहिए. और आखिर एक दिन में बच्चा कितने घंटे के लिए स्कूल जाता है , 6 घंटे, 7 घंटे. अधिक से अधिक 7 घंटे. मगर उसके बाद वह पूरे दिन घर में रहता है और घर में उसको सही सीख मिले. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में पालकों को भी शिक्षित करना बहुत आवश्यक है. उपाध्यक्ष महोदय, जब हम शिक्षकों के बारे में बात करते हैं तो जो शिक्षा अधिनियम है उसमें यह बात उल्लेखित है कि 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना पर इसका पालन अधिकतर नहीं हो पा रहा है. उसके साथ ही जो प्रिंसीपल की पोस्ट है वहां पर अधिकतर प्रभारी प्रिंसीपल भरे हुए हैं और इसमें संशोधन की आवश्यकता है.

उपाध्यक्ष महोदय- अब आप समाप्त करें.

श्री जयवर्धन सिंह- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट और .अभी तक मैने चार भाषण दिए हैं और मेरा सौभाग्य रहा कि हर बार आप ही आसंदी पर रहे. इसलिए दो मिनट आपको देना चाहिए. उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जब हम बुनियादी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो बाऊण्ड्री वॉल, बालक और बालिका के लिए शौचालय, बिजली की व्यवस्था,ये प्रत्येक स्कूल में होना चाहिय और इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो DEO है जो ब्लाक ऑफीसर है उनको आप थोड़ा टाईट कीजिए ताकि वे इसका पालन करें. अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे अनेक विद्यार्थी होते हैं जो कक्षा 5 या 8 वीं के बाद पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पाते. मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर बच्चे को शिक्षा में ही नंबर वन पर आना चाहिए. कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका किसी ओर चीज में हुनर होता है. कोई इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, सिक्यूरिटी गार्ड बन सकता है, फायर फाईटर बन सकता है. वेल्डिंग कर सकता है. तो इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, जो कौशल विकास है , तकनीकी शिक्षा है उसका जो इन्टीग्रेशन होना चाहिए स्कूल शिक्षा के साथ और खास कर बच्चों को काऊंसिलिंग होनी चाहिए. स्कूल काऊंसिलिंग मिलनी चाहिए और वह भी 13 वर्ष के बाद. मैं खुद का उदाहरण देता हूं. जब में देहरादून में पढ़ता था ,जब मैं 13 साल का था तो मुझे भी स्कूल काऊंसिलिंग मिली थी. करीयर काऊंसिलिंग मिली थी और उन्होंने कहा था कि तुमको बड़े होकर मॉस कम्युनिकेशन में होना चाहिए. अब मॉस कम्युनिकेशन तो पत्रकार की फील्ड होती है. और अब मुझे इस बात का एहसास होता है..

उपाध्यक्ष महोदय- राजनेता की भी तो होती है.

श्री जयवर्धन सिंह—जी हां, नेता की भी वही होती है,.मॉस कम्युनिकेशन ,जो हम जनका को कम्युनिकेट कर सकें. वह एक ही चीज होती है. मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसी करियर काऊंसिंलिंग स्कूलों में भी होनी चाहिए. आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद.

Smt. Parul Sahu (Surkhi)—Hon'ble Chair, There are nearly 4 lakh & 64 thousands student, who got admission under Right ot Education Act.

उपाध्यक्ष महोदय—हिन्दी में बोलें. अंग्रेजी के यहां रिपोर्टर नहीं हैं.

श्री वेलसिंह भूरिया—माननीय उपाध्यक्ष जी बोलने दें, माननीय सदस्या को बोलने दें.

उपाध्यक्ष महोदय—यह कहां से सुझाव आ रहा है. आप हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बोलें. हिन्दी में भी बोलें. यहां पर अंग्रेजी के रिपोर्टर्स नहीं हैं. आपका भाषण नहीं आ पाएगा.

Smt. Parul Sahu—Hon'ble Chair, today I have prepared in english only, grant me to speak in english, next I will try to speak in both.

उपाध्यक्ष महोदय—O.K., permission is granted.

Smt.Parul Sahu—Mostly the students got admission in Private CBSE Schools located in Urban & Semi Urban Areas. Its been nearly 4 years that those scholars are studying in this Private Schools. If we compare their personality with their counter parts they have really really gained a lot.

Seeing their exceptionally good results Hon'ble Chair, If we extent this facility by way of State Run Primary CBSE Schools in Block headquarters and also State Run Primary ICSE Schools in Metro Cities like Indore & Bhopal. It will become a great foundation of learning for our future.

Hon'ble Chair, most of the Government Officers and the Servants specifically send their wards to the Private CBSE Schools and if state will take this initiative, it will also reduce the burden of education expenses of our Govt. Officer and Servants.

उपाध्यक्ष महोदय—आप पूरी तरह से देख कर नहीं पढ़े, बीच बीच में देख लें और हिन्दी प्रदेश की कामकाज की भाषा है और अपनी विधानसभा की भाषा है और आप अच्छा हिन्दी बोलती हैं.

श्रीमती पारूल साहू—जी. अगर स्टेट हमारे मध्यप्रदेश में इस सिस्टम को इनीशिएट करते हैं कि CBSE पैटर्न हमारे सरकारी स्कलों में लागू हो जाए. it will really reduce जो बर्डन है हमारे Govt. officers के ऊपर एजुकेशन का जो खासकर फोकस करते हैं हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में तो उनका बर्डन काफी कम होगा. खासकर Govt. officers & Servants के बारे में है.

Secondary Honb'ble Speaker, If we see the maximum expense जो हमारे मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, वह लोग एजुकेशन में ही करते हैं, बच्चों की एजुकेशन में, इसमें भी उनको दूसरा विकल्प नहीं मिल पाता है. अगर हमारे यहां CBSE system को लागू किया जाता है तो इससे मिडिल इनकम ग्रुप को भी बेनिफिट होगा. यह हमारे उस ग्रुप के लिए ब्लेसिंग्स मानी जाएगी. जहां तक इन्फ्रा स्ट्रक्चर की बात है, अगर इस सिस्टम के लिए हमें इन्फ्रा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेन्ट होती है तो we can use जो हमारी existing buildings हैं for this purpose. दूसरी बात यह है कि अगर human resources के बारे मे किया जाएगा. human resource इस सिस्टम में चाहिए तो we can considered and we can make use of all reitred kendriya vidyalay teachers for their suggessions. At last, Hon'ble Chair, my main motive, बस यही उद्देश्य है कि आज हमारे देश और प्रदेश में एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए तो उनका भविष्य अगर हम उज्जवल चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम को हमारे प्रदेश में किस प्रकार से हम और बेहतर कर सकते हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के प्रयासों से लगातार हमारे प्रदेश में स्कूल बढ़ रहे हैं और उनको शिक्षा दी जा रही है. अगर एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम CBSE Pattern को अगर हम सरकारी स्कूल में भी लागू करेंगे तो मुझे व्यक्तिगत रूप से यह लगता है कि आने वाले भविष्य में हमारे प्रदेश के बच्चों को जो कंपीटेटिव सिनारो उनको फेस करना पड़ेगा, उसमें उनको आसानी होगी. इस सुझाव को मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को देना चाहूंगी. धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय—बहुत बहुत धन्यवाद पारूल जी. आप तो बहुत अच्छी हिन्दी बोलती हैं और भाषण भी हिन्दी में अच्छा देती हैं. आपके पिताजी हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ थे.

श्री बलबीर सिंह डण्डौतिया(दिमनी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्याओं का विरोध करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ. शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में रखती है. सभी कह रहे हैं कि न मंत्री के, न किसी विधायक के, न मेरे, किसी के बच्चे नाती

सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि ज्यादा से ज्यादा 5 परसेंट बच्चा गांव में पढ़ता है इसका कारण है और वह यह है कि एक विधायक जी ने बताया था कि यदि गांव का ही शिक्षक होगा तो पहले तो अपने काम करेगा फिर एक ऐसी चीज चल गयी है तम्बाकू, तम्बाकू हाथ में खाने के लिए लेकर के और दो चार लोगों को बैठा के चार घण्टे टाइम पास करेगा. मुख्यमंत्री जी ने योजनाएँ तो बहुत चलायी हैं और उन योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है लेकिन इसको कोई भी नहीं देख रहा है. आप किसी भी गांव में चले जाओ, एक शिक्षक आएगा तीन शिक्षकों के ऊपर, वह उनकी दरख्वास्त ले लेगा, लिख के धर लेगा. जैसे ही कोई अधिकारी आयेगा उनको दे देगा. ज्यादा अगर अधिकारी करेगा तो लिख के ले जाएगा तो मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि कि सरकारी स्कूलों में बच्चे तभी पढ़ेंगे जब मास्टरों की एक कमेटी बनायी जाएगी, अब क्लास में 5-10 या 15 लड़के पढ़ते हैं, उनका दो महीने में, चार महीने में एक बार उनका टेस्ट लिया जाए और शिक्षकों को बताया जाए कि यह लड़का कितना होशियार है. आज स्थिति यह है कि गांव में सरकारी स्कूल में पांचवी,आठवी के बच्चे के पास कोई भी चला जाए उसको अपना और अपने पिताजी का नाम लिखना नहीं आयेगा. सरकारी स्कूलों में इतना खर्चा हो रहा है कि किसी अन्य विभाग में इतना खर्चा नहीं हो रहा होगा. उनको जो तनख्वाह मिल रही है यदि वह शिक्षक सही नहीं पढ़ा रहा है तो उसकी तनख्वाह काटी जाए, अगर उनकी कक्षा का लड़का फेल होता है तो उनकी तनख्वाह काटी जाए और कमेटी बनायी जाए जो दो महीने, चार महीने में जाकर उनकी जांच करे,यही मेरा सुझाव है.

श्री सोहनलाल बाल्मीक- उपाध्यक्ष महोदय जी,यही बात तिवारी जी बोलते तो सामने से (xx) सब खड़े हो जाते, अब कोई नहीं बोल रहा.

श्री के. के. श्रीवास्तव—यह शब्द क्या है? यह कौन सी संसदीय भाषा है. आप इसको विलोपित करवा दें

सभापति महोदय—श्रीवास्तव जी बैठ जाएं.

श्री बलबीर सिंह डण्डौतिया—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि एक समिति बना दें, उस समिति में सरपंच या विधायक और सरकारी अधिकारी उस समिति में हों और वे उनकी जांच करें महीने में, पन्द्रह दिन में जांच करें, अगर कोई शिक्षक नहीं पढ़ाता है उनकी तनख्वाह कम की जाए. उपाध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया,धन्यवाद.

श्री संजय शर्मा(तेदूखेड़ा)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27,77 के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ.सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन दस वर्षों के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आपने किया है . मध्यप्रदेश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों की आस्था सरकारी स्कूलों के प्रति, सरकारी तंत्र के प्रति बढ़ी है. 1993 से लेकर के 2003 तक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आयी थी निश्चित ही पूरे प्रदेश के लोगों का भरोसा शासकीय विद्यालयों से उठ गया था क्योंकि शिक्षाकर्मियों की जो भर्ती हुई थी उसमें जिसप्रकार से कम तनख्वाह में काम किया गया था और उससे भी बड़ी विसंगति दोनो वर्ग में, काफी स्तर नीचे आया. आज के समय में सरकार स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी हैं उनकी मंशा शिक्षकों को प्रोत्साहन की की व्यवस्था , विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत से ऊपर बारहवीं में आने वालों को 25 हजार रुपये की राशि कम्प्यूटर खरीदने के लिए, मध्यांह भोजन की व्यवस्था, नि:शुल्क साइकिल की व्यवस्था पूरे पाठ्य पुस्तक निशुल्क देकर जो योजनायें प्रदेश में लागू की हैं इससे प्रदेश के..

उपाध्यक्ष महोदय-- आप अपने क्षेत्र की मांग रख लें.

श्री संजय शर्मा-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र की बात भी रखूंगा लेकिन हमारी सरकार ने जो काम किये हैं उसकी भी बात रखनी पड़ेगी तब ही क्षेत्र की बात पूरी होगी. माननीय मंत्री जी, बीच में बात आई थी कि शासकीय स्कूलों में दर्ज संख्या कम रहती है तो उसके लिए मेरा

सुझाव है कि अगर हम अपने एक-एक मॉडल स्कूल जैसे उत्कृष्ट विद्यालय बनाये थे उसी तर्ज फिर से एक स्कूल एक विधानसभा या एक जनपद में बनाये जायें जिसमें सभी विषय रहे, शिक्षकों की संख्या पूरी रहे ,पढ़ाई की पूरी व्यवस्था वहाँ पर रहे. भवन अच्छे रहे तो निश्चित ही प्राइवेट स्कूल की बराबरी पर हमारे स्कूल चलेंगे. चूंकि विषय पूरे नहीं रहते शिक्षक पूरे नहीं रहते इसलिए शासकीय स्कूलों में लोगों को एडमीशन कराने में दिक्कत होती है और जहाँ पर वर्ष 2007-08 में हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल मंजूर हो गये हैं वहाँ पर भवन नहीं बने हैं इस कारण से दिक्कत हो रही है . मेरी विधानसभा में एक पनारी है, शाहपुर है, देवरी है यहाँ पर भवनों के प्राक्कलन की राशि के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त है इस कारण वहाँ पर दो तीन वर्षों से भवन बनना निश्चित नहीं हो पा रहा है इनकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो जाए तो भवन बन जाएंगे जिससे उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी राहत मिलेगी. कुछ हमारे यहाँ पर प्राथमिक शालायें हैं जिनका माध्यमिक शालाओं में उन्नयन करना है. इमर्रा,बम्हौरी इन माध्यमिक शालाओं को उन्नयन कर हाईस्कूल खोले जाएं और सभी प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में जो रखरखाव की राशि पांच हजार या दस हजार रखी है इसको अगर बढ़ा दें तो रखरखाव व व्यवस्था अच्छी होगी . पांच हजार, दस हजार की राशि में रखरखाव अच्छे से नहीं हो पाता है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में खेल मैदान के लिए जगह नहीं है . अगर हम पंचायत के माध्यम से , पंचायत को जिम्मेदारी दे दें तो खेल मैदान अच्छे से बन जाएंगे. मेरे यहाँ एक ग्राम डोभी है ,वहाँ पर स्कूल में कामर्स का विषय पहले था किन्तु अभी बंद कर दिया गया है , इससे वहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है अतः पुनः वहाँ पर कामर्स विषय चालू किया जाये जिससे कि बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो . आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय--- माननीय मंत्री जी, अब अपनी बात रखें.

श्रीमती ऊषा चौधरी--- मेरा भी नाम था.

श्री रजनीश सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम था.

श्रीमती शकुंतला खटीक--- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम था हमको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय--- आप सभी लोग बैठ जाएं. मेरी बात सुन लें. रजनीश जी आपका नाम नहीं था . मैं खड़ा हूं आप लोग को बैठ जाना चाहिए. मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि नाम किसका है, क्योंकि नामों की सूची मेरे सामने रखी है. मेरा यह अनुरोध है जितना समय एलोकेटेड था जितना नियत था , उससे बहुत ज्यादा हो चुका है और बहुत सारे माननीय सदस्य बोल चुके हैं. फिर भी आप जितने भी पांच-छह लोग हैं, आप लोग आधा-आधा मिनट में अपने सुझाव दे दें. मैं समझता हूं कि इससे काम चल जाएगा.

श्री अरुण भीमावद(शाजापुर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तारीफ तो कर ही रहा हूं पर उसके पहले आसंदी की भी तारीफ में कुछ कहना चाहता हूं कि मां सरस्वती ज्ञान दिलाती है, नर्मदा मान दिलाती है और योग्यता स्थान दिलाती है और अगर तीनों मिल जाए तो इंसान को सम्मान दिलाती है यह आपमें हमने देखा है . इसलिए आपके सम्मान में मैंने यह बातें कही हैं .

उपाध्यक्ष महोदय--- लेकिन अब तीस सेकेंड हो गये हैं .

श्री अरुण भीमावद - मैं सरकार के समर्थन में बात कर रहा हूं निश्चित रूप से मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और आदरणीय पारस जी जैन साहब ने अनेक ऐसे कार्य किये जिसके कारण से एक जनआंदोलन बना है. अभी-अभी हमने देखा था पिछले चुनाव के समय एक नारा प्रचलित हुआ था कि अबकी बार मोदी सरकार उसी तर्ज पर पूरे मध्यप्रदेश की धरती पर प्रत्येक गांव में गलियो में एक नारा प्रचलित हुआ है कि स्कूल चलें हम. निश्चित रूप से मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी

ने स्कूलचलें हम को जनआंदोलन बनाया है और आज प्रत्येक गांव में हमें खुशी है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको छोड़ने के लिये उसके मां-बाप निकल रहे हैं एक सरपंच निकल रहा है जनप्रतिनिधि निकल-निकलकर उसको स्कूल भेज रहे हैं. इसलिये इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पारस जी जैन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने सुझाव के रूप में शाजापुर नगर में एक कन्या हायर सेकेंड्री विद्यालय है वह 30 वर्ष पुराना है और उसका अपना निजी भवन नहीं है वह माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंड्री स्कूल की भूमि भी उसको मिल चुकी है कृपया वहां भवन की राशि मंत्री जी स्वीकृत करवाएं. मैं यह भी निवेदन मंत्री जी से करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ल्यादोन और सतगांव दो हाईस्कूल हैं यहां हायर सेकेंड्री स्कूल खोले जाएं. यहां अध्यक्षीय दीर्घा में ग्राम चोसला के ग्रामीणजन उपस्थित हुए हैं. वे यहां इस आशा से आए हुए हैं कि बरसों से जो उनकी मांग हाईस्कूल की चली आ रही है तो माननीय मंत्री जी ग्राम चोसला में हाईस्कूल खोला जाए और मण्डोला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान उसको प्रथम पंक्ति में रखा था मण्डोला को वहां भी हाईस्कूल खोला जाए. तिलावद गोविंद और लड़ावद दो ऐसे गांव हैं जहां बरसों से हाईस्कूल की मांग चली आ रही है. इन दोनों गांवों में भी अगर हम हाईस्कूल खुलेगा तो वहां के बच्चों को लाभ होगा. आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री कमल मर्सकोले(बरघाट) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. शिक्षा का क्या महत्व है यह हम सब जानते हैं. शिक्षा की मनुष्य की मूल आवश्यक्ता है. निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने स्कूल चलें हम को एक जनआंदोलन बनाया है और उसमें उन्होंने आमजनता को भी इसमें सहभागी बनाने के लिये जो आव्हान किया है निश्चित रूप से वह सराहनीय है और इसके परिणाम शतप्रतिशत आ रहे हैं. सरकार ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये अच्छा काम किया है. मंत्री जी से मैं अपने क्षेत्र की मांग

रखना चाहता हूं. जो हमारी माध्यमिक स्कूलें हैं उनको उन्नयन करके हाई स्कूल किया जाए ये स्कूल हैं- माध्यमिक शाला ग्वारी, माध्यमिक शाला नयेगांव,बमनी,जेवनारा,आमागढ़,साल्हेकला,मोहगांव यादव और ऐरमा. वहीं कुछ स्कूलों को हाईस्कूल से हायर सेकेंड्री स्कूल में उन्नयन किया जाए यह स्कूल हैं- मऊ,ताखलाकला,भमौरी,चिमनाखारी,धोबीसर्रा,दौंदीबाड़ा,पाटन और रिड्डी. उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री बहादुर सिंह चौहान—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में छः ग्रामों में हाईस्कूल की व्यवस्था नहीं है जो कि इस प्रकार हैं, ग्राम हीड़ी, बनबना, सेमलिया, बरखेड़ा बुजुर्ग, डबलसिया, लसूड़िया मंदसूर इन ग्रामों में हाईस्कूल खोलने की व्यवस्था करने के लिये मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय—आपकी बात आ गई है.

श्री सोहनलाल वाल्मीक (परासिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय निर्धारित कर दिया है मैं शुरूआत में यह जरूर कहूंगा कि माननीय हमारे जितने भी पक्ष के सदस्य हैं उन्होंने शिक्षा नीति, मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी बहुत तारीफ की यह उनका अपना कर्तव्य था वह अपने तरीके से निभाया. मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं कहना चाहता हूं कि हमको सच्चाई को स्वीकारना चाहिये आज मुझे बताईये सदन में जितने भी सदस्यगण बैठे हैं क्या उनके बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आईपीएस या आईएएस या उससे कम श्रेणी के लोगों के बच्चे क्या शासकीय स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं हमारे लिये सोचने का विषय है. ह लोग तारीफ कर देंगे और बोल देंगे, यह अलग बात है मगर सच्चाई में जमीन पर हम देखेंगे यह स्थिति नहीं है आज शिक्षा में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, आज काम्पीटीशन का दौर है. प्रायवेट स्कूल की शासकीय स्कूल की तुलना करेंगे तो कहीं न कहीं हम

बहुत पीछे हैं. मैं अपने क्षेत्र की मांग करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में 389 प्राथमिक माध्यमिक शालाएं हैं जिसमें 140 शिक्षक कम हैं इन शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है. 42 शालाएं ऐसी हैं जो हाईस्कूल एवं हायर-सेकेन्डरी की जिनमें 25 भवनहीन हैं उनमें भवन ही नहीं है यह मेरे लिये दुर्भाग्य की बात है. मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो पांच किलोमीटर का निर्धारित किया है कि हाईस्कूल को पांच किलोमीटर के अंदर नहीं खोलेंगे पांच किलोमीटर के बाद खोलेंगे इसका पांच किलोमीटर का जो दायरा है कम किया जाये इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में अंदर हाईस्कूल खोलने की ज्यादा आवश्यकता है ग्राम जमुनिया लेढ़ू, ग्राम गाजनडोह, दमुआमाल, तथा ग्राम खिरसाडोह में हाईस्कूल खोलना जरूरी है. मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कन्या शालाओं की कमी है अगर यह शालाएं भी खोल देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. मेरे क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल खुला हुआ है यह लगभग 3 करोड़ रूपये की लागत से बना है उसका बजट समाप्त हो गया है उसके कारण उसकी बिजली फिटिंग नहीं हुई है, उसकी बाऊंड्रीवाल नहीं बन पायी है तथा वहां पर पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पायी है. आपने समय दिया धन्यवाद.

श्रीमती ऊषा चौधरी (रैगांव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि देश में समान शिक्षा, समान अधिकार की शिक्षा होनी चाहिये सरकारी स्कूलों में 99 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं अगर उन स्कूलों में खाने की व्यवस्था की गई है तो वह बच्चा सिर्फ खाने के लिये आता है उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है यह जो मध्यान्ह भोजन है उसको समाप्त कर दिया जाये उसके एवज में नीचे से लेकर ऊपर तक बंदर-बांट होता है गरीब बच्चों को उनको अधिकार नहीं मिल पाता है अगर सीधे बच्चे के खाते में उसका अधिकार एवं पैसा चला जाये तो जो बच्चा अपनी मां के हाथ री रोटी खाकर जायेगा उसका दिमाग एवं शरीर दोनों दुरूस्त होगा और वह पढ़ाई में भी आगे बढ़ेगा.

उपाध्यक्ष महोदय—इसके लिये आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल लगानी पड़ेगी.

श्रीमती ऊषा चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, यहीं से तो सारे कानून पास होते हैं. मेरा कहना यह था कि उस सरकारी स्कूल में चपरासी का बेटा पढ़े और कलेक्टर का बेटा भी पढ़े तो समान शिक्षा हो जायेगी अगर मंत्री का बेटा पढ़े और मजदूर का बेटा पढ़े तो भी समान शिक्षा हो जायेगी, क्योंकि प्रायवेट स्कूलों में खाने की व्यवस्था नहीं होती है.

उपाध्यक्ष महोदय--आप अपने क्षेत्र के विद्यालयों का उन्नयन नहीं चाहतीं ? यदि चाहती हों, तो आप बता दीजिये.

श्रीमती उषा चौधरी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट में अपनी बात खतम करूंगी. अगर प्रायवेट स्कूलों में खाने की व्यवस्था नहीं होती है वहां के बच्चे 99 परसेंट नंबर लाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे अपना दस्तखत करना नहीं जानते, इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि भोजन की व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिये. दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों में जो 20 सालों से शिक्षक उसी गांव के उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, वह पढ़ाने का काम कम करते हैं, अपने घर का काम ज्यादा करते हैं इसलिये वहां से ट्रांसफर करके बाहर के शिक्षक भेजे जायें. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की समस्या है पोहरी स्कूल में और नयागांव में हायर सेकेंड्री स्कूल करा दिये जायें. भरजनाखुर्द में भी हायर सेकेंड्री स्कूल करा दिये जायें, कोठी नगर पंचायत में हाई स्कूल बालिका करा दिया जाये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद.

श्री जालम सिंह पटेल मुन्ना भैय्या--माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा भी नाम है.

उपाध्यक्ष महोदय--जालम सिंह जी, आप तो हर विभाग पर बोलते हैं, आप अपने सुझाव लिख कर दे दीजियेगा, माननीय मंत्री जी उसको लेंगे, हम यह आसंदी से व्यवस्था दे रहे हैं.

श्री प्रताप सिंह (जबेरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा अच्छी हो, गुणात्मक हो, इस संबंध में दोनों दलों के लोगों की, इस सदन की चिन्ता है और यह बच्चों के भविष्य का प्रश्न है. अच्छी शिक्षा के लिये सभी लोगों के जो अच्छे सुझाव आये, उसका मैं भी समर्थन करता हूं साथ ही मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगें रखता हूं. जैसे हमारे यहां 10 किलो मीटर तक करीब 4 स्कूलों के प्रस्ताव करीब 3 वर्षों से आ रहे हैं यहां पर लेकिन वह उन्नयन नहीं हो पा रहा है माध्यमिक शाला से हाई स्कूल के लिये तो वहां की बेटियां बच्चे हाई स्कूल की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. यह जगहें हैं कुमसी मानगढ़, घटेरा, रौंण और सारसबगली. इसी प्रकार जो हाई स्कूल पहले खुल भी गये थे, उसमें सर्रा, झलौन, हिनोतीपुतरीघाट इनमें करीब 5 वर्षों से भवन नहीं हैं, तो मैं सदन में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में हमारे यहां 2 हाई स्कूल का उन्नयन हो जाये और पुरा हाई स्कूल में फिजिक्स और केमेस्ट्री और गणित के टीचर मिल जाये, तो बहुत अच्छा होगा, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद.

श्री बेल सिंह भूरिया (सरदारपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 77 का मैं समर्थन करता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र जो है, वह भौगोलिक दृष्टि से उबड़-खाबड़ और पहाड़ी एरिया है, वहां ज्यादा आदिवासी भाई लोग पिछड़े हुए हैं. वहां पर एक सख्त शिक्षा परिसर की आवश्यकता है और वहां पर उस क्षेत्र में इसाई मिशनरी के लोग ज्यादा हमारे आदिवासी भाइयों को बहला-फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 100-100 विद्यार्थियों का बालक-बालिका आश्रम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खोला जाये और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिंगनौद में हाई स्कूल उन्नयन कर हायर सेकेंड्री खोला जाये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिंगनौद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 100 बालिकाओं का छात्रावास खुला हुआ है, वह जर्जर टूटे फूटे भवनों में हमने व्यवस्था कर रखी है माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसी साल उसको स्वीकृत कर दिया जाये. इसी तरह

से नयापुरा में हाई स्कूल, तिरला में हाई स्कूल से हायर सेकेंड्री में उन्नयन किया जाये. सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका छात्रावास नयापुरा में खोल दिया जाये. माटोल में हाई स्कूल स्वीकृत कराया जाये, यही निवेदन है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिये मौका दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री पारस जैन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग की मांगों पर 26 लोगों के बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सुझाव आआये हैं , जिनके नाम सुन्दर लाल तिवारी, राजेन्द्र पाण्डेय जी, गोविन्द सिंह पटेल, गिरीश गौतम, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, मुरलीधर पाटीदार जी, जीतू पटवारी, कैलाश जाटव जी, लोकेन्द्र सिंह जी, रामकिशोर जी, दिलीप सिंह परिहार, फुन्देलाल सिंह मार्को, दिलीप सिंह शेखावत, श्री के.के. श्रीवास्तव, दिनेश राय, जयवर्द्धन सिंह, श्रीमती पारुल साहू, सर्वश्री बलवीर सिंह डण्डौतिया,संजय शर्मा, अरुण भीमावद, कमल मर्सकोले, बहादुर सिंह चौहान, सोहनलाल बाल्मीक, श्रीमती ऊषा चौधरी, प्रताप सिंह और वैलसिंह भूरिया. इन सबके महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं. अभी भी मैं सदन में कहना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के और भी सुझाव रह गये हैं, तो वह लिखकर मेरे पास, मेरे विभाग को दे सकते हैं. आदरणीय हमारे सुन्दर लाल तिवारी जी का उपकार मानता हूं कि वे सामने बैठे हैं. मैं उनको चार लाइन बताना चाहता हूं, शिक्षा की स्थिति के बारे में. **परिवर्तन होगा शिक्षा में, जन जन अब आशान्वित है, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, शासन दृढ़ संकल्पित है, नई प्लानिंग शिक्षण की, सब दूर नजर अब आयेगी, शासन के स्कूलों में गुणवत्ता जनता पायेगी, जनता पायेगी.**

उपाध्यक्ष महोदय -- पारस जी, यह कविता आप ही की लिखी हुई है.

श्री पारसचन्द्र जैन --- सभापति महोदय, जी हां.

..(व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक लाइन और जोड़ दें कि यह गुणवत्ता कब तक आयेगी.

उपाध्यक्ष महोदय -- वह बतायेंगे अपने भाषण में. सुनिये तो, धैर्य रखिये.

श्री पारसचन्द्र जैन --- सभापति महोदय, मैं महाकाल की नगरी और कृष्ण एवं सुदामा की शिक्षा स्थली से आता हूं. माननीय सुन्दरलाल तिवारी जी ने बहुत बातें कही हैं और भी सामने के लोगों ने बातें कहीं है कि सरकारी स्कूल की तरफ लोग जाते नहीं हैं. मैं उनको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि विकास खण्ड में उत्कृष्ट विद्यालय मध्यप्रदेश के अंदर चल रहे हैं. मेरे उज्जैन के अंदर भी 85 प्रतिशत अंक के बाद उन उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं. इसका यही कारण है कि शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन कितना सुधरा है और सरकारू स्कूलों की तरफ लोग आकर्षित हुए हैं. अब इसके लिये हमारे मध्यप्रदेश के मुखिया, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्यप्रदेश के अन्दर शिक्षा को सुधारने के लिये और स्कूलों में बच्चे आने के लिये मध्यप्रदेश के अंदर स्कूल चलो अभियान चालू किया है. इसको चार भागों में विभाजित किया गया है. दो जो मुख्य हैं, उनमें शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने का काम हमने उसके अन्दर किया है और हमारी इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में एक प्रेरक योजना हमने इसके अंदर जोड़ी है. आपने देखा होगा कि उस प्रेरक योजना से हर सदस्य जुड़ा है, चाहे समाज सेवी व्यक्ति हो, चाहे मीडिया का व्यक्ति हो. मुझे तो उम्मीद है कि सामने के भी सदन के सदस्य इस प्रेरक योजना से जुड़े हैं और 2 लाख से ज्यादा, प्रेरक योजना के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि इसके साथ साथ हर व्यक्ति की जवाबदारी है, जो सदन के अंदर बैठा है, चाहे नगरपालिका का कोई पार्षद हो बाहर, चाहे पंचायत के अंदर हो, हर व्यक्ति का दायित्व होता है कि हर बच्चे को स्कूल में भर्ती कराने का काम करे. यह स्कूल चलो अभियान हमारा चल रहा है. इसमें राष्ट्रपति महोदय भी आये थे और हमारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी आई थीं. उन्होंने भी

इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है. अभी मेरे पहले बात हो रही थी, जब खेल विभाग की मांगों पर बातचीत आई थी. मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 में विभिन्न राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता हुई है. उसके अंदर 43 स्वर्ण पदक, 45 रजत पदक और 72 कांस्य पदक कुल 160 पदक प्राप्त हुए हैं तथा मेडल सूची के अंदर देश के अंदर 8 वां स्थान है. इसी वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता मध्यप्रदेश में आयोजित की जायेगी. अब तक सबसे अधिक मेडल प्राप्त हमारे मध्यप्रदेश को हुए हैं. यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है. प्रदेश में 2013-14 में हायर सेकेन्डरी स्कूलों में पढ़ने वाली लगभग 66000 बालिकाओं को आत्मरक्षार्थ हेतु प्रशिक्षण दिया गया है. जिसके अंदर जूडो कराटे के अलावा अन्य कला को सीखाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है. विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये टोल फ्री काल सेन्टर तथा मोबाइल , दूरभाष आधारित प्रणाली इस वर्ष प्रारंभ की जायेगी.

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर अध्यापकों का एक इकाई से दूसरी इकाई में आन लाईन संविलियन किये जाने का काम एवं प्राचार्यों और व्याख्याताओं-शिक्षकों की भी पदोन्नति उपरान्त पद स्थापना भी आन लाइन की जावेगी. पहले यह काम नहीं था, शिक्षा को धंधा बना के रखा था लेकिन उसको समाप्त करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है. आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय की पारदर्शिता बनाने के लिये भी हमने कमप्यूटराइज्ड किये जाने का विचार किया है जिससे लोगों को लाभ मिलेगा. शिक्षकों की समस्या एवं शिकायतों का आन लाइन पंजीयन एवं निराकरण एवं मानीटरिंग की व्यवस्था भी शिक्षा विभाग करने के लिये जा रहा है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला एवं संभाग केन्द्रों पर संयुक्त संचालक द्वारा शिक्षकों की पदोन्नति , युक्तियुक्तिकरण एवं स्कूलों का युक्तियुक्तिकरण शीघ्रता से किया जा रहा है. संयुक्त संचालक, उप संचालक, , सहायक संचालक, प्राचार्य, व्याख्याता तथा शिक्षा संवर्ग के आदि पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्रता से मान्य की जा रही है. वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक 1552

माध्यमिक विद्यालय, और हाई स्कूलों में 810 हाइस्कूलों का हायर सेकेन्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है. वर्ष 2011-15 में शहरी क्षेत्र में 50 माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल से उन्नयम एवं 100 हाईस्कूलों का हायर सेकेन्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जायेगा. राज्य के मद से यह खोला जायेगा. हमने केन्द्र सरकार से 1000 हाई स्कूलों की मांग की है . पहले केन्द्र सरकार में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन अभी केन्द्र में हमारी सरकार आई है . मानव संसाधन मंत्री यहां पर आईं थी हमने उनसे बात की है कि मध्यप्रदेश को हाई स्कूल ज्यादा से ज्यादा दिये जायें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम हाई स्कूल आपको देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय-- दिल्ली में भी सरकार आने से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है.

श्री पारस जैन-- उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार से हमको निश्चित रूप से हाई स्कूल मिलेंगे और आवश्यकता पडेगी तो उपाध्यक्ष महोदय हम आपको भी साथ में ले चलेंगे. (हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 में 42 हजार 88 संविदा शिक्षकों के पदों पर आन लाइन शिक्षकों की भर्ती की गई है . सदन के कई सदस्यों ने यहां पर कहा है कि शिक्षकों की कमी है हम 39 हजार शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं और दिसम्बर तक भर्ती का प्रयास किया जा रहा है. शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं. शिक्षण प्रशिक्षण तथा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को राष्ट्रीय तथा अँतरराष्ट्रीय उत्कृष्ठ संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु एक नई योजना प्रारंभ की गई है. इस वर्ष मेरे विभाग द्वारा नई पहल कर विद्यालयों के विकास के लिये एक विद्यालय उपहार योजना लागू की गई है. इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि पहले गांव के अंदर कोई जमीन देता था तो हम उसका नाम भी उपहार योजना के माध्यम से उस विद्यालय पर लिखते थे, कोई जमीन देगा या शाला के कमरे

बनायेगा तो भी हम उसका नाम लिखेंगे .उपाध्यक्ष महोदय, फर्नीचर , कम्प्यूटर , खेल सामग्री,बाऊंड्री वॉल आदि के लिए भी उपहार योजना में समावेश किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, शासकीय एवं अशासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों में अध्ययनरत् ऐसे छात्र जिनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और कक्षा 12 वीं में जिन छात्र-छात्राओं को 85 प्रतिशत से ज्यादा अंक मिले हैं उनको कम्प्यूटर के लिए 25 हजार रुपये की राशि दी जा रही है. इसके अंतर्गत 10511 प्रतिभाशाली छात्रों को यह राशि प्रदान की गई है.

उपाध्यक्ष महोदय, कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् लगभग 94 लाख छात्र-छात्राओं को दो जोड़ी गणवेश हेतु रुपये 400 प्रति छात्र के मान से राशि चेक के माध्यम से वितरित की गई है.कक्षा 5 और 6 तथा कक्षा 8 से 9 तक अध्ययन के लिए पास के गांव से जाने वाले 9 लाख छात्र-छात्राओं को सायकल हेतु राशि 95 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में अध्ययरत् कक्षा 1 से 12 वीं तक के लगभग 1 करोड़ 30 लाख छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी जा रही है. जिस पर लगभग 220 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार की बात सदस्यों ने उठायी है. अधिनियम 2009 प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है. इसके तहत वंचित एवं कमजोर समूह के 4.95 लाख विद्यार्थियों को प्रदेश के प्रतिष्ठित प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाया जा चुका है. वर्ष 2014-15 में अब तक लगभग 70 हजार से अधिक बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाया जा चुका है.

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के मॉडल का अनुकरण करने की योजना का पैसा भी इस मद में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इनकी फीस का दिया जाता है. राज्य शासन के 9

विभागों की 30 प्रकार की समेकित छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से वितरित करने हेतु शिक्षा विभाग को नोडल विभाग निर्धारित किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के शासकीय, अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् 1 करोड़ 84 लाख छात्रों में से छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन राशि स्वीकृत कर सीधे हितग्राही के खाते में भुगतान की कार्रवाई की जा रही है.

आज दिनांक तक लगभग 1 करोड़ 35 लाख छात्रों की मेपिंग की जाकर 94 लाख छात्रों को 294 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति ऑन लाईन स्वीकृत की जा चुकी है. लगभग 105 करोड़ रुपये का ऑन लाईन भुगतान किया जा चुका है.

उपाध्यक्ष महोदय,विद्यालयों को एक ही स्थान पर एक ही बार कक्षा 1 में आवेदन तथा एक ही बार जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जायेगा यह व्यवस्था सरकार ने की है. छात्रों की जो राशि रहेगी वह सीधे छात्रों के खाते में जमा होगी. स्कालरशिप मिलाने की वित्त विभाग से सहमति मिलने पर वह स्कालरशिप भी दी जायेगी. इसकी मांग पिछले साल उठी थी.उपाध्यक्ष महोदय, अगस्त - सितम्बर 2014 तक बांट दी जावेगी. इस वर्ष दिसम्बर तक बांट दी गई है. शिक्षा विभाग द्वारा 105 करोड रुपये और सभी विभागों द्वारा 200 करोड़ रुपये की शिक्षावृत्ति बांटी जा चुकी है.भविष्य में पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साईकिल वितरण एवं अन्य योजनाएं भी समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी. इस वर्ष 1445 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा रही है. जिसमें कम्प्यूटर आधारित शिक्षा दी जाएगी. इसी प्रकार 224 विकासखणडों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना की जा रही है. उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 36 विद्यालयों में यह प्रारंभ हो गई है. जिसमें विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों की शिक्षा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दी जाएगी.

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में मदरसों के द्वारा भी गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की योजना संचालित है. इसके अंतर्गत 1490 मदरसों को अनुदान प्राप्त हो रहा है. वर्ष 2013-14 से मदरसों में कार्यरत् शिक्षकों के वेतन का भुगतान ई-बेंकिंग के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जा रहा है. प्रदेश के समस्त विद्यालयों की जी.आई.एस मेपिंग की जा रही है, जिसके माद्यम से विद्यालयों की भौगोलिक स्थिति एवं कक्ष, प्रयोगशाला आदि की स्थिति का आंकलन एक क्लिक पर (एजुकेशन पोर्टल) उपलब्ध रहेगा. अब तक लगभग 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. जुलाई माह तक समस्त शालाओं की मेपिंग हो जाएगी.

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में हाईस्कूल स्तर तक बच्चों के नामांकन की दर 41 प्रतिशत से बढ़कर 81 प्रतिशत हो गई है. इस अभियान के तहत 944 हाईस्कलों में भवन निर्माण एवं 4178 विद्यालयों में 28925 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें अतिरिक्त कक्ष प्रयोगशाला पुस्तकालय पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि पुस्तकालय नहीं हैं. पुस्तकालयों की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है. शाला भवन एवं उनमें शौचालय तथा पेयजल की मूलभूत व्यवस्थाएं करना भी हमारी सरकार का लक्ष्य है.

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं के लिए 207 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं 324 बालिका छात्रावास संचालित हैं, जिसमें लगभग 49600 छात्राएं अध्ययनरत् हैं तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् बालिकाओं के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 201 विकास खण्डों में छात्रावास आरंभ किये गये हैं. इनमें लगभग 17000 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं. इसके अतिरिक्त निःशक्त बच्चों के लिए 58 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं. साथ ही बेघर व अनाथ बच्चों के लिए 15 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, कक्षा 9 वीं में इस वर्ष 50 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की गई है. इन विद्यालयों में इस वर्ष 2 ट्रेड आई.टी. एवं सिक्योरिटी आरंभ किये गये हैं. इससे लगभग 2500 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे. इस योजना से विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे. प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर 41 उत्कृष्ट विद्यालय एवं 194 विकासखण्ड मुख्यालयों पर उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं, इन विद्यालयों का बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 90 प्रतिशत से अधिक रहा है. इसके अतिरिक्त शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 201 विकासखण्डों में केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूल आरंभ किये गये हैं. इनमें 31000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं. इन स्कूलों के भवन हेतु 297 लाख प्रति भवन का प्रावधान है. अभी तक 16 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. शेष में निर्माण कार्य प्रगति पर है. उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने जो बात कही थी, मैं उनको जवाब पत्र के द्वारा दूंगा. लेकिन हमारे श्री लोकेन्द्र सिंह जी और श्री पाटीदार जी और सबका मत है और उसमें मेरा भी मत है कि पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षाएं वापस प्रारंभ होना चाहिए. इसके लिए हमने भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया है, मेरी भी मंशा यह है कि पांचवीं और आठवीं बोर्ड निश्चित चालू होना चाहिए. श्री के.के. श्रीवास्तव साहब ने भी कहा है, उन्होंने जो नवीन हाईस्कूल टीकमगढ़ में होना चाहिए, मैं आज घोषणा करता हूं कि आपके यहां नवीन हाईस्कूल खोल दिया जावेगा. (मेजों की थपथपाहट)..उपाध्यक्ष महोदय, श्री दिनेश राय जी के क्षेत्र सिवनी के मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है, उनकी भी वहां पदस्थापना की जावेगी. श्री दिलीप सिंह परिहार के क्षेत्र में नीमच डाइट की मान्यता हेतु प्रस्ताव एनसीटीई को भेजा गया है. वहां से आने के बाद यह बात भी हो जाएगी.

श्री दिलीप सिंह परिहार - माननीय मंत्री जी धन्यवाद.

श्री पारसचन्द्र जैन - माननीय श्री पाटीदार जी ने बीमे की बात भी कही है, उसकी बात मैं आपसे कह चुका हूं. आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि मेरी मांगों का समर्थन कर उन्हें पास किया जाय.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—माननीय मंत्री जी मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ये उत्कृष्ट महाविद्यालय में उसी विद्यालय के 9 वीं के बच्चे जब पढ़ कर निकलते हैं और दसवीं में उनका एडमिशन होना होता है तब वे अपने स्कूल के बच्चों को नहीं लेते हैं और उनके मनचाहे विषय नहीं देते हैं . यह कह कर निकाल देते हैं कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं. और दूसरे विद्यालय के अच्छे बच्चों को भर लेते हैं ,उससे उनकी मेरिट बनी रहती है लकिन वो मेरिट फाल्स है, मेरा यह निवेदन है कि पहली च्वाईस उस विद्यालय के बच्चों को देना चाहिए. क्या आप ऐसा निर्देश जारी करेंगे.

श्री पारस जैन—आदरणीय तिवारी जी जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनके नियम बने हुए हैं वे मेरिट के आधार पर ही , मेरिट से भी कम के किसी व्यक्ति को लेते हैं तो आप शिकायत कराओं मैं उनको एडमिशन कराने का काम करूंगा.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—आप मेरी ..

एक माननीय सदस्य—मेरा एक निवेदन है कि अगर एक उत्कृष्ट विद्यालय एक विकास खंड स्तर पर है ,अगर बच्चे उस क्रायटेरिया में नहीं आएंगे तो वो बच्चे पढ़ने कहां जाएँगे.

उपाध्यक्ष महोदय—आप लोग मंत्री जी से मिल कर अलग से बात रख दीजिए. तिवारी जी आपकी बात आ गई है. क्षमा करें. (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—क्लेरीफाय कर दें, क्योंकि मंत्री जी ने जवाब दिया है. बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कही है. (व्यवधान)

6.49 बजे { अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए }

अध्यक्ष महोदय—अब मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा. प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 एवं 77 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएं.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि 31 मार्च,2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को—

अनुदान संख्या- 27	स्कूल शिक्षा(प्रारंभिक शिक्षा) के लिए छः हजार, पांच सौ सात करोड़, इकसठ लाख, उनहत्तर हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या-77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय(प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर) के लिए दो हजार तीन सौ तिरासी करोड़, चौदह लाख, चौबीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई,2014 को प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 6.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 17 जुलाई, 2014(26 आषाढ़, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल, **भगवानदेव ईसरानी**

दिनांक :16 जुलाई,2014 प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधानसभा